दुनिया के सर्वहारा तथा तमाम
मेहनतकश जनता और उत्पीड़ित
राष्ट्रीयताओं की जनता एक हो!

लाल चिनगारी

वर्ष–14 अंक–36 जनवरी–मार्च, 2018

मुखपत्र

बिहार–झारखण्ड
स्पेशल एरिया कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी
(माओवादी)

झूठा गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित 'काला दिवस' कार्यक्रम में एक कामरेड द्वारा पेश की गई कविता 'गणतंत्र या गनतंत्र?'

जब से मैंने होश संभाला
आज के दिन कंपकंपाती ठंड में भी
सुबह-सुबह नहाकर, हाथ में तिरंगा लिए
सबसे आगे रहकर प्रभातफेरी में
गणतंत्र दिवस की खुशी में
पूरे दम के साथ लगाया नारा।

मेरे स्कूल में प्रतिदिन होता था
संविधान की प्रस्तावना का पाठ
जिसमें सिखाया जाता था
बराबरी व भाईचारे की बात
लेकिन प्रतिदिन होता था
क्लास में प्रस्तावना के विपरीत बात
मेरा एक सहपाठी था 'हरिजन'
जिसे बैठाया जाता था सबसे पीछे
स्कूल में झाड़ू-पोछा भी था उसी के हिस्से।
घर में भी सिखाया जाता था
प्रस्तावना के विपरीत ही बात
जाति व धर्म की सर्वोच्चता की बात
मेरा बाल मन पड़ गया असमंजस में।
क्या है सही
वो, जो देख रहा हूं
या वो, जो लिखा है प्रस्तावना में?

जब मैं पहुंचा कॉलेज में
तब तक पढ़ चुका था
संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को
पढ़ चुका था मैं भगत सिंह के विचारों को।
मैंने देखना शुरु किया
रोज-ब-रोज व हर क्षेत्र में
संविधान में लिखी बातों की उड़ती धज्जियों को।
मैं कूद पड़ा छात्र आंदोलन में
संविधान में लिखी बातों को लागू कराने के लिए
करने लगा आंदोलन व धरना-प्रदर्शन
बदले में मिला मुझे
दर्जनों फर्जी मुकदमे व पुलिस की लाठियां
छोड़ दिया मैंने शामिल होना
गणतंत्र दिवस समारोह में।

कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही
निकल पड़ा सुदूर देहात में
संविधान में लिखित बातों को बताने
उसपर सरकार द्वारा अमल कराने
जनता को गोलबंद करने
और व्यापक जनांदोलन खड़ा करने।
वहां जाकर देखा मैंने
गणतंत्र तब्दील हो चुका है 'गनतंत्र' में
इस संविधान से आशा करना है फिजूल
हमें उतरना होगा नया संविधान के निर्माण में
हमें स्थापित करनी होगी नयी व्यवस्था।

अब मैं उतर चुका हूं
इस 'गनतंत्र' को ध्वस्त कर
वास्तविक गणतंत्र की स्थापना की लड़ाई में
कॉमरेड माओ के अनुसार
क्रांति के तीनों जादुई हथियार
पार्टी, जनसेना व संयुक्त मोर्चा को
बलशाली बनाने की लड़ाई में
दीर्घकालीन लोकयुद्ध के जरिए
इलाकावार सत्ता दखल की लड़ाई में
और आज 'काला दिवस' मनाते हुए भी
मैं ले रहा हूं संकल्प
अपने शरीर के खून की अंतिम बूंद तक
लड़ता रहूंगा इस 'गनतंत्र' के खिलाफ
जनता के वास्तविक गणतंत्र के लिए।।

लाल चिनगारी

वर्ष-14 अंक: 36
जनवरी-मार्च, 2018

विषय सूची:

1. सम्पादकीय 1
2. ऐ लाल फरेरे तेरी कसम... 21
3. का. मार्क्स के जन्मदिन... 26
4. जनता को जागृत करने... 28
5. नोटबंदी-जीएसटी-जीएम... 31
6. झारखंड में महिला आंदोलन... 35
7. भारत-इजरायल मैत्री... 38
8. भारत में फासीवाद की... 39
9. एमएसएस पर प्रतिबंध... 43
10. कविताएं 50
11. महत्वपूर्ण बुकलेट व पर्चे 53
12. प्रेस विज्ञप्ति 66
13. पीएलजीए की महत्वपूर्ण कार्रवाइयों की रिपोर्ट 69

सहयोग राशि - 20 रूपये

सम्पादकीय

इआरबीएस का साक्षात्कार

(लाल चिनगारी संपादकमंडल द्वारा लिया गया हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी की पूर्वी रीजनल ब्यूरो के सचिव कामरेड किसान के साक्षात्कार को ही हम इस अंक में सम्पादकीय के बतौर प्रकाशित कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति के बारे में हमारी पार्टी का मूल्यांकन समेत कई तात्कालिक विषयों पर हमारी पार्टी का मत जानने के लिए यह साक्षात्कार पार्टी सदस्यों, पीएलजीए के योद्धाओं, संयुक्त मोर्चा के साथियों समेत पूरी दुनिया के लिए उपयोगी साबित होगा, इसी उम्मीद के साथ हम इस साक्षात्कार को यहां प्रकाशित कर रहे हैं। - संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

(1) प्रश्न : अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय परिस्थिति के अंतर्गत इआरबी इलाकों के अंदर वर्तमान परिस्थिति का आप कैसे मूल्यांकन करते हैं?

उत्तर : इस सवाल का मूल अंश पर कुछ बोलने के पहले मैं मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व घरेलू परिस्थिति पर थोड़ी चर्चा करना चाहुंगा।

अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति : यह सर्वविदित है कि विगत 2008-2009 से साम्राज्यवाद का जो आर्थिक व राजनीतिक संकट की शुरूआत खुद साम्राज्यवाद के सरगना अमेरिका से हुई थी, वह संकट क्रमशः समूचे यूरोप सहित तमाम साम्राज्यवादी देशों में फैल गया और आज जब 2018 शुरू हो रहा है, तब यह बात जोरपूर्वक कही जा सकती है कि 9/10 वर्ष पार होने के बावजूद इस संकट का निकट भविष्य के अंदर कम होने या दूर होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा है। बल्कि, अमेरिका में मौजूदा समय में और खासकर नया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद पहले से चली आ रही जन-विरोधी नीतियों के साथ और कुछ खूंखार दमनात्मक नई जन-विरोधी नीतियों व नियमों को जोर-जबरन लागू किये जाने के कारण जारी संकट और गहराते जा रहा है। फिर, संकट का हल नहीं होते देख डोनाल्ड ट्रम्प ने 'अमेरिका फर्स्ट' या 'अमेरिका के हित सर्वोपरि (सबसे उपर) है' का नारा देकर पूरी दुनिया को अमेरीकी हित व वर्चस्व को मान लेने खातिर डरा-धमका रहा है। फिलहाल, समूची दुनिया के पैमाने पर अपना आधिपत्य व वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से रूस-चीन को सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में मानकर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका की प्रतिरक्षा व्यय में विशाल राशि का अनुमोदन की घोषणा की गयी है।

आर्थिक-राजनीतिक संकट ही वह आधार है, जिससे और ज्यादा लूट-शोषण के लिए खूंखार जन-विरोधी नीतियां अपनायी गयी हैं और अपनायी जा रही हैं। फिर भी आर्थिक व राजनीतिक संकट और गहराते जाने के तमाम लक्षणों की व्यापक अभिव्यक्तियां भी स्पष्ट परिलक्षित हो रही हैं। उदाहरणस्वरूप वे हैं : जनता का स्वास्थ्य संबंधी सुविधा सहित जन-कल्याण के लिए व्यय में भारी कटौती करना, 'कर सुधार बिल' लाकर गरीबों के करों में बढ़ोतरी और अमीरों के करों को कम करना, मजदूर वर्ग के वेतन व अधिकारों को संकुचित करना, उग्र राष्ट्रवाद व रंग भेद नीति को बढ़ावा देने के कारण काले लोगों पर अत्याचार की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होना, मुस्लिम देशों के लोगों को अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाना, फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ

जायनवादी-यहूदीवादी इजरायल को हर प्रकार का समर्थन व मदद देना, ऐसाकि तमाम अंतरराष्ट्रीय जनमत को बिलकुल नजरअंदाज कर यरूशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देना, आम मुसलमान जनता को आतंकी करार देकर उनके खिलाफ व्यापक घृणा व आक्रोश को बढ़ावा देना व उन पर शारीरिक हमले करने में उकसवा देना इत्यादि ताजा मिसालें हैं।

जाहिर है कि जर्मनी, फ्रांस-इंग्लैण्ड सहित यूरोप के अन्यान्य देश तो पहले से ही बतौर साम्राज्यवादी देश मौजूद है ही हैं। यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ अमेरीकी साम्राज्यवाद का आपसी विरोध भी क्रमशः बढ़ता ही जा रहा है। जैसा साझा व्यापार संधि के सवाल पर व यरूशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के सवाल पर जारी काफी विवाद स्पष्ट है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) की बैठक के दौरान विश्व के पैमाने पर एक स्थायी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण के सवाल पर जब समूचा यूरोपीय यूनियन व चीन सहित सभी देश इसके पक्ष में मत प्रकट किया, तब अमेरिका ने इसका कट्टर विरोध किया। फिर, विश्व जलवायु परिवर्तन व ग्लोबल वार्मिंग विश्व के पैमाने पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड व कार्बन उत्सर्जन कम करने के सवाल पर सभी देशों की आम सहमति व राय को अमेरिका द्वारा मानने से इन्कार किया गया। फलतः, यूरोपीय यूनियन के साथ अमेरिका का अंतरविरोध भी तीखा हुआ। एशिया के जापान तो पहले से ही आर्थिक तौर पर शक्तिशाली एक साम्राज्यवादी देश के बतौर अपनी भूमिका निभाते आ रहा था। पर, आज के समय में जापान को भारी संकट की मार झेलनी पड़ रही है और वह पहले से अपेक्षकृत कुछ कमजोर भी हुआ है।

फिर, मौजूदा विश्व में रूस देश तो एक शक्तिशाली साम्राज्यवादी देश के बतौर अपनी भूमिका निभा ही रहा है। पर, साम्राज्यवादी आर्थिक-राजनीतिक संकट से वह भी अछूता नहीं है। जिसकी अनेक अभिव्यक्तियां अभी दिखाई पड़ रही हैं। रूस और चीन- दोनों आपस में एक गठबंधन बनाकर अमरीकी साम्राज्यवाद का अकेला का वर्चस्व व आधिपत्य विस्तार के खिलाफ तीखा विरोध में उतर पड़ा है। साथ ही साथ 'ब्रीक्स' व शंघाई को-आपरेशन के नाम से कई देशों का एक गठबंधन बनाया है और एक विकल्प बैंक भी बनाया है। फिलहाल, दुनिया में दूसरी अर्थव्यवस्था वाला देश के रूप में विद्यमान चीन एक शक्तिशाली साम्राज्यवादी देश के बतौर उभरा है। जिसके कारण साम्राज्यवादियों के बीच की प्रतिस्पर्धा और तीखी हो गयी है और अनिवार्यतः साम्राज्यवादी देशों द्वारा एशिया-अफ्रीका-लातिन अमेरिका के तमाम पिछड़े हुए देशों में उदारीकरण, निजीकरण व भूमंडलीकरण की नीति को जबरन थोप कर लूट-खसोट की मात्रा बहुत हद तक बढ़ा दी गयी है। खासकर व्यापक पूंजी निवेश, खनिज सम्पदा सहित तमाम प्राकृतिक सम्पदा की लूट, सस्ता श्रमशक्ति, मालों का बाजार के रूप में लूट की चरागाह बना दी गयी है। फिर, अपनी लूटपाट की जगहों की वृद्धि करना, प्रभावाधीन इलाके को बढ़ाना तथा विश्व-बाजार का दखल व पुनर्दखल करना इत्यादि को लेकर साम्राज्यवादियों के बीच तीखा छीना-झपटी व कुत्तों की लड़ाई जारी है।

मौजूदा समय में एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के कई जगहों में साम्राज्यवाद द्वारा प्राक्सि युद्ध या स्थानीय युद्धों का उकसावा देना और खासकर पश्चिमी एशिया, अरब देश व अफ्रीका के कई देशों में दलाल शासक गुटों के अंदर फूट डालकर तथा एक को दूसरे के खिलाफ लड़वाकर पूरे देश को मार-दंगा-हत्या-पल्टा हत्या के स्थान में बदल दिया गया। जिसके कारण हजारों-लाखों की संख्या में नरसंहार और व्यापक संख्या में महिलाओं की इज्जत लूटे जाने की घटनाएं बेरोकटोक जारी है, हजारों लाखों की तादाद में विस्थापित होने की घटनाएं भी बेरोकटोक जारी है। सीरिया, लीबिया, यमन आदि देश इसकी ताजा मिसाल है और अफगानिस्तान व इराक तो अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा हजारों-लाखों टन बम गिराए जाने के कारण खंडहर में बदल गया है और अभी अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा पूरे ईरान व उत्तर कोरिया को भी खंडहर में बदल देने की धमकी दी जा रही है।

म्यानमार के रखाईन प्रांत से अन-सन-सूची सरकार द्वारा जब लाखों आम रोहिंग्या मुस्लिमों को आतंकी होने का बिल्ला लगाकर व्यापक हत्या, आगजनी, बलात्कार जैसा मध्ययुगीन अत्याचार के जरिए अपने वासभूमि से विस्थापित कर देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है तब तमाम दुनिया के जनमत की उपेक्षा कर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उसका शागिर्द भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी म्यानमार सरकार की उक्त चरम प्रतिक्रियावादी कार्यवाही का खुल्लम-खुल्ला समर्थन जताए हैं। न केवल समर्थन-ही जताए हैं बल्कि भारत से भी शरण लिए हुए रोहिंग्या मुसलमानों को तुरंत भगा देने की जुल्म-भरी कार्रवाई भी जारी है। फिलहाल, अमेरिका द्वारा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी आतंकवादियों के मददगार व पनाहगार का आरोप लगाकर आर्थिक सहयोग की राशि न देने सहित अन्यान्य अनेकों प्रकार के प्रतिबंध व धमकियां दी जा रही हैं; लातिन अमेरिका के विभिन्न देशों पर भी और खासकर वेनेजुएला व क्यूबा पर अनेक प्रकार प्रतिबंध लगाया गया ताकि उक्त देशों की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर होकर अमेरिका के आदेश पर चलने पर मजबूर हो जाए।

विपरीत तौर पर, एशिया, अफ्रीका व लातिन अमेरिका में खूंखार अमरीकी साम्राज्यवाद तथा समूचा साम्राज्यवाद विरोधी मनोभाव बहुत ही स्पष्ट है। फलस्वरूप, साम्राज्यवाद के साथ उत्पीड़ित राष्ट्रों और जनता के बीच अंतरविरोध और तीखा हुआ है तथा रोज दिन उसमें और वृद्धि हो रही है। भारत, फिलिपिन्स, पेरू में संचालित लोकयुद्ध इसकी ही ताजा

मिसालें हैं।

फिर साम्राज्यवाद का गहराता हुआ वित्तीय संकट के कारण जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैण्ड आदि यूरोपीय देशों के शासक वर्गों के बीच भी अंतरविरोध बढ़ रहा है। गहराता संकट वह आधार है जिससे इंग्लैण्ड द्वारा यूरोपीय यूनियन से बाहर आने की तथा स्पेन से कैटालोनिया राष्ट्रीयता द्वारा अलग हो जाने की मांग पर जुझारू संघर्ष का उभार होना इत्यादि घटनाएं हुई हैं। फलस्वरूप, इंग्लैण्ड के साथ जर्मनी-फ्रांस सहित समूचा यूरोपीय यूनियन का आपसी अंतरविरोध और तीखा हो गया। तमाम साम्राज्यवादी शासक वर्ग द्वारा इस संकट से निपटने के लिए लागू की गयी तथा की जा रही आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक नीतियां विफल साबित हो गयी है और आज भी हो रही हैं। इसके कारण इन सभी देशों में बेरोजगारी प्रबल हो गयी हैं, आर्थिक विकास में मंदी आयी है, मजदूर-कर्मचारियों के वेतन में और नौकरियों व जन-कल्याण योजनाओं में भारी कटौती की जा रही है। फलस्वरूप, सभी देशों में मजदूर लोग विशाल-विशाल जुलूस-प्रदर्शन व हड़तालों के सफल आयोजन के जरिए विरोध जता रहे हैं। जनता के अन्यान्य अंश भी विभिन्न रूपों के संघर्ष में उतर पड़े हैं। इसके साथ-साथ अन्यान्य अनेक आर्थिक व राजनीतिक कारणों से पूंजीवादी देशों में पूंजीपति वर्ग व मजदूर या सर्वहारा वर्ग के बीच का अंतरविरोध क्रमशः और तीव्र होता जा रहा है।

अभी के समय में विश्व-पटल पर नजर दौड़ाने से जो विशिष्ट पहलुवें दिखाई पड़ती हैं, खूब संक्षेप में वे हैं:-

i. एकल महाशक्ति के बतौर अमरीकी साम्राज्यवाद खुद की हेकड़ी वाली महाशक्ति की भूमिका को बरकरार रखने में अक्षम साबित हो रहा है और नाटो गठजोड़ के देशों को शामिल किए बिना कोई भी आक्रामक कार्रवाई में नहीं उतर पा रहा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का आगमन होने से विरोधी देशों पर बम गिराने व युद्ध थोपने की लफ्फाजी चल रही है। पर ये सब अभी तक फालतू बात ही साबित हुई है। फिलहाल, रूस-चीन को सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में घोषित कर दुनिया के पैमाने पर आधिपत्य व वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रतिरक्षा व्यय में विशाल राशि का अनुमोदन की लफ्फाजी चल रही है। इसके अलावा, अमेरिका व पूरे यूरोप में चरम दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी-फासीवादी विचारों की अभिव्यक्तियां जैसे- 'नस्लवाद', 'उग्र राष्ट्रवाद' व 'फासीवाद' का पुनः तेजी से उभार हो रहा है। ऐसा कि उसके चलते शारीरिक हमले व हत्या की घटनाएं भी दिखाई पड़ रही हैं। 2017 के दिसम्बर के पहला सप्ताह में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 'जायनवादी-यहूदीवादी इजरायल का नयी राजधानी यरूशलम है' कहकर फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ चरम उकसावापूर्ण कदम की घोषणा की गयी है।

ii. रूस और चीन-दोनों शक्तिशाली साम्राज्यवादी देशों को बतौर एक गठजोड़ उभर आने और 'शंघाई को-ऑपरेशन' व 'ब्रीक्स' गठबंधन के नेतृत्वकारी ताकत होने के कारण अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ प्रतिस्पर्धा व अंतरविरोध क्रमशः तीव्रतर होते जा रहा है। खासकर यूक्रेन से क्रीमियां निकलकर रूस में आ जाने से और रूस के साथ अच्छा दोस्ताना संबंध रहने के कारण व सीरिया और रूस पर लगाये गये प्रतिबंधों को लेकर तथा चीन के साथ दक्षिण चीन सागर पर आधिपत्य विस्तार व दक्षिण कोरिया में मिसाइल डिफेन्स सिस्टम के निर्माण का सवाल से लेकर अन्यान्य और अनेक विषयों को लेकर तीखा विरोध जारी है;

iii. पिछड़े देशों में पूंजी निवेश, संसाधनों व बाजारों को लूटने के लिए तथा दुनिया को पुनर्विभाजित करने के लिए तमाम साम्राज्यवादी देशों के बीच जारी प्रतिस्पर्धा में काफी वृद्धि होना;

iv. पिछड़े हुए देशों में अपनी पिट्ठू दलाल सरकार की स्थापना, प्रभावाधीन इलाके को न केवल बनाये रखने बल्कि और विस्तार करने के लिए एक देश के साथ दूसरे देश को लड़वा देना, एक-एक देश में अपने-अपने सशस्त्र गिरोहों का निर्माण करते हुए पूरे तौर पर मार-दंगा की भयंकर स्थिति को पैदाकर लूट, बलात्कार, हत्या तथा नरसंहार कर लाशों के ढेर में बदल देना और कई स्थानों में स्थानीय युद्ध का संचालन करते हुए पूरे देश को खंडहर में बदल देना और अमरीकी साम्राज्यवाद का मददपुष्ट यहूदीवादी इजरायल द्वारा फिलिस्तीनी जनता पर लगातार हमलों का संचालन करते हुए उनके भूभाग पर कब्जा जमाने का आक्रामक प्रयास जारी है।

उपरोक्त चर्चा से यह साफ जाहिर होता है कि मौजूदा विश्व में जारी मुख्य-मुख्य अंतरविरोध हैं, पहला, साम्राज्यवाद के साथ उत्पीड़ित राष्ट्रों व जनता के बीच; दूसरा, पूंजीवादी देशों में पूंजीपति व मजदूर वर्ग के बीच; तीसरा, साम्राज्यवादी देशों के बीच का आपसी अंतरविरोध यानी ये तीन अंतरविरोध मौजूद हैं। इन तीन मुख्य-मुख्य अंतरविरोधों के अंदर साम्राज्यवाद के साथ उत्पीड़ित राष्ट्र व जनता का विरोध ही प्रधान व निर्णायक होने के कारण विभिन्न रूपों के प्रतिरोध, सशस्त्र प्रतिरोध, विद्रोह, क्रांति, राष्ट्रीय व जनवादी क्रांति तथा राष्ट्रीय मुक्ति युद्ध इत्यादि मौजूदा दुनिया में प्रधान रूझान के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। यह हमारे क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने लिए अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति के अंदर अनुकूल पहलू होता है।

घरेलू परिस्थिति : यह बात सभी कोई भलीभांति जानते हैं कि मोदी सरकार यूपीए-1 व यूपीए-2 के नक्शेकदम पर ही चल रही है। साम्राज्यवाद खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ बहुत-ही घनिष्ठ संबंध व सांठगांठ बनाकर उसी के दिशा-निर्देशन में ही मोदी सरकार चल रही है। असलियत यह है कि सभी सरकारें साम्राज्यवाद और उसके खिदमतगार दलाल नौकरशाह पूंजीपति व सामंतों के पक्का दलाल होती हैं। मोदी सरकार भी ऐसा ही एक दलाल सरकार है। साफ जाहिर है कि भारत की केन्द्रीय सत्ता में आसीन आर.एस.एस. (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) -भाजपा के नरेन्द्र मोदी की सरकार ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी शासन चला रही है, जिसके फलस्वरूप एक ओर 'उग्र राष्ट्रवाद' और 'धार्मिक व साम्प्रदायिक भेद-भाव' इत्यादि विचारों को बढ़ावा मिलना जारी है और दूसरी ओर अमीर और गरीब के बीच खाई क्रमशः और भयंकर रूप से बढ़ते ही जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी बहुत तीव्र रूप धारण कर गयी है। कालेधन पर अंकुश लगाने व भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का झूठा वादा कर मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी के जरिए सारे गरीब व मध्यम वर्ग की संचित धनराशि को साफ कर दिया गया। कुटीर उद्योग, छोटे व मध्यम उद्योग-धंधे को भी बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, बैंक पूंजी को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ भ्रष्टाचार भी दुगुनी हो गया है। गो-हत्या के विरोध के नाम पर पूरे देश में अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिमों की मारपीट व हत्या की जा रही है। पशु हत्या बंद करने के नाम पर बूचरखाना बंद किया जा रहा है। फलस्वरूप पशु खरीद-बिक्री, पशु मांस की खरीद-बिक्री व चमड़ा उद्योग बंदी के कगार पर है। उक्त सभी कामों में लिप्त आम जनता अभी बेरोजगार हो गयी हैं। साथ-साथ जाति भेद, धार्मिक मतांधता, कुसंस्कार, छुआ-छूत, साम्प्रदायिकता आदि धड़ल्ले से बढ़ाया जा रहा है। 'हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान' नारे के जरिये ब्राह्मणवादी अहंकार, बड़े जाति के जैसा घमंड को स्थापित किया जा रहा है। महिलाओं पर जुल्म-अत्याचार दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' नारे की आड़ में विश्वविद्यालय के छात्राओं को छेड़खानी का शिकार होना पड़ रहा है व पुलिस की पिटाई खानी पड़ रही है। दरअसल सभी प्रकार की प्रतिवाद-प्रतिरोध की आवाजों को पुलिस के बूटों तले रौंदा जा रहा है।

मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मैनुफैक्चरिंग हब, मोमेंटम भारत आदि नारे की आड़ में कार्पोरेट घराने को संसाधनों व सस्ते श्रम की लूट के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कार्पोरेट घराना यानी पूंजीपति लोग ही लाखों-करोड़ों बेरोजगारों को नौकरी देंगे। जबकि अभी बड़े उद्योगों का हाल ऐसा है कि पहले एक मशीन से 4 मजदूरों को काम मिलता था और अभी एक मजदूर को ही 4/6 मशीन चलाना पड़ेगा। इसी तरह से सभी सार्वजनिक उद्योगों, सेवा संस्थानों (जैसे रेलवे, बैंक, बीमा, शिक्षा-स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों आदि) को कार्पोरेट घरानों को लगभग पूर्ण रूप से पानी के भाव में बेच दिया जा रहा है। मोदी सरकार के जमाना में व्यापक रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की ताजा मिशालें हैं फिलहाल में मोदी मंत्रीमण्डल द्वारा लिया गया सिंगल (एकल) ब्रांड यानी खुदरा व्यापार व निर्माण क्षेत्र में सौ-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति का निर्णय। साथ-साथ मजदूर-किसान विरोधी कानून बनाकर उनके आंदोलन को कुंद करने तथा पुलिस द्वारा मार-पीट, हत्या आदि के द्वारा मजदूर-किसानों पर दमन करने की कार्रवाई चलायी जा रही है। जिससे लाखों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। फिलहाल जीएसटी लागू करने के फलस्वरूप किसानों, छोटे-मध्यम किस्म के उद्योग-धंधे को झटका लगा है। इससे कृषि, औद्योगिक व सेवा क्षेत्र संकुचित होते जा रहा है।

डिजिटलीकरण, नगदी रहित अर्थ-व्यवस्था, आधार कार्ड आदि लागू कराने के जरिए साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी के शिकंजे में आम जनता को और ज्यादा से ज्यादा फंसाया जा रहा है। ऐसा कि निजता के अधिकार सहित मानव जीवन के सारे डाटा (तथ्य) उपलब्ध करवाकर साम्राज्यवादियों के खुफिया तंत्रों के हाथ को ही मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावे आर.एस.एस. ने सत्ता की मदद से ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी गिरोह का निर्माण किया और उसे सत्ता का संरक्षण भी प्राप्त है। फिर, गरीब व दलितों को नरसंहार करने वाले तत्वों को भी सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। इस कारण से ही बिहार के दलित हत्याकांड में संलिप्त रणवीर सेना के सभी अपराधियों को बाइज्जत रिहा कर दिया गया और मुम्बई सीरियल ब्लास्ट कांड के शातिर अपराधियों यानी साध्वी प्रज्ञा व कर्नल पुरोहित बाइज्जत रिहा हो गए।

दूसरी तरफ, कश्मीरी जनता पर लगातार पुलिसिया जुल्म और पुलिस द्वारा की जा रही हत्या तथा पैलेट गन से हजारों युवकों को अंधा बना देना आज भी चल रहा है। नगा-मिजो-मणिपुरी यानी पूर्वोत्तर भारत के राष्ट्रीयता की जनता पर सेना का दमन-अत्याचार भी लगातार जारी है। फिलहाल, अखबार के खबर के अनुसार म्यानमार के सीमा के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने कथित नगा विद्रोही के साथ अन्यान्य विद्रोहियों के अड्डे स्थल को ध्वस्त करने के नाम पर कई लोगों की हत्या कर दिया है। सभी को मालूम है कि कश्मीरी जनता व पूर्वोत्तर की जनता समेत तमाम राष्ट्रीयताओं की जनता लम्बे अर्से से अपने आत्मनिर्णय के अधिकार सहित स्वतंत्र हो जाने के लिए संघर्ष चलाते आ रही हैं और भारत सरकार उनलोगों को ही उग्रवादी-आतंकवादी कह रही है।

इसके अलावा, भारत सरकार का विस्तारवादी मनसूबा मोदी के समय में चोटी पर है। पाकिस्तान, नेपाल, बंग्लादेश,

श्रीलंका आदि सभी पड़ोसी देशों के आंतरिक मामले में अपना हस्तक्षेप व दखलंदाजी बढ़ाते जा रहा है। साम्राज्यवादी अमेरिका की 'चीन को घेरो' की योजना को साकार करने के लिए मोदी सरकार विभिन्न प्रकार की योजना व कार्यक्रम ले रही है। उसी सिलसिले में असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर लगभग 9 किलोमीटर का सेतु अरूणाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए बनाया गया है। अफगानिस्तान के मामले में भी भारत सरकार अमेरिका के साथ साझा कार्यक्रम चला रही है।

यह भी साफ जाहिर है कि कांग्रेसनीत यूपीए-1 सरकार व यूपीए-2 सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा के रूप में माओवादी पार्टी व माओवादी आन्दोलन को चिन्हित कर आन्दोलन को कुचल देने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवाद निर्देशित एलआईसी पॉलिसी के तहत 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' नाम से जो बर्बर युद्ध अभियान शुरू किया था, मौजूदा मोदी सरकार भी वही युद्धाभियान को और आक्रामक तरीका से चला रही है तथा सेना की अर्टीलरी के तोप से गोला फेंकने सहित और अन्यान्य घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। मोदी सरकार के आने के बाद से आपरेशन ग्रीन हंट का तीसरा चरण चल रहा है। पिछले दो वर्षों में मोदी सरकार ने मिशन-2016 व मिशन-2017 के तहत प्रचण्ड आक्रमणात्मक युद्धाभियान चलाया है। फिर, 2017 के उत्तरार्ध में ही मोदी सरकार द्वारा 'समाधान' (जो 2017 से 2022 तक चलाया जाने की योजना है) नाम से एक नया रणनीतिक हमला या अभियान चलाया जाना शुरू हुआ है। इसलिए मोदी सरकार 'घेरा डालो-विनाश करो' अभियान में बटालियन की संख्या में बलों को केन्द्रित कर रही है। दूसरी ओर जनता से माओवादियों को अलग-थलग करने के लिए व्यापक राहत-रीलिफ तथा सुधार का कार्यक्रम व तथाकथित विकास कार्यक्रम चला रही है। मनोवैज्ञानिक युद्ध के तहत व्यापक दुष्प्रचार चला रही है। गांव-गांव में एसपीओ का जाल बिछाने की कोशिश चला रही है। आदिवासियों को आदिवासियों से लड़वाने के लिए 'बस्तरिया बटालियन' व 'पहाड़िया बटालियन' जैसे बल बना रही है। आत्मसमर्पण करवाने के लिए सोची-समझी पालिसी के तहत व्यापक प्रलोभन दे रही है। घर-परिवार को लोभ-लालच दे रही है, नहीं तो डरा-धमका रही है, माओवादी होने का आरोप लगाकर जेल भेजने की धमकी दे रही है, आखिर में बुरी तरह से घरों की कुर्की के नाम पर सारे कुछ की लूट भी कर रही है।

साथ ही साथ मोदी सरकार बड़े पैमाने का सैन्यीकरण करने के लिए विशाल धनराशि खर्च कर रही है व आधुनिक अस्त्र-शस्त्र, फाइटर प्लेन, मिसाइल हमले के जरूरतमंद साजो-सामान आदि खरीद करना, विभिन्न साम्राज्यवादी देशों के सेनावाहिनियों के साथ साझा सैन्याभ्यास चलाना आदि कार्यक्रम चला रही है। व्यापक युवकों को सेना व पैरा मिलिटरी फोर्स में भर्ती कर रही है। माओवादियों को ध्वस्त करने के लिए पैरा-मिलिटरी बलों को उन्नत छापामार ट्रेनिंग, आधुनिक हथियार विभिन्न देशों से खरीद कर मुहैया करवाया जा रहा है। प्रदेश के पुलिसी व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त करने के लिए डीजीपी को केन्द्र से अलग धनराशि दिया जा रहा है। साम्राज्यवादियों के निर्देशन व देख-रेख में भारत के मौजूदा राष्ट्रयंत्र के सभी विभागों व शासन प्रणाली तथा अफसरशाही को फासीवादी नीति व तौर-तरीकों से लैस किया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा विरोधी आवाजों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए जिन सभी फासीवादी तरीके अपनाये गये हैं, वह इंदिरा गांधी की आपातकालीन स्थिति के दौरान अपनाये गये विभिन्न दमनात्मक तरीके को भी पार कर गया है। एक बात में कहने से न्यूनतम विरोधी आवाजों को भी पूरी तरह कुचल देने के लिए जो बर्बर फासीवादी तरीके अपनाये गये हैं, वह अभूतपूर्व है। फिलहाल, चंडीगढ़ से प्रकाशित दैनिक प्रत्रिका 'ट्रिब्यून' के महिला पत्रकार द्वारा ''500 रूपया में ही आधार कार्ड के सारे विवरण पाया जा सकता है'' जैसा एक तथ्य का खुलासा करते हुए एक रिपोर्ट लिखने के कारण उन पर केन्द्र सरकार द्वारा कई धारा लगाकर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। यह बात कही जा सकती है कि फिलहाल पूरे भारत में पुलिस व बंदूक का राज चल रहा है। फिलहाल, मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ता जन-असंतोष तथा जनाक्रोश की स्पष्ट अभिव्यक्तियां दिखाई पड़ रही है। उदाहरण के लिए : गुजरात विधानसभा चुनाव के जरिए प्रतिबिम्बित मोदी सरकार विरोध ी भावना व महाराष्ट्र के पुणे के पास भीमा-कोरगांव में दलितों पर किये गये हमले के कारण उक्त गांव से शुरू होकर पूरा महाराष्ट्र में जिस रूप से जनाक्रोश फूट पड़ा, वह बहुत-ही उल्लेखयोग्य है।

वस्तुतः घरेलू परिस्थिति के अंदर निहित मूल-मूल अंतरविरोधों के रूप में निम्नलिखित अंतरविरोधें मौजूद हैं- (i) साम्राज्यवाद के साथ भारतीय जनता का, (ii) सामंतवाद के साथ व्यापक जनता का, (iii) पूंजी व श्रम के बीच का, (iv) शासक श्रेणियों के बीच का। जिसमें अभी-अभी के लिए सामंतवाद के साथ व्यापक जनता का अंतरविरोध ही प्रधान अंतरविरोध है।

उपरोक्त अंतरराष्ट्रीय व घरेलू परिस्थिति का पूरे भारत के पैमाने पर जो प्रभाव पड़ता है, वह प्रभाव इआरबी अंतर्गत सारे राज्यों पर भी समान व सामान्य रूप से पड़ता है। यह हुआ सार्विकता का पहलू। पर, इआरबी अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कुछ विशिष्टताओं के पहलू भी विद्यमान है, वे हैं :

(1) इआरबी अंतर्गत चार राज्यों यानी बंगाल, झारखण्ड, बिहार व असम के अंदर झारखण्ड में बीजेपी-आजसू गठबंध न सरकार व असम में बीजेपी - असम गण-परिषद सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार नेतृत्वाधीन जनता दल (यू) व भाजपा की गठबंधन सरकार है, बंगाल में ममता बनर्जी की

तृणमूल पार्टी की सरकार है। इसी में झारखण्ड और असम में तो ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा-नीत गठबंधन सरकार है ही है, पर बिहार में जहां नीतीश की भाजपा के साथ गठबंधन सरकार है वहां भी ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी आरएसएस प्रभावित भाजपा सरकार की तमाम जन-विरोधी नीतियों का ही बोलबाला है। असम में माओवादी व संघर्षरत विभिन्न राष्ट्रीयता आंदोलन को पूरी तरह नाश करने के बुरे इरादे से क्रूर सामरिक अभियान जारी है। UAPA, NSC, सशस्त्र वाहिनी का स्पेशल पावर एक्ट, ये तमाम काले कानून जबरदस्त रूप से जारी है; फिलहाल असम में बीजेपी-नीत राज्य सरकार द्वारा लाखों की तादाद में बंगाली मुसलमानों को घुसपैठिया के रूप में चिन्हित कर असम की सीमा से बाहर बांग्ला देश की सीमा के अंदर खदेड़ देने की चरम मुस्लिम विरोधी एक कार्यवाही चलाये जाने की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गयी है। प. बंगाल, झारखण्ड, असम व बिहार में भी माओवादियों का खात्मा अभियान तथा अंधाधुंध गिरफ्तारी सहित तमाम काले कानून जारी है; जहां तक पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का विरोध का सवाल है, वो तो केवल 'मैं बड़ा कि आप बड़ा' जैसा अहंवादी बहस है, बुनियादी नीति-पॉलिसी व विषयों पर कोई विरोध नहीं है। दोनों ही साम्राज्यवाद निर्देशित नव-उदारवादी नीतियों का घोर समर्थक व उक्त नीतियों की लागू करने पर तुले हुए हैं। दोनों ही माओवादियों व आत्मनिर्णय अधिकार के लिए आंदोलनकारियों का खात्मा अभियान में सर्वाधिक बल प्रयोग की नीति पर लगभग पूर्ण सहमत हैं और अमल भी कर रहे हैं। दोनों ही विरोधी आवाज को येन-केन-प्रकारेण दबा दिए जाने के पक्षधर हैं। पिछले 7 वर्षों से प. बंगाल में ममता का शासनकाल इन तथ्यों को स्पष्ट उजागर करता है कि गद्दी पर बैठने के पूर्व ममता की तमाम दिखावा प्रगतिशील बात व भूमिका का, गद्दी पर बैठने के बाद की ममता की ठीक उसकी विपरीत बात व भूमिका ही दिखाई पड़ रही है। ममता खुद की निरंकुश व तानाशाही शासन के जरिए न्यूनतम विरोधी आवाज का भी हर प्रकार के फासीवादी तरीके से दबा दिए जाने की पद्धति लागू की हुई है। उनका आचरण व रूख इस रूप का हो गया है कि प. बंगाल का भाग्य निर्धारक ममता ही है और वह जो बोलेंगी समूचा प. बंगाल में उसी को ही मानना व लागू करना होगा।

ममता के बारे में और भी कहा जा सकता है कि न केवल भाजपा के साथ बल्कि, पश्चिम बंगाल में सीपीएम की वामफ्रंट सरकार जिस रूप से नव उदारवादी नीति सहित जिन तमाम जन-विरोधी नीतियों को लागू कर रही थी, वे सब के सब ममता सरकार भी लागू कर रही है। अलावा, माओवादी आंदोलन और अलग गोरखालैण्ड-कमतापूरी-झारखंडी यानी राष्ट्रीयता आंदोलन के सवाल पर जो नजरिया सीपीएम रखती थी, वही एक ही नजरिया ममता भी रखती है। सीपीएम जिस रूप से बर्बर आक्रमणात्मक कार्रवाई चलाकर उक्त आंदोलनों को और खासकार लालगढ़ जन-विद्रोह व गोरखालैण्ड आंदोलन को कुचलने की नीति अपनायी थी, ठीक उससे भी और एक कदम आगे बढ़कर ममता भी वही नीति अपनायी है। ममता बनर्जी सीपीआई (माओवादी) के नेता का. कोटेश्वर राव की हत्या की साजिश की योजना में प्रमुख भूमिका निभायी। सारे कुछ इस बात को साबित करता है कि सीपीएम व ममता के बीच बुनियादी नीति व पॉलिसी के मामले में खास कोई विरोध नहीं है। अत: यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि सीपीएम और ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा व ममता बनर्जी के बीच बुनियादी आर्थिक-राजनीतिक विषय पर कोई मूल फर्क नहीं है, बल्कि यहीं पर ममता-सीपीएम-बीजेपी, इन तीनों के बीच समानता दिखाई पड़ती है।

यह भी आज स्पष्ट है कि सीपीएम हो या बीजेपी या ममता बनर्जी हो- इसमें कोई भी मजदूर, किसान व मेहनतकश अवाम के वर्ग प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि शोषक वर्ग के प्रतिनिधि हैं। सीपीएम-बीजेपी और ममता बनर्जी सभी कोई उदारीकरण, निजीकरण व भूमंडलीकरण (LPG) की साम्राज्यवाद निर्देशित नीतियों का ही कट्टर समर्थक हैं और उक्त नीतियों को भी जबरन लागू करने खातिर जी-जान से प्रयासरत भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार व ममता बनर्जी तीनों ही उच्चाकांक्षी हैं व प्रचण्ड कुर्सी लोभी हैं।

वस्तुत: इआरबी अंतर्गत चारों राज्य में यानी प. बंगाल, झारखण्ड, बिहार, असम में बेरोजगारी की समस्या बहुत ही तीव्र है। चारों प्रांतों के और खासकर झारखण्ड, बिहार, असम के विशाल संख्या में नवयुवक-नवयुवती पंजाब-हरियाणा सहित मुम्बई-गुजरात-गोवा इत्यादि प्रांतों में रोजगार की खोज में चले जाने के लिए मजबूर होते हैं। जहां कम मजदूरी देकर सबसे भारी काम करवाया जाता है तथा कहीं-कहीं तो मामूली मजदूरी देकर बंधुआ मजदूर जैसा भी काम करवा लिये जाते हैं।

वाकई में, इआरबी अंतर्गत तमाम राज्यों में उपरोक्त ठोस स्थिति के वर्णन से साफ उजागर होता है कि देशी-विदेशी शोषक वर्ग द्वारा जिस प्रकार से अभूतपूर्व लूट-शोषण चलाया जा रहा है और उक्त शोषक वर्ग के हित में दलाल शासकों द्वारा जिस रूप से चरम फासीवादी तरीका अपनाकर और बंदूक की नोंक पर जनता को जिंदगी बिताने के लिए मजबूर किया जा रहा है, विपरीत रूप से जनता के विभिन्न रूपों का प्रतिवाद-प्रतिरोध संघर्ष भी क्रमश: व्यापक व तीव्र होते जा रहा है। यह बात भी स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य में हमारी माओवादी पार्टी का कहीं ज्यादा व कहीं अपेक्षाकृत कम प्रभाव मौजूद है। अत: अंतरराष्ट्रीय व घरेलू ठोस परिस्थिति दर्शाती है कि क्रांति के लिए उक्त परिस्थिति पहले की अपेक्षा ज्यादा अनुकूल है और अनुकूल परिस्थिति का फायदा लेने खातिर हमारी पार्टी भी मौजूद है। चूंकि इआरबी के अंतर्गत

राज्यों के अंदर केवल झारखण्ड में ही देश का 40 प्रतिशत खनिज संपदा सहित बंगाल व असम में भी खनिज संपदा व तेल संपदा का भंडार मौजूद है और चूंकि इन सारे भंडारों का ज्यादातर हिस्सा आदिवासी बहुल पहाड़-जंगल इलाके में ही है, जहां सीपीआई (माओवादी) की रहनुमाई में आज तीखा संघर्ष जारी है। इसलिए सारे संपदाओं को कारपोरेटों व दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों द्वारा लूटने की खुली छूट देने की बुरी नियत से ही हजारों-हजार अर्द्ध-सैनिक बल व पुलिस बलों के जरिए माओवादी आंदोलन व माओवादियों को खत्म करने का बर्बर सामरिक अभियान यानी ऑपरेशन ग्रीन हंट और माओवादी पार्टी को 2017 के अंदर पूरी तरह नाश करने के बुरे इरादों से मिशन-2017 नाम से आक्रामक युद्धाभियान चलाया गया है और अभी 2018 में भी 'समाधान' नाम से वैसा-ही एक नया रणनीतिक व क्रूर अभियान जारी है। पूरे झारखण्ड को पुलिस छावनी में बदल कर तथा प. बंगाल के उत्तरी हिस्से व वीरभूम-नदिया-मुर्शिदाबाद और पूरा जंगलमहल सहित मेदनीपुर, बांकुड़ा, पुरूलिया के समूचे इलाके में अनगिनत पुलिस कैम्पों की स्थापना कर दरअसल बंदूक का शासन जारी है। फिर, असम सहित पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में दीर्घदिन से जहां राष्ट्रीयता के आत्मनिर्णय अधिकार का आंदोलन तीव्र रूप से जारी है, वहां के समूचे इलाके पर भारत के मौजूदा शासकों का पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करने खातिर आक्रामक युद्धाभियान चलाया जा रहा है। ताकि कहीं पर तमाम संपदाओं की लूट के खातिर कोई बाधा या अवरोध न रहे। असम सहित तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में भी, हकीकत में बंदूक का शासन जारी है। बिहार की नीतीश सरकार भी कृषि-क्षेत्र में ज्यादा उपजाऊ व विकास के नाम से जिन सभी पॉलिसियों को अपनायी है, असल में वे सब साम्राज्यवाद व साम्राज्यवादी देशों के हित के लिए सर्वाधिक फायदामंद है। फलस्वरूप, कृषि-संकट इस जगह पर पहुंच गया, जहां किसानों की आत्महत्या रोजदिन की घटना बन गयी है। इधर, माओवादी पार्टी के नेतृत्व में विगत 50 वर्षों से बड़ा जमींदार व महाजन-सूदखोरों के खिलाफ यानी सामंतों व सामंती व्यवस्था के खिलाफ दुनिया हिला देने वाला वर्ग संघर्ष भी जारी है। इसलिए शोषक वर्गों के दलाल नीतीश सरकार भी माओवादी आंदोलन से प्रभावित अन्यान्य राज्यों के जैसा बिहार में भी वही सब दमनमूलक कार्रवाइयां व युद्धाभियान चला रही है। एक बात में कहा जाय तो तथाकथित ईमानदार व भ्रष्टाचार मुक्त व अच्छा आदमी बने रहने का नीतीश कुमार का मुखौटा खुल गया है। अभी नीतीश व उसकी सरकार का साम्राज्यवाद, सामंतवाद व नौकरशाह पूंजीवाद की दलाली करने का चरित्र साफ उजागर हो गया है। खूब संक्षेप में यही है इआरबी राज्यों में जारी मौजूदा परिस्थिति की कुछ विशिष्ट पहलुवें।

(2) प्रश्न : 2017 खत्म हो गया, दुश्मन के मिशन-2017 का इआरबी इलाकों में क्या स्वरूप रहा? पिछले कुछ समय में दुश्मन की रणनीति में आए बदलाओं का क्या विश्लेषण है? दुश्मन के चौतरफा हमले का प्रतिरोध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?

उत्तर : जाहिर है कि ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी दर्शन व विचारों से लैस बीजेपी की मोदी सरकार गद्दी पर बैठने के साथ-साथ उक्त 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' का तीसरा चरण, जिसका खूंखार स्वरूप मिशन-2016 व मिशन-2017 का बर्बर सैनिक अभियान चलाए जाने के बाद अब 2018 में 'समाधान' नाम से और एक मिशन की शुरूआत की गई है। मिशन-2017 में मुख्य केन्द्रीकरण केन्द्रीय कमेटी और विभिन्न स्पेशल एरिया कमेटी, राज्य कमेटियों के सदस्यों की हत्या के लिए और साथ-साथ डीके, बीजे, पूर्वी बिहार व पूर्वोत्तर झारखण्ड, ओड़िशा, बीजेओ आदि पर केन्द्रीकृत कर हमले हुए। मतलब 2017 के अंदर पूरी पार्टी व जारी जन-क्रांति को ध्वस्त कर देने का विशेषकर अमरीकी साम्राज्यवाद का निर्देशन पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों ने जो प्रतिक्रांतिकारी योजना बना थी, उसी को कार्यान्वित करने के मकसद से चरम फासीवादी व बर्बर तरीके अपना कर ही पूरे 2017 में उक्त अभियान चलाया गया है।

ऐसी स्थिति में पूरे भारत के पैमाने पर कठिन दौर और कुछ जगहों में धक्का खायी हुई हमारी पार्टी के लिए उक्त मिशन को पूरी तरह विफल कर देने की उचित कार्यनीति अपनाने की जरूरत को दर्शाती है। ऐसी कार्यनीति का सफल कार्यान्वयन की ताजा मिसाल है दण्डकारण्य के वीर कामरेडगण व वीर जनता द्वारा चलाया गया फिलहाल की कुछ शानदार जवाबी कार्रवाइयां और बीजे-पूर्वी बिहार व पूर्वोत्तर झारखण्ड-ओड़िशा-बीजेओ इत्यादि क्षेत्र में जारी प्रतिरोध कार्रवाइयां, जो दुश्मन को भारी चिंतित कर डाली। बाद में, केन्द्रीय गृहमंत्री की उपस्थिति में देश के सुरक्षा सलाहकार, पुलिस, अर्द्ध-सैनिक बल व मिलिटरी, तमाम प्रकार के खुफिया विभाग इत्यादि तमाम विभागों के सबसे उच्च ओहदे के अफसरों को लेकर आयोजित एक बैठक के जरिए अपनी रणनीति में कुछ बदलाव लाकर उसके अधीन कुछ नयी कार्यनीतियां ग्रहण कर उसे और आक्रामक स्वरूप दिए जाने का प्रयास किया गया। जैसे:-

1. क्रांतिकारी आंदोलन के इलाकों में तथा सीमा से सटे हुए राज्यों के सीमाक्षेत्र में संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर कॉरपेट सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना।
2. विभिन्न स्तरों के नेतृत्वकारी शक्तियों का सफाया करना।
3. खुफिया नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए गिरफ्तार साथियों के रिश्तेदारों को एस.पी.ओ. बनाने सहित आमतौर पर एस.पी.ओ., कोवर्टों और पहचान

करने वालों को और अधिक संख्या में तैयार करना और साथ ही साथ टीपीसी, जेजेएमपी, पीएलएफआई, जेपीसी, शांति सभा, ग्राम रक्षा दल, नागरिक सुरक्षा समिति, सेन्द्रा समिति इत्यादि प्रतिक्रांतिकारी गिरोहों का निर्माण व संचालन करना।

4. एक के बाद एक लगातार 'घेरा डालो- विनाश करो' के बर्बर सैनिक अभियान को ड्रोन, हेलिकॉप्टर व टोही विमान सहित वायुसेना की निगरानी व्यवस्था की मदद लेकर उसे और तेज करना।
5. टार्गेट पर निशाना साधने के लिए सूचना-तंत्र व एस. पी.ओ. का उपयोग कर तथा ड्रोन का सहारा लेकर टार्गेट प्वाइंट को निश्चित कर लेने के बाद ही सटीक रूप से चोट करना।
6. सेना के अर्टिलरी (artillery) यानी बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल कर तोप से लगातार गोला फेंकना या बमबारी करना।
7. एक-एक इलाके को कब्जा करने का लक्ष्य पर एक ओर ज्यादा से ज्यादा पुलिस कैम्पों को स्थापित कर व्यापक संख्या में उन्नत कमाण्डो बलों के जरिए आक्रमण चलाना और दूसरी ओर टार्गेट इलाके के चारों ओर पुलिस कैम्पों की स्थापना कर सप्लाई लाइन को पूरी तरह नष्ट कर डालने की कार्रवाई का संचालन करना।
8. सड़क, रेल मार्ग, सूचना-तंत्र-इत्यादि का और विकास व उन्नत करना।
9. बड़े पैमाने पर सुधार कार्यक्रम, मनोवैज्ञानिक युद्ध और आत्मसमर्पण के कार्यक्रमों को अंजाम देना तथा विभिन्न स्तरों के नेतृत्वकारी कामरेडों को गिरफ्तार करवा देने पर लाखों-करोड़ों इनाम राशि की खुली घोषणा करना।
10. कुर्की-जब्ती के नाम पर घर के तमाम कुछ को लूट लेना और खिड़की, दरवाजा, छत आदि को पूरी तरह तोड़-फोड़ देना और ऐसा कि घर सहित तमाम सामानों को आग के हवाले कर देना- इत्यादि, इत्यादि चलाकर मनोबल को गिराने की कोशिश करना।

फिर, एनडीए सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी द्वारा 2017 के 15 अगस्त को भाषण के जरिए चरम धोखाधड़ीपूर्ण नारा यानी 2017 से 2022 तक 'नया भारत' का निर्माण का एक प्रतिक्रांतिकारी व नयी रणनीतिक योजना ''समाधान'' का ऐलान किया गया। असल में, मिशन-2016 व मिशन-2017 को बहुत हद तक विफल होते देख अभी ''समाधान'' नाम से एक नयी व प्रतिक्रांतिकारी योजना लागू की गयी है। जिसकी मूल बातें निम्न प्रकार हैं; जैसे- माओवादी विरोधी अभियानों में हिस्सा लेनेवाले पुलिस, अर्द्ध सैनिक व कमांडो बल आत्मरक्षात्मक तरीकों को छोड़कर पूरी तरह आक्रामक हमले करने, भारतीय वायु सेना और विभिन्न अर्द्ध-सैनिक बलों के एयरबोर्न (युद्ध विमान व हेलिकॉप्टरों से हमले करने वाली) बलों के हवाई हमले करने, खुफिया तंत्र को और विस्तारित व मजबूत करने, ह्यूमन इंटेलिजेंस (मानव आधारित खुफिया तंत्र) सहित विशेषकर टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को विस्तारित व मजबूत करने तथा यूएवी/ड्रोन, उपग्रह (सेटेलाइट), थर्मल इमेजिंग, इनफ्रारेड टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी कैमरा, रडारों को इस्तेमाल कर खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करने, केंद्र व राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय में खमियों को दूर कर बेहतर समन्वय हासिल करने, साम्राज्यवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के लूट के लिए जरूरी मौलिक सुविधाओं की स्थापना करने, काउण्टर इंसर्जेंसी और काउण्टर टेररिस्ट ऑपरेशनों में इजरायल की मदद लेने, माओवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उनकी आर्थिक स्रोत पर चोट पहुंचाने इत्यादि निर्णयें लिये गये हैं।

उक्त राणनीति-कार्यनीति लागू करने के लिए 8 मोर्चों पर काम करने के प्रस्ताव से 8 अक्षरों को लिकालकर 'समाधान' शब्द बनाया गया, उसी को अपनी वर्तमान रणनीति के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पेश किया गया : एस-स्मार्ट लीडरशीप (सक्रिय नेतृत्व), ए-एग्रेसिव स्ट्रॉटजी (आक्रामक रणनीति), एम-मोटिवेशन एण्ड ट्रेनिंग (प्रेरित करना और प्रशिक्षित करना), ए-एक्शनबुल इंटेलिजेंस (कार्रवाई में इस्तेमाल की जाने वाली गुप्त समाचार), डी-डॉश बोर्ड बेस्ट इंडिकेटर्स (हाथ में उपलब्ध सूचक), एच-हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी (टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना), ए-एक्शन प्लान फार इच थ्रेट (प्रत्येक चुनौती का सामना करने के लिए उचित कार्ययोजना), एन-नो एक्सेस टू फाइनॉन्सिग (आर्थिक स्रोतों पर रोक लगाना) - SAMADHAN - समाधान - यही रणनीति है।

ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि दुश्मन का मौजूदा ताकतवर पक्ष क्या एकमात्र, परम और अपरिवर्तनीय है? द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद ने हमें सिखाया है कि हर वस्तु या घटना के अंदर 'दो विपरीत चीजों की एकता व संघर्ष' का नियम ही बरकरार रहता है। इसीलिए हर वस्तु या घटना को 'एक को दो में विभाजन' करके ही तथा उसके बारे में सही व गहरा विश्लेषण के जरिए ही उसमें निहित दोनों पक्षों का ठोस मूल्यांकन किया जा सकता है। इस नियम का इस्तेमाल करके ही दुश्मन की ताकतों को ठोस रूप से आंका जा सकता है और अभी-अभी के समय में कौन-सा पहलू सापेक्ष रूप से प्रधान है व कौन-सा पहलू गौण है, उसे भी सही तौर पर तय किया जा सकता है।

परंतु ऐसा कर पाने में अक्सर हम कुछ न कुछ गलतियां कर बैठते हैं और एकांगीपन का शिकार हो जाते हैं। तब, कभी दुश्मन की ताकत को ज्यादा करके आंकने और कभी कम करके आंकने- यह दो प्रकार की गलतियां हो जाती है। साथ ही साथ सब कुछ को सापेक्ष या तुलनात्मक रूप से न

देखने व विचार न कर पाने की गलती भी हो जाती है। ऐसा होने पर हमारे अंदर दो प्रकार के गलत चिंतन पैदा होते हैं। पहला, दुश्मन की ताकत को ज्यादा करके आंकने, जो हमारे अंदर शिथिल, निष्क्रिय व निराशा की मानसिकता पैदा करती है और कम शक्ति लेकर शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ हम लड़ नहीं सकते हैं, जैसे चिंतन को पैदा करता है। दूसरा, दुश्मन की ताकत को छोटा करके आंकने की कमी, जो हमारे अंदर कुछ हठधर्मी या अराजक चिंतन जैसा 'वाम' भटकाववादी चिंतन को पैदा करता है। पहला वाला दक्षिण भटकाव और दूसरा वाला 'वाम' भटकाव की ओर हमें ले जाता है। तब कभी हम केवल प्रतिकूल पहलू, तो कभी केवल अनुकूल पहलू को ही एकमात्र जैसी सोच लेते हैं और उचित व सही कार्यनीति का निर्धारण करने में अक्षम साबित होते हैं।

उपरोक्त 'दो विपरीत चीज की एकता व संघर्ष' और 'एक को दो में विभाजन' के नियमों को व्यवहार में लागू करके ही हम मौजूदा प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर विपरीत रूप से निहित अनुकूल पहलू को ढूंढ निकाल सकते हैं। साथ ही साथ और एक बात हमें समझना है कि दुश्मन द्वारा हम पर तीव्र हमले व चरम फासीवादी आक्रमण चलाने की कार्रवाई कतई उसके ताकतवर पहलू को नहीं दर्शाता है, बल्कि हकीकत में यह उसके भीतर से कमजोर होते रहने के पहलू को ही उजागर करता है।

उल्लिखित बातों के बारे में गहरी समझदारी हासिल करके ही हम मिशन-2017 को विफल कर पाये हैं और ऐसी समझदारी हासिल कर पाने से ही हम नयी रणनीतिक योजना 'समाधान' (2017 से 2022) को भी पूरी तरह विफल कर देंगे। हालांकि किसी भी प्रकार की जारी अभूतपूर्व आक्रामक कार्यवाही का मुकाबला करने के लिए हमारी कार्यनीतियां व योजनाएं क्या होगी- इसके लिए हमें अवश्य ही मौजूदा देश-दुनिया तथा अंतरराष्ट्रीय व घरेलू परिस्थिति के अंदर हमारे लिए अनुकूल पहलुओं को ढूंढना बहुत ही जरूरी है। साथ ही अतीत की गलतियों से सबक लेकर तथा अभी भी हमारे अंदर जो सारी कमजोरियां काम कर रही हैं, उसे दूर हटाकर और पार्टी को क्रमागत बोल्शेवीकरण के जरिए और मजबूत बनाना भी बहुत जरूरी है।

जिन सभी बिन्दुओं पर हमारी कार्यनीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करनी है, वे हैं:-

1. इआरबी अंतर्गत सभी राज्यों में पार्टी को लगातार बोल्शेवीकरण की प्रक्रिया के जरिए और मजबूत बना कर ही जारी सेट-बैक की स्थिति से पूरी तरह उबर आने का जोरदार प्रयास चलाना होगा।
2. सैनिक कार्यभार संबंधी कार्यनीति की रूपरेखा तैयार करते हुए दुश्मन के चौतरफा हमले के विरूद्ध भौगोलिक धरातल के अनुसार गुरिल्ला युद्ध के दांव-पेंच को हिम्मत व बुद्धि इन तीनों के तालमेलपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को हैरान-परेशान तथा उसकी सप्लाई लाइन को नष्ट करने के लिए लगातार छोटी व अपेक्षाकृत मध्यम किस्म की कार्रवाइयों का संचालन करने के साथ-साथ चौतरफा मुंहतोड़ जवाबी हमले की योजना अपनानी होगी और योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपनी कम ताकतों को लेकर भी जरूरत के अनुसार दुश्मन की एक टुकड़ी पर तथा कमजोर स्थल पर कम समय के अंदर बिजली की रफ्तार से अचानक हमला कर कुछ को सफाया व हथियार जब्त करने के उद्देश्य से बलों को केन्द्रित करना और फिर ठीक समय पर बलों को विकेन्द्रित करने का तरीका यानी जाल फेंकने व समेटने के तरीके को इस्तेमाल करने में माहिर होना होगा।
3. सैद्धांतिक व राजनीतिक कार्यभार और सांगठनिक कार्यभार संबंधी कार्यनीति- इत्यादि मुख्य-मुख्य कार्यनीति की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करनी होगी। साथ-ही-साथ, मजदूर वर्ग व किसान सहित छात्र व युवा, महिला और बुद्धिजीवी, राष्ट्रीयता की जनता, धार्मिक अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी - इत्यादि तमाम के बीच क्रांतिकारी कामकाजों को आगे बढ़ाने खातिर राजनीतिक-सांगठनिक व संघर्ष संबंधित कार्यनीतियों की स्पष्ट रूपरेखा भी प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यनीतियों को सही समय पर तय नहीं कर पाने से अनुकूल परिस्थिति का फायदा हम उठा नहीं पाएंगे। हमें याद रखना होगा कि अगर क्रांतिकारी परिस्थिति का फायदा क्रांतिकारी तत्व नहीं उठाते हैं, तो प्रतिक्रांतिकारी लोग उसका फायदा अपने वर्ग-हित में पूरी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं और क्रांति के बदले प्रतिक्रांति की लहर फैल जाती है। हिटलर का फासीवाद, 1927 में चीन में च्यांग-काई-शेक का चरम फासीवादी हमला व इन्डोनेशिया में अमेरिका के खुफिया विभाग CIA द्वारा उकसाया गया प्रतिक्रांतिकारी हमले, जिससे लाखों की तादाद में हत्याएं हुई, चीली में भी CIA द्वारा संचालित मिलिटरी जनरल पिनोचेर का प्रतिक्रांतिकारी व फासीवादी हमले, जिससे लाखों की हत्याएं हुई- आदि इसकी मिसालें हैं।

वस्तुत: जवाबी कार्यनीतियों का निर्धारण करते समय हमें इस बात को हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि भाकपा (माओवादी) के गठन की शुरूआत से ही हमें एक के बाद एक 'घेरा डालो व विनाश करो' तथा 2009 से जारी 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' जैसा बर्बर सैनिक हमले का लगातार सामना करना पड़ा व प्रतिरोध संघर्ष का भी संचालन करना पड़ा। इस दौरान हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा और जानों की कुर्बानी देनी पड़ी। फिर भी हम अतीत की भूलों से सबक लेकर आगे बढ़े हैं और उसी के बल पर टिके हुए हैं और आज उससे भी आगे बढ़ने

खातिर प्रयासरत हैं। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से बूढ़ा पहाड़ के चारों ओर लातेहार-गढ़वा-पलामू-गुमला क्षेत्र को लेकर लगभग एक-दो किलोमीटर बाद-बाद में एक रणनीतिक बंदी शिविर जैसा बनाकर दुश्मन पक्ष युद्ध को एक कार्यनीति का लक्ष्य के अनुसार 'इलाका कब्जा के लक्ष्य पर जो युद्ध चलाया जाता है' उसी लक्ष्य को सामने रखकर इन सारे क्षेत्रों में अर्द्ध-सैनिक बलों तो तैनात है ही, लेकिन मिशन-2017 का जो बर्बर व प्रतिक्रांतिकारी अभियान चलाया गया है- उससे माओवादियों को उखाड़ फेंकने के नापाक इरादों से जो युद्धक कार्यवाही चलायी गयी है, उसके तहत पिछले एक-दो महीनों से सेना की आर्मर यूनिट के जरिए तोप से गोला-बारी चलायी गयी है। उदाहरणस्वरूप, बूढ़ा पहाड़ में 2017 नवम्बर 23 से 26 तक सेना के आर्टीलरी विभाग की आर्मर यूनिट द्वारा तोपों से लगातार गोला व बमबारी की गयी, अक्टूबर महीना के 8 से 10 तारीख के अंदर पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरू, छोटानागरा, गुवा, नोवामुंडी आदि क्षेत्रों में घेरकर शाम 4-5 बजे से लेकर रात्रि 10-11 बजे तक युद्धक विमानों का प्रचण्ड डरावनी आवाज में इस्तेमाल किया गया है। पर इन सारे युद्धाभियान के रूपों को अपने अतीत के अनुभवों पर आधारित होकर नये तरीकों का इस्तेमाल कर हमने विफल कर दिया है। इस प्रकार से हमारे अनुभव के भंडार में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के अनुभव मौजूद हैं। समय-समय पर हम हमारी पार्टी व आंदोलन का मूल्यांकन करते हुए सकारात्मक व नकारात्मक पहलू का सटीक विश्लेषण कर पार्टी के अंदर निहित कमजोरी व गैर-सर्वहारा रूझानों के खिलाफ दोष निवारण आंदोलन चलाकर पार्टी को अधिक बोल्शेवीकरण करने की प्रक्रिया भी अपनाये हैं। एक ओर पार्टी को क्रमशः दोषमुक्त कर मजबूत करने और दूसरी ओर ऑपरेशन ग्रीन हंट के तीसरे चरण का सफलतापूर्वक मुकाबला का प्रयास किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन हंट के तीसरा चरण के तहत चलाया गया मिशन-2016 व मिशन-2017 के भीषण सैनिक हमले के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध चलाते हुए जरूरत के तौर पर नये कार्यनीतियों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांगठनिक और प्रचार क्षेत्रों में शोषक-शासकों के काले कारनामों का उचित जवाब देते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया बरकरार रख पा रहे हैं। ऐसा करके ही दण्डकारण्य, झारखण्ड, बिहार, प. बंगाल-ओड़िशा व झारखण्ड सीमा क्षेत्र, आंध्र-ओड़िशा सीमा क्षेत्र, ओड़िशा, महाराष्ट्र-गढ़चिरोली, पश्चिमी घाटी आदि क्रांतिकारी आंदोलनों पर गंभीर चोट पहुंचाने के लिए शासक वर्ग द्वारा चलाया गया मिशन-2016 व मिशन-2017 को हमने विफल किया है। फिर, देशव्यापी क्रांतिकारी आंदोलनों को कुचलने के लक्ष्य से ही अपनायी गयी एक नई योजना 'समाधान' (2017-2022) को भी हम अपने अनुभवों पर आधारित होकर तथा उचित कार्यनीति का इस्तेमाल कर पूरी तरह विफल कर देंगे।

वस्तुतः, अतीत की लडाइयों के दौरान जो अनुभव हमें प्राप्त हुआ है, उस पर आधारित होकर भविष्य में चाहे कितने ही मिशन क्यों न आवें, हम उन सबों को विफल कर सकते हैं व पूरी तरह परास्त कर सकते हैं। वशर्ते कि जनता पर आधारित होकर हम अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू परिस्थिति के अंदर निहित अनुकूल पहलुओं का फायदा उठाने में सक्षम हो सकें। इस विषय के मद्देनजर बहुत-ही संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू परिस्थिति और उसमें निहित अनुकूल पहलुओं पर एक सरसरी नजर डालनी चाहिए, जो पहला प्रश्न के जवाब में दिया गया है।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पूरी पार्टी, पीएलजीए, संयुक्त मोर्चा सहित पूरी कतार व इतिहास निर्माण करने वाली जनता सभी कोई मिलकर न केवल मिशन-2016 व मिशन-2017 को पूरी तरह विफल कर दिया, बल्कि क्रमशः आगे बढ़कर कोई भी मिशन या नई योजना को विफल करते हुए जारी कृषि क्रांतिकारी लड़ाई तथा जनयुद्ध को एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे।

3. प्रश्न : आदिवासी इलाकों में ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी ताकतों की क्या विशिष्टताएं हैं? इसका मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?

उत्तर : सच कहा जाए तो अन्यान्य इलाकों की तुलना में आदिवासी इलाकों में ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी तत्वों का आक्रमण सबसे ज्यादा दमनात्मक व क्रूर है। क्योंकि समूचा आदिवासी इलाके में जो खनिज सम्पदा सहित प्राकृतिक सम्पदा का भण्डार मौजूद है, तमाम कारपोरेट व सीबीबी (दलाल नौारशाह पूंजीपति) उसे येनकेन-प्रकारेण लूटने खातिर गिद्ध की नजर लगाकर बैठे हुए हैं। इसलिए अनगिनत एम. ओ.यू. करार किया गया है। और भारत की तमाम दलाल शासक पार्टियां उसी मंशा को पूर्ति करने के लिए चरम फासीवादी तरीका लागू कर उनके विश्वस्त दलाल की भूमिका अदा कर रही हैं। दरअसल, माओवाद व माओवादियों को देश की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा कहकर उसे सम्पूर्ण रूप से और खासकर आदिवासी इलाकों से सम्पूर्ण रूप से उखाड़ फेंकने तथा खत्म करने के उद्देश्य से जो बर्बर सामरिक अभियान सहित अन्यान्य जुल्मी रूपों को लागू करने का अभियान चलाया जा रहा है, एक बात में कहा जाए तो वह अभूतपूर्व है। पर, भारत के कारपोरेट नियंत्रित प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया का अधिकांश हिस्सा उस अभूतपूर्व जुल्म-अत्याचार-आक्रमण से संबंधित एक- भी समाचार को सही ढंग से नहीं प्रचार करना ही अपना फर्ज समझता है। उल्टे, सरकार-पुलिस व प्रशासन का झूठ-फरेब वाला वक्तव्य को ही बढ़ा-चढ़ा कर प्रचार करते हैं। हकीकत यही है कि समूचा आदिवासी बहुल इलाके को कार्पेट सिक्यूरिटी के घेराव के अंदर लाया गया है और जहां दलाल सरकारें स्ट्रटीजिक हेमलेट (strategic hamlet) या रणनीतिक बंदी

शिविर का इलाका के बतौर पेश आ रही हैं और इलाके की जनता को बंदूक की साये में जीवन बिताने खातिर मजबूर की गयी है। फलत: पहाड़-जंगल जो आदिवासी जीवन के साथ ओतप्रोत है, उसके सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार रोज दिन या हर पल का जो लगाव रहता है वह आज पूरी तरह खतरा में है; आदिवासी जनता के भीतर घर जो अत्यन्त पवित्र माना जाता है, वहां सब कुछ को आज पुलिस के बूटों तले रौंदा जा रहा है; कठिन मेहनत कर जो पैसे कमोबेश घर में सुरक्षित रखा जाता है, वह सब कुछ लूट लिया जाता है, मुर्गा-मुर्गी, खस्सी आदि लूट लिया जाता है; गाय, बैल, बकरा, बकरी के चारा के लिए जंगल जाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है; शाम के बाद रिश्तेदारों के घर जाना-आना, शादी अनुष्ठान के लिए रात्रि में जाना-आना व खुशियां मनाने की सभी प्रकार की आजादी छीन ली गयी है; अंत में, सर्वाधिक घृणित अपराध के रूप में चिन्हित महिलाओं पर यौन-अत्याचार जैसे बलात्कार या सामूहिक बलात्कार लगभग सभी आदिवासी इलाकों के सर्वत्र ही आदिवासी बच्ची-किशोरी-युवती-शादी हो गयी महिला-अधेड़ महिला और ऐसा कि ज्यादा उम्र वाली महिला- कोई भी मां-बहन-बेटी इस जघन्य व पाशविक अत्याचार का दंश नहीं झेली होगी, शायद ही ऐसी संख्या मिल पाएगी; उदाहरणस्वरूप, जिलगा पहाड़ में स्थित झुमरा गांव के ठीक बगल में ही जब से पुलिसिया बेस कैम्प को बैठाया गया, तब से केवल झुमरा गांव के ही लगभग 50 की संख्या में बेटी-पतोहु-भाभी-चाची बलात्कार का शिकार बनी हैं, पलामू-लातेहार-गढ़वा-गुमला-बूढ़ापहाड़ के तलहटी गांवों के अनेकों महिलाएं पुलिस के पाशविक अत्याचार और बलात्कार का शिकार हुई हैं; जमुई-मुंगेर के पहाड़ के तलहटी में स्थित गांवों की महिला जबरदस्त सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई हैं; पाकुड़-संथाल परगना के पहाड़-जंगल में स्थित गांवों में, पारसनाथ पहाड़ के चारों ओर स्थित गांवों में, सारंडा-पोड़ाहाट-बुण्डू-चांडिल-कोल्हन क्षेत्र के अनगिनत गांवों में, दलमा पहाड़-जंगल के आसपास के गांवों में, प. बंगाल के लालगढ़ तथा जंगलमहल इलाके के विभिन्न गांवों में अनेकों महिला क्रूर यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हैं; ऐसाकि बोकारो जिला नावाडीह थाना के अंतर्गत एक गांव की एक युवती दिन के उजाले में ही तत्कालीन नावाडीह थाना का दारोगा प्रमोद सिंह द्वारा बलात्कार का शिकार होने की बात तो सभी लोग जानते हैं। पर, आज तक उपरोक्त तमाम बलात्कार की घटनाओं के बारे में कोई जांच नहीं हुई। किसी को सजा मिलनी तो बहुत दूर की बात है। सबसे ताज्जुब होने की बात तो यह है कि न केवल प्रशासन चुप है बल्कि थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए जाने से उसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और चिंताजनक बात है कि एक-दो छोड़कर बाकी सभी मीडिया लगभग नीरव दर्शक की भूमिका अदा कर रही हैं। फिर, तमाम आदिवासी इलाके जो युग-युग से शांत, हरा-भरा व प्रदुषण मुक्त वातावरण का सृजन कर आदिवासी व गैर-आदिवासी जनता को शांतिपूर्ण जीवन बिताने में मदद करता था, वह इलाके आज पुलिस के बूटों तले रौंदा जा रहा है, बंदूक की गोली और मोर्टार गोला व तोपों की आवाज से वातावरण को प्रदुषित करने सहित आदिवासी जीवन के सारे कुछ को बेहद दर्दनाक बना दिया गया, मांदल-नगाड़ा की आवाज पर रोक लगा दिया गया व तीर-धनुष लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बच्चों की मुस्कान को भय से मां की गोद में चिपक कर रोने में बदल दिया गया। साथ ही साथ घरों की सारी संपत्ति को लूट लेना, बेरहमी से मारपीट करना, व्यापक गिरफ्तारी कर व झूठा मुकदमा लगाकर सालों-साल के लिए जेल में ठूंसना, ऐसाकि मुठभेड़ व फर्जी मुठभेड़ के नाम से हत्याएं करना पुलिस व प्रशासन की रोजदिन की दिनचर्या बन गयी है। महिलाओं पर ढाये जाने वाला अत्याचार की बात तो पहले ही उल्लेख की गयी है।

समूचे आदिवासी इलाके मलेरिया, टीवी, एनीमिया, कुपोषण के कारण जन्म से ही बच्चे विभिन्न प्रकार के खतरनाक बिमारियों से पीड़ित रहते हैं और भूख के मारे मौत के मुंह में घुस जाते हैं। ऐसा कि भूख से भी झारखण्ड में आम जनता मर रही हैं, जिसका जिन्दा मिसाल है- सिमडेगा के 11 वर्ष की संतोषी, धनबाद के रिक्शा चालक बैजनाथ राम, देवघर के रूप लाल मराण्डी व गढ़वा के प्रेमनी कुवंर की मौत पिछले दो महीनों में भूख के कारण से हुई है। न सबों को राशन कार्ड दिया जाता है और न ही ठीक से राशन के अनाजों को बांटा जाता है। न स्वच्छ भारत की कोई वास्तविक अभिव्यक्ति है और न कोई चालू स्वास्थ्य केन्द्र है, न नियमित डाक्टर है, न ही दवा की सप्लाई है। आदिवासी इलाके में प्राइमरी स्कूल नहीं है, स्कूल है भी तो पैखाना-बाथरूम नहीं है और मास्टर नहीं है, 'माओवादी इलाके में खतरा है' जैसा झूठा प्रचार कर आदिवासी बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाता है। विकास के नाम पर सारंडा, सरयू इत्यादि जैसी अनेकों कार्ययोजना जिसके लिए हजारों-लाखों करोड़ रूपये का बजट बनाया गया उसमें से केवल पुलिस-मिलिट्री के आवागमन को आसान करने के मकसद से रोड-रास्ता का जाल बिछाया जाने को छोड़कर आदिवासी जीवन में बुनियादी बदलाव लाने की दिशा में लगभग कुछ भी नहीं किया गया है। तब विकास खातिर विशाल राशि कहां चली जाती है? किसी को समझने की कोई दिक्कत नहीं है कि विकास योजना के सारे रूपये नेता-मंत्री-ठेकेदारों के जेब में पहुंच जाता हैं। ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी ताकतों ने केन्द्र व विभिन्न राज्यों में सरकारी गद्दी पर बैठने के साथ तुरंत ही झारखण्ड में सीएनटी-एसपीटी कानून, जिसके सहारा से जमीन पर आदिवासी-मूलवासियों का अधिकार व मालिकाना की थोडी-सी कानूनी गारंटी रहती

है और कोई भी उस जमीन का खरीद नहीं कर सकता है, में रघुवर सरकार संशोधन लाकर विकास कार्य के लिए जरूरी है, कहकर जमीन छीनकर कारपोरेटों के हाथों में देने की जो षड़यंत्रात्मक कोशिश की थी, वह व्यापक जन-रोष के दबाव से अभी-अभी वापस लेने में मजबूर हुई है। पर, दूसरा षड़यंत्रात्मक योजना अपनाकर आदिवासी-मूलवासियों की जमीन छीनने का भूमि अधिग्रहण कानून विधानसभा में पारित करवा लिया गया है। उसका एकमात्र उद्देश्य है दलाल नौकरशाह पूंजीपति (सीबीबी) व विदेशी पूंजीपति या कारपोरेटों को झारखण्ड के विशाल खनिज भण्डारों को लूट की खुली छूट देना और इस तरह से रक्तपिपासु शोषकों के हितों की रक्षा करना।

फिर, रघुवर दास सरकार द्वारा पारित स्थानीयता नीति संबंधी कानून पूरा का पूरा आदिवासी-मूलवासी के स्वार्थ विरोधी है और इस स्थानीयता नीति का अर्थ है, अपनी वास भूमि पर आदिवासी जनता को प्रवासी का जीवन बिताने के लिए मजबूर करना। जाहिर है कि प्रशासनिक व पुलिस विभाग सहित अन्यान्य आफिसर के पद पर स्थानीय आदिवासी-मूलवासी की नियुक्ति लगभग नहीं के बराबर ही होगी। पर, सबसे भारी काम व कम वेतन मिलने से संबंधित काम तो आदिवासी-दलित लोगों का ही काम है जैसा नियम जारी है।

जाहिर है कि झारखण्ड राज्य अलग होने के बाद से रघुवर दास सरकार का आगमन तक कारपोरेट व दलाल बड़ा बुर्जुआ के साथ लगभग 109/110 एमओयू का समझौता था और रघुवर दास सरकार आने के बाद पहले के अलावा और कुछ करार किया गया तथा 'मोमेंटम झारखण्ड' नारा के तहत फिलहाल और 210 करार किया गया। जिसका मतलब है अगर उक्त करारों का कार्यान्वयन किया जाएगा, तो पहले के लाखों लाख विस्थापित हुए लोगों के साथ नया करके और कई लाख आदिवासी मूलवासी को विस्थापन का दंश झेलने के लिए मजबूर होना। फिर, 'रघुवर दास सरकार के जमाने में, पहले से लाखों की संख्या में आदिवासी किशोरी व युवती को रोजगार देने के नाम पर असल में नौकरानी व यौन कर्मी के रूप में प्रशासन व लड़की तस्करों की मिलीभगत से जो बाहर भेजा गया है' उन सभी के बारे में यह सरकार न तो कोई पता लगाने का गंभीर प्रयास की और न ही ऐसी तस्करी रोकने के लिए कोई कड़ा कदम ही उठायी। बल्कि, इस सरकार के बीते तीन सालों के दौरान बाहर भेजी गयी ऐसी लड़कियों की संख्या में और काफी इजाफा हुआ।

ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद द्वारा आदिवासी जनता, जिसका धार्मिक रीति-रिवाज व आचार-आचरण पूर्ण रूप से पहाड़-पत्थर-जंगल-पेड़-झरना यानी प्रकृति पर आश्रित है, को हिन्दु कहकर जोर-जबरन परिभाषित करने का षड़यंत्रात्मक प्रयास जारी है। हर कोई का अपना-अपना पसंद के अनुसार कोई भी धर्म व धार्मिक रिवाज पर विश्वास रखने का स्वीकृत अधिकार का, धर्मांतरण संबंधी कानून पास करवा कर, पूरी तरह उल्लंघन करते हुए जबरन हिन्दु धर्म को मानने के लिए दबाव डालकर बाध्य करने का प्रयास जारी है।

ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी द्वारा ढाया जा रहा जुल्म-सितम का और एक चरम दमनात्मक अभिव्यक्ति है, गो-रक्षा व लव-जेहाद के नाम पर धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमानों को विभिन्न बहाना लगाकर तंग-तबाह, गाली-गलौज, मारपीट और अंत तक भीड़ जुटाकर हत्या करना। पूरे भारत में मुसलमानों की इस रूप से जो हत्याएं की जा रही है, झारखण्ड, बिहार व असम में ऐसी कई घटनाएं हुई है। झारखण्ड में तो गो-मांस खाने का मिथ्या आरोप लगाकर दस-बारह मुसलमानों की बर्बर रूप से हत्या की गयी है। साथ ही साथ वैसी ही मिथ्या आरोप लगाकर इसाई धर्म मानने वाले कई लोगों की भी हत्या कर दी गई है। इसके अलावा, सभी को हिन्दू धर्म के रीति-रिवाज को मानते हुए तब अपना अलग कुछ धार्मिक रिवाज है तो उसे मनाया जा सकता है- ऐसा फरमान ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी ताकतों द्वारा जारी किया जा रहा है।

अब सवाल है कि ऐसे जुल्मों का मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना है? पहली बात तो यह है कि ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद का अर्थ क्या है उसके बारे में यानी जाति-आधारित ब्राह्मणवादी सामंतवाद द्वारा चलाया जा रहा शोषण-जुल्म के विशिष्ट चरित्र और रूपों को लेकर तथा सामाजिक व विचारधारात्मक रूप से ब्राह्मणवाद और जाति प्रथा निम्न जातियों व दलितों के उत्पीड़न को जिस रूप से बढ़ा देती है की समस्या को लेकर जनता के बीच व्यापक राजनीतिक भंडाफोड़ का काम करना, यानी विचारधारात्मक क्षेत्र में व्यापक जनमत तैयार करना जो हमारा प्रथम व प्रधान कर्तव्य है- उसे कार्यान्वित करते रहना। साथ-ही-साथ, भारत के अर्द्ध-औपनिवेशिक, अर्द्ध-सामंती चरित्र रहने के कारण यहां पर फासीवाद व निरंकुशता यातनाशाह जो एक दूसरे के साथ हाथे-हाथ मिलाकर चलता है, उस बारे में भी चर्चा चलाना। फिर, ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी बीजेपी ने पिछले साढ़े तीन वर्षों के फासीवादी तरीका अपनाकर तथा अत्यंत चतुराई से आदिवासी की भलाई, सब का विकास आदि 'लुभावने नारे' की आड़ में समूचे आदिवासी इलाके की जनता पर जो युद्ध छेड़ रखी है, उसे देख आदिवासी सहित अन्यान्य दलित-उत्पीड़ित जनता आज खुद ही बीजेपी सरकारों की असली मंशा के बारे में बहुत हद तक समझ पायी है। वे समझ पा रहे हैं कि पूर्वजों के समय से लेकर आज तक जो जमीन-जायदाद व पहाड़-जंगल वे अपना कहकर समझ रहे थे, उसे छीनकर बड़ा-बड़ा पूंजीपतियों के हाथ में दे देने का एक गंभीर षड़यंत्र का वास्तव रूप देने का ही रघुवर दास सरकार का प्रयास जारी है। पर, गौरवपूर्ण संघर्ष की परम्परा

से लैस तथा सिद्धू-कान्हू-बिरसा मुण्डा की वीर भूमि की संतान इस तरह अन्यायपूर्ण सारे कुछ मुंह बंद कर मान लेने को तैयार नहीं है। इसलिए इन सारे शोषण-जुल्म-अत्याचार व जुल्मी नियम-कानूनों के खिलाफ वे संगठित, जागरूक व हथियारबंद होकर 'खुद की समस्या खुद ही हल करें' के तरीका अपनाकर लगातार विभिन्न रूपों के संघर्ष में उतर पड़े हैं। साथ ही इस बात को याद रखना है कि इआरबी अंतर्गत लगभग सभी स्थानों में पार्टी है, पीएलजीए है, जन मिलिशिया है, केकेसी-आरपीसी है, अन्यान्य जन संगठनें भी हैं। मतलब व्यापक व जुझारू प्रतिवाद-प्रतिरोध आंदोलन भी है और सशस्त्र प्रतिरोध भी है। हमारा कर्तव्य है कि परिस्थिति के अनुसार सशस्त्र प्रतिरोध चलाने पर जोर देने के साथ-साथ जन प्रतिरोध आंदोलन के पहलुओं पर भी उचित जोर देना। अवश्य ही सशस्त्र प्रतिरोध को जनयुद्ध के बतौर रूप देकर आगे बढ़ाना ही हमारा अहम कर्तव्य रहेगा। हकीकत में समूचे आदिवासी इलाकों में फासीवादी सरकार द्वारा जारी बर्बर व अन्यायपूर्ण युद्ध चलाया जा रहा है। ताकि तमाम खनिज तथा प्राकृतिक सम्पदा पर कारपोरेट व दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों का पूर्ण नियंत्रण व लूट का राज कायम हो सके। आदिवासी जनता ने भी सिद्धू-कान्हू-वीर बिरसा की तरह देशी-विदेशी लूटेरे दुश्मनों को मार भगाने की लड़ाई की है तथा स्वतंत्र रहकर अपनी इच्छानुसार आर्थिक-सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था का संचालन करने की लड़ाई की परम्परा के अनुसार और सीपीआई (माओवादी) की रहनुमाई में आज का न्यायपूर्ण प्रतिरोध युद्ध चला रही हैं और जिसे अंतिम रूप से दुश्मनों को पूरी तरह परास्त होने तक चलाती भी रहेगी।

(4) प्रश्न : मोदी की नव उदारवादी नीतियों और साम्प्रदायिक नीतियों के बीच के संबंध को आप कैसे देखते हैं? इआरबी में कौन सी ताकतें हैं, जिनके साथ क्रांतिकारी ताकतें एकजुट हो सकती हैं व संघर्ष के कौन-कौन से तत्व इस्तेमाल कर सकते हैं?

उत्तर : अगर आप पूछते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का साम्राज्यवाद-निर्देशित नव उदारवादी नीतियों के साथ साम्प्रदायिक नीतियों का संबंध को कैसे देखा जाना चाहिए, तो मेरा कहना है कि तमाम साम्राज्यवादी नीतियां एक-एक देश के प्रभावशाली शोषक व उसकी दलाली करने वाली शासक पार्टियों की जोर-जबरनपूर्वक शासन प्रणाली के साथ-साथ सामाजिक रीति-रिवाज, शिक्षा-संस्कृति-धर्म, साम्प्रदायिकता, जाति (caste), राष्ट्रीयता इत्यादि मुद्दे पर भी काफी भेद-भाव व दबाव रहती ही है। शासक पार्टियां हर समय जनता के बीच फूट डालकर अपना उल्लू सीधा करने या राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए जब जैसी जरूरत उपरोक्त हथियारों का इस्तेमाल करती रहती हैं। अभी ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी मोदी सरकार उग्र हिन्दू राष्ट्रवाद को हर प्रकार से बढ़ावा दे रही है, ऐसा कि आरएसएस तो भारत को हिन्दू राष्ट्र के बतौर घोषणा करने की जोरदार वकालत कर रहा है। साथ-ही-साथ मोदी व मोदी सरकार धर्म व साम्प्रदायिकता के मुद्दे पर आधारित होकर ही गो-हत्या बंद या गो-रक्षा कानून और लव-जिहाद का नारा लाकर अभी तक पूरे भारत में भीड़ द्वारा हमला चलाने का हीन कौशल अपनाकर दर्जन से उपर मुसलमान की हत्या कर चुकी है और लगभग सौ से उपर मुसलमान जनता को पीट-पीट कर घायल कर दी है। फिर, धर्मान्तरण कानून बनाकर इसाई धर्म मानने वालों पर, उनके गिरजाघरों पर और गो-मांस खाने का आरोप लगाकर उन पर हमला बोल रही है, उनके अनेकों प्रकार के रीति-रिवाजों पर प्रतिबंध लगा दी है।

दरअसल, जनता साम्प्रदायिक दंगा बिल्कुल ही नहीं चाहती है। वाकई में, साम्प्रदायिक दंगा-फसाद शोषक वर्गों के वर्गीय फायदा के लिए साजिशपूर्ण कायदे से लगाया जाता है और उग्र हिन्दुत्ववादी पार्टियों के हिन्दू वोट बैंक की संख्या वृद्धि के लिए हिन्दू-मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण करवाने में मदद करता है।

चूंकि शोषक-शासक वर्ग और उग्र हिन्दुवादी व अन्यान्य धर्म के कुछ इने-गिने प्रतिक्रियावादी तत्व को छोड़कर बाकी आम मेहनतकश जनता दंगा-फसाद बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है। इसलिए इन तमाम साम्प्रदायिकता विरोधी ताकतों को क्रांतिकारी ताकतों के साथ एकजुट किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। अलावा, तमाम अल्पसंख्यक मुसलमान जनता, धर्मान्तरण बिल के कारण परेशान जनता, आदिवासी को हिन्दू कहकर परिचय देने के दबाव के कारण उत्पीड़ित आदिवासी जनता और तमाम प्रगतिशील व जनवादपसंद व्यक्ति व ताकतें भी क्रांतिकारी ताकत के साथ एकजुट हो सकती हैं। क्योंकि उपरोक्त सभी प्रकार के तत्वों व ताकतें भी इस बात से भलीभांति वाकिफ हैं कि हकीकत में साम्प्रदायिकता विरोधी असल तत्व माओवादी व माओवादी पार्टी ही है।

जहां तक साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष का सवाल है, वह बहुत प्रकार के हो सकते हैं। विचारधारात्मक व राजनीतिक भंडाफोड़ का संघर्ष, प्रतिवाद-विक्षोभ- जुलूस, जुझारू प्रदर्शन, प्रतिरोध व दंगा लगाने वाले मूल-मूल षड़यंत्रकारी व सरगना को जन-अदालत में विचार कर उचित सजा देने का संघर्ष इत्यादि रूपों को, जब जैसा जरूरी तब वैसा रूप का इस्तेमाल किया जा सकता है। सांगठनिक रूप से साम्प्रदायिकता विरोध ी मोर्चा या मंच या कौमी एकता मंच इत्यादि रूपों का संगठन का गठन कर आंदोलन चलाया जा सकता है। फिर, साम्प्रदायिक गुण्डों के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए गांव-गांव व इलाके-इलाके में प्रतिरोध वाहिनी का गठन व दिन-रात ड्यूटी की व्यवस्था होना अनिवार्य है। जहां तक इआरबी राज्यों में इस प्रकार के समस्या को लेकर संघर्ष का सवाल है, वहां इस साम्प्रदायिक समस्या के सभी पहलुओं की ओर से हल के लिए उचित कार्यनीति अपनाने में प. बंगाल में हमारी माओवादी पार्टी सबसे आगे है व उनके पास साम्प्रदायिकता विरोधी

बहुमुखी संघर्ष के बहुत सारे अनुभव का भंडार मौजूद है; पं. बंगाल के बाद बिहार-झारखण्ड का स्थान आता है। ये दोनों प्रांतों में भी साम्प्रदायिक दंगा विरोधी संघर्षों का अनुभव मौजूद हैं और झारखण्ड व बिहार के आदिवासी, दलित, मेहनतकश जनता, आम तौर पर साम्प्रदायिक दंगा विरोधी होती हैं। मिसालस्वरूप- सन् 1989 में भागलपुर में लगाया गया भीषण साम्प्रदायिक दंगा के खिलाफ जनता का जबरदस्त प्रतिरोध, झारखण्ड के हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर में दंगा के विरूद्ध व्यापक जन-विरोध की घटनाएं इत्यादि। असम में हमारी पार्टी कमजोर स्थिति में रहने के कारण दंगा विरोधी आंदोलन भी बहुत कमजोर ही है और शासक पार्टियों की फूट-परस्त नीति के राजनीतिक भंडाफोड़ के काम को भी ठीक रूप से चलाने में हम नहीं सफल रहे हैं। फिर भी जहां तक हो सके वहां तक तो हमारी कोशिश जारी ही है। दरअसल ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी आरएसएस-बीजेपी व कुछ प्रतिक्रियाशील बड़ा अफसर की मिलीभगत व साजिश के तहत जनता को आपसी विरोधों में फंसाकर विभक्त रखने के बुरे इरादों से आगजनी, दंगा, महिलाओं के साथ बलात्कार व हत्या की तांडवलीला आदि को योजनाबद्ध ढंग से संचालन किया जाता रहा है। इसलिए बंगाल-झारखण्ड व बिहार-असम के आदिवासी, दलित, मेहनतकश जनता स्वाभाविक रूप से ही साम्प्रदायिकता विरोधी विभिन्न रूपों के संघर्षों में शामिल होते हैं। फिर भी, साम्प्रदायिक विरोधी संघर्ष का सवाल पर और भी बहुत कुछ करना बाकी है। सच कहा जाए तो अनुभव बताता है कि उग्र हिन्दू राष्ट्रवाद का बुरा प्रभाव पर जितना चोट किया जाएगा और विपरीत में जनता के आम दुश्मनों के विरूद्ध सभी प्रकार के दोस्तों को लामबंद कर जितने हद तक एकतबद्ध संघर्ष का विकास किया जाएगा और फिर माओवादी आंदोलन को जितना बढ़ाया जाएगा, उतना ही साम्प्रदायिक दंगा-फसाद में कमी आयेगी।

(5) प्रश्न : गोरखालैंड आंदोलन के प्रति पार्टी का क्या रूख है? इस आंदोलन के इतिहास व वर्त्तमान की वे कौन से पहलू हैं, जो इसके भविष्य को तय कर सकते हैं?

उत्तर : इस आंदोलन के बारे में पार्टी का रूख क्या है, को ठीक से समझने के लिए कुछ बातों को सिलसिलेवार ढंग से रखना जरूरी है। वह यह है- पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग जिला के सदर दार्जीलिंग कर्शियाङ और कलिंपोङ सब-डिविजनों तथा पार्श्ववर्ती इलाकों को केंद्रित कर एक अलग गोरखालैंड राज्य की मांग करना, नागरिक अधिकार को गारंटीशुदा बनाना, बांग्ला भाषा को जोर-जबरन थोप देने के खिलाफ और विभिन्न अधिकारों की मांग पर एक आंदोलन शुरू हुआ है। हालांकि कई वर्षों पहले भी यह गोरखालैंड आंदोलन जुझारू रूप लेकर कुछ हद तक आगे बढ़ा था। पर, आंदोलन के शीर्ष नेता सुभाष घिसिंग की गद्दारी के कारण उक्त आंदोलन अपने लक्ष्य तक बढ़ने में विफल रहा। फिर भी उस समय जैसा अभी भी इस आंदोलन में अंतर्निहित व्यापक जनता की बात को ध्यान में रखकर ही अनेक कमजोरियों के बावजूद-हम इस आंदोलन के प्रति सहानुभूति व समर्थन जता रहे हैं। साथ ही साथ व्यापक जनता की आशा-आकांक्षा के साथ संगति रखकर ही और आंदोलन की सफलता के लिए बल देकर हम कहना चाहते हैं कि अगर इस इलाके की जनसाधारण के लिए सच्ची स्वाधीनता, सच्चा जनवादी अधिकार और सच्ची मुक्ति हासिल करना हो, अगर सचमुच में उसकी बुनियादी मसलों को हल करना हो, अगर सभी राष्ट्रीयता की व्यापक जनता के समान अधिकार व मान-मर्यादा कायम करना हो और इनके सर्वांगीण विकास के रास्ते को प्रशस्त करना हो, तो अवश्य ही गोरखालैंड की विभिन्न राष्ट्रीयता की उत्पीड़ित जनता को गोलबंद होकर अपनी संगठित शक्ति पर निर्भर करके हिम्मत व धैर्य के साथ कठिन संघर्ष के दौर से गोरखालैंड आंदोलन को अर्थनीतिक शोषण व राजनीतिक उत्पीड़न से मुक्त एक अलग गोरखालैंड की स्थापना की लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। हमारा कहने का मकसद यह है कि आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में सही मायने की मुक्ति हासिल किए बिना अर्थात् स्थानीय प्रतिक्रियावादी शोषक वर्गों सहित 'देशी'-विदेशी शोषकों द्वारा गोरखालैंड इलाके की व्यापक जनसाधारण पर जो बर्बर शोषण व शासन की व्यवस्था लम्बे समय से चली आ रही है उसे जड़ से उखाड़ फेंके बिना तथा मजदूर-किसान, मंझौला तबका तथा व्यापक उत्पीड़ित जनता का राज व शासन व्यवस्था कायम किये बिना केवल अलग गोरखालैंड राज्य पाने मात्र से ही व्यापक जनसमुदाय की सही मायने की मुक्ति हासिल कर पाना संभव नहीं है एवं आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में हो अथवा भाषा, शिक्षा व संस्कृति के क्षेत्र में हो, तमाम राष्ट्रीयता के जनसाधारण का विकास का रास्ता उन्मुक्त नहीं हो सकता, सभी राष्ट्रीयता के लिए समान अधिकार कायम नहीं हो सकता, जनता की सच्ची स्वाधीनता, सच्चा जनवाद और सच्ची मुक्ति हासिल करना संभव नहीं हो सकता।

इस आंदोलन का इतिहास निम्न रूप है : इस बात को भी अनेक लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग जिला मूलतः तीन पहाड़ी सब-डिविजनों क्रमशः दार्जीलिंग सदर, कलिंपोङ व कर्शियाङ तथा मैदानी इलाका के सिलिगुड़ी को लेकर गठित हुआ है। इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने 1835 में सिक्किम नरेश से कलिंपोङ को छोड़कर बाकी पहाड़ी भूखंड को बलपूर्वक दानस्वरूप लिखवा लिया था। इसके पश्चात 1865 में अंग्रेजी हुकूमत ने भूटान से जोर-जबरन कलिंपोङ को छीन कर सिक्किम नरेश से लिया गया भूखंड के साथ जोड़ दिया।

बाद में, 1841 में ही, ब्रिटिश साम्राज्यवादी लोगों ने इस क्षेत्र को चाय बगान बनाने के लिए चुन लिया था तथा योजना

बनायी थी। फलस्वरुप 1861 के अंदर ही चाय उपजाने की अच्छी जगह होने के कारण 22 चाय बगान लगाए गए। 19वीं शताब्दी के अंत तक और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में चाय उद्योग का विकास होने के साथ-साथ चाय मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। चाय मजदूरों की संख्या में वृद्धि इस इलाके की एक महत्वपूर्ण घटना है। तराई के मैदानी इलाकों के चाय बगानों के मजदूरों का अधिकांश हिस्सा ही तत्कालीन बिहार (अभी झारखंड) के छोटानागपुर और संथाल परगना इलाके के आदिवासी जनता हैं और पहाड़ी इलाका के चाय बगानों के मजदूरों का बहुसंख्यक हिस्सा नेपाल के लिम्बुआन क्षेत्र (Limbuan region) से आयी हुई जनता है। नेपाल से आए मजदूरों के अंदर नेपाल के विभिन्न जाति (Caste) की जनता और नेपाली आदिवासी जनता वहां बस गयीं।

तब तक अंग्रेजी साम्राज्यवादी लोगों ने पर्वतीय चौरस (जो उबड़-खाबड़ न हो) जमीनों पर नेपाल से आए लोगों को वास करने के लिए उत्साहित किया ताकि अंग्रेज बगान मालिकों को चाय-उद्योगों के लिए दास-मजदूर की आवश्यकता पूरी हो सके। इन लोगों ने ही जंगली हिंसक जानवरों से लड़ाई कर कठोर मेहनत करके पहाड़ी जमीनों को खेती योग्य बनाया। 18वीं सदी में नेपाल के सामंती राजाओं और उच्च वर्ण के सामंती प्रभुओं के शोषण-उत्पीड़न के फलस्वरूप नेपाल की गरीब जनता और आदिवासी जनता की जमीनों की मिलकियत संकुचित होती रही। क्रमशः इनकी अच्छी किस्म की प्रायः कुल जमीने व फसलें इन राजाओं और सामंती प्रभुओं के कब्जे में जाती रही। घोर गरीबी की हालत से उबर पाने की मंशा लेकर गरीब और आदिवासी जनता (उदाहरणस्वरूप लिम्बुआन लोग) पूर्व की दिशा में हटते हुए अंततोगत्वा दार्जीलिंग व सिक्किम में वास करने के लिए विवश हुए। इन्होंने ही कठोर मेहनत करके इस इलाके की खेती में काफी विकास लाए। लेकिन यहां के भी अधिक जमीनों व फसलों के मालिक जमींदार व महाजन लोग ही होते थे। इसे छोड़ व्यापारियों का शोषण तो है ही। इन पर्वतीय वाशिंदों को अपनी जरूरत की लकड़ियां लाने के लिए घुस देना पड़ता है। फिर बात-बात में विभिन्न तरह के जुल्म-अत्याचार, मारपीट, तंग-तबाही और फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार किया जाना आदि रोज दिन की घटनाएं हैं।

अतएव, देखा जाता है कि सभी चीजों को उपजाते अथवा तैयार करते हैं मजदूर, किसान व मेहनतकश जनता, लेकिन सभी चीजें चली जाती हैं शोषक लोगों के कब्जे में और उसकी मिलकियत में। इसके बावजूद भाषा, शिक्षा व संस्कृति के द्वार प्रायः बंद हैं। ऐसी परिस्थिति क्रमशः इस इलाके की आम जनता के लिए बरदाश्त के बाहर हो पड़ी है।

इधर 1950 की भारत-नेपाल संधि की धारा 7 के अनुसार भारतीय नेपालियों (वसवासकारियों) को प्रवासी के रूप में मानने की आशंका से गोरखा जनता के नागरिक अधिकार का प्रश्न ही आज संकट में है। वस्तुतः यह मसला तब गंभीर रूप धारण किया जब असम आंदोलन में गोरखा जनता को भी विदेशी की संज्ञा दी जाती रही। हाल ही में कई हजार गोरखा जनता, जो मेघालय राज्य के जोराई के पहाड़ी कोयला खदानों में काम करते थे, को विदेशी कहकर खदेड़ा गया। इन सभी कारणों से ही उनके अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न तीव्र होता गया। ऐसी एक पृष्ठभूमि से ही अतीत में और अभी गोरखालैंड आंदोलन का उदय हुआ।

मौजूदा गोरखालैंड आंदोलन में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा नाम के संगठन ही हिरावल भूमिका अदा कर रहा है। प्रसंगक्रम में उल्लेखनीय है कि 'अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज' नामक संगठन बहुत पहले से ही उत्तर बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों में बसे हुए नेपाली जनता की भाषा, शिक्षा, संस्कृति तथा आर्थिक, सामाजिक और नागरिकत्व की समस्या का हल करने संबंधी मांग करते आ रही है। यही वह पहलू है, जिसको हासिल करने के लिए उनको निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना व अमल करना जरूरी है, वे हैं :

प्रथमतः साधारण दुश्मन के रूप में साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाही पूंजीपति और सामंतवाद को चिन्हित करनी चाहिए, साधारण दुश्मन के विरूद्ध अपनी एकता को मजबूत बनाना चाहिए। इनके विरूद्ध जिनके साथ जितना हद तक एकता स्थापित करना संभव हो, उनके साथ उतना हद तक एकता स्थापित करना चाहिए। अपनी मुक्ति हासिल करने के लिए दुश्मनों की राजसत्ता छीन कर उस पर कब्जा कायम करने के लिए गोरखालैंड को एक शोषणहीन-उत्पीड़नहीन गोरखालैंड में रूपांतरण करने के लिए यहां के तमाम मजदूर-किसान और आम मेहनतकश जनता को एकजुट हो जाना चाहिए। साथ ही साथ जनविरोधी, धर्मवादी, वर्णवादी तथा भाषा संबंधी भेदभाव को दूर कर तमाम शोषित-उत्पीड़ित व्यापक जनता को गोलबंद हो जाना चाहिए एवं साधारण दुश्मनों के खिलाफ जिन्हें गोलबंद करना संभव हो उनके साथ बृहत्तर एकता कायम करना चाहिए। इस तौर-तरीके से ही गठन करना होगा, एक सच्चे अर्थ का जन मुक्ति मोर्चा अथवा संयुक्त मोर्चा जो दुश्मन वर्ग को पराजित कर अपनी मुक्ति हासिल करने हेतु और गोरखालैंड को शोषणहीन एक गोरखालैंड बनाने हेतु एक अन्यतम हथियार होगा।

द्वितीयतः दुश्मन को शिकस्त देने हेतु और अपनी मुक्ति हासिल करने हेतु सही मार्ग से दृढ़तापूर्वक क्रमशः आगे बढ़ना होगा। दुश्मन वर्ग की पुलिस-मिलिटरी अथवा सशस्त्र सैन्यबल ही उसका शासन-यंत्र अथवा राजसत्ता का मुख्य अंग है और यही है उसका शोषण-शासन जारी रखने का मुख्य हथियार। अगर दुश्मन की शोषण-शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना हो तो, मुख्य केन्द्रीय कर्त्तव्य के रूप में उसकी इस सैन्यशक्ति को निर्मूल करना ही होगा और ऐसा करने के लिए हथियारबंद संघर्ष के मार्ग को मजबूती के साथ

पकड़ना होगा। हथियार पकड़ने में साहसी होना होगा, युद्ध करने में साहसी होना होगा, युद्ध के दौर से जनफौज व आधार इलाका निर्माण करना होगा। पहले क्रमशः देहाती इलाके को मुक्त कर बाद में शहरी इलाके को घेर डालना होगा। धरना देकर अथवा दया, अनुग्रह व रिलिफ की भीख मांग कर समस्याओं का हल न कभी हुआ है और न होगा। चुनाव अथवा किसी भी तरह के शांति मार्ग से मौजूदा शोषण व शासन व्यवस्था को उखाड़ा नहीं जा सका है और न उखाड़ा जाना संभव है। अवश्य ही मीटिंग, जुलूस और विभिन्न तरह के आंदोलन चलाने होंगे। लेकिन इसका उद्देश्य दुश्मन गुट और उसकी शोषण-शासन व्यवस्था के विरूद्ध जनता की घृणा को तीव्रतर करना मुख्य व केन्द्रीय कर्त्तव्य के रूप में राजसत्ता पर कब्जा कायम करने के लिए हथियारबंद संघर्ष निर्माण करने हेतु जनसमूह को जागरूक व संगठित करना और क्रमशः सशस्त्र प्रतिरोध अथवा लाल प्रतिरोध संघर्ष और छापामार युद्ध का निर्माण करना होगा।

विभक्त न हों एकताबद्ध हों; सही दुश्मनों के खिलाफ सही दोस्तों को गोलबंद करें; हथियार उठाने में साहसी हों; विजय हासिल करने में साहसी हों; फुटपरस्त शक्तियों को पराजित करें और गोरखालैंड को जनता का जनवादी शासन-व्यवस्था वाला गोरखालैंड यानी एक शोषणहीन-उत्पीड़नहीन गोरखालैंड में बदल डालें- यही गोरखालैंड आंदोलन के मूल नारे होने चाहिए।

(6) प्रश्न : इआरबी के अंतर्गत कई कमेटियों के महत्वपूर्ण कामरेडों ने हाल-फिलहाल आत्मसमर्पण किया है। इससे आपकी पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन नकारात्मक शिक्षकों से हमारे कामरेडों व जनता को क्या सबक लेना चाहिए?

उत्तर : यह बात सही है कि कई कमेटियों के कुछ कामरेडों द्वारा आत्मसमर्पण करने से पार्टी का कुछ नुकसान अवश्य ही हुआ है। खासकर, इआरबी राज्यों के अंदर झारखण्ड में ही जहां तीखा क्रांतिकारी वर्ग-संघर्ष तथा वर्गयुद्ध क्रमशः जन युद्ध का रूप लेता जा रहा है, वहां दुश्मन का आक्रमण भी क्रमशः और तीव्र रूप लेता जा रहा है। सच कहा जाए तो दुश्मन तमाम प्रतिक्रियावादी व फासीवादी तरीके अपनाकर जनता के खिलाफ एक अन्यायपूर्ण युद्ध छेड़ दिया है और साथ ही साथ विश्व जनता के खूंखार दुश्मन अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा निर्देशित 'कम तीव्रतावाला युद्ध (एलआईसी)' पालिसी के तहत आत्मसमर्पण नीति का व्यापक रूप से इस्तेमाल कर रहा है।

अगर हमारी पार्टी के विभिन्न कमेटियों से कई कामरेडों द्वारा आत्मसमर्पण की बात पर सोचा जाए तो यह साफ उजागर हो जाता है कि कुछ नैतिक व आर्थिक रूप से भ्रष्ट, कायर व बहुत दिनों से दुविधा के अंदर रह कर मानसिक तौर पर पीछे हट रहा था, वैसे तत्व ने अधःपतित होकर अंततः दुश्मन के पास आत्मसमर्पण करने का रास्ता ही चुन लिया है। बीजे में- बीजे सैक से दो और बीआरसी व जेआरसी रीजन स्तर से चार, जोनल स्तर से चार और सबजोन व एरिया कमेटी स्तर से कई लोग और प. बंगाल में बीजेओ (बं-झा-ओ) बोर्डर कमेटी से एक, रीजन स्तर से एक व जोन स्तर से एक व एरिया स्तर के कई लोग, बिहार के पूर्वी बिहार व उत्तर-पूरब झारखण्ड स्पेशल एरिया कमेटी के निचला स्तर एरिया स्तर के कई लोग तथा असम से भी क्षेत्रीय कमेटी के एक- दो सदस्य आत्मसमर्पण कर चुके हैं। जिसमें कई अधःपतित तत्व सीधा तौर पर दुश्मन पक्ष की मदद में जुटकर गद्दार बन चुके हैं और जनता व क्रांति का दुश्मन के रूप में चिन्हित हुए है।

हालांकि आत्मसमर्पण को लेकर बड़े पैमाने पर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा झूठा प्रचार चलाया जा रहा है। केन्द्र व विभिन्न राज्य सरकारों की तरफ से माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण की जो संख्या तमाम मीडिया के जरिए प्रचार किया गया है या किया जा रहा है, सच कहा जाय तो उसमें दो-तिहाई या लगभग 75 प्रतिशत बिल्कुल झूठ का पुलिंदा के अलावे और कुछ भी नहीं है। फिलहाल, एक जनवादी संगठन द्वारा रांची के एसपी पर पांच सौ से अधिक निर्दोष लोगों को (जिनके साथ माओवादियों के कभी भी किसी प्रकार का न संबंध था न आज ही है) माओवादी होने का मिथ्या आरोप लगाकर आत्मसमर्पण दिखाने की घटना को लेकर उच्च अदालत में मुकदमा दर्ज करना इसकी ताजा मिसाल है। सवाल है कि उपरोक्त कुछ आत्मसमर्पण को ही केवल आत्मसमर्पण के रूप में कहा जाएगा और क्या पूरे देश को गिरवी देनेवाले को देश के साथ चरम गद्दारी करने वाला आत्मसमर्पण नहीं कहा जाएगा? असल में, तथाकथित आजादी के बाद से जितनी सरकारें आयी हैं, वे सारे के सारे साम्राज्यवाद के पास धीरे-धीरे समूचे भारत को गिरवी रखने का काम करती आयी हैं, जो अब मोदी सरकार के जमाने में चरम पर है। खासकर उदारीकरण-निजीकरण-भूमंडलीकरण की नीतियां धड़ल्ले से अमल में लाकर आज जब देश की पूरी खनिज सम्पदा सहित प्राकृतिक सम्पदा को 'मेक इन इंडिया', 'मैनूफैक्चारिंग हब', 'डिजिटल इंडिया' आदि नारों की आड़ में कारपोरेटों व नौकरशाह दलाल पूंजीपतियों के हाथ बेच दिया गया है व दिया जा रहा है, तब यह क्या आत्मसमर्पण व गद्दारी नहीं है? निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि देश को गिरवी रखने का आत्मसमर्पण सबसे निकृष्ट, घृणित आत्मसमर्पण है, जो न केवल अपराध है, बल्कि देश के साथ गद्दारी भी है।

इस नकारात्मक पहलू को लेकर आम कार्यकर्ताओं को घृणित आत्मसमर्पण पालिसी से संबंधित सारे पहलुओं को लेकर विचारधारात्मक, राजनीतिक व सैद्धांतिक रूप से शिक्षित किया जा रहा है। क्योंकि आत्मसमर्पण चिंता की जड़ सैद्धांतिक व विचारधारात्मक चिंतन में निहित है, इसीलिए यह

कोई हल्का सवाल नहीं है। आत्मसमर्पण को केवल उपरी तौर पर एक-एक अलग-थलग घटना के रूप से देखा जाएगा, तो आदर्शबोध की जगह से यह बहुत कमजोर सोच की अभिव्यक्ति होगी। इसलिए इस सवाल पर व्यापक बहस व चर्चा होनी चाहिए। साथ ही आम जनता को भी इस बहस में शामिल करनी होगी। फिर आत्मसमर्पण करना सही है या गलत, इस पर भी व्यापक जनता के बीच बहस की जरूरत है। आम जनता के बीच भी इस सवाल का मौजूदा सत्ता व व्यवस्था के साथ क्या संबंध है, उसके बारे में राजनीतिक भंडाफोड़ किया जा रहा है। सभी को यानी कार्यकर्ता व जनता को हर प्रकार से शोषण मुक्ति के लक्ष्य पर अडिग रहने के लिए और आत्मसमर्पण नीति को तीव्र घृणा करने के लिए तथा आत्मसमर्पण करने वालों को जनता से अलग-थलग कर उसे घृणित व्यक्ति के रूप में चिन्हित करने के लिए व्यापक प्रचार व शिक्षा का काम किया जा रहा है।

वस्तुत:, कई अध:पतित व्यक्ति द्वारा आत्मसमर्पण, वस्तु का एक पहलू है। विपरीत में दूसरा पहलू यह है कि ऐसे अध:पतित व सड़े हुए तत्वों का पार्टी में न रहने से पार्टी और मजबूत हुई तथा बोल्शेविक दृढ़ता में भी बढ़ोतरी हुई।

(7) प्रश्न : इआरबी अंतर्गत 'सैट बैक' की अभी क्या स्थिति है?

उत्तर : आपको मालूम ही है कि सीसी-4 बैठक द्वारा पार्टी व आंदोलन का मूल्यांकन किया गया। जिसके जरिए इआरबी राज्यों की पार्टी व आंदोलन सैट-बैक की स्थिति में है, जैसा कहा गया है। उस स्थिति से सम्पूर्ण रूप से बाहर आने के लिए कुछ जरूरी कार्यनीति व कार्यभारों को भी तय किया गया है, जो अभी लागू-ही है। फिर, इआरबी की 8वीं बैठक द्वारा, पहले की सैट-बैक की स्थिति की ठोस हालात क्या है और कहां तक उससे बाहर हो पाने में समर्थ हुआ है, पुन: इसका आकलन किया गया और इस निचोड़ पर पहुंचा गया था कि सैट-बैक की स्थिति में कोई विकास न होकर बल्कि एक कदम पीछे खिसकने की स्थिति जैसी बनी हुई है। पुन: कुछ फौरी कार्यसूची तय किया गया था। जैसे- पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए 8 सूत्री कार्यसूची; फौजी मोर्चा के लिए 8 सूत्री कार्यसूची; संयुक्त मोर्चा के क्षेत्र में 9 सूत्री कार्यसूची। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण सरकुलर भी जारी किया गया। जैसे- बोल्शेविकरण पर ''हमारे विचारों और कार्यशैली में आमूल-चूल परिवर्तन लायें!'', ''पार्टी, पीएलजीए, क्रांतिकारी जन कमेटियों व जन संगठनों का बोल्शेवीकरण करें'', ''पार्टी में जीवन शैली से संबंधित तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर''। फौजी मोर्चा पर यूनिफाइड कमान से संबंधित विषयों, कमान को सुसंगठित करने का विषय; अभी जब आत्मगत शक्तियों में कुछ कमी आयी है, तब प्रतिरोध कार्रवाइयों का उचित रूपों का विषय, रणनीतिक संयुक्त मोर्चा पर केकेसी-आरपीसी व क्रांतिकारी मोर्चा का गठन व कार्यसूची का विषय, कार्यनीतिक संयुक्त मोर्चा और फासीवाद-विरोधी मोर्चा से संबंधित और कुछ कार्यक्रमों का विषय इत्यादि।

फिर, फरवरी 2017 में संपन्न सीसी-5 का मूल्यांकन के अनुसार समूचे देश के क्रांतिकारी आंदोलन को कठिन दौर से उबारकर आगे बढ़ाने के लिए पिछले चार वर्षों में आंदोलन द्वारा हासिल किया गया सकारात्मक-नकारात्मक पहलुओं, नये अनुभवों और सामने खड़ी हुई समस्याओं को पहचानना जरूरी है। साथ ही साथ मौजूदा राजनीतिक स्थिति में अनुकूल व प्रतिकूल पहलुओं को पहचानना जरूरी है। इनके आधार पर भविष्य संबंधित कर्तव्यों को रेखांकित कर सकते हैं।

उपरोक्त दिशा के जरिए यह भी कहा गया है कि मध्य और पूर्वी रीजनों में रीजन स्तर की विस्तारित बैठकें आयोजित कर विभिन्न रीजन के अंतर्गत राज्यों में आंदोलन की स्थिति की समीक्षा के जरिए सही आकलन कर, विभिन्न राज्यों के लिए उचित कर्तव्य लिए गये हैं। पूर्वी रीजन के अंतर्गत विभिन्न राज्यों व स्पेशल एरियाओं में राज्य स्तर के प्लेनम आयोजन करने की प्रक्रिया जारी है. डीके और बीजे व पूर्वी बिहार-पूर्वोत्तर झारखण्ड में अभी भी छापामार युद्ध एक हद तक तेजी से जारी है। लाल प्रतिरोध इलाके, छापामार इलाके और छापामार आधार इलाकों में जल-जंगल-जमीन-इज्जत-अधिकार के लिए, विभिन्न आर्थिक समस्याओं पर, ऑपरेशन ग्रीन हंट हमलों के खिलाफ, ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी के खिलाफ हजारों जनता ने हमारी पार्टी के नेतृत्व में कई आंदोलन चलायी है। बोल्शेवीकरण सहित हमारे द्वारा लिए गये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की वजह से कठिन दौर से उबरने के लिए दृढ़संकल्प, आत्म-बलिदान की चेतना और अनुशासन बढ़ रहा है।

उल्लिखित तमाम चर्चाओं के बतौर निष्कर्ष व निचोड़ कहा जा सकता है कि इआरबी क्षेत्र में जारी धक्का खायी हुई स्थिति से बाहर आने का स्रोत व आधार स्पष्ट है। बशर्ते कि उक्त स्रोत व आधारों को अथक प्रयास कर ठीक-ठीक उपयोग या इस्तेमाल किया जाए।

अभी सभी राज्यों के सभी जगहों पर पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान पूरी पार्टी में बोल्शेवीकरण की उक्त प्रक्रिया गंभीरतापूर्वक चलाये जाने के कारण कमोबेश कई सकारात्मक पहलुवें दिखाई पड़ रहा है। उदाहरणस्वरूप, पार्टी के लगभग सभी स्तरों की कमेटियों की कमेटी बैठक व एक-एक इलाके की पुनर्गठन करने के कामों की अग्रगति कहां तक हो पायी, उसकी समीक्षा होना शुरू हुई है, एकीकृत कमान सहित अन्य कई स्तरों के कमान का पुनर्गठन का काम जारी है, मैदानी क्षेत्र जहां पार्टी का अस्तित्व व कामकाज लगभग नष्ट होने के कगार पर पहुंच गया था, वहां पुन: कामकाज की शुरूआत करने खातिर, शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार, कुछ ठोस योजना अपनायी गयी है। कस्बों व छोटे शहरों और औद्योगिक मजदूर,

ठेका मजदूर व श्रमजीवी जनता के बीच, छात्र व युवाओं के बीच, मेहनतकश महिलाओं के बीच भी पुनः कामकाज की शुरूआत करने के लिए शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार, किसी-किसी कमेटी की पहल से कुछ प्रारंभिक योजना अपनायी गयी है; कुछ जन-मुद्दों को लेकर कहीं-कहीं कुछ जन-आंदोलन भी दिखाई पड़ रहा है।

तमाम विषयों पर व्यापक चर्चा व शिक्षा क्लास का जो भी आयोजन किया जा सका, उससे किसान जनता सहित अन्यान्य गैर-किसान व मेहनतकश जनता के बीच जाकर व्यापक प्रचार व सांगठनिक काम करने के कारण गांव स्तर से लेकर इलाकाई स्तर पर केकेसी सहित कुछ जगहों पर क्रांतिकारी जन कमेटी का पुनर्गठन कर उसे कुछ सक्रिय कर पाना धीरे-धीरे संभव हो रहा है। जब्त जमीन जनता के कब्जा में ही रहे, इसके लिए पुनः प्रयास शुरू हुआ है। किसानों के अन्यान्य समस्या व मुद्दों को लेकर भी कुछ सक्रियता पहले की अपेक्षा बढ़ी है। साथ ही आक्रमण की जवाबी कार्यवाही का भी कुछ न कुछ सिलसिला जारी है। उदाहरणस्वरूप, 2018 की जनवरी में औरंगाबाद-पलामू के सीमा क्षेत्र में स्थित छकरबंदा जंगल इलाके में कोबरा कमाण्डो के साथ हुई मुठभेड़ में हमारी पीएलजीए द्वारा दो कोबरा कमाण्डो का सफाया कर उसके बुरे मनसूबे पर पानी फेर दिया गया।

कुल मिलाकर कहने से इआरबी के विभिन्न राज्यों में सैट-बैक की जो स्थिति थी, अभी उस स्थिति से बाहर आने के कई स्रोत व आधारों की स्पष्ट अभिव्यक्तियां कुछ-कुछ दिखाई पड़ने लगी हैं। पर, अभी भी सैट-बैक की स्थिति से संपूर्ण रूप से बाहर आने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है और जरा-सा भी आत्मसंतोष की भावना नहीं पालन-पोषण कर सभी को एकजुट होकर कठिन मेहनत व पसीना बहाकर ही सैट-बैक की स्थिति से बाहर आने की कोशिश में लगा हुआ रहना पड़ेगा। तभी हम उक्त पीछे हटने की स्थिति से बाहर आने में सक्षम हो सकते हैं।

(8) प्रश्न : इआरबी में चलाए गए 'बोल्शेविकरण अभियान' का पार्टी कैडरों पर क्या प्रभाव पड़ा व वे अपने-आप को कितना बोल्शेविक बना पाए?

उत्तर : सैट-बैक की स्थिति से बाहर आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है, पार्टी को सैद्धांतिक-राजनीतिक-सांगठनिक व सामरिक यानी हर पहलू की ओर से और साथ-ही-साथ दृढ़तापूर्वक वर्ग लाइन व जन-लाइन को व्यवहार में लाने से संबंधित सभी पहलुओं की ओर से मजबूत बनाना। इसी उद्देश्य से ही उक्त सभी पहलुओं पर शिक्षा क्लास व चर्चा चलायी गयी और बोल्शेवीकरण पर जो सरकुलर जारी किया गया उसे केन्द्रित कर पार्टी के स्तरानुसार कमोबेश शिक्षा, बहस व आलोचना-आत्मालोचना का दौर चलाया गया। अलावा, पार्टी में जीवन-शैली से संबंधित विषय और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग से संबंधित विषय- ये दोनों को लेकर भी शिक्षा क्लास चलाया गया। फलस्वरूप, सभी कामरेडों व कार्यकर्ताओं के अंदर 'बोल्शेवीकरण अभियान' चलाने की जरूरत पर कम से कम एक समझ बन गयी। लिहाजा कहा जा सकता है कि पार्टी कैडरों पर बोल्शेवीकरण अभियान का एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सभी के अंदर एक दिलचस्पी देखी गई और सभी कोई एक अच्छा बोल्शेविक बनने का प्रयास करना प्रारंभ किया। हालांकि खुद को एक सच्चा बोल्शेविक बना पाना दो/चार दिनों के अंदर संभव नहीं है। खासकर सर्वहारा दर्शन के अनुसार खुद को एक सच्चा कम्युनिस्ट के रूप में बदल पाने के लिए तथा ''व्यक्ति व समूह'' या ''मैं और हमलोग'' इन दो के अंदर दूसरा यानी ''समूह'' या ''हमलोग'' पर जिसका अर्थ है सच्चा मायने में खुद को जनता के एक निष्ठावान सेवक के रूप में रूपांतरण करना, जो उतना आसान नहीं है। बल्कि, एक लम्बी, कठिन व जागरूक प्रयास के जरिए ही उक्त सर्वहारा गुण से खुद को लैस किया जा सकता है। आजीवन उसे बनाया रखना तो हर कम्युनिस्ट के लिए एक चुनौती है।

अलावा, दीर्घकालीन लोकयुद्ध की लाइन के अनुसार खुद की जीवन-शैली को बना पाना भी हमारे लिए एक चुनौती स्वरूप ही बना हुआ है और रहेगी भी। क्योंकि यह केवल एक-दो रोज के लिए नहीं, जब तक के लिए जरूरी है, तब तब के लिए बने रहना हम सबों के लिए एक चुनौती-भरा काम ही है और रहेगा। एक लम्बी प्रक्रिया के जरिए और तीव्र वर्ग संघर्ष व क्रांतिकारी प्रतिरोध युद्ध में भाग लेकर तथा सिद्धांत पर अपने पकड़ को क्रमशः मजबूत करने की प्रक्रिया पर दृढ़तापूर्वक अमल करके ही केवल खुद को सच्चा बोल्शेविक के बतौर रूपांतरण किया जा सकता है।

वाकई में, 'कैडर लोग अपने आपको कितना बोल्शेविक बना पाया' सवाल का जवाब तो केवल सापेक्ष रूप से या तुलनात्मक ढंग से कह पाना ही संभव होगा और उचित भी होगा। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि आम कैडर बीते कल-परसों से आज अपेक्षाकृत थोड़ा ज्यादा खुद को बोल्शेविक बना पाए। पर, अभी अनेक लम्बा रास्ता, उतार-चढ़ाव, बांक-मोड़ व कठिनाइयों को पार करना बाकी रह गया। उन सबों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद ही कोई भी कामरेड खुद को एक सच्चा बोल्शेविक बना पाएगा और इस रूप से एक सच्ची कम्युनिस्ट पार्टी जो मा-ले-मा सिद्धांत से और दीर्घकालीन लोकयुद्ध के व्यावहारिक पहलू व जीवन शैली से लैस, आलोचना-आत्मालोचना की पद्धति से समृद्ध, जनता से घनिष्ठ संबंध रखता हो इत्यादि गुणों से लैस पार्टी बन उठेगी।

उक्त प्रश्न का यही उत्तर है।

(9) प्रश्न : क्रांति के उत्तराधिकारियों को तैयार करने में इआरबी कितना सफल रही है? इस विषय में हमें क्या करना चाहिए?

उत्तर : पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांति के उत्तराधिकारियों को तैयार करने में अभी तक इआरबी उतना सफल नहीं हो पायी है, जितना कि होना चाहिए था। अभी के समय में इआरबी के सामने दूसरी पंक्ति के नेतृत्व देने लायक कामरेड बनाने का बहुत महत्वपूर्ण व कुंजीवत (vital) कर्तव्य पड़ा हुआ है। हालांकि ऐसे दूसरी पंक्ति के होनहार कामरेडों के लिए सैद्धांतिक-राजनीतिक पाठ्यसूची तैयार है और व्यावहारिक या फील्ड ट्रेनिंग का सिलेबस भी तैयार है। पर, अभी भी दुश्मन द्वारा चलाया जा रहा आक्रामक युद्धाभियान की स्थिति में वैसे कार्यक्रमों का लागू करना भी बहुत कठिन है। दरअसल, पं. बंगाल को छोड़कर बिहार-झारखण्ड-असम प्रांतों में दीर्घदिन से शासक श्रेणियों की चरम अवहेलना के कारण, जो आदिवासी-दलित-गरीब तथा चाय बगीचा के गुलाम मजदूर (जिसका आज 'न घर का न घाट की' स्थिति) हैं, उस पिछड़े हुए, गरीब व शिक्षा का घोर अभावग्रस्त इलाके में ही हमारी पार्टी का ज्यादा काम तथा आधार मौजूद है। ऐसी वस्तुस्थिति के कारण ही मार्क्सवादी सिद्धांत को पूरा आत्मसात करने का स्तर तक समझदारी पैदा करना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। हालांकि ऐसी वस्तुस्थिति पार्टी के वर्ग आधार जो सटीक जगह पर है, उसे दर्शाता है। फिर भी हमारे दो संस्थापक व शिक्षक का. सीएम व का. केसी हर समय हमें गरीब व भूमिहीनों को नेतृत्व में तथा स्थानीय नेतृत्व में वैसा ही गरीब-भूमिहीनों को लाने के लिए सिखाए हैं, जिसको वास्तवायित करना हमारा एक अहम कर्तव्य है। पर, ऐसे अनगिनत आदिवासी व गरीब कार्यकर्ताओं को शिक्षित-दीक्षित व प्रशिक्षित करने के लिए बहुत से क्रांतिकारी छात्र-युवा व बुद्धिजीवी पेशेवर कामरेडों की जरूरत है; बहुत ही प्रयत्न व निष्ठा के साथ सबसे उत्पीड़ित व गरीब-भूमिहीन कार्यकर्ताओं को मार्क्सवाद के क, ख सिखाना जरूरी है। ऐसी संख्या संघर्षरत मूल एरिया में बहुत ही कम या कहा जाये तो चिंताजनक रूप से कम है। इससे मूल आधार वर्गों के कैडरों को राजनीतिक रूप से तैयार करने का काम भारी बाधा के सामने खड़ा हो गया है।

इस महत्वपूर्ण विषय पर इआरबी ने सभी महत्वपूर्ण कमेटियों का ध्यान आकर्षित किया है और शहर से क्रांति के प्रति दृढ़ निष्ठा रखनेवाले छात्र, युवा व बुद्धिजीवी कामरेडों को जितना जल्द संभव संघर्षरत एरिया में भेजने खातिर आह्वान रखा है। उम्मीद है कि कुछ दिनों के अंदर ऐसे छात्र-युवा व बुद्धिजीवी कामरेड जरूर मिलेंगे और दूसरी व तीसरी पंक्तियों के कुछ अच्छा नेतृत्वकारी कामरेड तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी।

(10) प्रश्न : इआरबी अंतर्गत इलाकों में लगातार उभर रहे छोटे-बड़े जनांदोलनों को आप किस प्रकार देखते हैं और इसे क्रांति का राही बनाने के लिए क्या योजना होनी चाहिए?

उत्तर : इआरबी अंतर्गत सभी राज्यों में, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, लेकिन जनता लड़ रही हैं। कहीं तबकाई आंदोलन तो कहीं किसानों का आंदोलन, कहीं मजदूरों का आंदोलन तो कहीं छात्र-युवा, शिक्षक व पैरा शिक्षकों का आंदोलन, कहीं डॉक्टरों का आंदोलन तो कहीं जीएसटी कि खिलाफ छोटा व्यापारी व दुकानदारों का आंदोलन, कहीं राष्ट्रीयता के आत्मनिर्णय के अधिकार का आंदोलन तो कहीं अपनी भाषा-शिक्षा-संस्कृति व सांस्कृतिक पहचान बचाने का आंदोलन, कहीं जल-जंगल-जमीन पर अधिकार कायम रखने का मुद्दा पर आंदोलन तो कहीं एमओयू और भयंकर विस्थापन का विरोध का मुद्दा पर आंदोलन, कहीं गांव-देहात से तमाम पुलिस कैम्प वापस लाने तो कहीं जनता की जनसत्ता स्थापित करने का आंदोलन, कहीं सीएनटी-एसपीटी में संशोधन व भूमि-अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन तो कहीं स्थानीयता नीति व धर्मांतरण कानून के खिलाफ आंदोलन, कहीं महिलाओं पर हो रहे विभिन्न प्रकार के चरम यातनाओं के खिलाफ आंदोलन तो कहीं महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी व समान अधिकार व समान मान-मर्यादा स्थापित करने का आंदोलन, कहीं अल्पसंख्यकों पर हो रहे चरम फासीवादी आक्रमण के खिलाफ आंदोलन तो कहीं देशव्यापी पैमाने पर जारी जबरदस्त फासीवादी आक्रमण व बंदूक के साये में जिंदगी बिताने में मजबूर किए जाने के खिलाफ आंदोलन इत्यादि जनांदोलन का उभार साफ तौर पर देशव्यापी पैमाने पर दिखाई पड़ रहा है।

इन तमाम जनांदोलनों को हम क्रांतिकारी लड़ाई का पक्षधर बनाना चाहते हैं। पर, इस चाहत को वास्तव में बदलने का काम उतना आसान नहीं होगा। क्योंकि ऐसे जनांदोलनों के अंदर बहुत-सी अवसरवादी, वोट-लड़वा व गांधीवादी-संशोध नवादी पार्टियों तथा ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी बीजेपी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों का स्वार्थ निहित रहता है। इसलिए वैसी पार्टियां तमाम जन-आंदोलनों को खुद को चुनाव में जीतकर एमएलए, एमपी व मंत्री बनकर अपनी पार्टी को गद्दी पर बैठाने के उद्देश्य से संचालित करती है। पर, जनता के उपरोक्त विभिन्न आंदोलनों से जुड़े हुए आम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। फिलहाल, इन आंदोलनों के अंदर एक विशिष्ट पहलू दिखाई पड़ रहा है कि सभी आंदोलनों का मूल लक्ष्य है मौजूदा फासीवादी व्यवस्था को बदलना और विकल्प के रूप में एक जनता की जनवादी-व्यवस्था का निर्माण करना। इसलिए ऐसे जनांदोलनों को केवल बाहर से ही समर्थन देने के बदले इसके भागीदार बनने की कोशिश करनी होगी। तब जाकर इन आंदोलनों के भागीदार विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलनों का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस पर व्यापक चर्चा करनी होगी। केवल व्यवस्था से उत्पन्न कुछ

समस्याओं को लेकर आंदोलन करना ही यथेष्ट नहीं है, बल्कि जिस व्यवस्था के कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उस व्यवस्था को ही बुनियादी तौर पर बदलने की जरूरत है, इस बिंदु पर भी व्यापक चर्चा करनी होगी। नहीं तो बाप-दादा के जमाने से जिन समस्याओं को लेकर केवल धरना, जुलूस-प्रदर्शन और मांगपत्र पेश करने की शैली चली आ रही है, वही आज भी चलती रहेगी, तो कब इसका अंत होगा? अंत तो तभी होगा, जब मौजूदा सड़ी-गली व्यवस्था को तोड़कर एक नया जनवादी समाज की स्थापना होगी। इस दृष्टिकोण से ही हम उक्त तमाम आंदोलनों को क्रांति की राह के राहगीर बनाने के लिए एक योजना अपनाए हैं। हालांकि इसके लिए हम हमारे अंदर ''ऐसे आंदोलनों के साथ कोई संबंध नहीं, ये सब केवल अवसरवाद का शिकार है'' जैसा कठमुल्लावादी विचारों के खिलाफ काफी सैद्धांतिक-राजनीतिक बहस चलाकर कमोबेश उसे दूर हटाया और फिर कई लोगों को यह कहना कि ''अभी फौज व लाल आधार इलाके के निर्माण पर नहीं ऐसे जनांदोलन के साथ जुट जाना ही मुख्य काम है'' के खिलाफ भी जोरदार बहस चलाकर उसे भी कमोबेश दूर हटाया गया। तब-ही हम ऐसे आंदोलनों को क्रांति की राह पर लाने के लिए एक व्यवस्थित योजना अपनाने में कुछ हद तक समर्थ हुए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के महान शिक्षक कामरेड कार्ल मार्क्स की दो सौवीं जन्मदिवस को 5 मई से 11 मई, 2018 तक क्रान्तिकारी उत्साह और जोश-खरोश के साथ मनाएं!

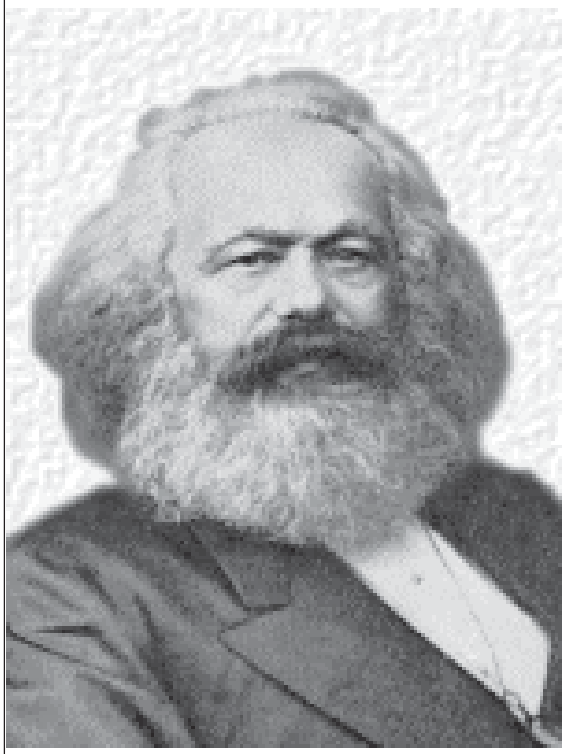

सर्वहारा विचारधारा, राजनीति और वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक और महान दार्शनिक कामरेड कार्ल मार्क्स का दो सौवां जन्मदिवस (द्विशतवार्षिकी) भी नजदीक आ रहा है। कामरेड मार्क्स ने एक नयी और वैज्ञानिक सिद्धांत व कार्यपद्धति तैयार की और मानव को एक नयी दिशा दिखाई। मार्क्सवादी विचारधारा का विकास तीखी वर्ग-संघर्ष की प्रक्रिया के दौरान तथा इसके अंग के रूप में बुर्जुआ व निम्न-बुर्जुआ विचारधारा, अर्थनीति, राजनीति और संस्कृति के खिलाफ संघर्ष में और मजदूर वर्ग के आन्दोलनों में से उभरे 'दक्षिण' व 'वाम' अवसरवादों के खिलाफ संघर्ष में हुआ। हजारों सालों से वर्ग-शोषण और उत्पीड़न के जंजीरों से बंधे मानव समाज के लिए मार्क्सवाद ने एक नयी युग की शुरूआत की। मार्क्स की विचारधारा ने वर्ग विहीन समाज की तरफ संक्रमण को - और इस तरह समाज की मुक्ति को - एक वास्तविक संभावना में तब्दील की।

मालूम हो कि हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी द्वारा पूर्व में ही विश्व सर्वहारा के महान शिक्षक कामरेड कार्ल मार्क्स का दो सौवां जन्मदिवस 5 मई से 11 मई, 2018 तक क्रांतिकारी उत्साह और जोश-खरोश के साथ मनाने का आह्वान किया गया था। लाल चिनगारी, संपादकमंडल आप तमाम पार्टी सदस्यों, पीएलजीए के योद्धाओं, संयुक्त मोर्चा के साथियों समेत सभी पाठकगण को हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी द्वारा जारी आह्वान को व्यवहार में उतारने यानी 5 मई से 11 मई, 2018 तक आम सभा, जुलूस, रैली, सेमिनार, गोष्ठी आदि आयोजित कर व्यापक जनता के बीच कामरेड कार्ल मार्क्स के विचारों को फैलाने की अपील करती है।

नक्सलबाड़ी की पीढ़ी के वरिष्ठ कम्युनिस्ट और हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य अमर शहीद कामरेड नारायण सान्याल को शत्-शत् लाल सलाम!

नक्सलबाड़ी की पीढ़ी के वरिष्ठ कम्युनिस्ट और हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड नारायण सान्याल हमें बहादूरी से दीर्घकालीन लोकयुद्ध को अंतिम जीत तक जारी रखने के लिए प्रेरित करते रहेंगे!

हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता नक्सलबाड़ी की पीढ़ी के आखिरी क्रांतिकारियों मे से एक कामरेड नारायण सान्याल (विजय दा) कैंसर बिमारी से 80 साल की उम्र में 16 अप्रैल, 2017 को शहीद हो गये। दुश्मन उन्हें गलत मुकदमे में फंसा कर 9 साल तक जेल में रखकर तंग-परेशान किया। बढ़ती उम्र व लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण वह 2014 में जेल से रिहा हुए। शहीद होने के समय तक उन पर अलग-अलग राज्यों में विभिन्न तरह के मुकदमे चल रहे थे। गिरफ्तार होने के समय से ही वह बिमारियों से पीड़ित थे, पर इतने साल जेल में गुजारने, भारत सरकार द्वारा सोच-समझ कर इलाज करवाने में की गई अवेलहना के कारण गिरफ्तारी के समय की बिमारियां और बिगड़ गई। उनकी असमय मृत्यु के लिये सीधे-सीधे भारत सरकार ही जिम्मेदार हैं। उनकी शहादत हमारी पार्टी, भारतीय क्रांति और जनता के लिए एक बड़ा नुकसान है। हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी अपने प्यारे कामरेड विजय दा को तहेदिल से विनम्रतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती है और जिस आशय के लिये वह जीये और मृत्यु प्राप्त किये, उसको पूरा करने के लिए अंतिम जीत तक क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष में काम करने की मुट्ठी बंद कर शपथ लेती है। हमारी केन्द्रीय कमेटी उनके परिवार वालों, दोस्तों और उनके सभी साथियों, जो देश भर मे फैले हुए है, उन्हें तहेदिल से शोक संदेश भेजती है। संपूर्ण पार्टी, पीएलजीए और पूरे देश भर के क्रांतिकारी जन संगठन, इस आदर्श कामरेड को लाल श्रद्धांजलि पेश करेंगे, सर्वहारावर्गीय गुणों से सिखेंगे, नक्सलबाड़ी के रास्ते के लिये उनकी जीवन भर की प्रतिबद्धता से प्रेरणा प्राप्त करेंगे और एक शोषण मुक्त व उत्पीड़न मुक्त समाज के उनके सपने को साकार करने की शपथ लेते हैं।

शुरूआती राजनीतिक जीवनः-

कामरेड नारायण सान्याल का जन्म 1937 ई. में पश्चिम बंगाल राज्य के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। वे बचपन में ही औपनिवेशिक शासन के खिलाफ, भारत के बंटवारे और कम्युनिस्ट अन्दोलन खासकर तेभागा अन्दोलन से प्रभावित हो गये थे। वे बहुत ही संवेदनशील उम्र में ही कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित हो गये थे और स्टूडेंट्स फेडरेशन (छात्र संघ) के कार्यकर्ता बन गये थे। जल्दी ही वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गये। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर एक सार्वजनीक क्षेत्र के बैंक में नौकरी कर लिये। उन्होंने अपना राजनीतिक काम भाकपा से संबंधित बैंक कर्मचारियों की यूनियन में जारी रखा, जिसका नेतृत्व गले तक संशोधनवाद में डूबा हुआ था। कामरेड माओ के नेतृत्व वाली सी.पी.सी. द्वारा सी.पी.एस.यू. के खुश्चेवी संशोधनवादी गुट के खिलाफ छेड़ी गई महान बहस ने पूरी दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियों में संशाधनवाद विरोधी संघर्ष को तेज कर दिया। भारत में भी सच्चे कम्युनिस्टों ने भाकपा के संशोधनवादी नेतृत्व पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिये और वैचारिक संघर्ष शुरू हो गया, जोकि भारत चीन युद्ध के समय अपने चरम पर पहुंच गया। कामरेड विजय दा अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में इस बहस का बहुत ही रूचि के साथ अनुसरण किये। वे सी.पी.सी. को समर्थन किये और भाकपा के अन्दर क्रांतिकारियों के खेमे में शामिल हो गये। वह पार्टी टूटी और माकपा बनी, तो वे इस उम्मीद के साथ नयी पार्टी में शामिल हुए कि वह संशोधनवाद से निर्णायक तौर पर संबंध विच्छेद करेगी और क्रांतिकारी पथ अख्तियार करेगी। पर, जल्द ही यह साबित हो गया कि नयी पार्टी अपने कार्यक्रम और व्यवहार में दक्षिणपंथी-अवसरवादी है। कामरेड चारू मजुमदार और कामरेड कन्हाई चटर्जी जैसे सच्चे कम्युनिस्टों ने इसकी तीखी आलोचना शुरू की। खासकर कामरेड सी. एम. के ऐतिहासिक आठ दस्तावेजों ने क्रांतिकारी पथ का अनुसरण करने वालों, जोकि माओ विचारधारा और सी.पी.सी. का समर्थन करते थे, पर मुलम्मा चढ़ाने का काम किया। माकपा के अन्दर इस तीखे वैचारिक संघर्ष से कामरेड विजय

दा बहुत प्रभावित हुए। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की पृष्ठभूमि में और देश के अन्दर बढ़ते हुए क्रांतिकारी संकट के कारण आन्तरिक संघर्ष तेज हो गया। जिसकी परिणति नक्सलबाड़ी के शानदार क्रांतिकारी किसान संघर्ष के रूप मे हुई। कामरेड विजय दा दृढ़ता से का. चारू मजुमदार की क्रांतिकारी लाइन का समर्थन किये और नक्सलबाड़ी के क्रांतिकारी संघर्ष की जय-जयकार की। माकपा से सभी संबंध तोड़कर, वे क्रांतिकारी कार्यवाहियों मे कूद पड़े। वे नव-गठित भाकपा(माले) के सदस्य बन गये। उसके कुछ ही समय बाद कामरेड विजय दा ने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी और एक पेशेवर क्रांतिकारी बन गये। नक्सलबाड़ी की लपटों को फैलाने और आधार क्षेत्र स्थापित करने के लक्ष्य से भाकपा (माले) के नेतृत्व ने उन्हें 60 के दशक के अंतिम वर्षों में सामंती उत्पीड़न में जीवन जी रहे बिहार के किसानों को संगठित करने के लिये भेज दिया। नक्सलबाड़ी द्वारा पैदा की गई हलचल ने बिहार में सामंतवाद विरोधी संघर्ष के लिये आग में घी डालने का काम किया। 1969 के दौरान पूरे देश में जमींदारों और पुलिस के हमलों में सैकड़ों साथी शहीद हो गये थे, जबकि राजकीय दमन में हजारों साथियों को जेल में डाल दिया गया। उन मुश्किल घड़ियों में भी विजय दा नक्सलबाड़ी की लाइन को दृढ़ता से उपर उठाये रखे और उस संशोधनवादी लाइन से डटकर टक्कर लिये, जिसने अपना सर उस समय उठाया था। वे सत्य नारायाण सिंह (केन्द्रीय कमेटी सदस्य, भाकपा-माले) की विभाजनकारी, दक्षिणपंथी -अवसरवादी और दिवालिया लाइन के खिलाफ संघर्ष का दृढ़ता से नेतृत्व किये और बहादूरी से नक्सलबाड़ी की लाइन को उपर उठाये रखे। कामरेड विजय दा बिहार राज्य कमेटी के सचिव बने। पर कुछ समय के बाद ही 1972 में हुई उनकी गिरफ्तारी के कारण उन्हें बिहार के आन्दोलन को मार्गदर्शन देने और उसे विकसित करने का मौका नहीं मिला।

क्रांतिकारी शक्तियों की एकता मे भूमिका और भाकपा (माले) पी.यू. का गठन

अपनी गिरफ्तारी के बाद कामरेड विजय दा को पहले बिहार का जेल में रखा गया। उन्होंने पुलिस हिरासत में क्रूर यातना का सामना किये, पर वह दृढ़ रहे और दूसरों को भी दुश्मन का सामना बहादूरी से करने के लिये प्रेरित किये। अन्य नेतृत्वकारी साथियों के साथ, वे और दूसरे क्रांतिकारी जेल अधिकारियों द्वारा संचालित किये गये हमलों को झेले। उनके साथ मिलकर वे जेलबंदियों की बहुत सारी मांगों समेत राजनीतिक बंदियों की मांगों पर हुए आंदोलनों को नेतृत्व दिये। कामरेड नारायण सान्याल ने समान समझदारी रखने वाले कामरेडों जैसे कि कामरेड परिमल सेन (अजय दा, जो भाकपा (माओवादी) के केन्द्रीय कमेटी सदस्य बने) और कामरेड अजीत (जो भाकपा (माओवादी) की प. बंगाल राज्य कमेटी के सदस्य बने) के साथ नजदीकी संबंध स्थापित किया। उन्होंने सामूहिक तौर पर भाकपा (माले) नेतृत्व द्वारा क्रांतिकारी संघर्ष की समीक्षा की और कुछ बुनियादी सवालों पर एक जैसे विचार विकसित किये। इस पर अधारित होकर अभी भी कोई सच्ची पार्टी होने से, इस समीक्षा की बुनियाद पर, सच्चे क्रांतिकारियों की एकता की समझदारी पर पहुंचे। भाकपा (माले) की लाइन, कामरेड सी.एम. की भूमिका, टूट-फूट एवं अनेकता पर दक्षिणपंथी-अवसरवादियों द्वारा मनमानी ढंग से हमले संचालित करने की परिस्थिति में और कामरेड सी.एम. की शहादत और नक्सलबाड़ी संघर्ष के पीछे हटने के बाद कामरेड विजय दा ने जेल से ही सच्ची क्रांतिकारी शक्तियों को एकताबद्ध करने और आन्दोलन को पुनः निर्मित करने के प्रयासों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आपातकाल हटने के बाद, कामरेड विजय दा और अन्य बहुत सारे कामरेड जेलों से रिहा हुए। उन्होंने और समान विचार रखने वाले अन्य कामरेडों ने भाकपा (माले) की 8वीं कांग्रेस द्वारा अपनायी गई लाइन और आन्दोलन की उनकी खुद की समीक्षा के अधार पर सच्चे क्रांतिकारी ग्रुपों के साथ वार्ता चलाने के लिऐ प्रयास तेज कर दिया। पर यह प्रयास अपने अनुसार नतीजे नहीं दे सके। वह समझ गये कि यह प्रयास तब तक सफल नही होंगे, जब तक कि वे अपनी समीक्षा के आधार पर एक क्रांतिकारी आन्दोलन नही खड़ा कर लेते। इसी समझदारी से उन्होंने नवंबर 1978 में कांग्रेस आयोजित की। भाकपा (माले) का ऐतिहासिक महत्व, एकता के बारे में और 'सफाया की लाइन' के बारे में तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज पारित किये गये और इस ऐतिहासिक कांग्रेस में ही नयी पार्टी भाकपा (माले) पार्टी यूनिटी गठित हुई। पार्टी को चलाने के लिये एक केन्द्रीय सांगठनिक कमेटी बनाई गई और कामरेड विजय दा उसके सदस्य बने। पार्टी ने रणनीतिक दृष्टि से दक्षिण मध्य बिहार में एक क्रांतिकारी किसान आन्दोलन खड़ा करने का फैसला किया। प. बंगाल के नदिया और मुर्शिदाबाद जिलों में भी किसानों में काम शुरू किया गया।

पार्टी यूनिटी बनने के बाद, सी.ओ.सी. (केन्द्रीय सांगठनिक कमेटी) ने अन्य क्रांतिकारी ग्रुपों के साथ एकता स्थापित करने के प्रयास जारी रखे। पहली एकता कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठन के साथ 1980 में हुई, जिसमें कि भाकपा (माले) यू. ओ. बनायी। 1982 में, भूतपूर्व भाकपा (माले) के कामरेड शर्मा और कामरेड अप्लासूरी के ग्रुप के साथ भाकपा (माले) यू.ओ. का विलय हुआ और भाकपा (माले) पी.यू. बनी। मुख्यतः बंगाल में काम करने वाली सी.सी.आर.आई. का बिहार धड़ा, 1988 में पी.यू. से जुड़ गया। 1990 में भाकपा (माले) (सी.टी.) की पंजाब इकाई के संग्राम ग्रुप का विलय पी.यू. में हो गया। कामरेड विजय दा ने इन सभी विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

क्रांतिकारी आन्दोलन को विकसित करने में भूमिकाः-

विलय से मजबूत होकर, पी.यू. ने बिहार के मगध क्षेत्र में कृषि क्रांति को विकसित करने के परिप्रेक्ष्य से कार्य शुरू किया। पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व के एक महत्वपूर्ण हिस्से ने इस कार्यभार पर केन्द्रीकरण किया। कामरेड विजय दा ने आगे होकर इस कार्य को नेतृत्व प्रदान किया। नक्सलबाड़ी के किसान संघर्ष के अनुभव से शिक्षा पाकर और जन दिशा को लागू कर, कोयल-कैमूर, जहानाबाद और औरंगाबाद में एक शक्तिशाली सामंतवाद विरोधी संघर्ष खड़ा किया गया, पार्टी इकाइयां बनायी गई, मजदूर और किसान संगठन (एम.के.एस. एस.) स्थापित किया गया, जमींदारों के गुण्डों और सरकारी हथियारबंद बलों का मुकाबला करने के लिऐ जनमिलिशिया का निर्माण किया गया और छापामार दस्ते तैयार किये गये। जन संगठनों और मिलिशिया से पार्टी और छापामार दस्तों में भर्ती कर आन्दोलन को मजबूती प्रदान की गई। मिलिशिया और दस्तों को जमींदारों और पुलिस बलों से हथियार जब्त कर विस्तार किया गया। आन्दोलन की सफलताओं और विकास को मजबूत करने के लिये पार्टी की शिक्षा प्रदान की गई। इसी तरह, पार्टी द्वारा बंगाल के मैदानों खासकर नदिया, मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में माकपा के सामाजिक फासीवादी शासन के खिलाफ लड़ते हुये संघर्ष को विकसित किया गया। पी.यू. के नेतृत्व के एक हिस्से ने इस आन्दोलन को विकसित करने के लिऐ केन्द्रीकरण किया और यह पी.यू. द्वारा नेतृत्व किया गया महत्वपूर्ण संघर्ष इलाके के तौर पर उभरा।

बिहार और बंगाल दोनों में ही, सामंतवाद विरोधी संघर्षों के साथ-साथ, पुराने अनुभवों से सबक लेते हुए, साम्राज्यवाद, सामंतवाद और जनता के अन्य मुद्दों पर राजनीतिक गोलबंदी की गई। पटना, कोलकाता, कृष्णनगर में छात्रों, नौजवानों, महिलाओं और अन्य उत्पीड़ित तबकों को मजदूर, छात्र और युवा संगठनों में संगठित किया गया। पंजाब के कुछ हिस्सों और आंध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम और विजयनगर जिलों में ग्रामीण क्रांतिकारी आन्दोलन विकसित किया गया था। इस प्रकार, पार्टी ने पूर्वी भारत में जनाधार के साथ क्रांतिकारी आन्दोलन विकसित किया। इन सभी कार्यों की योजना और क्रियान्वयन में पार्टी की सी.ओ.सी. के सदस्य के नाते कामरेड विजय दा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था।

आन्तरिक संघर्ष मे पार्टी का नेतृत्व करने मे भूमिका:-

उसी समय जब पुराने अनुभवों का सार संकलन कर और नये उच्च स्तर के कार्यभार तय करके आन्दोलन को आगे बढ़ाने की परिस्थितियां परिपक्व हो रही थी, पार्टी का महासचिव अशोक एक दक्षिणपंथी-अवसरवादी लाइन लेकर सामने आया। इस लाइन का वकालत करने वालों ने दावा किया कि अर्ध-सामंती, अर्ध-औपनिवेशिक संबंधो में मौलिक परिवर्तन होने से कृषि में पूंजीवादी संबंध विकसित होने के कारण आधारभूत परिवर्तन आ गया है, जिसने कृषि क्रांति और दीर्घकालीन लोकयुद्ध को निरर्थक बना दिया है। पर वे अपने दावों को मार्क्सवादी विश्लेषण पद्धति से साबित ना कर पाए और ना ही अपनी लाइन को ही लागू करने के लिये ठोस रणनीति पेश कर पाए। इस संशोधनवादी लाइन ने पार्टी के क्रांतिकारी चरित्र को ही समाप्त कर देने और अभी तक प्राप्त सभी सफलताओं को खत्म कर देने का खतरा खड़ा कर दिया था। यह राजनीतिक-वैचारिक संघर्ष पार्टी की 1987 में हुई केन्द्रीय कांफ्रेन्स में चरम पर पहुंच गया। कामरेड विजय दा ने गलत लाइन को हराने और सही लाइन और पार्टी को बचाने के लिये इस संघर्ष का दृढ़ता से नेतृत्व किया। फलस्वरूप, कांफ्रेन्स में गलत लाइन की हार और दीर्घकालीन लोकयुद्ध की लाइन की जीत हुई। पार्टी ने उच्च स्तर की एकता हासिल की। अशोक और एक अन्य केन्द्रीय सांगठनिक कमेटी का सदस्य पार्टी छोड़ कर भाग गया और कामरेड विजय दा महासचिव चुने गये। 1987 से 1998 तक उन्होंने महासचिव के तौर पर कुशलतापूर्वक पार्टी को नेतृत्व प्रदान किया। 1998 में भाकपा (माले) पी.यू. और भाकपा (माले) पीपुल्स वार में एकता हुई और नयी पार्टी भाकपा (माले) पीपुल्स वार बनी।

विलय और एकीकृत पार्टी में भूमिका:-

पी.यू. के सचिव के तौर पर कामरेड विजय दा भाकपा (माले) की 8वीं कांग्रेस की सच्चे कम्युनिस्टों की पिछले समय की सही समिक्षा के आधार पर एकता की समझदारी को लगतार उंचा उठाए रखे। घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति मे आए बदलावों के बारे में एक ही तरह की समझदारी की बुनियाद पर भाकपा (माले) पी.डब्लयू. के बीच 1995 में एकता के बारे में चर्चा शुरू हुई। एकता की प्रक्रिया के भाग के तौर पर 1997 मे पी.यू. की केन्द्रीय कांफ्रेंस बुलाई गई, जिसमें पार्टी द्वारा नेतृत्व किये गये आन्दोलन के 18 सालों की समीक्षा की गई। कांफ्रेंस के दौरान एक केन्द्रीय सांगठनिक कमेटी सदस्य द्वारा पार्टी लाइन पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करते हुए एक आलोचनात्मक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। इस दो लाइनों के संघर्ष ने पी.यू. की राजनीतिक लाइन को समृद्ध किया और आलोचनात्मक दस्तावेज द्वारा किये गये कुछ मूल्यवान और सही अलोचना को कांफ्रेंस ने पी.ओ.आर. में शामिल कर लिया। कामरेड विजय दा ने दो लाइनों के संघर्ष को सही तरीके से चलाने मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और कांफ्रेंस को सफलतापूर्वक संपन्न करने में योगदान दिया, इसने पी.यू. और पी.डब्लयू. की एकता में सब से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तीन साल की एकता प्रक्रिया

और सभी मूल विचारधारात्मक, राजनीतिक, सांगठनिक और सैन्य मामलों पर एक साझी समझदारी बनने के बाद दोनों पार्टियों का विलय भाकपा (माले) पी.डब्लयू. के तौर पर हुआ। पी.यू. की तरफ से प्रतिनिधिमण्डल और उसके दृष्टीकोण को एकता की इच्छा से सामने रखने का नेतृत्व कामरेड विजय दा ने किया। एकता के बाद, एकीकृत पार्टी ने 1970 की 8वीं कांग्रेस के लगभग 30 साल बाद 9वीं कांग्रेस करने की तैयारी शुरू की। एक वरिष्ठ कामरेड और पोलित ब्यूरो सदस्य के तौर पर कामरेड विजय दा इसकी तैयारियों, आन्दोलन का सार संकलन कर कांग्रेस के दस्तावेज तैयार करने और 2001 में की गई कांग्रेस को चलाने मे गंभीरता से भाग लिये। जब कांग्रेस में एक वामपंथी लाइन उभरी तो केन्द्रीय कमेटी के एक वरिष्ठ (बुजुर्ग-elder) कामरेड के तौर पर उसे हराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दक्षिण पश्चिम ब्यूरो के पी.बी.एम. इन्चार्ज के तौर पर उन्होंने ब्यूरो सचिव के साथ मिलकर ब्यूरो को मार्गदर्शन दिया। जब कर्नाटक मे दक्षिणपंथी-अवसरवादी लाइन ने सिर उठाया, तो वे दूसरे कामरेडों के साथ मिलकर उसे टक्कर दिये और उसे हराया। जब असम में नई क्रांतिकारी शक्तियां उभरी, तो राजनीतिक-वैचारिक शिक्षा देकर उसे मजबूत करने में उन्होंने मदद दी और वहां पार्टी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वे उत्तर-पूर्व के कुछ राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के कुछ संगठनों के साथ रिश्ते भी बनाये रखे।

एक पुराने कामरेड जोकि नक्सलबाड़ी के दौर से ही क्रांतिकारी आन्दोलन में थे और भाकपा (माले) पी.डब्लयू. के केन्द्रीय कमेटी और पोलित ब्यूरो सदस्य के तौर पर नई पार्टी को चलाने मे कामरेड नारायाण सान्याल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें क्रांतिकारी आन्दोलन और उसका नेतृत्व करने वाली पार्टी में एकता के फायदों और अनेकता के नुकसानों का अनुभव था। पी.यू. और पी.डब्लयू. की एकता से देश के अन्दर ज्यादातर मार्क्सवादी-लेनिनवादी ताकतों की बहुसंख्या एक हो गई थी। पर पी.डब्लयू. और एम.सी.सी. के बीच चल रही झड़पें उन्हें अत्यधिक चिंतित करती थी। दोनों तरफ से और बिरादराना पार्टियों की ईमानदार कोशिशों से एम. सी.सी. और पी.डब्लयू. ने इन झड़पों को अपनी अत्मालोचना करते हुए सफलतापूर्वक बंद किया। इसने 2001 में दोतरफा रिश्तों के लिए रास्ते साफ कर दिये, जो एकता वार्ता मे परिणत हुए। भाकपा (माले) पी.डब्लयू. के केन्द्रीय कमेटी की तरफ से कामरेड विजय दा ने एम.सी.सी. के साथ एकता वार्ता और एकीकृत पार्टी के लिए समृद्ध समझदारी के साथ दस्तावेज तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिससे दोनों पार्टियों का विलय और भाकपा (माओवादी) का जन्म हुआ। वे नई पार्टी की केन्द्रीय कमेटी और पोलित ब्यूरो सदस्य बने और नये कार्यभारों को निर्धारित करने और आन्दोलन को विस्तार करने के कार्यभार का सूत्रीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक नया रीजनल ब्यूरो उत्तर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के क्षेत्र को मिला कर सी.ई.आर. बी. विस्तार के काम को योजनाबद्ध तरीके से चलाने के लिए बनाया गया। कामरेड विजय दा इस आर.बी. के सचिव बने। इस से पहले कि आर.बी. काम करने लगती, वे एकता के 15 महीनों के अन्दर ही गिरफ्तार हो गये।

जेल जीवन, रिहाई और खुली कार्रवाइयां:-

28, दिसम्बर 2005 को कामरेड नारायाण सान्याल को आंध्रा की एस.आई.बी. द्वारा स्थानीय और केन्द्रीय एजेंसियों की मदद से अपहरण कर लिया गया और आंध्रा के ही एक जिला अदालत में 5 जनवरी, 2006 को पेश किया गया। उनके उपर बहुत सारे मुकदमे मढ़ दिये गये। तिरूपति में चन्द्रबाबू नायडू पर हमले, जहानाबाद जेल ब्रेक, गिरिडीह के होमगार्ड शस्त्रागार पर हमले, मधुबन बहु-हमले, दण्डकारणय में 24 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सफाए आदि मुकदमे मढ़ दिए गए। छत्तीसगढ़ की एक स्थानीय अदालत में उन्हें एक झूठे मुकदमे में मानव अधिकार कार्यकर्ता डा. विनायक सेन और व्यवसायी पीयुश गुहा के साथ-साथ दोषी करार दिया गया और उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लम्बी अवधि की कारावास उनकी क्रांतिकारी भावना और इच्छा शक्ति को तोड़ने में नाकाम रही। वे जेल में मालेमा और पार्टी लाइन पर दृढ़ता से समर्पित रहे। पर लम्बे जेल काल, जेल के मुश्किल हालातों और सेहत के सहुलियतों के अभाव ने उनके सेहत को भारी नुकसान पहुंचाया। जब नवम्बर, 2014 में 9 साल के लम्बे कारावास के बाद वह रिहा हुए, तो उनकी सेहत संबंधित समस्याएं काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इसके बावजूद, उन्होंने केन्द्रीय कमेटी के सामने आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे और कुछ ना कुछ जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। इस तरह उन्होंने क्रांतिकारी आन्दोलन में योगदान देने के लिए भरपूर प्रयास किया और अपनी आखिरी सांस तक अपनी पूरी ताकत लगा दिए। वे कैंसर बिमारी से 16 अप्रैल, 2017 को अपने परिवार वालों, साथियों और दोस्तों के बीच हमें हमेशा के लिए छोड़ गये।

हमारे प्यारे कामरेड विजय दा का देहांत हमारी केन्द्रीय कमेटी, पार्टी, क्रांतिकारी आन्दोलन और देश की उत्पीड़ित जनता के लिए बहुत ही शोक की बात है। एक दृढ़ कम्युनिस्ट के तौर पर उनका आजीवन योगदान, सच्चे क्रांतिकारियों की एकता के लिए उनकी भूमिका और पी.यू.-पी.डब्लयू. और पी.डब्लयू.-एम.सी.सी.आई. के विलय में भूमिका, पार्टी और केन्द्रीय कमेटी में उनकी भूमिका हमें हमेशा प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। उनका अदम्य साहस, युवा उत्साह, पहलकदमी, जनता की मुक्ति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना, मालेमा और पार्टी की बुनियादी लाइन पर दृढ़ रहना, दक्षिणपंथी

और वाम अवसरवाद के खिलाफ संघर्ष और उन्हें हराना, कम्युनिस्टों की एकता के लिए मजबूत इच्छा, जनता तथा साथियों के साथ घुल-मिल जना, जेल में कभी न झुकने का उनका कम्युनिस्ट प्रण और जेल से बाहर आने के बाद उनके द्वारा दिखाया गया उत्साह हमारी यादों में लम्बे समय तक उकेरित रहेगा।

कामरेड विजय दा महान कम्युनिस्ट गुणों के साक्षात उदाहरण थे। वह कभी भी खुद को मान्यता दिलवाने के लालायित नहीं रहे। वे अपने साथियों और उत्पीड़ित जनता के साथ करीबी रिश्ते बनाये रखते थे। वे सीधा-सादा जीवन और कठोर संघर्ष का जीवन जीये। वे अपना मत जाहिर करते समय हमेशा खुले और सपष्ट रहते थे। वे चर्चा के मुद्दों पर कभी भी बिना अध्ययन और जांच-पड़ताल के अपना मत नही रखते थे। वे जनवादी-केन्द्रीयता और सामूहिक कार्यशैली को हमेशा सम्मान देते थे। किसी मुद्दों पर खुद सहमत न होते हुए भी, वे बहुमत के मत का अनुसरण करते थे। केन्द्रीय कमेटी के बुजुर्ग साथी होने के नाते वे अपने साथियों को मदद करने और योगदान देने के लिए तैयार रहते थे। क्रांति के लिए अपना सब कुछ न्यौछवार करने के लिए उम्र भर अविवाहित रहे।

ऐसे गुणों के मालिक होने के कारण, कामरेड नारायण सान्याल आसानी से अपने साथियों और उत्पीड़ित जनता का प्यार, सत्कार और मान्यता हासिल कर लेते थे। उनका 5 दशक लम्बा क्रांतिकारी जीवन, उनके कम्युनिस्ट गुण और उनका आत्म बलिदान हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेगा।

जैसे ही नक्सलबाड़ी क्रांतिकारी किसान संघर्ष अपने 50 साल पूरे कर रहा है, कामरेड नारायण सान्याल 5 दशकों के लगातार क्रांतिकारी संघर्ष के बाद हम से बिछड़ गए हैं। उनके जैसा कामरेड हमारे लिए एक आदर्श है। हमारी केन्द्रीय कमेटी, पार्टी, पीएलजीए और क्रांतिकारी जन संगठनों में हर एक को उनसे शिक्षा लेकर और शाषक वर्गों और साम्राज्यवादियों व ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादियों के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए, उनके कम्युनिस्ट गुणों से शिक्षा प्राप्त कर दीर्घकालीन लोकयुद्ध को आगे बढ़ाएं। हम अपने प्यारे कामरेड विजय दा को लाल सलाम और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि कामरेड विजय दा जिस लक्ष्य के लिए जीये और शहादत प्राप्त किये, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रास्ते में आने वाली हर अड़चनों व बाधायों को पार करते हुए दीर्घकालीन लोकयुद्ध की लाइन पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहेंगे।

★

पृष्ठ संख्या 38 का शेष...

गये होते तो यहूदी समुदाय के लिए एक अलग देश की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन साम्राज्यवादी दुनिया में ऐसा होना मुमकिन ही नहीं था। अमेरिका के नेतृत्व में इजरायल की स्थापना और उसका वहां बसे फिलिस्तीनी नागरिकों को बाहर निकालना लगातार बढ़ता गया। इजरायल द्वारा किया जा रहा सीमा-विस्तार और आज भी फिलिस्तीनी आबादी पर सैनिक हमले, यह सब कुछ मध्य पूर्व के तेल ठिकानों पर अपना दबदबा कायम करने की साम्राज्यवादी राजनीति का हिस्सा है। इनका साथ देने के लिए साम्राज्यवादी मीडिया ने इस कारनामे पर पर्दा डलने के लिए इस्लाम को खतरा घोषित करने का अभियान चलाया है।

उपरोक्त तथ्यों की रोशनी में जब हम इजरायल सरकार की मौजूदा हरकतों को देखते हैं, तो साफ पता चल जाता है कि यहूदियों पर अतीत में ढाये गये जुल्मों के बावजूद यूनान, इटली और जर्मनी से बदला लेने की चाहत उनके मन से क्यों गायब है, जबकि फिलिस्तीनी अरब जनता पर उन्होंने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है।

गौरतलब है कि भारत की वर्तमान सरकार जिस विचारधारा से प्रस्थान करती है, उसमें हिन्दुओं पर अतीत में हुए सभी कथित अन्याय और अत्याचार का हिसाब चुकाना एक प्रमुख और केंद्रीय बिंदु है। जबकि इजरायल के यहूदी इस प्रतिशोधवाद से प्रस्थान नहीं कर रहे हैं। फिर भी दोनों को नजदीक लाने का काम जिस समान लक्ष्य ने किया है, उसे इन दोनों से ज्यादा साम्राज्यवाद ने निर्धारित किया है। यानी इस्लाम को मानव-सभ्यता का दुश्मन घोषित कर देना। अपनी स्थापना के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिटलर के यहूदी विरोधी अभियान से प्रभावित था और उसके नेता भारत में मुस्लिम-समुदाय के खिलाफ इसी तरह का अभियान लेना चाहते थे। आज इसी विचारधारा पर बनी सरकार, एक यहूदी राज्य इजरायल के सैन्य अभियानों, हथियारों, गुप्तचर सेवाओं से प्रशिक्षण लेने तथा उसके प्रचार तंत्र को अपनाना चाहती है। इजरायल का हथियार उद्योग इस समय काफी आगे बढ़ा हुआ है। उसके मौजूदा शासक बेंजामिन नेतनन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही साथ-साथ अमेरिकी साम्राज्यवाद की छत्रछाया में ''मुस्लिम आतंकवाद'' से निपटने की योजना बना रहे हैं। इसकी आड़ में सभी साम्राज्यवादी नीतियों को जनता की निगाह से दूर रखा जा रहा है। बहरहाल परेशान जनता का मुख्य दोष मुसलमानों पर डालकर धनवानों को बचाने की साजिश के दौर में भारत-इजरायल मैत्री को भारत की बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इजरायली गुप्तचर संस्था, 'मोसाद' की मदद से भारत सभी आतंकवादी संगठनों का सफाया कर देगा। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा, एशियाई महाशक्ति बनेगा, सुरक्षा-परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल कर लेगा, वगैरह-वगैरह। साम्राज्यवाद परस्त नीतियों के पालन से भारत सरकार और इजरायली सरकार का कितना भला होगा, यह तो अनुमान की बात है, लेकिन आम आदमी की तबाही तय है।

★

कामरेड कार्ल मार्क्स के जन्मदिन (5 मई) के अवसर पर कामरेड एंगेल्स द्वारा जून, 1877 के मध्य में लिखित लेख

विज्ञान के इतिहास में मार्क्स ने जिन महत्वपूर्ण बातों का पता लगाकर अपना नाम अमर किया है, उनमें से हम यहां दो ही उल्लेख कर सकते हैं।

पहली तो विश्व इतिहास की सम्पूर्ण धारणा में ही वह क्रांति है, जो उन्होंने सम्पन्न की। इतिहास का पहले का पूरा दृष्टिकोण इस धारणा पर आधारित था कि सभी तरह के ऐतिहासिक परिवर्तनों और सभी तरह के ऐतिहासिक परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन ही है तथा सम्पूर्ण इतिहास में उन्हीं की प्रधानता है। लेकिन लोगों ने यह प्रश्न नहीं किया था कि मनुष्य के दिमाग में से विचार आते कहां से हैं ओर राजनीतिक परिवर्तनों की प्रेरक शक्तियां क्या हैं? केवल फ्रांसीसी और कुछ-कुछ अंग्रेज इतिहासकारों की नवीनतर शाखा में यह विश्वास बरबस प्रविष्ट हुआ था कि कम से कम मध्ययुग से, सामाजिक और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए उदीयमान पूंजीपति वर्ग का सामन्ती अभिजात वर्ग के साथ संघर्ष यूरोप के इतिहास की प्रेरक शक्ति रहा है। मार्क्स ने सिद्ध कर दिया कि अब तक का सारा इतिहास वर्ग-संघर्षों का इतिहास है, अब तक के सभी विविधरूपी और जटिल राजनीतिक संघर्षों की जड़ में केवल सामाजिक वर्गों के राजनीतिक और सामाजिक शासन की समस्या, पुराने वर्गों द्वारा अपना प्रभुत्व बनाये रखने तथा नये पनपते हुए वर्गों द्वारा इस प्रभुत्व को हस्तगत करने की समस्या ही रही है। लेकिन इन वर्गों के जन्म लेने और कायम रहने के कारण क्या हैं? इनका कारण वे शुद्ध भौतिक, गोचर परिस्थितियां हैं, जिनके अन्तर्गत समाज किसी भी युग में अपने जीवनयापन के साधनों का उत्पादन और विनिमय करता है। मध्ययुग के सामन्ती शासन का आधार छोटे-छोटे कृषक समुदायों की स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था था, जो अपनी जरूरत की प्राय: सभी चीजों का स्वयं उत्पादन कर लेते थे। इनमें विनिमय का प्राय: पूर्ण अभाव था, शस्त्रध ारी सामन्त बाहर के आक्रमणों से इनकी रक्षा करते थे, उन्हें जातीय या कम से कम राजनीतिक एकता प्रदान करते थे। नगरों के अभ्युदय के साथ अलग-अलग दस्तकारों और परस्पर व्यापार का विकास हुआ जो पहले आन्तरिक क्षेत्र में सीमित था और आगे चलकर अन्तरराष्ट्रीय हो गया। इस सबके साथ नगर के पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ और मध्यवर्ग में ही उसने सामन्तों से लड़-भिड़कर सामन्ती व्यवस्था के अन्दर एक विशेषाधिकार प्राप्त श्रेणी के रूप में अपने लिए स्थान बना लिया।

परन्तु 15वीं शताब्दी के मध्य के बाद से, यूरोप के बाहर की दुनिया का पता लगने पर, पूंजीपति वर्ग को अपने व्यापार के लिए कहीं अधिक विस्तृत क्षेत्र मिल गया। इससे उसे अपने उद्योग-धन्धों के लिए नयी स्फूर्ति मिली। प्रमुख शाखाओं में दस्तकारी का स्थान मैनुफेक्चर ने ले लिया, जो अब फैक्टरियों के पैमाने पर स्थापित था। फिर इसकी जगह बड़े पैमाने के उद्योग ने ले ली, जो पिछले सदी के आविष्कारों, खासकर भाप से चलनेवाले इंजन का व्यापार पर यह प्रभाव पड़ा कि पिछड़े हुए देशों में पुराना हाथ का काम ठप हो गया और उन्नत देशों में उसने संचार के आधुनिक नये साधन-भाप से चलने वाले जहाज़, रेल, वैद्युतिक तार- उत्पन्न किये। इस प्रकार पूंजीपति वर्ग सामाजिक सम्पत्ति और सामाजिक शक्ति दोनों को अधिकाधिक अपने हाथों में केन्द्रित करने लगा यद्यपि काफी अरसे तक राजनीतिक सत्ता से वह वंचित रहा, जो सामन्तों और उनके द्वारा समर्थित राजतन्त्र के हाथ में थी। लेकिन विकास की एक मंजिल ऐसी आयी- फ्रांस में महान क्रांति के बाद- जब उसने राजनीतिक सत्ता को भी हथिया लिया और तब वे वह सर्वहारा वर्ग और छोटे किसानों के ऊपर शासन करनेवाला वर्ग बना गया। इस दृष्टिकोण से समाज की विशेष आर्थिक स्थिति का सम्यक ज्ञान होने से सभी ऐतिहासिक घटनाओं की बड़ी सरलता से व्याख्या की जा सकती है, यद्यपि यह सही है कि हमारे पेशेवर इतिहासकारों में से ज्ञान का सर्वथा अभाव है। इसी प्रकार हर ऐतिहासिक युग की धारणाओं और उसके विचारों की व्याख्या बड़ी सरलता से, उस युग की आर्थिक जीवनावस्थाओं और सामाजिक तथा राजनीतिक सम्बन्धों के आधार पर (ये सम्बन्ध भी अर्थिक परिस्थितियों द्वारा ही निर्धारित होते हैं) की जा सकती है। इतिहास को पहली बार अपना वास्तविक आधार मिला। यह आधार एक बहुत ही स्पष्ट सत्य है, जिसकी ओर पहले लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं गया था, यानी यह सत्य कि मनुष्यों को सबसे पहले खाना-पीना, ओढ़ना-पहनना और सिर के ऊपर साया चाहिए, इसलिए पहले उन्हें लाज़िमी तौर पर काम करना होता है, जिसके बाद ही वे प्रभुत्व के लिए एक-दूसरे से झगड़ सकते हैं और राजनीतिक, धर्म, दर्शन आदि को अपना समय दे सकते हैं। आखिरकार इस स्पष्ट सत्य को अपना ऐतिहासिक अधिकार प्राप्त हुआ।

समाजवादी दृष्टिकोण के लिए इतिहास की यह नयी धारणा सर्वोच्च महत्व की थी। इससे पता लगा कि पहले के सम्पूर्ण इतिहास की गति वर्ग-विरोधों और वर्ग-संघर्षों के बीच में रही है, कि शासक और शासित, शोषक और शोषित वर्गों का अस्तित्व बराबर रहा है और यह कि मानव-जाति के अधिकांश भाग के पल्ले सदा से कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, आनन्दोपभोग बहुत कम। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए कि मानव-जाति के विकास की सभी पिछली मंजिलों में उत्पादन

का विकास इतना कम हुआ था कि ऐतिहासिक विकास इस अन्तरविरोधी रूप में ही हो सकता था, ऐतिहासिक प्रगति कुल मिलाकर एक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय के क्रियाकलाप का ही विषय बना दी गयी थी और बहुसंख्यकों के भाग्य में अपने श्रम द्वारा जीवन-निर्वाह के अपने स्वल्प साधन और इसके अतिरिक्त विशेषाधिकार सम्पन्न समुदाय के लिए अधिकाधिक प्रचुर साधन उत्पादित करना रह गया था। परन्तु इतिहास की यही जांच-पड़ताल, जो हमें इस प्रकार पहले के वर्ग शासन की स्वाभाविक एवं बुद्धिसम्मत व्याख्या प्रदान करती है। (अन्यथा हम मानव-स्वभाव की दृष्टता द्वारा ही उसकी व्याख्या कर सकते थे), साथ ही साथ हमें यह बोध कराती है कि वर्तमान युग में उत्पादक शक्तियों के अति प्रचण्ड विकास के कारण मानव-जाति को शासक और शासित, शोषक और शोषित में बांट रखने का अन्तिम बहाना भी, कम से कम सबसे उन्नत देशों में, मिट चुका है; कि शासक बड़े पूंजीपति अपनी ऐतिहासिक भूमिका समाप्त कर चुके हैं, और जैसा कि व्यापारिक संकटों और खासकर पिछली भयानक गिरावट और सभी देशों में फैली मन्दी से सिद्ध हो चुका है, वे समाज का नेतृत्व करने के योग्य अब नहीं रह गये हैं, बल्कि उत्पादन के विकास में बाधक बन गये हैं; कि ऐतिहासिक नेतृत्व सर्वहारा वर्ग के हाथ में चला गया है, ऐसे वर्ग के हाथ में चला गया है जो समाज में अपनी समग्र स्थिति के कारण सम्पूर्ण वर्ग शासन, सम्पूर्ण दासता एवं सम्पूर्ण शोषण का अन्त करके ही अपने को मुक्त कर सकता है; और यह कि सामाजिक उत्पादक शक्तियां, जो इतनी विकसित हो गयी हैं कि पूंजीपति वर्ग के काबू से बाहर हैं, बस प्रतीक्षा में हैं कि एकजुट सर्वहारा उन्हें अपने हाथों में ले ले, जिससे कि ऐसी अवस्था कायम की जा सके जिसमें समाज का प्रत्येक सदस्य न केवल सामाजिक सम्पदा के उत्पादन में, बल्कि वितरण और प्रबन्ध में भी हाथ बंटा सकेगा और जो अवस्था सम्पूर्ण उत्पादन के नियोजित संचालन द्वारा सामाजिक उत्पादन शाक्यिों और उनकी उपज को इतना बढ़ा देगी कि प्रत्येक व्यक्ति की सभी उचित आवश्यकताओं की उत्तरोत्तर बढ़ती मात्रा में पूर्ति सुनिश्चित हो जायेगी।

मार्क्स ने जिस दूसरी महत्वपूर्ण बात का पता लगाया है वह पूंजी और श्रम के सम्बम्ध का निश्चित स्पष्टीकरण है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने यह दिखाया कि वर्तमान समाज में और उत्पादन की मौजूदा पूंजीवादी प्रणाली के अन्तर्गत कैसे पूंजीपति मजदूर का शोषण करता है। जब से राजनीतिक अर्थशास्त्र ने यह प्रस्थापना प्रस्तुत की कि समस्त सम्पदा और समस्त मूल्य का मूल स्रोत श्रम ही है, तभी से यह प्रश्न भी अनिवार्य रूप से सामने आया कि इस बात से हम इस तथ्य का मेल कैसे बैठायें कि उजरती मजदूर अपने श्रम से जिस मूल्य को उत्पादन करता है, वह पूरा का पूरा उसे नहीं मिलता, वरन उसका एक अंश उसे पूंजीपति को दे देना पड़ता है? पूंजीवादी और समाजवादी, दोनों ही तरह के अर्थशास्त्रियों ने इस प्रश्न का ऐसा उत्तर देने का प्रयत्न किया, जो वैज्ञानिक दृष्टि से संगत हो, परन्तु वे विफल रहे। अन्त में मार्क्स ने ही उसका सही उत्तर दिया वह उत्तर इस प्रकार है: उत्पादन की वर्तमान पूंजीवादी प्रणाली में समाज के दो वर्ग हैं- एक ओर पूंजीपतियों का वर्ग है, जिसके हाथ में उत्पादन और जीवन-निर्वाह के साधन हैं, दूसरी ओर सर्वहारा है, जिसके पास इन साधनों से वंचित रहने के कारण बेचने के लिए केवल एक माल- अपनी श्रम-शक्ति- ही है और इसलिए वो जीवन-निर्वाह के साधन प्राप्त करने के लिए मजबूर है। परन्तु किसी माल का मूल्य उसके उत्पादन में और इसीलिए उसके पुनरूत्पादन में भी लगी सामाजिक दृष्टि से आवश्यक श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है। अत: एक औसत मनुष्य की एक दिन, एक महीना या एक वर्ष की श्रम-शक्ति का मूल्य इस श्रम-शक्ति को एक दिन, एक महीना या एक वर्ष तक कायम रखने के लिए आवश्यक जीवन-निर्वाह के साधनों में लगे श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है। मान लीजिये कि किसी मजदूर को एक दिन के जीवन-निर्वाह के साधनों के उत्पादन के लिए छ: घण्टे का श्रम चाहिए या उसी बात को यों कहें कि उनमें लगा श्रम छ: घण्टे के श्रम की मात्रा के बराबर है, तो श्रम-शक्ति का एक दिन का मूल्य ऐसी रकम में व्यक्त होगा, जिसमें भी छ: घण्टे का श्रम लगा हो। अब यह भी मान लीजिये कि इस मजदूर को काम पर लगानेवाला पूंजीपति उसे बदले में यह रकम देता है और इसलिए उसकी श्रम-शक्ति का पूरा मूल्य उसे अदा करता है। अब अगर मजदूर दिन में छ: घण्टे पूंजीपति के लिए काम करता है तो वह पूंजीपति की पूरी लागत को चुकता कर देता है- छ: घण्टे के श्रम के बदले छ: घंटे श्रम देता है। पर ऐसी हालत में पूंजीपति के लिए कुछ नहीं रहता और इसलिए वह तो इसे बिल्कुल दूसरे ही ढंग से देखता है। वह कहता है: मैंने इस मजदूर की श्रम-शक्ति छ: घण्टे के लिए नहीं बल्कि पूरे दिन के लिए खरीदी है और इसलिए वह मजदूर से 8, 10, 12, 14 या इससे भी अधिक घण्टों की उपज अशोधित श्रम की, ऐसी श्रम की जिसका भुगतान नहीं किया गया होता, उपज होती है और यह सीधे पूंजीपति की जेब में पहुंच जाती है। इस तरह पूंजीपति की नौकरी करनेवाला मजदूर केवल उस श्रम-शक्ति का मूल्य ही नहीं पुनरूत्पादित करता जिसके लिए उसे मजदूरी मिली है, बल्कि इसके अलावा वह अतिरिक्त मूल्य भी पैदा करता है जिसे पहले पूंजीपति हस्तगत करता है और जो बाद में निश्चित आर्थिक नियमों के अनुसार समूचे पूंजीपति वर्ग के बीच वितरित होता है। यह अतिरिक्त मूल्य वह मूल कोष होता है जिससे लगान, मुनाफा, पूंजी का संचय बनता है- संक्षेप में

शेष पृष्ठ संख्या 42 पर...

जनता को जागृत करने के लिए उसके बीच अपनी सैन्य-शक्ति को बिखेर दो तथा दुश्मन से मुकाबले के लिए अपनी सैन्य-शक्ति को केन्द्रित कर लो!

साम्राज्यवादियों के स्वंयसेवक नरेंद्र मोदी और रघुवर दास की ब्राहम्णीय-हिदुत्व-फासीवादी सरकारें आज पूरे झारखण्ड से क्रांतिकारी आन्दोलन को खत्म करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। दरअसल इनका लक्ष्य 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हमारे क्रांतिकारी आन्दोलन को कुचलना है। इसलिए ही मिशन 2017 चलाया गया था और अब एक नया रणनीतिक हमला या अभियान 'समाधान' उसी की ही निरंतरता है। इसी के तहत ही आज हमारे बीजे सैक के सभी क्षेत्रों में ऑपरेशन ऑलआउट चला रहा है।

बेशक दुश्मन के इन दमन अभियानों ने हमें काफी गंभीर नुकसान भी पहुंचाया है। हमारी आत्मगत शक्तियों का नुकसान हुआ है। आज हम धक्का खाए हुए की स्थिति में है। हमने पहल कदमी खोई है। जिसका एक कारण युद्ध के विज्ञान पर मजबूत पकड़ना न होना भी था यानी मार्क्सवादी दृष्टकोण से युद्ध में आ रहे बदलावों को ना समझ पाना और सही रणकौशल इस्तेमाल ना कर पाना भी था। इस धक्का खायी हुई परिस्थिति से मजबूत होकर निकलना हमारे लिए एक चुनौती है, लेकिन द्वंद्वात्मक भौतिकवादी विश्लेषण पद्धति और कार्यपद्धति को अपना कर हम चुनौती को पूरा कर सकते हैं और धक्का खायी हुई की स्थिति से मजबूत होकर उभर सकते हैं।

मार्क्सवादी पद्धति यानी भौतिकवादी द्वंद्वात्माक पद्धति के अंदर केवल तीन नियमों को सामने रखकर ही आगे की चर्चा की जा रही है। वे तीन नियम होते हैं।

(1) विरोधी तत्वों की एकता और संघर्ष

(2) मात्रात्माक परिवर्तनों से गुणात्माक परिवर्तन

(3) निषेध का निषेध।

हमें द्वंद्वात्मक भौतिकवादी विश्लेषण पद्धति के उपरोक्त तीन नियमों के अनुसार ही आज की बीजे के क्षेत्र की परिस्थिति को देखना होगा और इन्हीं तीन नियमों पर आधारित होकर ही हमें वर्तमान समय के लिए अपनी कार्यनीति बनानी होगी। आज दुश्मन के बल कम से कम बटालियन की संख्या में हमारे क्षेत्र में घुसते हैं, कई बार तो कई-कई बटालियन एक साथ तैनात की जाती है और अभियान चलाती है। आज बीजे की परिस्थिति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं (1) हमारा इलाका मुख्यत: ग्रामीण इलाका है, जो कि जंगल-पहाड़ी व अर्द्ध-जंगल पिछड़े मैदानी इलाकों से बना है। कुछ इलाकों में तो पार्टी लम्बे समय से वर्ग संघर्ष चला रही है। मुख्यत: यह एक गुरिल्ला जोन है, पर हम यहां धक्का खायी हुई की स्थिति में हैं, (2) शत्रु की ताकत में श्रेष्ठता है, (3) पीएलजीए का आकार छोटा है और तुलनात्माक रूप से कमजोर है, (4) यहां प्रत्यक्ष तौर पर माओवादी पार्टी नेतृत्व दे रही है और कृषि क्रांति चला रही है।

हमारे बीजे की विशेषताएं यह बताती है कि यहां फिर से पीएलजीए का तेजी से विकसित होने और दीर्घकालीन जनयुद्ध में पहलकदमी हासिल करने व दुश्मन को हराने की भरपूर संभावनाएं हैं। दूसरी ओर हमारी पीएलजीए को पहले की तरह तत्काल बड़ी कार्रवाइयों में जाना भी असंभव है। अगर हम इन विशेषताओं से गलत तरह से निपटते हैं, तो हम और ज्यादा धक्का भी खा सकते है। लेकिन अगर हम अभी की ठोस परिस्थितियों के अनुसार छापामार युद्ध प्रणाली से लड़ते हैं और हमारे बल दृढ़ता के साथ जनता में सांगठनिक और राजनीतिक काम करते हैं, तो हम जरूर इस धक्का खायी हुई की परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। इसलिए हमें युद्ध को और खासकर छापामार युद्ध प्रणाली के विज्ञान को समझना और लागू करना होगा।

कामरेड माओ का कहना है ''छापामार युद्ध क्या है? यह एक पिछड़े देश व एक बड़े अर्द्ध-औपनिवेशिक देश में एक लम्बे समय के लिए अपरिहार्य है और इसीलिए सशस्त्र शत्रु को पराजित करने तथा अपने मजबूत गढ़ खड़े करने के लिए जनता की सशस्त्र शक्तियों के लिए संघर्ष की सर्वोत्तम किस्म है।'' किसी भी युद्ध का सबसे बुनियादी नियम होता है, अपनी शक्ति को सुरक्षित रखना और दुश्मन की शक्ति को नष्ट करना, लेकिन हमारी परिस्थिति यह है कि हमें अपनी शक्ति को सुरक्षित भी रखना है और उनका विस्तार भी करना है। हमारे सामने सवाल यह है कि हम ऐसी कौन सी नीति अपनाएं ताकि हम अपनी शक्ति को सुरक्षित भी रख सकें, उसका विस्तार कर सकें और दुश्मन की शक्ति को नष्ट भी कर सकें।

अपनी सैन्य-शक्ति को केन्द्रित रखकर ही पीएलजीए अपने से ज्यादा शक्ति वाले दुश्मन का सामना कर सकती है व उसका सफाया कर सकती है। वर्तमान समय में बीजे के अन्दर क्योंकि आज हमारी पीएलजीए और दुश्मन बलों में शक्ति संतुलन प्रतिकूल है, इसलिए जन प्रकृति वाला छापामार युद्ध चला कर ही हम कदम ब कदम शक्ति में इस प्रतिकूल संतुलन में परिवर्तन ला सकते हैं। आज हमारी यूनिटें छोटी और कमजोर है, पर छापामार युद्ध चलाते हुए व रणनीतिक रक्षा का युद्ध लड़ते समय कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण मुहिम (टीसीओसी) चलाने की आज भी भरपूर संभावनाएं हैं। इन्हें चलाते हुए ही हम अपनी छोटी छापामार यूनिटों को विशाल छापामार दस्तों में विकसित कर सकते हैं। हमें युद्ध और जनता

में सांगठनिक काम के बीच द्वंद्वात्माक रिश्ते को समझना होगा। दुश्मन से लड़ना और उसे मारने या तंग-परेशान करना एवं जनता को संगठित करना दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम दुश्मन का प्रतिरोध नहीं करते तो सांगठनिक काम भी नहीं कर सकते, इन दोनों कामों को अलग-अलग चरण में नहीं रखा जा सकता। अगर जनता में कुछ सांगठनिक काम कर भी लिया जाए, तो दुश्मन अपनी सैन्य-शक्ति से उसे तहस-नहस कर देगा। पिछले कुछ समय के अनुभव भी यही दिखाते हैं। इस तरह मार्क्सवादी द्वंद्ववादी भौतिकवादी विश्लेषण से हम यह समझ सकते हैं कि उपरोक्त दो कार्य को हम बिल्कुल भी अलग-अलग दो चरणों में विभाजित नहीं कर सकते।

रणनीतिक तौर पर 'दस का मुकाबला एक से करो' एवं कार्यनीतिक तौर पर 'एक का मुकाबला दस से करो'

हमें अपने हर कार्य में मार्क्सवादी द्वंद्वात्माक विश्लेषण और कार्यपद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए। मार्क्सवाद हमें बताता है कि हर पदार्थ दो विपरीत तत्वों से बना होता है। हर पदार्थ के दो चरित्र होते हैं। हर पदार्थ को अनंत हिस्सों में बांटा जा सकता है। बड़ा और छोटा, मजबूती और कमजोरी, सकारात्माक और नकारात्मक, विकसित हो रहे और नष्ट हो रहे तत्वों को मिलाकर कोई पदार्थ बनता है। सवाल यह है कि अपने सैन्य काम में हम इस नियम का कैसे इस्तेमाल करें। आज दुश्मन संख्या में बहुत बड़ा है और बड़े स्तर पर हथियारबन्द है। वह एक बड़े दानव जैसा दिख सकता है, लेकिन अगर हम केवल उपरी चीजें देखकर ही फैसला कर लेंगे, तो हम निराश हो सकते हैं व निष्क्रिय आत्मरक्षा में जा सकते हैं। का. माओ ने कहा है, ''जब हम किसी चीज का अध्ययन करें, तो हमें उसकी अन्तर्वस्तु को परखना चाहिए, उसके बाहरी रूप को अन्तर्वस्तु की देहरी तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शक भर मानना चाहिए तथा एक बार देहरी पार कर लेने पर हमें उस चीज की अन्तर्वस्तु को मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। विश्लेषण की यही पद्धति एक विश्वसनीय और वैज्ञानिक पद्धति है।'' लेकिन हर बड़ी चीज को छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। दुश्मन भले ही कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर वह छोटे-छोटे टुकड़ों से ही बना हुआ है, जिन्हें तोड़ा जा सकता है। हमारे इलाकों में दुश्मन कई बटालियनों की तैनाती कर सकता है, पर हर बटालियन कम्पनियों से बनी है, कम्पनियां प्लाटून व प्लाटून सैक्शन से बनता है। फिर उन्हीं सैक्शन को बांट कर अगल-अलग काम में तैनाती होती है। संपूर्ण में देखने से दुश्मन का सिर्फ मजबूत पहलू ही नजर आ सकता है, पर टुकड़ों में देखने से उसके कमजोर-कमजोर स्थान भी दिखाई देने लगेंगे। दुश्मन को तोड़ने के इरादे से उसे कैसे देखना है, तो हम 'बांटो और खत्म करो' का तरीका अपना कर सैन्य कार्रवाइयों को अंजाम दे सकते हैं।

का. माओ कहते हैं, ''युद्ध में लड़ाइयां केवल एक-एक कर ही लड़ी जा सकती है और दुश्मन बलों को सिर्फ एक-एक करके ही खत्म किया जा सकता है।..... यह खाना खाने के मामले में भी सही है। रणनीतिक रूप में हम खाना खाने को हल्के रूप में लेते हैं.... हम जानते हैं, हम अराम से खा लेंगे। पर असल में हम टुकड़ों में खाते हैं, पूरी थाली का खाना एक बार में ही खाना असंभव है। सैनिक भाषा में इसी को दुश्मन बलों का एक-एक करके सफाया करना कहते हैं।'' आज की परिस्थिति में बेशक पहले जैसी बड़ी कार्रवाइयां करने की हमारी ताकत बीजे में नहीं है। पर दुश्मन को टुकड़ों में देखने से आज भी बहुत सी छोटी और तेज छापामार कार्रवाइयां की जा सकती है। दुश्मन की छोटी टुकड़ियां जो अपनी किलेबंदियों के बाहर विभिन्न कामों में तैनात है, उनको निशाना बनाया जा सकता है। संतरी-पेट्रोलिंग बैच या फिर मार्च या पेट्रोलिंग के समय फ्रंट या रेयर गार्ड को निशाना बनाया जा सकता है।

जन चरित्र वाला छापामार युद्ध चलाते हुए हमें आज की एक विशेष समस्या पर जरूर ध्यान देना होगा। यह समस्या है, दुश्मन द्वारा हमारे इलाकों में सड़क-रेल मार्ग और सूचना तंत्र का विस्तार और विकास करना। दुश्मन हमारे इलाकों में अपना ढांचा मजबूत बना रहा है, यह हमारे लिए प्रतिकूलताएं बढ़ाएगा। छापामार युद्ध चलाते समय हमें दुश्मन द्वारा बनायी जा रही सड़कों, रेल मार्ग और सूचना तंत्र के ढांचे को जरूर ध्वस्त करना होगा। हमारे इलाकों में दुश्मन द्वारा बनायी गयी विभिन्न प्रतिक्रांतिकारी संगठनों जैसे की टीपीसी-जेजेएमपी आदि के खिलाफ जन आन्दोलन और जन छापामार कार्रवाइयों को चला कर उन्हें जरूर खत्म करना चाहिए।

माइन युद्ध तंत्र का उपयोग आज की परिस्थिति में बहुत ही बखूबी से किया जा सकता है। इन कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए जो जरूरी है, वह है- दुश्मन के बारे में बारीक अध्ययन, छापामार कार्रवाइयों में औचकता, तेज व कम अवधि की कार्रवाइयां। लेकिन आज की परिस्थिति में हमें अपने मकसद में सफलता हासिल करने के लिए जरूर ही सैन्य कार्रवाइयों के लिए अपने बलों का केन्द्रीकरण करना होगा। अपने कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण के लिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपनी एकीकृत कमान व्यवस्था मजबूत करें। कुछ साथियों में एकीकृत कमान के बारे में कुछ गलत विचार पाये जाते हैं, पर यह वैज्ञानिक सच्चाई है कि एकीकृत कमान के तले अपनी शक्तियों का केन्द्रीकरण किये बिना हम आज की परिस्थिति में ना तो कोई सैन्य कार्रवाई को सफल कर सकते और ना ही क्रांति के लिए जनता को संगठित करके आज के हमारे दायित्व को पूरा कर सकते हैं। हम संगठन को मजबूत करने और फिर सैन्य प्रत्याक्रमण शुरू करने को दो अलग-अलग चरणों में भी बांट नहीं सकते, ऐसा करना हमें और धक्का खाए हुए की तरफ ही धकेलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम एक जन चरित्र वाला छापामार युद्ध

तेज करके, सैन्य शक्तियों को कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण के लिए केन्द्रीकरण करके, दुश्मन को छोटे -छोटे टुकड़ों में खत्म करते हुए, हम जनता का हौसला मजबूत करते हुए व जन कार्य करते हुए अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं एवं अपनी पीएलजीए में बहाली अभियान सफलतापूर्ण तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ इसी पद्धति से ही हम अपनी छोटी छापामार यूनिटों को बड़े छापामार दस्तों में विकसित कर सकते हैं।

मार्क्सवाद हमें बताता है कि हर बदलाव मात्रात्मक बदलावों से गुणात्मक बदलावों की प्रक्रिया से ही होता है। दुश्मन को टुकड़ी में देखना और उसे टुकड़ों में खत्म करना, इसी तरह अपनी ताकत को टुकड़ों में बढ़ाना भी मात्रात्मक से गुणात्मक बदलाव है। इन्हीं बदलावों से दुश्मन अपनी बरतरी की स्थिति से निम्नता में और हम कमजोरी की स्थिति से बरतरी की स्थिति में बदल जाते हैं। का. माओ कहते है, ''युद्ध एक प्रकार की शक्ति-प्रतियोगिता है, लेकिन युद्ध के दौरान शक्ति की मौलिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है।''

अपनी शक्ति के केन्द्रीकरण और दुश्मन को टुकड़ों में खत्म करने को ही कामरेड माओ ने 'दस का मुकाबला एक से करो और एक का मुकाबला दस से करो' बताया है।

''जनता को जागृत करने के लिए उसके बीच अपनी सैन्य शक्ति को बिखेर दो''

दुश्मन की ताकत का गलत विश्लेषण कर, उसकी ताकत को ज्यादा आकलन करने, उसको 'एक का दो में विभाजित होने' के नियम के अनुसार ना देखने से एक दूसरी समस्या अति केन्द्रीकरण की भी आती है। हमारा इलाका एक बड़ा इलाका है, यह जंगल-पहाड़ अर्द्ध-जंगल और दूर-दराज के मैदान इलाकों को मिलाकर बना है। यहां का अपना एक क्रांतिकारी आन्दोलन और छापामार युद्ध का इतिहास है। आज भी राजनीतिक तौर पर यह दुश्मन की तुलना में बरतरी है। लेकिन धक्का खायी हुई इस स्थिति में हमारे संगठन कमजोर हुए हैं। इस स्थिति से उबरने के लिए और आने वाले आगे के समय में दुश्मन के और अधिक तीव्र चौतरफा हमले का मुकाबला करने के लिए हमें जनता को जागृत करना होगा। नवउदारवाद के इस समय में जनता पर राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक हमले तेज होंगे। जनता ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी नीतियों का जुझारू तरीके से प्रतिरोध कर रही है। यह क्रांति में आ रहे एक बड़े ज्वार की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन इसी परिस्थिति में हमारी आत्मगत ताकतें कमजोर हुई है। हमारी संगठनकर्ता यूनिटें छोटी और कमजोर हो गई है, लेकिन हमारी पीएलजीए एक राजनीतिक सेना है, यह दुश्मन से युद्ध भी करती है और जनता को संगठित भी करती है। जनता में काम करना तथा चन्दा या धन इकट्ठा करना- लाल सेना के ये तीन कार्यभार एक दूसरे से पूर्णतया जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे सैन्य-बलों को संगठनिक काम करने के लिए जनता में बिखेर देना चाहिए। सांगठनिक और सैनिक यूनिटें एक साथ मिलकर अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए जनता को संगठित कर सकती है। हमारे साथियों को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आम जनता को संगठित करने के लिए अच्छे और निपुण संगठनकर्ता बनना होगा। एक जन चरित्र वाले छापामार युद्ध की छापामार कार्रवाइयों में आम जनता की भागीदारी बहुत ज्यादा होती है, जनता को जन मिलिशिया में संगठित करना होगा। जनता को बिजली काट देने पुल उड़ा देने, सड़कें खोद देने, अफवाह फैलाने, दुश्मन की सप्लाई लाइन काट देने जैसी विभिन्न कार्रवाइयों में लगाया जा सकता है। अगर हम सचमुच दुश्मन को मार गिराना चाहेंगे, तो हमें सेना और जनता द्वारा एक साथ मिलकर किये जाने वाले काम और हथियार हर जगह मौजूद मिलेंगे। लेकिन इस कार्य को सफल करने की एक ही शर्त है- वह यह कि उसे लक्ष्य लेकर जनता में उतरना होगा।

अति केन्द्रीकरण और अति विकेन्द्रीकरण हमारे द्वारा परिस्थितियों के द्वंद्वात्मक विश्लेषण ना करने और उस विश्लेषण पर आधारित कार्यनीति ना अपनाने की वजह से होता है। अपनी शक्तियों को केन्द्रीकरण करना, और बिखेरना एक कला है, जिसमें हमें निपुण होना होगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहली शर्त, इसके अनुरूप सांगठनिक ढांचा तैयार करना है। नीचे से लेकर उपर तक एकीकृत कमान इसी नीति को लागू करने के लिए बनाई जाती है। अपनी कार्यनीति को लागू करने के लिए हमें पीएलजीए के अन्दर इस ढांचे को तुरंत खड़ा करना होगा। का. माओ इस कार्यनीति के बारे में इस तरह बताते हैं, ' यह कार्यनीति जाल फेंकने की तरह है। हमें योग्य होना चाहिए कि किसी भी क्षण जाल दूर तक फेंक सकें और उसे किसी भी क्षण फिर समेट सकें। आम जनता को अपने पक्ष में करने के लिए हम यह जाल दूर तक फेंकते हैं और दुश्मन से निपटने के लिए उसे समेट लेते हैं। ....यहां 'जाल दूर तक फेंकने' का मतलब है छोटे दायरे में अपनी सैन्य शक्ति को बिखेरना''

प्रतिक्रांतिकारी नया 'समाधान' हमले को परास्त करें! दुश्मन के बलों का सफाया करते हुए, उनके पास से हथियार छीन लें!

नोटबंदी-जीएसटी (वस्तु सेवा कर)- जीएम बीज के आयात में छूट देना- टीएफए (व्यापार सरलीकरण समझौता) सभी जनसंहार पॉलिसी के अभिन्न अंग हैं!

(यह लेख हमारी पार्टी की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के बांगला मुखपत्र 'विप्लवी युग' के दिसम्बर 2017 अंक में छपे लेख का हिन्दी अनुवाद है। इस लेख के महत्व को देखते हुए ही इसे हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं। - संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

बीते 13 अप्रैल, 2017 को रात 12 बजे वस्तु एवं सेवा कर संक्षेप में जीएसटी (गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स) बिल पूरे देश भर में पास हो गया। जिसका लक्ष्य संपूर्ण देश के लिए एक व एकीकृत बाजार गठन करना है। यह नई कर व्यवस्था केन्द्रीय व राज्य स्तर में विभिन्न तरह के परोक्ष टैक्सों को मिला कर बनेगी। फिलहाल जीएसटी में जिन केन्द्रीय टैक्सों को एकीकृत किया जाएगा, वह है :- (1) केन्द्रीय आंतर्शुल्क (2) अतिरिक्त आन्तर्शुल्क (3) सेवा टैक्स (4) अतिरिक्त सीमा शुल्क (5) विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (6) विशेष उत्पादन शुल्क।

इसके अलावा राज्य सरकार के जिन सभी करों को जीएसटी में शामिल किया जाएगा, वह है :- (1) राज्य के मूल्य युक्त कर (वैट-वैल्यू एडेड टैक्स)/विक्रय कर) (2) विनोदन (मनोरंजन) कर (3) केन्द्रीय कर जो राज्यों तहशील करते है (4) चुंगी (प्रवेश) कर (5) भ्रमण पर (पर्यटन) कर (6) विलासिता (ऐयाशी) कर (7) लॉटरी आदि पर निधारित कर।

चूंकि जीएसटी को लागू करने की प्रक्रिया बहुत जटिल और बहुत समय की जरूरत है इसलिए उसे लागू करने के लिए स्व-शासित जीएसटी काउन्सिल (परिषद) गठन किया गया, जहां केन्द्रीय वित्त मंत्री सहित राज्य सरकार और केन्द्र शासित राज्य सरकारों के वित्त मंत्री होंगे। उन मंत्रियों में किसी विषय पर मतविरोध होने पर तीन चौथाई भाग की सम्मति के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। इस टैक्स व्यवस्था को लागू करना और राजस्व अदा करने के लिए ''जीएसटी नेटवर्क नामक और एक स्वशासित संस्था गठन किया जाएगा, जिसमें केन्द्र सरकार की भागीदारी 24.5 प्रतिशत, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित राज्य सरकारों की सम्मिलित भागीदारी भी 24.5 प्रतिशत होगी। बाकी 51 प्रतिशत भागीदारी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एनएसई स्टैटेजिक इंवेस्टमेंट कंपनी और एलआईसी हाउसिंग फाइनांस के जैसे 5 गैर सरकारी संस्थाओं के हाथ में होगी। सुनने में आ रहा है कि जीएसटी नेटवर्क की कार्यवाही संसद के कंट्रोलर एण्ड आडिटर जेनरल (कैग) के ओहदे के बाहर होंगे। वास्तविक में मोदी सरकार कर अदायगी के क्षेत्र को भी गैर सरकारीकरण करने की ओर एक कदम आगे बढ़ाकर ले गए। ज्ञात रहे, जीएसटी लागू करने का मामला कोई नयी बात नहीं है बल्कि इसे लेकर चर्चा 2003 से ही चलते आ रही है।

सरकार की जीएसटी के पक्ष में तथ्य निम्न प्रकार की है - (1) जीएसटी के माध्यम से एक साफ व सरल कर व्यवस्था लागू की जाएगी (2) कर की दर और कर के ढांचा में सार्विकता लायी जा सकेगी (3) एक ही माल पर बारंबार कर थोपने का पथ बंद हो जाएगा।

असल में हमारे देश के संचालक लोग की नीयत कभी भी साफ नहीं होती है। फलस्वरूप वे जनता के स्वार्थ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे देश के किसी भी तरह की आम जनता 'सरकार जनता के लिए कुछ कर सकती हैं' ऐसी बात कभी भी विश्वास नहीं करती है। कुछ दिन पूर्व ही मोदी सरकार देश के काला धन उद्धार के नाम पर ''नोट बंदी'' की घोषणा की थी। हमलोगों ने देखा कि उसने कितना बड़ा एक शर्मनाक धोखा जनता को दिया। आम जनता की भंयकर क्षति करने के बाद, आखिर में देखा गया कि जरा सा भी काला धन गिरफ्त में तो नहीं आया बल्कि इस मौके पर किसी-किसी को ''काला धन'' को सफेद (कानूनी) करने का मौका मिल गया। इधर नोट बंदी के धक्का से उद्योग वृद्धि दर 5.59 प्रतिशत (नवम्बर 2016) से घट कर 1.2 प्रतिशत में लुढ़क गए। अनेकों व्यक्ति आत्महत्या किए, खरीफ फसल की खेती नहीं हुई, अनेकों मजदूर बेरोजगार हो गए, मछली पालन के कारोबार ने भी काफी क्षति का सामना की। इतना जनता को हानि पहुंचाने के बाद काला धन उद्धार का क्या फल मिला-

मोदी सरकार को आज इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा।

ये मोदी सरकार नोटबंदी जैसा जीएसटी लाने के मामले में भी कुछ-कुछ धोखा दे रही है। दरअसल नोटबंदी और जीएसटी के बीच अंतरसंबंध भी है।

आम जनता को जीएसटी बिल लागू होने से जिन सभी की हानियां होगी, वह है प्रथमत: आम छोटे व मध्यम स्तर के व्यापारी, जो इस कर व्यवस्था के बारे में वाकिफ नहीं है। फलस्वरूप उनलोगों को अतिरिक्त खर्च की मार झेल कर इस कर व्यवस्था के अंदर जगह बनाना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि उक्त व्यवस्था में टैक्स देने के लिए एक नई सॉफ्टवेयर की जरूरत है जिसे उनलोगों को खरीदना होगा। इसके अलावे एकाउन्ट प्रस्तुत करने के लिए इसी बीच में ही चार्टर्ड फर्म (एकाउन्ट प्रस्तुत करने वाली कानूनी अधिकार प्राप्त कंपनी) उनलोगों से ज्यादा रूपये मांग रही है। इसके अलावे उक्त साफ्टवेयर को हर वर्ष खरीदना होगा या उतना रूपया खर्च कर सॉफ्टवेयर को अपडेट करवाना होगा। फलस्वरूप पहला धक्का में ही छोटे व मध्यम स्तर के व्यापारियों (दुकानदार से शुरू कर कुटीर उद्योग तक के व्यापारियों) के माथे पर खर्च की बीड़ा दबाते जा रहा है। द्वितीयत: पूर्व में ही कहा जा चुका है कि कर अदायगी का जिम्मा देश की सरकार के पास होना चाहिए था, लेकिन वह गैर सरकारी संस्थाओं के पास चला जाएगा। इस प्रक्रिया से बहुत ही स्वाभाविक एक सवाल उठ खड़े होते हैं कि जीएसटी नेटवर्क में गैर सरकारी फाइनांस संस्थाओं को जिम्मा दिया गया, लेकिन घरेलू सरकारी बैंकों को क्यों नहीं शामिल किया गया? तृतीयत: निर्यातकारी संस्थाओं के हिसाब का आंकड़ा कहता है कि फलस्वरूप निर्यात के खर्च में कम से कम 1 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होगी। चतुर्थत: चूंकि जीएसटी एक परोक्ष टैक्स है, इसलिए जनता पर ही इसका बोझ पड़ेगा; आम तौर पर जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ेगा और अमीरों पर टैक्स का बोझ घटेगा। मोदी सरकार इतना दिन से विभिन्न दांव-पेंच अपनाकर अमीरों पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए प्रयास चलाते आ रहे हैं। इसलिए 2009 से 2010 तक जहां प्रत्यक्ष कर 61 प्रतिशत था, 2015 से 2016 तक वह घटकर 51 प्रतिशत में आ खड़ा हुआ। इसके बावजूद मोदी सरकार इस देश के अमीरों को सीधा-सीधा प्रत्यक्ष रूप से कर माफी करते जा रही है, कर्ज के दायरे से माफी की छूट दे रही है; फिर भी उनलोगों की आश नहीं मिट रही है इसलिए जीएसटी के माध्यम से सरासर प्रत्यक्ष कर के दायरे से अमीरों को मुक्ति देकर वह परोक्ष कर के माध्यम से आम जनता के कंधे पर करों के बोझ को थोप रहे हैं। पंचमत: अतिरिक्त सीमा शुल्क व विशेष अतिरिक्त सीमांत शुल्क में जीएसटी लागू होने के फलस्वरूप अतिरिक्त आयात रोकने का पथ भी बंद हुआ। क्योंकि कर का बोझ घट जाने से विदेशी माल धड़ल्ले से आकर घरेलू बाजार से घरेलू कृषि उत्पाद व औद्योगिक उत्पाद को आसानी से ही बाजार से हटा देगा। फलस्वरूप बंग्लादेश के जूट (पटसन) या वियतनाम या थाइलैंड के चावल आकर घरेलू पाट या चावल के उत्पादनकारी किसानों के साथ प्रतियोगिता चला सकती है। इस तरह प्रतियोगिता के मौके का इस्तेमाल कर लूटेरा बहुराष्ट्रीय कार्पोरेट बीज, कीटनाशक, खाद कंपनियां देश में प्रवेश करेंगे। वे लोग कहेंगे कि प्रतियोगिता में टिकने के लिए जीएम सीड (बीज), उसके उपयोगी खाद, कीटनाशक इस्तेमाल करना होगा। वे लोग इस रूप से हमारे देश के किसानों को और ज्यादा शोषण के जंजीरों में फंसा सकेंगे।

सरकार नोटबंदी के समय कथनी में कहे थे कि काला धन के व्यापारियों को दुरूस्त करना और देश के विद्रोहियों (उनके भाषा में आतंकवादियों) के आर्थिक स्रोतों को ध्वस्त करने के लक्ष्य से ही इस कदम उठाया गया था। लेकिन जब वित्तमंत्री अरूण जेटली सच्ची बात को आम देशवासियों के पास उजागर किए कि सरकार का कैसलेश (नगद रहित) लेन-देन चालू करना यानी डिजिटल लेनदेन के घेरे में संपूर्ण देश की जनता को समेटना ही लक्ष्य है, तब झोली से बिल्ली निकल गई। दरअसल यही मोदी सरकार का घटिया इरादा था। इससे एक ओर कार्पोरेट पूंजी के जुआरी कारोबार का विशाल इलाका बनेगा, विपरीत में खुदरा व्यापारियों का नाश होगा।

इजारेदारी कार्पोरेट पूंजी के हमले के फलस्वरूप वर्तमान में भारत सहित विश्वव्यापी आम जनता की खरीदने की क्षमता करीब खतम होते जा रही है। इसलिए उपभोक्ता सामग्री की मांग इतना कम है कि बढ़ती पूंजी का पहाड़ बनते जा रहा है और उसे उत्पादन के क्षेत्र में विनिवेश करने का कोई मौका नहीं है। इसलिए उक्त पूंजी का अभी विशाल आकार में आर्थिक कारोबार में ही विनिवेश हो रहा है, जिस विनिवेश में कोई संपदा सृष्टि नहीं होता है लेकिन मुद्रा (अर्थ) परिचलन व विभिन्न तरह के आर्थिक सामग्री खरीद-बिक्री के माध्यम से इन आर्थिक कारोबारी और अमीर बनते जाते हैं। फिलहाल इस आर्थिक कारोबार का क्षेत्र इतना विशाल होते जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि में माल लेकर व्यवसाय-वाणिज्य के लिए जितना मुद्रा की जरूरत है, उसके 70 गुना से भी ज्यादा मुद्रा विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए हाथ बदली होता है।

बीते कई वर्षों से भारत में जितना विदेशी निवेश आया है, उसका बहुत गुना कम परिमाण ही औद्योगिक उत्पादन में शामिल हुआ है, ज्यादा से ज्यादा एफआईआई नामक जुआरी निवेश है। इस निवेश से सिर्फ शेयर सहित विभिन्न आर्थिक सामग्री का हस्तांतरण कर देश के करोड़ों-करोड़ रूपया लूट ले रहा है, बीते कई वर्षों से सरकार उनको मदद करने के लिए इस तरह के निवेश के उपर से सभी रूकावटों को खत्म कर दे रहा है।

इन आर्थिक क्षेत्रों के नियंत्रक कंपनियां चाहती है कि

सभी तरह के आर्थिक लेन-देन विभिन्न तरह के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वालेट (रूपये रखने का छोटा बैग) आदि के माध्यम से हो, जिन पर उनलोगों का एकाधिकार व नियंत्रण है। इस उद्देश्य से ही कई दशकों से हमारे देश में कार्पोरेट पूंजीपतियों की बात मानकर व्यापक रूप से बैंक, बीमा के गैर सरकारीकरण का पहल चल रहा है और कृषि व छोटे उद्योगों को दिये जा रहे कर्ज को क्रमिक रूप से घटाते जा रहा है और अमीरों के लिए उपभोग की सामग्रियों (जैसे- गाड़ी, मकान खरीदने विदेश भ्रमण/सैलानी आदि) के लिए बैंक लोन में वृद्धि की जा रही है। ताकि फाइनांस कंपनियां खुलेआम आर्थिक मालों को लेकर जुआरी व्यवस्था चला सके (प्रासंगिक रूप से किसान व आम जनता की क्रय क्षमता वृद्धि होने पर जिस तरह के उपभोक्ता सामग्री की मांग में वृद्धि होती है, उससे आर्थिक माल का व्यापार बहुत ज्यादा होता नहीं है) दूसरी ओर, वित्तीय पूंजी किसी भी तरह के उत्पादन में अंशग्रहण नहीं करके भी उत्पादन व व्यापार-वाणिज्य के सभी आर्थिक लेन-देन पर कंट्रोल कायम कर सिर्फ विशाल परिमाण मुनाफा कमा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि, विकासशील देशों के सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र की बागडोर कंट्रोल करते हैं। फलस्वरूप ये लोग किसी भी संकट आने पर तत्काल अपनी वित्तीय पूंजी को हटा ले जाकर हमारे देश की आर्थिक नीति को ध्वस्त कर दे सकते हैं, देश को दिवालिया बना सकते हैं। दूसरी ओर, जनता अगर कैशलेस (नगद रहित) विनिमय (आदान-प्रदान) करने के लिए मजबूर किया जा सके, तब बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल के देशी-विदेशी इजारेदार कारोबारियों व बड़े-बड़े सामानों को बेचनेवाली कंपनियों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडिल, अलिबाबा, क्विकर जैसी कंपनियां रिटेल मार्केट (खुदरा बाजार) से छोटे-मध्यम व्यापारी, दुकानदार व हॉकरों-फेरीवालों के समूचे व्यापार को लूट ले सकेगा। वे लोग जनता को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से षड़यंत्र रचकर प्रधानत: 2000 रूपये के नोट बाजार में छोड़े हैं जिसके माध्यम से आम जनता के लिए खरीददारी करना नामुमकिन है।

इस देश में, उक्त नगदरहित लेन-देन की प्रक्रिया के बतौर ई-कामर्स का व्यापार व्यापक विस्तार किया है। मिसाल के बतौर, 2010 में ई-कामर्स के माध्यम से आर्थिक लेनदेन के परिमाण जहां 500 करोड़ मार्किन डालर था, वहां 2015 में वह वृद्धि होकर 2100 करोड़ मार्किन डालर में पहुंचा; उक्त दर से अगर वृद्धि होते जाय तब 2020 तक आर्थिक लेन-देन 11,900 करोड़ मार्किन डालर तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा करीब सभी बैंकों के नेट बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, ओला, उबेर, स्नैपडील, नौकरी डॉट कॉम, शादी डॉट कॉम जैसी कई उल्लेखनीय ई-कॉमर्स संस्था का नाम है। विसा, मास्टर कार्ड के अलावे भारत में दो बड़े ई-कॉमर्स संस्था अमेरिका के 'टाईगर ग्लोबल' और जापान के 'साफ्ट बैंक' संस्था कार्यरत है। इस साफ्ट बैंक संस्था में चीन के अलिबाबा सबसे बड़े हिस्सेदार हैं। आकड़े के अनुसार, टाईगर ग्लोबल ने विश्व स्तर पर 109 संस्था के माध्यम से 3400 करोड़ मार्किन डालर निवेश की है। जिसके अंदर भारत के फ्लिपकार्ट, अमेजन, ओला, उबेर, क्विकर- जैसे संस्थाएं भी हैं। इनलोगों ने भी भारत के बाजार में करीब 200 करोड़ मार्किन डालर निवेश किया है। वे लोग एक ओर जैसे ओला, स्नैपडील आदि संस्था के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में निवेश कर रहे हैं, वैसे ही चीन अलिबाबा के माध्यम से परोक्ष रूप से निवेश कर रही है। 'एक्सेल' नामक और एक ई-कॉमर्स संस्था भी भारत में सक्रिय है। इसी बीच उस संस्थाओं के दादागिरी से इस देश के छोटे व्यापारियों को व्यापक हानि का सामना करना पड़ रहा है। उक्त संस्थाओं को भारत के बाजार पर पकड़ बनाने के लिए अनेक समय क्षति होते हुए भी बड़े फायदे हुए हैं। जीएसटी लागू होने पर इन लोगों का मुनाफा कई गुणा बढ़ जाएग, विपरीत में छोटे व मध्यम स्तर के व्यापारी और ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। इसी बीच यह प्रक्रिया शुरू हो गया है। क्योंकि जीएसटी की घोषित नीति से पूरा कर व्यवस्था ही इनर्फोमेशन टेक्नोलॉजी तथा इन्टरनेट पर आश्रित हो जाएगी, फलस्वरूप देशी-विदेशी इजारेदार बड़े कारोबारी मालामाल हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।

इसके अलावा, जीएसटी लागू होने पर रोजमर्रा के सामग्री की कीमत आसमान छूने लगेगी, क्योंकि आम जनता पर परोक्ष टैक्स का बोझ 0 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 40 प्रतिशत दर पर बढ़ेगा। फलस्वरूप कुछ सामानों के दाम कम होने के बावजूद अधिकांश वस्तुओं के दाम में बढ़ोत्तरी होगी। फिलहाल बाजार में दवा की किल्लत शुरू हो गयी है।

मनमोहन से शुरू कर आज तक मोदी सरकार उदारवादी नीति के पथ पर चल कर तो ग्रामीण बैंकों को सही मायने में निकम्मा बनाकर किसानों पर पशु के जैसा हमले चला रहा है। प्रसंगत: विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता के मुताबिक कृषि कार्य में बहुत ही कम किसान शामिल हुए हैं और ऐसा कोई मिसाल नहीं है जहां समझौता के अनुसार कृषि कार्यों से किसानों को लम्बे समय का फायदा हुआ है। ग्रामीण सहकारी बैंकों पर हमले चलाने का एक विशेष उद्देश्य है व्यापक संख्या में किसानों को बेसहारा कर कृषि कार्य के मामले में उनकी सारी आजादी लूट लेकर समझौता के अनुसार कृषि कार्य करने के लिए ही बाध्य करना है। हमलोग पूर्व में ही कह चुके हैं कि अतिरिक्त सीमांत शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क जीएसटी में शामिल करने के बाद भारत राष्ट्र सस्ते में कृषि सामग्री आयात को कंट्रोल कर किसानों की रक्षा करने का जो हथियार था, उसे नष्ट कर दिया है। इस देश के किसानों के ऐसे ही माली हालत है। वास्तविक में हर रोज इस

देश के अखबार में किसानों की आत्महत्या की खबर सुनने में आती है। आत्महत्या के इस सिलसिले से मौत की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। निर्लज्ज सरकार का इससे कोई हिल-डोल दिखाई नहीं पड़ रहा है। ब्रिटिश जमाना से ही साम्राज्यवाद के खिदमतगार आरएसएस और उसके दलाल मोदी सरकार देश के किसानों के स्वार्थ को साम्राज्यवाद के पैरों के नीचे परोस कर 'देशप्रेम' का गीत सुना रहा है।

इसलिए वे लोग विमुद्रीकरण-जीएसटी के साथ ही साथ बीते पहली जुलाई से जेनेटिकली (जीन परिवर्तित) बीज का आयात करने की प्रक्रिया की पहल किया है। बाजारू मीडिया इसे दूसरी हरित क्रांति नाम देकर स्वागत किया है। जेनेटिक ईंजीनियरिंग एप्रुवल कमेटी ने पहली जुलाई 2017 को जीन परिवर्तित (जेनेटिक/मोडिफाइड) तेल का बीज इस्तेमाल करने के लिए अनुमति दी है। दरअसल मोदी सरकार उक्त प्रक्रिया से विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए देश के कृषि उत्पाद के बाजार को मुक्त-द्वार करने के लिए और एक कदम आगे बढ़ गए। 56 इंच का सीना से दलाली करने के लिए दु:साहस की कमी नहीं है!

आवें, अब ट्रेड फेसिलिटेशन एग्रिमेन्ट संक्षेप में टी.एफ. ए. (व्यापार सहायताकारी समझौता) के बारे में जानें! दरअसल, नोटबंदी तथा विमुद्रीकरण-जीएसटी-जीएम बीज को व्यवहार करने के लिए छूट देना और टीएफए लागू करना एक ही पॉलिसी का अलग-अलग हिस्सा है। ये सभी प्रोग्राम हमारे देश को बहुराष्ट्रीय संस्था यानी कार्पोरेट घराना और उनके घरेलू दलालों के हाथों में सुपुर्द करने के कुप्रयास के अलावे और कुछ भी नहीं है। इस देश के दलाल मोदी सरकार और उसके गुर्गे देश की जनता को विभिन्न तरह के मीठी-मीठी बातों से सिर्फ धोखा ही दे रहा है।

साम्राज्यवादी इजारेदार वित्तीय पूंजी हमारे देश में और बेरोकटोक पथ से प्रवेश कर सके, इसी प्रयास में टीएफए और एक कदम मात्र है। 1996 के विश्व व्यापार संगठन के सिंगापुर बैठक में दुनिया में व्यापार-वाणिज्य को सुगम करने के लिए 4 प्रस्ताव पेश हुआ था। (1) आमतौर पर दो देशों के द्विपक्षीय समझौता के माध्यम से जो पूंजी निवेश होता था, अभी एक बहुपक्षीय समझौता करने की नीति ग्रहण करने का प्रस्ताव पेश हुआ, (2) देशी-विदेशी हर संस्था को ही समान मौका मिले, इसलिए प्रतियोगिता मूलक पॉलिसी ग्रहण करने की बात आयी, (3) विदेशी संस्था की सरकारी संसाधन क्रय करने के लिए समान अधिकार होगा, (4) अनियंत्रित व्यापार-वाणिज्य की सुविधा के लिए कानून की समता करना चाहिए। उपरोक्त प्रस्तावों को सुनने से समतावादी बात जैसे लगने पर भी असल में यह समतावाद 'तिमी मछली के साथ पुट्ठी मछली' की प्रतियोगिता में दोनों पक्ष को ही समान दृष्टि में देखने का 'समतावाद' है। असल उद्देश्य समता के नाम पर देश के व्यापार-वाणिज्य की रक्षा करनेवाले सभी संरक्षण को खत्म कर देना है। पहले भारत इसका विरोध किया था। उस समय वाजपेयी सरकार का जमाना था। 2003 के दोहा राउण्ड (बैठक) में यह मामला फिर से सामने आया। उस समय भारत, चीन सहित अनेकों देश इसका विरोध करने पर अभी पीछे हट गए। 2013 के विश्व व्यापार संस्था का बाली राउण्ड में यह मुद्दा फिर ट्रेड फेसिलिटेशन एग्रिमेंट (टीएफए) नामक एक बहुराष्ट्रीय समझौता के बतौर पेश हुआ। भारत सरकार इस समझौता को मान लिए। उनलोगों ने देश को बिक्री करने के बदले 'खाद्य अधिकार सुरक्षा' बिल पारित कर देशवासियों के लिए मरहम पट्टी करने की व्यवस्था किया। 2015 में मोदी सरकार उस समझौता को मान्यता देने के लिए तत्पर हुई। 2016 में विश्व व्यापार संगठन के 76 नम्बर देश के बतौर भारत सरकार समझौता पर दस्तखत की। 2017 के मार्च में 'ट्रेड फेसिलिटेशन इन सार्विज' नामक एक मसविदा प्रस्तुत कर कार्पोरेट घराने के विश्वस्त ताबेदार के बतौर वाहवाही मिलने के बावजूद पिछड़े व अविकसित देशों के सामने उनके दलाली का चेहरा साफ हो गया। बात यह है कि इस टीएफए को मान्यता देने से उनके लिए एकीकृत कर संरचना लागू करना छोड़कर और कोई पथ खुला नहीं है। इसलिए मोदी सरकार जीएसटी के मामले में इतनी तत्परता दिखा रही है।

विमुद्रीकरण, जीएसटी, मॉडिफायड जीन का व्यापक प्रसार और टीएफए- इन सभी का एक लक्ष्य के साथ दूसरे का लक्ष्य जुड़ा हुआ है। लक्ष्य बहुत साफ है; हमारे देश के घरेलू व्यापार को नष्ट कर देश के मजदूर-किसान को भूखा रखकर विदेशी बहुराष्ट्रीय संस्था, कार्पोरेट घराना और उसके देशीय दलालों को शक्तिशाली बनाना ही लक्ष्य है। जुआरी पूंजी के कारोबारियों के 'अच्छे दिन' लाना है। इसी का नाम 'देश प्रेम' है। इसी का नाम 'विकास' है। इसी का नाम 'अच्छे दिन' है। यही मोदी की 'मन की बात' है। हमें याद रखना होगा कि मानव को कत्ल करने की यह हत्यालीला एक दिन की कार्यसूची नहीं है और सिर्फ मोदी सरकार ही गोरखधंधे के कारोबारी हैं, ऐसा भी नहीं है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के जमाना से ही मानव की हत्या करने की इस नीला नक्शा (Blue print) तैयार किया गया है। मोदी छप्पन इंच की छाती फूलाकर उसमें सिर्फ सील-मोहर लगा रहा0 है।

आज सभी जनवादप्रिय लोगों को एकताबद्ध होकर उन देशद्रोहियों को उखाड़ फेंकना होगा। वर्ग संघर्ष के साथ अस्मिता की लड़ाई एकजुट होगी; जनवाद की मांग की लड़ाई के साथ मुक्त विचार की लड़ाई गोलबंद होगी; सभी के मेलबंधन से व जनता की मुखर दोस्ती से आज नया सबेरा लाना होगा।

झारखंड में महिला आंदोलन को और जोरदार करने के महत्व पर ध्यान दें!

(इस लेख का अंग्रेजी अनुवाद हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के अंग्रेजी मुखपत्र 'पीपुल्स वार' के अंक-12 में भी दिया गया है। इस लेख का महत्व को समझते हुए ही हम यहां भी इसे प्रकाशित कर रहे हैं। - संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

हम सबों को मालूम है कि लगभग 70-75 वर्ष पहले से ही जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में स्वायत्त शासन राज्य की मांग पर झारखंड आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पर, उस समय से आज तक ये आंदोलन किसी समय में जुझारू नारा रखने के बावजूद नेताओं के अवसरवादी-सुविधाभोगी बनने व बेइमानी के कारण विफल रहा। सारे नेता लोग चुनाव के खेल में व आराम-ऐयाशी जिंदगी बिताने की लालच से पूरी तरह फंस गए। फिर हम सबों को यह भी मालूम है कि कई दशक पहले से ही उसी अवसरवादी-समझौतावादी नेतृत्व द्वारा शुरु किया गया झारखंड राज्य अलग करने के आंदोलन में भी महिलाएं पूर्णरुप से भगीदारी निभायी थी। महिलाएं सोच रही थी कि सही मायने में हमारा ही झारखंड होगा, क्योंकि सिद्धू-कान्हू-चाँद-भैरव की लड़ाई से भी यही शिक्षा मिलती है यानी महिलाओं की भूमिका के बारे में उस लड़ाई से अच्छी शिक्षा मिलती है। क्योंकि सिद्धू-कान्हू सही मायने में झारखंडी जनता की मुक्ति के लिए लड़ाई किए थे।

'झारखंड राज्य हमारा होगा' बोलकर आदिवासी नेता शिबु सोरेन ने 1973-74 ई. में जोरदार ढंग से आंदोलन किया था और नारा दिया था ''जोतदार, जमींदार और सूदखोर-महाजनों को मार भगाओ'', ''मारो दरोगा'', ''झारखंड को बनाएंगे लालखंड, वोट से नहीं चोट से लेंगे झारखंड'' मतलब झारखंड में मजदूर-किसान का राज बनेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही शिबु सोरेन ने इस आंदोलन को त्याग दिया और आराम की कुर्सी में बैठ गया। वह अपने पहले एमपी और बाद में झारखंड के मुख्यमंत्री भी बन गए।

पर, हम आंदोलनकारी महिलाओं को क्या मिला? पुराना पुरुष सत्तावादी शोषण-शासन तो जस के तस रह ही गया, साथ में ऊपर से और मिला प्रतिवाद करने पर जेल यातना व पुलिस जुल्म। ऐसा तो किया ही है, फिर अपने कार्यकर्ताओं के जरिए भी महिलाओं की इज्जत को रौंदते हुए बेइज्जती या जुल्म चलाया गया। कुछ महिलाओं से पहनी हुई साड़ी भी खोलवाया। लाल साड़ी या बढ़िया साड़ी आदिवासी महिलाओं को पहनना नहीं चाहिए, बोलकर प्रचार किया और ब्रा का इस्तेमाल तो महाअपराध है जैसी बात भी कहा। इसके लिए बहुत तरह की सजा की कार्रवाई भी की जाती थी। असल बात है, यहां के महिलाओं के लिए तो उसने कुछ भी नहीं किया, सिवाय पुरुष सत्ता वाला शासन व जुल्म ही कायम रखा। उसके एमपी-मंत्री बनने के समय से ही झारखंड की अकूत संपत्ति को यानी वेश-किमती प्राकृतिक सम्पदा लूटने के लिए और छूट दे दिया देशी-विदेशी पूँजीपति को और महिलाओं की श्रम शक्ति व इज्जत लूटने के लिए ज्यादा छूट मिल गयी, बाकी मेहनतकश जनता की श्रमशक्ति को व्यापक रुप से लूटने की छूट तो है ही है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च से 31 मार्च, 2018 तक क्रांतिकारी उत्साह और जोश-खरोश से मनाएं!

अभी तक झारखंड में जितनी सरकारें बनी है और बन रही है, सभी कोई महिला सशक्तिकरण-स्वावलंबी-महिला उत्थान आदि बातों को रटते ही रह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री

नरेन्द्र मोदी तो 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' नारा लगाकर हकीकत में ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी आर.एस.एस. द्वारा महिलाओं के लिए मनुवाद में लिखित नियम-नीति को (यानी जन्म के बाद बाप के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहकर केवल घर का काम व और संतान पैदा कर उसे लालन-पालन करना) ही व्यवहार में लागू करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। देश में व्यापक पैमाने पर पुलिस व गुण्डे-गिरोह द्वारा सामूहिक दुष्कर्म जारी है। झारखंड के लाखों बेटी-पतोहू को दिल्ली-मुम्बई से लेकर देश के बाहर तस्करों के जरिए भेजा गया है या भेजा जा रहा है।

अब, महिलाओं की भलाई व विकास के नाम पर केंद्र सरकार हजारों-करोड़ों रुपये दे रही है, कहकर डींग हांक रही है। वास्तव में पिछले तीन वर्षों के मोदी जमाना को देखा जाय तो महिलाओं की स्थिति जस का तस या ज्यों की त्यों बनी हुई ही है। विकास या सशक्तिकरण- महिला उत्थान के लिए बहुत नाम मात्र ही खर्च किया जाता होगा और बाकी राशि किनके-किनके पॉकेट में जा रही है, कहना मुश्किल है। लड़की या महिलाओं के नाम से बैंक में रुपये जमा करने का भी असली मकसद पूँजीपति लोगों को फायदा पहुंचाना है।

महिला मुक्ति आंदोलन को गुमराह करने के लिए तरह-तरह की जालसाजी अपनाया गया है। पंचायत के विकास के नाम पर आदिवासी महिलाओं व दलित महिलाओं को भी मुखिया चुना जाता है। फिर वार्ड मेम्बर चुना जाता है, जिला परिषद चुना जाता है। फिर आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका के रुप में चुना गया है, यह काम को चलाने के लिए उन्हीं लोगों के नाम से ही रुपये-पैसे निकालता है। लेकिन, सही मायने में देखा जाए तो न महिलाओं के लिए कुछ विकास हो रहा है, न ही आम जनता के लिए। फिर कहीं बाथरुम बना दिया गया, पर कोई काम का नहीं है। कहीं कॉलोनी बना दी गयी, तो कहीं चापाकल बना दिया गया। जबकि सिंचाई के लिए तालाब बनना चाहिए, डैम होना चाहिए, पर ये सब को तो नहीं बनवा रहा है, सिर्फ छोटा-छोटा डोभा बना दिया गया है। उसमें नहाने के लिए भी नहीं बनता है। उसमें बच्चा भी गिरकर मर जाता है, मवेशी भी गिरकर मर जाता है। और जहां नदी, नाला, जंगल, पहाड़ है, वहां पर तो पुलिस कैम्प बनाया जा रहा है। वहां के महिलाएं तो स्वतंत्र रुप से जंगल, पहाड़, नदी, नाला भी नहीं जा सकती है। वहां जाने पर महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं और इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। वे जो बोलेगा वह बात सुनना है, नहीं सुनने पर माओवादी के नाम से केस कर देता है और जेल में ठूंस देता है, ऐसे सैकड़ों मिसाल झारखंड में मौजूद हैं और दूसरे प्रांतों में भी मौजूद है। पुलिस द्वारा सामूहिक दुष्कर्म, विभिन्न प्रकार के यौन उत्पीड़न के समाचारों से दैनिक अखबारों का पन्ना भरा हुआ रहता है। इससे आदिवासी-मूलवासी, दलित, गरीब व ऐसाकि मध्यम वर्गीय महिलाओं की दशा भी बहुत ही दर्दनाक है।

दरअसल, जनता या सब का विकास के नाम पर लूट-पाट व अत्याचार का राज ही चल रहा है। बड़ा नौकरशाहों व पुलिस अफ्सरों को कमाने-धमाने का राज मिल गया और इससे हम गरीबों पर जबरदस्त शोषण होता है, जुल्म होता है और मौत भी होती है। हमारी माँ-बहन, बहू, बच्चों का क्या दशा है व क्या दशा होगी, यह तो साफ है। आये दिन सुनते ही आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की बस्तर जिला की घटना, जहां 28 आदिवासी महिलाओं के साथ पुलिस-प्रशासन ने बलात्कार किया और यातनाएं दी। इताना ही नहीं 14 वर्षों की दो लड़कियां बाजार गयी थी, नवजात बच्चे के लिए कपड़ा खरीदने के लिए, मगर वहां पर ही उक्त दो लड़कियों पर पुलिस ने गोली चलाकर जान से मार दिया, माओवादी बोलकर। जनता ने साफ तौर पर तथ्यों के साथ प्रमाण दिया कि वे दोनों लड़कियां माओवादी नहीं थीं।

झारखंड में अभी सीएनटी-एसपीटी कानून को सुधार करने के लिए रघुवर दास सरकार ने घोषणा कर दी और विधानसभा से जबरन पारित भी करवा लिया, यहां की जनता और महिलाओं की राय लिए बिना ही पूँजीपतियों के इशारे पर पारित किया। मुंह से बोल रहा है, हम जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि ये सब जनता के लिए नहीं कर रही है। फिर, बड़े-बड़े पूँजीपतियों व कारपोरेट घरानों के लिए जबरन जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। इस रुप से आदिवासी-मूलवासियों की जल-जंगल-जमीन छीनी जाएगी और यहां से लोहा-कोयला-ताँबा-सब कीमती खनिज सम्पदा निकालकर लेते जाएगा। हमलोग जमीन को खोकर और गरीब हो जाएंगे। इससे ज्यादा से ज्यादा समस्या और गंभीर होगी। बाल-बच्चों का पालन-पोषण करने में भारी परेशानी होगी। यह सब जोर-जबरन चलाने के लिए पहले से तैनात हजारों पुलिस बलों के बाद भी और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जाएगा और यहां के जनता को परेशान किया जाएगा और मुर्गी, बकरी या कोई भी फल को जबरन उठाकर ले लिया जाएगा। इससे आदिवासी महिला व लड़कियों के लिए जंगल, नदी जाना भी मुश्किल हो जाएगा। उनलोगों पर बलात्कार चलाया जाएगा और बुरी व गंदी बात बोलना तो उनका नियम है। उपरोक्त लिखी गई सारे बातों से भी यही साबित होता है, इसीलिए यहां पर मजबूत महिला क्रांतिकारी संगठन बनाना जरुरी है और नारी मुक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाना जरुरी है। तभी अपनी इज्जत व जल-जंगल-जमीन को अपने कब्जा में रखा जा सकता है।

फिर नोटबंदी से महिलाओं की स्थिति और गंभीर बना दी गयी। सब्जी बेचकर शहर में ठेके पर मजदूरी कर और मुर्गी, बकरी बेचकर पुराने 500 व 1000 रुपये की जो नोट गरीब

महिलाएं रखी थी, बेटी को पढ़ाने के लिए व शादी कर देने के लिए। तो नोटबंदी के बाद सुनने को मिला है कि यह रुपये 8 नवम्बर, 2016 के बाद से नहीं चलेगा, पुराना नोट बदलना ही होगा, तो सब बैंकों में जमा कर दिया गया। बाद में निकालने के लिए जा रहे हैं तो समय पर पैसा ही नहीं दिया, स्कूल फीस नहीं दे पाने के चलते कई बेटियां आत्महत्या भी कर ली। महिलाओं के लिए परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया। नरेन्द्र मोदी ने बोला था काला धन वापस लाएंगे, गरीब लोगों की गरीबी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे व जाली नोटों को बंद करेंगे। अभी देखा जा रहा है कि गरीबों से सब रुपये लूट लिया गया और बड़े-बड़े पूँजीपतियों को दे दिया जा रहा है और वे पूँजीपति लोग हमारे झारखंड में ही पूँजी लगाकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं और महिलाओं पर शोषण भी और बढ़ा रहे हैं।

रघुवर दास सरकार ने झारखंड का बजट पेश किया और बोला कि तीन साल में ग्रामीणों की आमदनी दोगुनी करने कर लक्ष्य रख गया और आदिवासियों के लिए 802600 करोड़, शिक्षा गारंटी ऋण योजना 50 करोड़ की लागत से शुरु होगी-(24/01/2017 का 'प्रभात खबर' अखबार से उद्धृत)। इसके माध्यम से सरकार एसटी छात्रों को उच्च शिक्षा में लोन का गारेंटर बनेगी। फिर ('प्रभात खबर' अखबार के अनुसार) आदिवासी महिलाओं के लिए 7684.51 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा, महिलाओं के कल्याण के लिए 213 योजनाएं, नई योजनाएं भी शुरु की जाएगी। बच्चों के पालना-घर गांव से शहर तक की कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए बनाया जाएगा। अल्पसंख्यकों के महिलाओं के लिए 107 करोड़ रुपये का प्रावधान, शिक्षा के लिए 16968 शिक्षकों की नियुक्ति- कृषि के लिए 25 हजार किसानों को पंपसेट देने को बोला गया है। असल में यह सिर्फ धोखा है और छलावा है। किसानों व आदिवासी महिलाओं को सुविधा देने के नाम पर अपना जेब भरता है। सच तो यह है कि 1947 से अलग झारखंड राज्य बनने के पहले तक लगभग 60 लाख लोग झारखंड में विस्थापित हो चुके हैं और अभी रघुवर दास सरकार जिस तेवर से कुछ एमओयू को कार्यान्वित करने पर आमदा हुई है, उससे तो लाखों-लाख लागों की विस्थापित होने की संभावना है। इसके अलावा, अन्यान्य राज्यों में कितना विस्थापित व बेघर हुए हैं, उसकी संख्या तो बहुत ही ज्यादा है। उनलोगों को कोई पुनर्वास की जगह भी नहीं दिया गया। अगर कहीं दिया भी है तो बंजर जमीन ही।

सरकार एक तरफ महिलाओं के विकास व सुविधा देने के लिए बोल रही है। पर, कोई भी काम पूरा नहीं करती है, अधूरा ही छोड़ देती है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की बात भी बोली जा रही है, कुछ गांव में प्राथमिक विद्यालय से लेकर मिडिल स्कूल तक बनाते जा रहे हैं। हकीकत में केवल नाम के लिए बनाया गया है। पर, पढ़ाई ठीक से नहीं होती है। छात्रों व बच्चों के भोजन के लिए और स्कूल ड्रेस के लिए रुपये आती है, किताब आती है, पर बच्चे लोगों को कुछ भी ठीक से नहीं दिया जाता है। सिर्फ इने-गिने दलाल लोग व मास्टर लोग रुपये खा जाते हैं। पढ़ाई भी ठीक से नहीं कराते और खाना भी ठीक से नहीं देते। छात्र-छात्राएं अपने पैसे खर्च कर व कुछ ट्यूशन कर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और दिल्ली-मुम्बई नौकर-नौकरानी काम के लिए चले जाते हैं। वहां भी इज्जत के साथ नहीं रह पाते हैं। वहां भी शारीरिक शोषण होता है। कहीं पर भी महिलाओं की सुरक्षा नहीं है।

महिलाओं को जाति और धर्म के नाम पर भी शोषण किया जाता है। जैसाकि उच्च जाति की महिलाओं की पति मर जाने से दूसरी शादी नहीं कर सकती हैं। अगर शादी के दूसरा दिन ही उसका पति मर गया, तो भी वह शादी नहीं कर सकती है। उन महिलाओं की जीवन-जिंदगी कैसे बीतेगी और उनकी समाज में कोई इज्जत भी नहीं रह जाती है। इस तरह के विभिन्न शोषण-जुल्म व अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए हम मेहनतकश आदिवासी महिला सहित तमाम मेहनतकश महिलाओं को एकताबद्ध हो जाना चाहिए और मौजूदा शोषण-जुल्म-अत्याचार और तमाम किस्म के पितृसत्ता के खिलाफ आंदोलन को तेज करते हुए उसे क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ना होगा।

आवें, तमाम आदिवासी-मूलवासी महिलाएं दलित-गरीब-अल्पसंख्यक महिलाएं, मेहनतकश महिलाएं, प्रगतिशील महिलाएं, समाजसेवी महिलाएं, शिक्षिका, छात्र-छात्राएं, बुद्धिजीवी-डॉक्टर-वकील और अन्यान्य मेहनत कर खाने वाले अवाम- संगठित हो जाएं, संगठन बनाएं, सही नारी मुक्ति आंदोलन सहित विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर आंदोलन का निर्माण करें और अंत में इन तमाम आंदोलनों को देश में जारी क्रांतिकारी आंदोलन के साथ जोड़ दें। इसी रास्ते पर ही आपका-हमारा-मेहनतकश नारियों का- सभी का कल्याण व शोषण से मुक्ति हो सकती है, मनुष्य जैसे जीने का अधिकार हासिल हो सकता है। आवें, हम मेहनतकश महिलाएं इस लड़ाई में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने खातिर हर तरह से तैयार हो जाएं। इसलिए ही झारखंड में तथा पूरे भारत में महिला आंदोलन की जरुरत है। याद रखें कि महिलाओं की भागीदारी के बिना किसी भी समाजिक बदलाव को लाने का आंदोलन सफल नहीं हो सकता है।

आवें, जल-जंगल-जमीन हमारा है, नहीं छोड़े हैं, नहीं छोड़ेंगे!

महिलाओं के हर प्रकार के अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखेंगे!

नारी मुक्ति आंदोलन को सही दिशा में आगे बढ़ायेंगे!

मुस्लिम विद्वेष पर आधारित भारत-इजरायल मैत्री

(14 जनवरी, 2018 को अपने 6 दिवसीय भारत दौरे पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनन्याहू जब दिल्ली पहुंचे, तो यहां के प्रधानमंत्री ने सरकारी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उनका स्वागत किया और अपनी दोस्ती की मिसाल पेश करने की कोशिश की। आज जब भारत-इजरायल के शासकों के बीच दोस्ती अपने चरम पर है और इसे एक बहुत बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है, तो हमें जरूर इस दोस्ती के पीछे छिपे उद्देश्यों को समझना होगा।

यह लेख पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इजरायल दौरे के बाद एक हिन्दी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इस लेख को हम यहां इसलिए प्रकाशित कर रहे हैं ताकि हमारे पाठकगण इस दोस्ती के पीछे के शासक वर्गों के खतरनाक इरादे को समझें। - संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

पिछले दिनों भारत-इजरायल की दोस्ती की बात को मीडिया में खूब तवज्जो दी गयी। प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा को मीडिया ने दो बिछड़े भाईयों की मिलन की तरह प्रोजेक्ट किया। दोनों देशों की दोस्ती का यह नया पड़ाव था भी, क्योंकि इसके पहले भारत, इजरायल फिलीस्तीन में से फिलीस्तीन को अपने से ज्यादा करीब समझता रहा है लेकिन बदलती विश्व परिस्थिति में पिछले 25 सालों से वह इजरायल के ज्यादा करीब आता जा रहा है। दोनों देशों की सरकारों के बीच प्रगाढ़-मैत्री के बारे में विचार करने के लिए निम्नलिखित तथ्य गौरतलब है।

इजरायल का वर्तमान इलाका, येरूशलम सहित यहूदियों का ई.पू. 'ईसा पूर्व' से आदिम स्थान रहा है। पिरामिड सभ्यता के मिस्री शासकों ने लगभग ई.पू. तीन हजार वर्ष में यहां अधिकार कर उन्हें गुलाम बनाया। गुलामी का यह कटु-अनुभव यहूदी कभी नहीं भूले। इनकी प्रार्थना की शुरूआत में कहा जाने लगा- 'एक समय था कि हम मिस्र के गुलाम थे।' यूनानी सभ्यता का विस्तार में इस प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया। ई.पू. प्रथम शताब्दी में यहूदियों ने आजादी की बहादुराना लड़ाई लड़ी और सफलता भी हासिल की। गुलामी प्रथा झेलने वाले यहूदियों ने गुलामी प्रथा को अपने शासन में पूरी तरह तो खत्म नहीं किया (तत्कालीन व्यवस्था में इसका विकल्प नहीं था), फिर भी यह नियम बनाया गया कि सात वर्ष तक गुलाम रहने के बाद उसे आजादी मिल जायेगी।

यहूदियों की आजादी रोमन साम्राज्य ने खत्म कर दी। रोमन साम्राज्य ने यहूदियों को इस क्षेत्र से विस्थापित कर यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों में दास के रूप में बेचा। कालांतर में गुलामी प्रथा की समाप्ति के पश्चात विभिन्न देशों में यहूदी समुदाय बस गये।

यहूदियों को विभिन्न देशों में राजनीतिक सत्ता के नजदीक पहुंचने का मौका सीधे नहीं मिला। फलस्वरूप व्यापार तथा आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से यहूदी समुदाय खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करने में लग गया। इस प्रक्रिया में इनके बारे में यह धारणा पनपने लगी कि ये लोग धन कमाने के लिए छल-कपट तथा क्रूरता का सहारा लेते हैं। शेक्सपीयर की रचना वेनिस का सौदागर (मर्चेंट ऑफ वेनिस) में शाइलाक का जिक्र किया है, जो कर्ज समय पर वापस न मिलने पर कर्ज लेने वाले का एक पांव का मांस काट लेने की शर्त रखता था। इसमे शाइलाक को एक यहूदी दिखाया गया है।

यहूदियों को यह महसूस होता रहा है कि हर देश में उनके साथ दूसरे दर्जे की नागरिकता का व्यवहार किया जाता रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वे पराये देश में हैं। फिर भी उनकी धन संपदा उनको मजबूत करती रही और लोकतांत्रिक राज्य और समाज में उनका राजनीतिक प्रभाव भी इस आर्थिक समृद्धि में मजबूत हुआ। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवादी अत्याचारों ने उन्हें हिला कर रख दिया। औरतों, बच्चों समेत यहूदियों को गैस चेम्बर में बंद कर विषैली गैस द्वारा मार डालने की अमानवीय घटना ने उन्हें न केवल जर्मनी से भागने पर मजबूर किया, बल्कि एक यहूदी देश होने की दबी इच्छा को भी उभार दिया।

इस कारण दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते-होते अमेरिका व ब्रिटेन में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों ने फिलिस्तीन देश को अपना मूल स्थान बताते हुए वहां एक यहूदी देश स्थापित करने की आकांक्षा को उजागर किया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते-होते यहूदी गुरिल्ला गतिविधि द्वारा इस प्रदेश में छापामार कार्यवाही करने लगे और अपनी आबादी का विस्तार भी करने लगे। अमेरिका व ब्रिटेन ने तेल बाहुल्य क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने के लिए यहूदियों की इस आकांक्षा का पूरा लाभ उठाते हुए उनका साथ दिया। यहूदियों के प्रति विश्व सहानुभूति के वातावरण में सोवियत संघ समेत समाजवादी दुनिया ने भी उनका साथ दिया। फलस्वरूप 15 मई, 1948 को इजरायल के रूप में विश्व मानचित्र पर एक यहूदी राष्ट्र स्थापित हो गया।

दरअसल यह एक सही समस्या का गलत समाधान था। समानता, भाईचारा और आजादी यदि सही मायने में लागू हो

शेष पृष्ठ संख्या 25 पर...

भारत में फासीवाद की कुछ विशिष्टताएं

(यह लेख भारत में फासीवाद की कुछ विशिष्टताओं को बेहतर तरीके से सामने लाती है, इसीलिए इस लेख को इन्टरनेट पर उपलब्ध एक वेबसाइट से लेकर हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं ताकि हमारे पाठकों को फासीवाद को समझने में आसानी हो। - संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

फासीवाद के प्रेत ने भारत पर हमला कर दिया है। यह अपना शिकंजा फैला रहा है और जनजीवन के हर क्षेत्र को अपनी जकड़ में ले रहा है। एक सदी पहले नागपुर में संघ परिवार के बोये हुए जहरीले बीज संघ प्रचारक मोदी के सत्ता में आने से फलने लगे है। पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के रथ पर सवार होकर संघ परिवार के सभी को भारत को ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी राज के अधीन लाने के लिए अपने फन फैला रहे हैं। संघ परिवार प्राचीन भारतीय संस्कृति और देशभक्ति के नाम पर राज्य की मदद और शह से गो-रक्षा, लव-जेहाद आदि का बहाना बनाकर धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलितों, प्रगतिशील लोगों, क्रांतिकारियों और वे सब, जो किसी भी रूप में उनके विरोधी हैं, पर शारीरिक हमले कर रहे हैं।

ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी मीडिया द्वारा, चाणक्य दुर्भावनापूर्ण कुप्रचार द्वारा लगातार शैक्षणिक संस्थानों पर हमले कर बौद्धिक जगत पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। इन ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादियों को टक्कर देने और इन्हें हराने के लिए इनकी असली फितरत और वैश्विक संदर्भ में फासीवाद के इतिहास को और उसके साथ-साथ भारत में इसकी विशिष्ट अभिव्यक्तियों को भी समझना होगा।

फासीवाद और उसकी कार्यपद्धति

(1) फासीवाद, बुर्जुआ के वर्ग शासन के दो मुख्य रूपों में से एक है, दूसरा रूप बुर्जुआ जनवाद है। पूंजीपति वर्ग जनवादी नियमों, मूल्यों, अधिकारों आदि का पालन करते हुए अपना शासन तब-तक चलाता रहता है, जब तक कि उसकी पूंजीवादी लूट-खसोट बिना किसी प्रतिरोध के जारी रह सके। लेकिन जब पूंजीवादी व्यवस्था को संकट अपनी चपेट में ले लेता है और वे अति मुनाफे हासिल ना कर सके या इस व्यवस्था को मेहनतकश वर्ग के उभारों और बगावतों का सामना करना पड़ता है तो बुर्जुआ अपने जनवादी शासन के मुखौटे को उतार फेंकता है और शासक वर्गों के सबसे प्रतिक्रियावादी तत्वों की खुल्लम-खुल्ली तानाशाही का सहारा लेता है। यह कारपोरेट तंत्र भी है क्योंकि यह राज्य और कारपोरेट शक्तियों का विलय है।

(2) यूरोप में फासीवाद तब उभरा जब विश्व पूंजीवादी व्यवस्था अपने सबसे गंभीर संकट का सामना कर रही थी। हम आज भारत और पूरी दुनिया में फासीवादी ताकतों की यह वृद्धि उस समय देख रहे हैं, जब आर्थिक संकट ने एक बार फिर विश्व पूंजीवादी व्यवस्था को अपनी गिरफ्त में लिया है।

(3) फासीवाद ने सत्ता में आने के लिए खुद को हमेशा जन-समूहों की लामबंदी और लोकतंत्र पर अधारित किया है।

(4) फासीवाद जनसमूहों को अति-राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर लामबंद और संगठित करता है। ऐसा करने के लिए वह किसी अल्पसंख्यक समूह या समुदाय को देश की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में चित्रित करके बहुसंख्यक समुदाय या जाति को उनपर हमला करने के लिए लामबंद करता है और उन्हें अलग-थलग कर देता है। फासीवाद जनता को अपने जनवादी अधिकारों को त्यागने को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और वर्तमान में 'आतंकवादी-खतरे' का हो हल्ला भी मचाता है।

फासीवाद को समर्थन करने वाले वर्ग

कई बार ये समझा जाता है कि फासीवाद मुख्यतः लंपट-बुर्जुआ या पेटी-बुर्जुआ द्वारा प्रोत्साहित और समर्थन किया जाता है। समय और स्थान का ध्यान न रखते हुए पूंजीवादी वर्ग को प्रगतिशील वर्ग के तौर पर देखा जाता है। पर असल में ''फासीवाद वित्तीय पूंजी के सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी अंधभक्त, कट्टर अंधराष्ट्रवादी और सर्वाधिक साम्राज्यवादी तत्वों की खुल्लम-खुल्ली आतंकवादी तानाशाही होती है।'' जहां तक साम्राज्यवादी देशों का सवाल है, यह सही है। लेकिन भारत जैसे अल्प विकसित या तीसरी दुनिया के देशों या अर्द्ध सामंती-अर्द्ध औपनिवेशिक देशों के संदर्भ में वे दलाल बड़े पूंजीपति और जमीन्दार वर्ग हैं, जो फासीवादी तानाशाही का इस्तेमाल करते हैं। भारत के ठोस हालातों में, इस समीकरण में जाति और धर्म भी घुस आते हैं। इस तरह यह दलाल बड़े बुर्जुआ और जमीन्दार वर्गों के उच्च जाति, हिन्दू कट्टर प्रतिक्रियावादी, अंध-राष्ट्रवादी तत्वों की तानाशाही है। इसलिए इसे विचारधारा के तौर पर ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद के रूप में वर्णन किया जा सकता है। यह उस समय सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई दिया था, जब संपूर्ण बड़े दलाल पूंजीपतियों अंबानी, अडानी, टाटा, बिड़ला, अग्रवाल आदि अपने पूरे संसाधनों के साथ मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर उपर चढ़ाने में लगे हुए थे।

फासीवादी शासन के संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र

बुर्जुआ विचारधारा में चुनावों को लोकतंत्र के तौर पर परिभाषित किया जाता है। अगर नियमित रूप में चुनाव हो और शासक वर्गों के विभिन्न ग्रुपों को चुनाव लड़ने और

जीतने का मौका मिल रहा हो, तो लोकतंत्र फल-फूल रहा है, समझा जाता है। भले ही इकट्ठा होने, सभा करने, अपना मत व्यक्त करने, हड़ताल करने के आदि के हक को कदमों तले कुचला जा रहा हो। पर मेहनतकश जनता और वे संगठन और पार्टियां, जो जनता के लिए संघर्ष करती है, उनके लिए यही हक जनवाद को परिभाषित करते हैं। इस नजरिए से देखा जाए तो भारत कभी भी जनवादी देश नहीं रहा। कश्मीर व उत्तर-पूर्व के राष्ट्र (राज्यों) हमेशा फासीवादी शासन में है। खासकर जहां तक संघर्षरत जनता का सवाल है- देश के दूसरे भागों में संघर्षरत जनता, खासकर वे जो इस शोषण व्यवस्था के लिए खतरा बन गये है, तेलंगाना संघर्ष के दिनों से ही हमेशा फासीवादी दमन सहन किये हैं। जनवादी अधिकार एक सीमित हद तक, सीमित तरह से सिर्फ शहरी इलाकों में ही रहे हैं। वह भी अब और सीमित और सिकुड़ गये हैं। टाडा, पोटा, यू. ए. पी. ए., ए. एफ. एस. पी. ए., देश द्रोह जैसे अति दमनकारी और फासीवादी कानून गढ़े और लागू किए गए हैं। पुलिस और सशस्त्र बल कानून से खुली छूट पाकर कानूनों को तोड़ते हैं और मुठभेड़ों के नाम पर सरेआम कत्ल करते हैं। इस राज्य शक्ति के साथ जुड़े हुए हथियारबंद खुफिया गिरोह जैसे रणवीर सेना, टीपीसी, जेजेएमपी, जेपीसी, सलवा जुडूम, नियामुद्दीन गुट आदि को क्रांतिकारी आन्दोलन पर कातिलाना हमले करने के लिए मदद की जाती है और भड़काया जाता है।

संघ परिवार की टोलियां जैसे कि श्रीराम सेना, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद आदि और शिव सेना, हिन्दू वाहिनी आदि को वर्तमान भाजपा-संघ सरकार में मुस्लिमों, ईसाइयों और दलितों पर हमले करने और योजनाबद्ध कत्लेआम करने के लिए खुली छूट दे दी गई है। यह फासीवाद के पुराने लक्षणों में से एक है। विश्वविद्यालयों, गांव, कस्बे सब इन हमलों से त्रस्त हैं, पुलिस नौकरशाही और तो और न्यायपालिका की भी इन फासीवादी ताकतों से मिलीभगत है।

हिन्दुत्व और ब्राह्मणीय हिन्दू फासीवाद की वृद्धि

हिन्दुत्व जो कि एक राजनीतिक विचारधारा है, हिन्दू से अलग है। हिन्दू एक धर्म है, जबकि हिन्दुत्व खासकर पिछले 3-4 दशकों से फल-फूल रहा है, भले ही आर. एस. एस. 1925 से ही हिन्दुओं को हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान के नारे से अपने पीछे लगाने की कोशिश कर रहा हो। राम की मूर्ति की पूजा के लिए बाबरी मस्जिद के दरवाजे खुलने से लेकर बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने और मुम्बई और अन्य जगह पर मुस्लिमों के कत्लेआम को इस देश में फासीवाद के बढ़ने का पहला चरण कहा जा सकता है। दूसरा चरण, नरेंद्र मोदी का गुजरात का मुख्य मंत्री बनने के बाद एक कट्टर हिन्दू नेता व बड़ी पूंजी के वफादार नौकर के तौर पर उभरना और उसके शासन काल के दौरान गुजरात में मुस्लिमों का कत्लेआम का था। तीसरा चरण, बड़ी पूंजी द्वारा उसके नाम को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाना और उसके बाद उसका प्रधानमंत्री के तौर पर निर्वाचित होना है। प्रधानमंत्री के तौर पर उसकी पदवी बढ़ जाने के बाद फासीवादी ताकतों को सर्वाधिक सीमा तक खुला छोड़ दिया है।

अंधराष्ट्रवाद के नाम पर साम्राज्यवादी पूंजी की चाकरी

भाजपा और संघ परिवार अपने भीड़-उत्तेजक कामों से देशभक्ति और अंधराष्ट्रवाद की गलत धारणाओं को 'भारत-माता की जय', 'वंदेमातरम्' आदि नारों और पाकिस्तान को गाली-गलौज के नाम पर लोगों के मनों में बैठा रहा है। ऐसा रूख अखित्यार कर वह अपनी जन विरोधी और साम्राज्यवाद परस्त नीतियों पर पर्दा डालना चाहते हैं। असल में तो आर. एस. एस. ने कभी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उसने तो असहयोग आन्दोलन और भारत छोड़ो आन्दोलन का विरोध किया था। वह तो तिरंगे झण्डे की भी खिलाफत करता है।

भाजपा ने सभी क्षेत्रों समेत रक्षा क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के लिए दरवाजे खोल दिये हैं। इसने फारमेसी, केबल टीवी नेटवर्क, डी. टी. एच. समेत रक्षा क्षेत्र के बिना सरकारी अनुमति के स्वचलित रास्तों से 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के लिए अनुमति दे दी है। भाजपा सरकार ने किसानों की जमीनों का अधिग्रहण आसान करने के लिए और उन्हें कारपोरेट जगत और रियल एस्टेट के दरिन्दों को देने के लिए, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे किसानों, आदिवासियों और विभिन्न जन संगठनों के सख्त विरोध का सामना करना पड़ा, तो उसने कारपोरेट जगत की जरूरतों के अनुसार उचित संशोधन करने के लिए राज्य सरकारों को चोरी-छिपे आदेश दे दिया।

भारत के परमाणु बाद्धता कानून में अमरीकी आपत्तियों को दूर करने के लिए मोदी सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है, ताकि अमरीकी बड़ी कम्पनियां यहां परमाणु संयंत्र खोल सके जबकि जर्मनी, जापान और दूसरे विकसित देश परमाणु उर्जा से मुक्ति पाने की ओर बढ़ रहे हैं।

भाजपा सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों और बीमा कंपनियों का निजीकरण करने और उनको विदेशी वित्तीय संस्थानों के नियंत्रण में देने के लिए कदम उठा रही है। विमुद्रीकरण और मुद्रारहित अर्थव्यवस्था आदि बड़े वित्तीय संस्थानों को फायदा पहुंचाने के लिए ही है।

श्रम कानूनों में संशोधन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और निजी कंपनियों को मनमर्जी से ठेके पर भर्ती और छंटनी करने की अनुमति देने और मजदूरों को संगठित ना होने देने, कंपनियों को मजदूरों को अनियमित मजदूरों के तौर पर बिना अधिकारों और घटिया पगार और काम के हालातों में भर्ती करने की अनुमति देने के लिए किया जा रहा है।

साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थानों और कम्पनियों के सामने घुटने-टेकने और अपने देशद्रोही कार्य को छुपाने के लिए वे हर अन्तरराष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद का हौवा खड़ा कर और पाकिस्तान को गाली-गलौज कर रहे हैं और अंधराष्ट्रवाद को उत्तेजित कर रहे हैं। भले ही सरकार अभी सीधे-सीधे चीन को गाली-गलौज का सहारा नहीं ले रही है, पर वह अपने दुरूत्साही (गलत काम करने के लिए उकसाने वाले) आज्ञाकारी मीडिया द्वारा चीन को गाली-गलौज का सहारा ले रहा है और इस तरह अपने आपको एक बहादूर योद्धा दिखा रहा है।

ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी साम्प्रदायिक हमले और हर क्षेत्र का भगवाकरण

भाजपा और संघ हर क्षेत्र का भगवाकरण करने की कोशिश कर रहा है। अंधविश्वास, इतिहास के गलत चित्रण, घृणित जाति व्यवस्था के रहते हुए भी हिन्दू धर्म को गौरवान्वित करने, आधुनिक धर्मनिरपेक्ष उदार मूल्यों की जगह ब्राह्मणीय विचारधारा, असमानता व पितृसत्तात्मक मूल्यों को दिमाग में बैठा देने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों को बदला जा रहा है। पारम्परिक भारतीय मूल्यों के नाम पर संघ परिवार के संगठन एन्टी-रोमिओ दल बना कर, वेलेंटाईन दिवस आदि पर और लव-जेहाद का विरोध करने के नाम पर महिला और पुरूषों पर हमले चला रहे हैं। इसके पीछे एक साजिश है। असल में ब्राह्मणीय विचारधारा अंतर्जातीय और अंतधार्मिक शादियों की विरोधी है, इसलिए ह्रासोन्मुख पश्चिम मूल्यों का विरोध करने के नाम पर वे जाति व्यवस्था और पितृसत्तात्मक मूल्यों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

शिक्षा का भगवाकरण

वर्तमान शासन द्वारा पाठ्यक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों का भगवाकरण नये उत्साह के साथ किया जा रहा है। उन सभी राज्यों में, जहां वह सत्ता में है, भूतकाल को झूठलाते हुए और मुस्लिम शासकों की निंदा करते हुए स्कूली किताबों को झूठे इतिहास से भरा जा रहा है ताकि बच्चों के भोले-भाले दिमाग को प्रभावित किया जा सके। संघ परिवार की पृष्ठभूमि रखने वाले शिक्षकों को विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थानों के मुख्य के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है। वह सभी प्रगतिशील, उदारवादी, जाति-विरोधी संगठनों, छात्रों और बुद्धिजीवियों को निर्दयी पंजों से दबाने की कोशिश कर रहा है। ए.बी.वी.पी. के गुण्डे और दूसरे संघ परिवार के संगठन अफसरशाही से घुल-मिल कर, दरअसल उसे दुरूत्साहित कर प्रगतिशीलों को निकाल बाहर फेंकने या उन्हें धमकाने और वश में रखने की दण्डात्मक कार्रवाइयां चला रहे हैं। संस्थानों के इस तरह के मुखियाओं द्वारा छात्रों का निलंबन या निकाल बाहर करना आम बात हो गई है। शराफत और मर्यादा के दिन गुजर गये हैं। हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला और अन्य के संघर्ष में, चेन्नई के ए. पी. एस. ए., जेएनयू, बी. एच. यू., पंजाब विश्वविद्यालय और एफ. टी. आई. आई. आदि के संदर्भ में सुस्पष्ट रूप में देखा जा सकता है।

इसके पीछे भी एक अन्य षड्यंत्र है। छात्रों का ध्यान बेरोजगारी, साम्राज्यवादी और कारपोरेट लूट-खसोट, बढ़ती गैर-बराबरी आदि से हटाया जा रहा है। सिर्फ 'वंदेमतराम्' गाने और 'भारत माता की जय' के नारे लगाने को ही देशभक्ति की कसौटी बनाया जा रहा है।

दलितों, मुस्लिमों और ईसाइयों का कत्ल

हिन्दुत्ववादी गुण्डा समूहों को खुला छोड़ देने से, दलितों, मुस्लिमों, ईसाइयों पर लव-जेहाद, गो-मांस खाने, धर्मांतरण आदि के नाम पर हमले किए जा रहे हैं। यह अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों को अधीन करने और फौरी राजनीतिक लाभ पाने के लिए समुदायों का ध्रुवीकरण करने के लिए भी किए गए हैं। भले ही संघ परिवार सभी हिन्दुओं समेत दलितों की बात करता है, पर हिन्दू धर्म और हिन्दुत्व की प्रकृति ही जातिवाद को अपने सबसे भद्दे रूप में उना और सहारनपुर जैसी घटनाओं में दलितों पर हमलों, अन्तर्जातिय विवाह होने से प्रतिष्ठा-कत्ल (ऑनर कीलिंग) आदि को बढ़ावा देती है। गो-रक्षा के नाम पर निगरानी-दल उपद्रव मचा रहे हैं।

भाजपा समान आचार संहिता के नाम पर हिन्दू संहिता को थोप रही है। समान आचार संहिता मुस्लिमों को प्रताड़ित करने के लिए भाजपा के हाथ का डण्डा है। वह धर्म निरपेक्षता, जनवादी मूल्यों और लैंगिक समानता के लिए समान आचार संहिता का प्रचार नहीं कर रही। धर्मांतरण विरोधी कानून, अत्याचार विरोधी कानून आदि बनाये गये हैं, जो सुनने में तो अत्युत्तम लगते हैं, पर असल में मुस्लिमों और ईसाइयों को अपना शिकार बनाते हैं। इस माहौल में बड़े स्तर पर अल्पसंख्यकों की अगल-थलग बस्तियों का बनना जारी है।

न्यायपालिका और हिन्दुत्व ताकतों का घनिष्ठ संबंध

न्यायपालिका से आशा की जाती है कि वह संविधान द्वारा प्रतिष्ठापित उद्धार, जनवादी और धर्म निरपेक्ष मूल्यों को उपर उठाएगी। पर न्यायपालिका भगवा ताकतों के हाथ का हथियार बनते जा रही है। भले ही कई बार कुछ अपवाद भी मिलते हैं, पर आम तौर पर देशभक्ति और आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर न्यायपालिका दिन-प्रतिदिन भगवा बनती जा रही है। तथाकथित आतंकवादियों और माओवादियों व उनसे सहानुभूति रखने वालों को जमानत नहीं मिलती और उन्हें बहुत ही कमजोर सबूतों के आधार पर फांसी की सजा या उम्र कैद सुना दी जाती है। दूसरी तरफ हिन्दू साम्प्रदायिक हत्यारों, उच्च जाति की निजी सेनाओं और उनके मुखियाओं को गंभीर अपराधों में भी जमानत देकर या बाइज्जत बरी करके आजाद छोड़ दिया जाता है। सुरक्षा बलों का मनोबल बनाए रखने के नाम पर सुरक्षा बलों द्वारा किये जा रहे घृणित से घृणित

अपराधों जैसे कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं मुस्लिमों, आदिवासियों, दलितों आदि जो कि अपने अधिकारों के लिए लड़ते है, उन्हें यातनाएं देने, आदिवासी गांवों को जलाने, मुठभेड़ों के नाम पर ठंडे दिमाग से किये गए कत्लों की तरफ से न्यायपालिका आंख फेर लेती है।

न्यायपालिका सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजाने, गाय व गो मुत्र के गुणों आदि पर फैसले देकर देशभक्ति की अपनी धारणा को थोप रही है। न्यायपालिका की रूढ़ीवादी विचारधारा की चरमपोशी फासीवाद की एक खास विशेषता है। माओवादियों और आतंकवादियों से लड़ाई के नाम पर सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है।

महिलाएं

समाज में महिलाओं की भूमिका पर रूढ़ीवादी विचारों और दृष्टिकोण को अत्याधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं द्वारा पुरूष और परिवार की सेवा के परम्परावादी 'स्त्री धर्म' पर जोर दिया जा रहा है। सरस्वती शिशु मन्दिरों में इस पितृसत्तात्मक विचारधाराओं को लड़कियों के दिमागों में थोपा जा रहा है। संघ द्वारा दुर्गा वाहिनी और इस तरह के महिला संगठन जो कि सिर्फ महिलाओं के दिमागों में मुस्लिम विरोधी और इसाई विरोधी विचारधारा को भरने के लिए बनाए गए हैं, मात्र शक्ति और 'स्त्री शक्ति' की गलत धारणा भी उनके दिमागों में भर रहे हैं, जिनमें लैंगिक समानता और न्याय के लिए कोई जगह नहीं है। बल्कि जिनके अनुसार महिलाओं का मात्र एक धर्म पति, बच्चों (खासकर पुरूष बच्चों) और सास-ससुर की सेवा करना और इन पितृसत्तात्मक मूल्यों को अपने बच्चों को सिखाना है।

महिलाओं द्वारा इन जंजीरों को तोड़ने का हर प्रयास शारीरिक हिंसा और हिंसक हमलों का सामना करता है। महिलाओं का पहनावा, उनका आचरण आदि सब संघ की जांच-परीक्षण के अधीन है। हिन्दुत्वादी मनुधर्म के मूल्यों को लागू करना चाहते हैं, जोकि यह कहते हैं कि महिलाएं किसी भी तरह की आजादी के योग्य नहीं है।

अखण्ड भारत और राष्ट्रीयताएं

आर. एस. एस. और भाजपा ने हमेशा अखण्ड भारत की वकालत की है, और तो और आर. एस. एस. राष्ट्रीयता की भावनाओं के बढ़ने के डर से भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की भी विरोधी थी। इसकी विचारधारा दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के हितों की अच्छी सेवा करती है। सम्पूर्ण-भारत की विचाराधारा और मुस्लिम विरोधी विचाराधारा कश्मीर के संघर्ष में एक हो जाती है और कश्मीर में दमन दिन-प्रतिदिन तेज हो रहा है। भले ही विभिन्न कारणों से राष्ट्रीयताओं की आत्मनिर्णय के आन्दोलन पिछले कुछ समय मे पीछे-हटने का सामना कर रहे हैं, पर जब भी आन्दोलन उभर कर आगे बढ़ेंगे, भाजपा और केन्द्रीय सरकार कई गुना ज्यादा दमन करेगी। अखण्ड भारत की विचारधारा शासक वर्गों की विस्तारवादी योजना की सेवा करती है और इस तरह दक्षिण एशिया क्षेत्र में छोटे राष्ट्रों के लिए खतरा है।

जी. एस. टी., जिसका मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते समय विरोध किया था, अब लागू हो गया है। इस तरह की सभी आर्थिक नीतियां, छोटे और क्षेत्रिय पूंजीपतियों को नजरअंदाज कर बड़े दलाल पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। इस बढ़ते हुए फासीवाद का जितना संभव हो उतना व्यापक संयुक्त मोर्चा बनाकर ही सामना किया जा सकता है और हराया जा सकता है। क्रांतिकारी शक्तियों, प्रगतिशील और जनवादी शक्तियों, जाति विरोधी और ब्राह्मणवाद विरोधी शक्तियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिला संगठनों आदि को एक साथ इकट्ठा होने और फासीवादी संगठन और फासीवादी राज्य से लड़ने की जरूरत है।

★

पृष्ठ संख्या 27 का शेष...

वह सारी दौलत बनती है जिसका संचय बनता है- संक्षेप में वह सारी दौलत बनती है जिसका गैर-मेहनतकश वर्ग उपभोग अथवा संचय करते हैं। इससे यह सिद्ध हो गया कि आज के पूंजीपतियों द्वारा धन संचय उसी प्रकार दूसरों के अशोधित श्रम का हस्तगतकरण है, जिस प्रकार दास-स्वामियों या भू-दास श्रम का शोषण करनवाले सामन्ती प्रभुओं का ध न-संचय था और शोषण के इन सभी रूपों में अन्तर केवल अशोधित श्रम के हस्तगतकरण के तरीके और ढंग का ही है। पर इस बात ने सम्पत्तिधारी वर्गों के ढोंग से भरे शब्दजाल का अन्तिम औचित्य भी समाप्त कर दिया, जिसका आशय यह होता था कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में कानून और न्याय अधिकारों और कर्तव्यों की समानता तथा हितों के सामंजस्य का बोलबाला है और यह प्रकट कर दिया कि वर्तमान पूंजीवादी समाज, अपने पूर्ववर्ती समाजों की ही भांति और उनसे किसी भी तरह कम नहीं, जनता की विशाल बहुसंख्या के उपर निरन्तर घटते ही जाते अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा शोषण की एक भीमकाय संस्था मात्र है।

★

'माओवादी' एमएसएस पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने गिरिडीह के मजदूरों की जीवन रेखा ही काट दी है!

(झारखंड सरकार द्वारा विगत 22 दिसम्बर, 2017 को 28 साल पुराने पंजीकृत ट्रेड यूनियन 'मजदूर संगठन समिति' को बिना किसी नोटिस दिये भाकपा (माओवादी) का अग्र संगठन बताते हुए प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई। झारखंड सरकार के इस अप्रत्याशित अलोकतांत्रिक व गैर-संवैधानिक घोषणा के पीछे मजदूर संगठन समिति के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर चल रहे जनांदोलन ही एकमात्र कारण के रूप में नजर आता है। पिछले साल यानी वर्ष 2017 में इस मजदूर यूनियन द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम व आंदोलन संगठित किये गये, जो झारखंड सरकार के लिए परेशानी का सबब बना। 'महान नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह की अर्द्ध-शताब्दी समारोह समिति, झारखंड' का जब गठन हुआ, तो इसमें कई प्रगतिशील बुद्धिजीवियों व आंदोलनकारियों के साथ-साथ 'मसंस' के कई नेता भी इस समारोह समिति के सदस्य बने और जब इस समारोह समिति द्वारा 25 मई से 20 अगस्त, 2017 तक कई शहरों में कार्यक्रम की घोषणा हुई, तो झारखंड सरकार के कान खड़े हो गए और इन समारोहों को विफल करने के लिए एड़ी-चोटी एक कर दिये। फलस्वरूप 25 मई को रांची में प्रस्तावित समारोह को समारोह स्थल पर हजारों कार्यकर्ताओं के पहुंचने के बाद भी परमिशन न होने का बहाना बनाकर प्रशासन ने रोक दिया। इस विफलता से आक्रोशित समारोह समिति ने अपने धनबाद व गिरिडीह में प्रस्तावित समारोह को शानदार रूप से सफल किया, 20 अगस्त को गिरिडीह में आयोजित समारोह में प्रसिद्ध कवि व आरडीएफ के अध्यक्ष वरवरा राव भी शामिल हुए।

इस बीच, 9 जून, 2017 को गिरिडीह के मधुबन थाना अंतर्गत पारसनाथ पहाड़ पर फर्जी मुठभेड़ में दुर्दांत माओवादी बताकर डोली मजदूर मोतीलाल बास्के की हत्या सीआरपीएफ कोबरा के जवानों ने कर दी और इस हत्या का जश्न मनाने के लिए झारखंड के डीजीपी डीके पांडेय ने गिरिडीह एसपी को एक लाख रूपये नगद दिये और 15 लाख बाद में देने का वादा किया। चूंकि मोतीलाल बास्के एक डोली मजदूर था और मजदूर संगठन समिति का सदस्य भी था, इसलिए इस फर्जी मुठभेड़ के खिलाफ 'मसंस'

ने पहल लेकर वहां 'दमन विरोधी मोर्चा' का गठन कर एक व्यापक जनांदोलन खड़ा किया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण राजनीतिक दल व सामाजिक संगठन शामिल हैं। यह जनांदोलन आज भी जारी है।

हालिया घटना, जिसने आग में घी का काम किया, वह था झारखंड में 'महान बोल्शेविक क्रांति का शताब्दी समारोह समिति, झारखंड' का गठन व इसके बैनर तले झारखंड में 17 जगहों पर पुलिस-प्रशासन से लड़ते हुए शानदार समारोहों को आयोजन। मालूम हो कि इसके पहले ही समारोह यानी 7 नवंबर को गिरिडीह में आयोजित समारोह की शानदार सफलता के बाद 12 नामजद व 800 अज्ञात पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। साथ ही मजदूर संगठन समिति के नेतृत्व में मधुबन में स्थित जैन कोठियों में कार्यरत मजदूरों व डीवीसी चंद्रपुरा एवं बोकारो थर्मल में भी व्यापक आंदोलन चल रहा था।

बहरहाल, 22 दिसंबर, 2017 को मजदूर संगठन समिति को झारखंड सरकार द्वारा तमाम नियम-कानून को धता बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसका पूरे देश में व्यापक विरोध भी हो रहा है। इसी कड़ी में एक स्वतंत्र पत्रकार ने इस लेख को लिखा है, इसमें 'मजदूर संगठन समिति' के आंदोलनों से गिरिडीह जिला के मजदूरों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसका वखूबी वर्णन किया गया है। यह लेख और इसका शीर्षक भी इन्टरनेट पर उपलब्ध एक वेबसाईट से लिया गया है।

- संपादकमंडल, लाल चिनगारी)

गिरिडीह यानी पहाड़ों की जगह। यहां के सैकड़ों पहाड़ और घाटियों की खुबसूरती और यहां के निवासियों की वह खूबी थी, जिसकी पनाह में हजारों साल पहले जैन मुनियों ने शरण लिया और अपना अंतिम समय बिताया। सरकारी पोर्टल पर गिरिडीह की ऐतिहासिक विकास यात्रा का अगला पड़ाव सीधा महान बादशाह अकबर के कर वसूली के संदर्भ में और फिर अंग्रेजों के कोयला खदान के विवरण के रूप में पेश किया जाता है। संथाल, मुंडा और अन्य बहुत सी आदिवासी समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी के इतिहास को न देख पाने का नजरिया आज भी गिरीडीह के जंगलों, खेतों और वहां के निवासियों को नजरअंदाज कर देने के परिणाम में दिखता है। जब तक राज्य को देखने का नजरिया केंद्र की कर वसूली और आर्थिक व्यवस्था का कथित आधुनिक आईना बना रहेगा, आदिवासी समुदाय की खेतिहर व्यवस्था को विकास का रोड़ा बताने का सिलसिला भी जारी रहेगा व विकास के नजरिये से पर्यावरण और लोगों की जिंदगी बाहर ही बना रहेगा। यह उपनिवेशिक सोच ही है जो 'संपत्ति के नये अर्थ ही नहीं राज्य की संकल्पना को भी एकदम बदल दिया और यह यहां के पूववर्तियों के प्रति समझदारी, आर्थिक दृष्टिकोण से एकदम अलग था। (अ रूग एण्ड पीजेंट स्लेव : आदिवासी प्रतिरोध 1800-2000, लेखक : शषांक केला, पृष्ठ 20)।)' जनसंख्या पंजीकरण के मसले पर असम की आदिवासी जनता को पंजीकृत करने के मसले पर 30 नवम्बर 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने असम सरकार के अधिकारी की आलोचना करते हुए कहा कि 'जिस तरह का बयान आपने पेश किया है, यह काम का ठीक तरीका नहीं है। इस तरह के सतही बयान जनता और राज्य की सेहत के लिए ठीक नहीं है। यदि आप यह कह रहे हैं कि 15 प्रतिशत जनता मुख्यधारा में नहीं हैं, तो मैं पूछ रहा हूं कि इस संदर्भ में राज्य की ओर से आपकी क्या भूमिका है।' नदी, पहाड़, खेत, खनिज और मेहनती लोगों से भरे गिरीडीह की जिंदगी इस विकास के आधुनिक नजरिये के धुंए और खदान में फंसती हुई दिख रही है। जब नवम्बर 2017 के मध्य में दिल्ली धुंध और प्रदूषण से बेहाल था और लगभग 15 दिनों तक यह देश की सबसे बड़ी खबर थी, तब मैं गिरिडीह के चतरो इलाके में था, जहां पिछले 20 सालों से चौबीसों घंटे धुंध और राख का अंधेरा छाया हुआ है। विकास के नाम पर सिर्फ इंसानों की जिंदगी ही नहीं जानवरों और पेड़-पौधों की जिंदगी भी तबाह हो रही है। लेकिन इसे विकास के सूचकांक की तरह देखा जा रहा है।

गिरिडीह शहर के एक तरफ पारसनाथ की जंगलों से भरी हुई पहाड़ियां हैं, जिसमें धर्म-कर्म और धर्म से जुड़े व्यवसाय का फैलाव तेजी से बढ़ा है। बिहार से आकर बसे चाय की दुकान चलाने वाले विनय मिश्रा बताते हैं, 'पहले यहां जैन धर्म के तेरहपंथी, बीसपंथी जैसी धार्मिक धारा की धर्मशालाएं थी और पारसनाथ शिखर जी पर मंदिर थे। 1990 के बाद धर्मशालाओं व मंदिरों की बाढ़ आ गई है। पहाड़ के अंदर के गांवों की जमीनों की बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई है। आदिवासी लोग मजदूर बनते गये हैं। जंगलों की कटाई भी बढ़ गई है। व्यवसाय बढ़ा है, लेकिन यहां के लोगों का नुकसान भी हुआ है और हो रहा है। पिछले कुछ सालों से पारसनाथ के इन जंगलों में आग लगने की घटना तेजी से बढ़ी है। जंगल

विभाग इसकी जिम्मेदारी मूलत: यहां के निवासियों पर डालता है।' 30 अप्रैल, 2016 को टाइम्स ऑफ इंडिया का शहर संस्करण लिखता है, 'पारसनाथ के जंगलों से आयुर्वेदिक बूटियां तेजी से खत्म हो रही हैं।' डीएफओ एमके सिंह ने इसकी जिम्मेदारी महुआ बीनने, मवेशी चराने और लकड़ी बीनने वालों पर डाल दिया। लेकिन सवाल यह भी है कि यह आग पिछले दस सालों में इतनी तेजी से क्यों बढ़ा है? दूसरा, यह भी कि जिस जंगल पर तीस से अधिक गांव जिंदा हैं और उसी में रह रहे हैं, वही लोग उसमें आग क्यों लगाएंगे? पारसनाथ आदिवासी समुदाय का संगठन 'मरांग बुरू सांवता सुसार वैसी' के उपाध्यक्ष बुधन हेम्ब्रम का कहना है कि 'हम बहुमूल्य पेड़ों को नष्ट करने वाले दोषियों पर सीधी कार्यवाही करने की बात के अलावा यह भी कहना चाहते हैं कि प्रशासन और स्थानीय जनता को इस आग लगने के मसले को गंभीरता से विचार करना होगा।' 'द टेलीग्राफ' ने 5 जनवरी, 2010 में एक खबर लगाया था कि 'झारखंड के जंगल परिक्षेत्र में 172 किलोमीटर की वृद्धि हुई है और स्थानीय जनता के प्रयासों से हुआ है।' इसी रिपोर्ट में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हवाले से बताया गया है कि 'यह बढ़ोतरी पलामू, गुमला, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग और गिरिडीह में ग्रामवासियों के प्रयास से हुआ है।' इस सर्वे से यह बात साफ होती है कि जनता का और खाासकर आदिवासी समुदाय का वन और पर्यावरण के प्रति वह रुख नहीं है, जो प्रशासन और वन कटाई के ठेकेदारों, अवैध कटाई करने वालों का होता है। पारसनाथ इलाके के युवाओं ने मिलकर 'पारसनाथ वन सुरक्षा समिति' का गठन कर आग बुझाने का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया है: ''हम लोगों ने पारसनाथ पहाड़ के चारों तरफ स्थित लगभग पचास गांवों में फरवरी से ही वन के फायदे से संबंधित पर्चा वितरण, पोस्टर चिपकाना व सभी गांवों में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। सभी गांवों से दो शिक्षित युवाओं को कमेटी में शामिल किया और उनके मोबाइल नम्बर का आदान-प्रदान किया। जब गर्मियों में जंगल में आग लगनी शुरू हुई, तो जिधर भी कोई ग्रामीण आग लगा देखते, फोन से कमिटी के सदस्यों को सूचित करते थे। (रूपेश कुमार सिंह की 'जनज्वार वेबसाईट' में छपी रिपोर्ट)।'' मजदूर संगठन समिति, मधुबन शाखा के साथियों ने बताया कि संगठन आग रोकने के लिए खुद भी प्रचार-प्रसार और तकनीक प्रयोग का प्रचार करता है। यहां यह जानना जरूरी है कि पारसनाथ पहाड़ में माओवाद को खत्म करने के अभियान में जुटी सरकार की नीति के तहत पुलिस और सीआरपीएफ की मजबूत घेराबंदी है और चारों ओर उनके कैंप लगे हुए हैं। यह बात भी लोगों के जबान पर है कि आग इन सुरक्षा प्रहरियों की ओर से लगाया जाता है, जिससे माओवादी गुरिल्लों का ठहरना मुश्किल हो जाय। यह बात कितनी सच है, इसे परखने की जरूरत है लेकिन यह रणनीति गुरिल्लों के खिलाफ बहुत से देशों में अपनाया जा चुका है। आरोप-प्रत्यारोप के बीच न सिर्फ नजरिये का फर्क दिखता है बल्कि पर्यावरण और जनता के बीच के रिश्ते की नासमझी भी दिखती है। ध र्म में व्यवसायिकता के पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव को नजरअंदाज इस आधाार पर कर दिया जाता है क्योंकि यह बेहद संवेदनशील मसला होता है। उत्तराखंड राज्य में धर्म के आधार पर हुए कई सारी आयोजित यात्राओं के चलते पर्यावरण की गंभीर समस्या पैदा हुई थी। इसके परिणामों के संदर्भ में इसे देखने से स्थिति साफ हो सकती है।

पारसनाथ, शिखर जी में 1970 तक वहां तीन कोठियां थी, जो बीसपंथी, तेरहपंथी और श्वेताम्बर जैन मतावलंबियों की कोठियां थीं। 1990 तक इनकी संख्या में मत के आधार पर छह हुई। साम्राज्यवादी वैश्वीकरण की प्रतिक्रियावादी राजनीति ने धर्म को शिखर पर पहुंचा दिया। अब यहां 27 से अधिक कोठियां हैं। धर्मशाला के नाम पर होटलों का व्यापार चरम पर है। 'ट्रस्ट' के नाम पर करोड़ों की पूंजी आदिवासी और वन की जमीन को हथियाने का मानो अभियान ही चल पड़ा है। धर्म का व्यवसाय इतना बढ़ चुका है कि 2004 में रांची उच्च न्यायालय ने इन कोठियों के आय-व्यय का ब्यौरा

रखने के लिए प्रशासन को एक कमेटी गठित करने का प्रावधान किया। ज्ञात हो कि पारसनाथ, शिखरजी में हर साल लाखों यात्री आते हैं। इतने अधिक यात्रियों के आने का दबाव न सिर्फ स्थानीय लोगों और पर्यावरण पर पड़ता है बल्कि दूर के इलाकों की जिंदगी को भी अपने असर में लिया हुआ है। 24 किलोमीटर की पहाड़ में परिक्रमा और इन कोठियों, धर्मशालाओं में ठहरने वालों लोगों का कूड़ा, पाखाना, पेशाब का निपटान की कोई व्यवस्था नहीं है। यह गंदगी जंगलों में डंप कर दिया जाता है और मल-मूत्र और अन्य पानी वाले कचड़े को पीरटांड़ पहाड़ की एक छोटी सी नदी खपेयवेड़ा में गिरा दिया जाता है। यह छोटी से नदी विभिन्न सैकड़ों गांवों से गुजरते हुए जाती है और यही उनके लिए पीने के पानी का स्रोत भी होता है। झारखंड सरकार पारसनाथ के पर्यटन विकास के लिए पारसनाथ रेलवे स्टेशन से शिखर जी तक की सीधी रेल सेवा की परियोजना का प्रस्ताव बनाने में लगी हुई है, लेकिन इस पर्यटन का जो भार यहां के लोगों पर पड़ रहा है, उसे ठीक करने की योजना दूर-दूर तक नहीं दिख रही है।

पारसनाथ पहाड़ और शिखर जी में डोली ढोकर 30 किलोमीटर कठिन पहाड़ की चढ़ाई से लाखों लोगों को धर्म की सैर कराने वाले और इन धर्म की कोठियों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या लगभग 20 हजार है। इन मजदूरों और आसपास के गांवों के लोगों और यहां तक कि धर्म के यात्रियों के लिए भी पारसनाथ में अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। इन कोठियों में धर्मार्थ चलने वाले कुछ चलताऊ किस्म के अस्पताल हैं। यहां मजदूरों को संगठित करने वाला 'मजदूर संगठन समिति' मजदूरों और गरीबों के लिए पांच बेड वाला मुफ्त इलाज करने वाला 'श्रमजीवी अस्पताल' चला रहा है, जहां दवाओं का भी पैसा नहीं लिया जाता है।

गिरीडीह शहर का दूसरा और मुख्य पक्ष उद्योग और खदान है। इसके पहाड़ों के नीचे कोयला, बॉक्साइट और माइका जैसे संसाधान भरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस बारे में यहां के मूलवासियों को पता नहीं था। झारखंड के प्राचीनतम आदिवासी समूह लोहा, कोयला जैसे संसाधानों का प्रयोग अच्छी तरह जानते थे। खेती के विविध तरीके प्रचलन में थे। 1856 तक अंग्रेजों ने यहां से कोयला निकालने के लिए खदान का काम शुरू कर दिया था। 1936 में यहां कोयला खदान के लिए बकायदा अलग से कंपनी स्थापित किया गया और 1956 में सीसीएल यानी केंद्रीय कोयला खदान लिमिटेड भारत सरकार के दायरे में आ गया। भारत के प्रथम दो कोयला खदानों में से एक गिरीडीह के हिस्से में आया। बॉक्साईट खदान और माईका उद्योग तेजी से फैला। गिरिडीह शहर का रूप और रंग बदलता गया। कोयला खदान और माईका उद्योग के लिए उड़ीसा, बंगाल, बिहार, यूपी सहित विभिन्न इलाकों से आए मजदूरों का धौड़ा यानी मुहल्ला बसता गया। शहर के भीतर माइका पर काम करने वाली फैक्ट्री और मजदूरों का जमाव बढ़ता गया। 1980-85 तक यह शहर मजदूरों और फैक्ट्रियों से भरा हुआ था। केवल गिरिडीह शहर में उस समय लगभग दो लाख मजदूर थे। आज भी भारत की सबसे पुराना कोयला खदान इस शहर में जिंदा है और अनवरत कोयला निकाला जा रहा है। लेकिन बाद के दिनों में न सिर्फ मजदूर कम होते गये है, साथ ही माइका उत्पादन बर्बाद होने के बाद यहां मजदूरों की बसावट भी कम होती गई है। लेकिन गिरिडीह के बाहर इलाकों में 1990 के वैश्वीकरण के साथ ही सैकड़ों की संख्या में स्टील, स्पंज आयरन, केबल व इसी तरह की फैक्ट्रियां लगी, जिनसे विकास के छतरी के नीचे तबाही का मंजर अब भी अदृश्य बना हुआ है।

गिरिडीह के टुंडी-धनबाद रोड पर चतरो, श्रीरामपुर की धुंआ और राख उगलती फैक्टरियां हैं, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी का दम घुट रहा है। गिरिडीह से टुंडी रोड पर चतरो की तरफ बढ़ते ही स्पंज आइरन की कंपनियां धुंआ और राख उगलती दिखाई देंगी। दिन में अंधेरे का आलम है। 1980 में मोंगिया की स्पंज आइरन की फैक्टरी लगी। 1996-2000 के बीच सबसे अधिक फैक्टरियां खुली। 2006 तक आते आते यहां लगभग 60 फैक्टरियां खुल चुकी थी। यह साम्राज्यावादी वैश्वीकरण का पहला और दूसरा दौर था, जिसमें विकास के लिए एक तरफ फैक्टरियों को जमीन लूटने और मजदूरों का शोषण करने की खुली छूट दी गई थी। जनता के प्रतिरोध के प्रति रवैया दुश्मनागत होता जा रहा था। मजदूर और किसान जमीन और मजदूरी हासिल करने के लिए मर रहे थे। इस इलाके में भी पानी का दोहन, प्रदूषण, स्थानीय समुदाय और निवासियों को रोजगार, नदी-नालों को गंदा करने, स्वास्थ्य और मजदूरों का शोषण-उत्पीड़न की पूरी छूट मिली हुई थी और यह आज भी जारी है।

चतरो और श्रीरामपुर के इलाके में काम कर रही फैक्टरियों में ज्यादातर स्पंज आइरन कंपनियां हैं। कुछ सरिया और वायर फैक्टरी हैं। इन कंपनियों के नाम निम्न हैं : मोंगिया स्टील लिमिटेड, सलूजा आयरन एण्ड स्टील पॉवर लिमिटेड, सत्यम स्टील एण्ड आयरन कंपनी प्रा. लिमिटेड, हर्षित पावर एण्ड इस्पात प्रा. लिमिटेड, निरंजन मेटॉलिक्स, अतिबीर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, बालमुकुंद स्पंज आयरन लिमिटेड, शिवम आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड आदि। पिग आयरन और हार्ड कोक बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली कंपनी 'लाल फेरो एल्वाय कंपनी प्रा. लिमिटेड' के इंडक्शन फर्नेश को कंपनी के भीतर 2009 में लगाने के संदर्भ में 'इन्वायर्नमेंटल ईम्पैक्ट असेसमेंट' और 'इन्वायर्नमेंटल मैंनेजमेंट प्लान' का जनसुनवाई के आधार पर अंतिम रिपोर्ट जिसे भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 2010 में भेजा गया था। इस रिपोर्ट ने जंगल, फसल, खेत, सामान्य जनजीवन, स्वास्थ्य, जमीनी पानी, नदी और पोखर, स्वास्थ्य और रोजगार आदि पर प्रदूषण के प्रभाव की

चर्चा की है। 2013 में उपरोक्त कंपनी के 12000 टन पिग आयरन, 15000 टन हार्ड कोक और 18000 टन इनगॉट्स के उत्पादन के संदर्भ में श्रीरामपुर में जनसुनवाई जिला प्रशासन के विविध अधिकारियों की उपस्थिति में हुई। इस जनसुनवाई में मजदूर यूनियन के एक पदाधिकारी और कुलची के निवासी तुलसी तुरी ने साफ तौर पर कहा कि 'पिछले समय में हमारे बहुत से प्रदर्शनों के बावजूद प्रदूषण पर कोई नियंत्रण नहीं किया गया।' गांव से महज 500 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद प्रशासन पदाधिकारियों ने वादा किया कि धुंआ और शोर के प्रदूषण को रोक लिया जाएगा। टिकोडीह के राजेन्द्र बायन ने कहा कि 'यहां के लोग खेती पर निर्भर हैं। इस कंपनी से इसका काफी नुकसान होगा। पीने का पानी उपलब्ध कराना होगा।' गांव के लोगों ने इसी सुनवाई के दौरान बताया कि पानी का तल पहले से लगभग 60 फीट नीचे चला गया है। विसवाडीह के राजीव सिन्हा ने बताया कि 'प्रदूषण की वजह से लोग जमीन बेचकर यहां से जाने के लिए विवश हो रहे हैं। फैक्टरियां 1000 फीट नीचे से पानी खींचकर निकाल रही हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि या तो यहां सिर्फ फैक्टरियां रहें या हम लोगों को प्रदूषण मुक्त जीवन जीने दें।' यह कंपनी अपनी घोषित नीति पर चले तब भी यह पानी का दोहन 160 एम3 प्रतिदिन के हिसाब से करेगा। इस कंपनी ने वादा किया, वह प्रदूषण को रोकने की पूरी व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा, पीने का पानी, रोजगार और लगभग चार एकड़ का ग्रीन क्षेत्र विकसित करेगा। पिग आयरन और हार्डकोक जैसे उत्पादन के दौरान कार्बन के विविध रूपों का गैस और कचड़े का उत्सर्जन बड़े पैमाने पर होता है। इससे मुख्य हिस्सा हवा में लगातार घुलता रहता है। यह संवेदनशील क्षेत्र के लिए काफी नुकसानदायक होता है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र का दायरा 25 किलोमीटर तक का है। लेकिन 10 किलोमीटर का दायरा सघन रूप में प्रभावित होता है। चतरो, श्रीरामपुर के इलाके खेती प्रधान हैं। इस क्षेत्र में उसरी नदी-घाटी क्षेत्र महज पांच-छह किमी के दायरे में आ जाता है। सापेक्षिक रूप से यह क्षेत्र जनसंख्या घनत्व वाला है। जिस समय यहां फैक्टरी के लिए जमीन अधिग्रहण, जनसुनवाई और सरकारी पर्यावरण विभाग से अनुमति हासिल करने की औपचारिकताएं पूरी की जा रही थीं, उस समय तक यहां के लोगों का प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन काफी तेज हो चुका था। उपरोक्त जनसुनवाई में किसी ने भी फैक्टरी लगाने के प्रति पक्षधर रवैया अख्तियार नहीं किया था। फिर भी विकास की ऊंची दर हासिल करने की दौड़ में पर्यावरण और लोगों की जिंदगी को कमतर करके देखा गया।

'द टेलीग्राफ' के 25 फरवरी, 2009 को शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट के हवाले बताया गया है कि उस समय 39 फैक्टरियां स्टील और आयरन उत्पादन की थीं और 15 माईका उद्योग से जुड़ी हुई थीं। आयरन, स्टील, माईका फैक्टरियों, कोल खदानों से भरे गिरिडीह में कोई प्रदूषण बोर्ड नहीं है। डाक्टरों के रिपोर्ट के अुनसार क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, न्यूमोनिया, केन्जेक्टिवाइटिस, टीबी, स्क्लेरोसिस जैसी घातक बिमारीयों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 2008 में ही जब वन विभाग और पर्यावरण विभाग से जुड़े अखिलेश शर्मा के नेतृत्व में सर्वेक्षण के दौरान स्वाती स्पंज और आदर्श फ्यूल कंपिनयां प्रदूषण मानक पर खरी नहीं थीं। गिरीडीह वह जगह है, जिसकी खुबसूरती से रविन्द्रनाथ टैगोर अभिभूत थे और उन्होंने इसे दूसरा घर बना लिया था। आज भी उनका घर द्वाशिका भवन बचा हुआ है। लेकिन 'विकास' की परिभाषा में यह सब मुद्दा नहीं होता। दो महीने तक लगातार चले ग्रामीणों और जन संगठनों के संगठित विरोध के चलते 2009 की जुलाई के महीने में चतरो, श्रीरामपुर, मोहनपुर व अन्य इलाकों में चार प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने दौरा किया। टीम में शामिल उपाधीक्षक वंदना डादेल ने बताया कि 'हमने तीन कंपनियों- अतिबीर, वेंकेटेश्वर और बालमुकुंद प्रा. लिमिटेड का दौरा किया। स्थानीय निवासियों ने लगातार शिकायतें रखी है कि मोहनपुर में स्पंज आयरन प्लांट्स मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं। हमने पाया कि इन प्लांटों में से सात यूनिट में ईएसपी नहीं है। हमने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया था कि प्रत्येक ईएसपी को एक दूसरे से जुड़ी व्यवस्था में रखा जाय। लेकिन अतिबीर की दो यूनिटों में ही ईएसपी लगा हुआ था। (द टेलीग्राफ, 14 जुलाई 2009)।' जून 2009 में धनबाद स्थित एनजीओ ग्रीन एण्ड लेवर वेलफेयर की चार सदस्यीय टीम ने चतरो और आसपास के गांव का दौरा किया। एनजीओ के कार्यकारी अध्यक्ष कुमार अर्जुन सिंह के अनुसार 'चतरो, महतोडीह, गंगापुर, कलामाझो जामबाद, उदानबाद और अन्य बहुत से गांव स्पंज आयरन की यूनिटों के वजह से चिंताजनक हालात में हैं। इन इलाकों की फैक्टरियां सारे नियम कानूनों को तोड़ रहे हैं। प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उद्योग विभाग कार्यवाही करने में असफल रहा है।' उसी समय बना एक और संगठन पूर्वांचल पर्यावरण संघर्ष समिति की 11 सदस्यीय टीम ने मांग किया कि फैक्टरियों में इलेक्ट्रो-स्टेटिक प्रिसिपीटेटर यानी ईएसपी, जो राख और धुंए को साफ करता है, को अनिवार्य किया जाय और बिना पंजीकरण के गांव की जमीनों पर इन कंपनियों ने जो कब्जा किया है, उसे वापस किया जाय। इस टीम ने मोहनपुर में प्रस्तावित लाल फेरो एल्वॉय कंपनी की पिग, इग्नोट और कोक कंपनी स्थापित करने का भी विरोध किया, लेकिन हालात में थोड़े समय के लिए कुछ असर दिखा, फिर स्थिति बद से बदतर होती गई।

मैं 7 नवम्बर से 9 नवम्बर, 2017 तक गिरिडीह शहर, चतरो, श्रीरामपुर, मोहनपुर और पारसनाथ में लोगों से मिला। इस दौरान धान कटाई का समय चल रहा था। ज्यादातर लोग या तो खेतों में थे या काम की खोज में घर-गांव से बाहर थे। गिरिडीह जिला क्षेत्र में एक फसल की खेती मुख्य है और यह

लगभग पूरी खेती की जमीन का लगभग 60 प्रतिशत है। मात्र डेढ़ प्रतिशत खेती योग्य जमीन पर दो फसल होती है। पिछले कुछ सालों से सब्जी का उत्पादन पर जोर बढ़ा है। पिछले बीस सालों में तीन बार सुखाड़ की स्थिति पैदा हुई। फैक्टरियों की वजह से पोखरों के पानी का जल्द सूख जाना, छोटे छोटे नालों में कचड़ा बहाने की वजह से पानी का पारम्परिक स्रोत कम होते गये हैं। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जैसी योजना से पानी की समस्या का हल तो दूर इससे सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं। पानी का प्रबंधन न होने से गर्मियों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। ऐसे में खेती मुख्यत: मौसम पर निर्भर है और एक फसली होना एक नियति की तरह हो गया है। यदि इस खड़ी फसल को प्रदूषण भी खा रहा हो, तो यहां के हालात का अनुमान लगा सकते हैं।

इस इलाके में घूमते हुए कुछ गांव के लोगों और फैक्टरी मजदूरों से बात करना संभव हो पाया। महुआटांड़ गांव के लोगों ने बताया कि चतरो और श्रीरामपुर में जब फैक्टरियां खुल रही थीं, तब यहां की फैक्टरियों के मालिकों और प्रशासन ने जमीन पर काबिज होते हुए वादा किया था कि यहां के गांव के लोगों को नौकरी दी जायेगी, स्कूल और अस्पताल खुलेंगे और उचित मुआवजा दिया जायेगा। चतरो में 'मजदूर संगठन समिति' का कार्यालय है। इस संगठन के चतरो सचिव कन्हाई पाण्डे बताते हैं कि 'ये सिर्फ खोखले वादे थे। यहां किसी भी फैक्टरी में स्थायी मजदूर के रूप में नियुक्ति नहीं की गई। ट्रांसपोर्ट, ढुलाई, लदाई, कचरा छंटाई जैसे काम ही स्थानीय लोगों को दिया जाता है। यह सब कैजुअल मजदूरी है। मालिक न्यूनतम मजदूरी भी देना नहीं चाहते। मजदूर संगठन समिति के आंदोलनों से ही मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलना शुरू हुआ। आज भी फैक्टरीयों में 70 प्रतिशत मजदूर बाहर के हैं और 30 प्रतिशत स्थानीय हैं। जो बाहरी मजदूर हैं, उनको गिरिडीह शहर में अलग-थलग लॉज में रखा जाता है। उन्हें अन्य मजदूरों और संपर्कों से काटकर रखा जाता है। स्थानीय मजदूरों को कभी भी काम न होने की शर्त पर गेट से वापस कर दिया जाता है।' वह बताते हैं कि '2007 से गांव के लोगों ने आवाज उठानी शुरू की, हमारा संगठन भी इस आंदोलन में शामिल हुआ। आंदोलन लंबे समय तक चला। अधिकारी से लेकर मीडिया तक आया लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। कुछ छह-सात साल के प्रयास के बावजूद जब कुछ नहीं हुआ तो गांव के लोग निराश हुए और बहुत से लोगों ने गांव छोड़कर जाना भी शुरू कर दिया।' आज भी न तो चतरो में और न ही श्रीरामपुर में कोई अस्पताल है। गिरिडीह में एक सरकारी अस्पताल है। इन दोनों ही इलाकों को जिसमें सर्वाधिक फैक्टरियां है, चालबाजी के साथ ईएसआई के दायरे से बाहर रखा गया है।

इन फैक्टरियों को कोयला गिरिडीह और झारखंड के खदानों से मिलता है जबकि लौह अयस्क ओड़िशा से आता है। पिछले कुछ सालों से जापान अपने यहां लौह अयस्क और कोयले का पहाड़ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर यहां से खनिजों की खरीदारी कर रह रहा है। इससे लौह अयस्क के दाम में बढ़ोतरी हुई है। फिर भी बैंक से कर्ज, श्रम का भयवाह शोषण, सामाजिक जिम्मेवारियों से मुक्ति और पर्यावरण और मानव जीवन को बर्बाद करने वाली तकनीक के लगातार उपयोग से ये फैक्टरियां न सिर्फ चल रही हैं बल्कि मालिकों का मुनाफा बढ़ा रही हैं। फैक्टरियों में न्यूनतम 12 घंटे की एक शिफ्ट होती है, जिसके बदले उन्हें 250 से 300 रूपये की मजदूरी मिलती है। स्थायी मजदूरों को इसके लिए 500 रूपये मिलता है। यह मजदूरी भी 2004 से लेकर 2006 तक 'मजदूर संगठन समिति' के नेतृत्व में लड़ने के बाद मिला। इस मजदूर यूनियन के महासचिव बच्चा सिंह बताते हैं कि मजदूरों को सिर्फ वहीं पर बोनस मिल सका, जहां हमारी यूनियन है। कुल चार फैक्टरियों में ही मजदूरों को बोनस मिल सका है। आज भी मजदूरों को सेफ्टी के लिए जूता, हेल्मेट, चश्मा, वर्दी आदि उपलब्ध नहीं कराया जाता। कुछ समय तक दो फैक्टरियों ने एक महीने के हिसाब से 3 किग्रा चना और दो किग्रा गुड़ मिला, बाद में वह भी बंद हो गया। फैक्टरी की भट्ठी पर काम करना सबसे अधिक जोखिम का काम होता है। उनकी सुरक्षा के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। चतरो से सटा हुआ एक गांव महुआटांड़ के रहने वाले एक मजदूर चंदन टुडु बताते हैं कि 'फैक्टरी का कचरा एक ट्रक भरने में, लगभग 50-55 टन के एवज में कुल 600 रूपये मिलते हैं और इसमें कुल चार मजदूरों को लगना होता है। यानी लगभग 150 रूपये प्रति मजदूर। यह काम भी अधिक नहीं मिलता।' मजदूर संगठन समिति के सचिव कन्हाई पांडे बताते हैं कि 'पहले दुर्घटना होने पर फैक्टरी मालिक घायल या मृत मजदूर को सड़क पर या जंगलों में फेंक आते थे।' मजदूर बताते हैं कि इस तरह की आपराधिक कृत्य के सहयोग में पुलिस भी शामिल रही है। लेकिन बाद के समय में गांव के लोगों और मजदूरों ने एकताबद्ध होकर मालिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मजदूरों ने बताया कि 2009 में अतिबीर फैक्टरी में एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस के सहयोग से उसका अंतिम दाह-संस्कार की तैयारी भी कर ली गई थी। लेकिन मजदूरों ने उन्हें पकड़ लिया और न्याय की लड़ाई में परिवार के लिए कुछ मुआवजा दिला सका। आज इस इलाके में फैक्टरियों का उत्पादन बढ़ा है, नई तकनीक आई है लेकिन धुंआ और राख उगलते इन फैक्टरियों में बीसियों साल पुरानी उस तकनीक का प्रयोग अब भी नहीं हो रहा है, जिससे यहां के गांवों और पहाड़ों को राहत मिल सके। इस इलाके में एक समय में 20 से 25 हजार मजदूर काम करते थे लेकिन अब यह संख्या सिर्फ 10 हजार के आसपास रह गई। इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी पहले से भी कम हो गई है। स्थानीय लोग मजबूर होकर काम के लिए बाहर जा रहे हैं।

ये फैक्टरियां पानी के स्रोत के लिए जमीन के नीचे के पानी का दोहन बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। लगभग 25 सालों में इन फैक्टरियों ने इस कदर पानी को खींच निकाला है कि आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे में पानी हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। फुलची गांव के तुलसी तुरी बताते हैं कि 'तालाब गर्मी के आने के पहले ही सूख जाते हैं। चापाकल के लिए बहुत गहरे 100 फीट पाईप डालना होता है। तब भी गर्मी के महीने में पानी नहीं आता। जबकि पहले 20 से 25 फीट गहरे में पानी मिल जाता था। कपड़ा धोने, नहाने के लिए कई किलोमीटर दूर उसरी नदी पर जाना होता है। पीने के पानी के लिए काफी दूर जाना होता है।'

इन फैक्टरियों ने यहां सिर्फ जीवन का स्रोत ही नहीं सुखाया है बल्कि यहां की जमीनों की लूट भी की है। मोंगिया की स्पंज आयरन कंपनी ने लालपुर नदी को एक काले बहते नाले में बदल दिया है। इस नदी के किनारे के श्मसान घाट और उससे सटी 22 एकड़ जमीन को कब्जे में ले लिया। इसी तरह एक और फैक्टरी मालिक ने इसी इलाके में गोचर जमीन का 20 एकड़ कब्जा कर लिया। श्मसान घाट के पुजारी भुवनेश्वर राणा बताते हैं कि श्मसान की पूरी जमीन को कब्जा कर उसे फैक्टरी के गैराज में बदल दिया गया है और अब सिर्फ मंदिर के लिए एक छोटी सी जगह ही बच गई है। भुवनेश्वर राणा को श्मसान की जमीन हासिल करने के एवज में पांच पर जेल हो चुकी है और पुलिस और गुंडों की पिटाई अलग से है। लेकिन अब भी अपनी ही जमीन से वे बेदखल हैं। फैक्टरी मजूदरों के लिए जवाहर लाल नेहरू पार्क बनाया गया लेकिन अब यह भी मुन्नालाल नामक जमीन माफिया के कब्जे में है। यह पार्क जिला कारागार से सटा हुआ है। झिरिया गांव के राजेन्द्र कोल बताते हैं कि 'इस इलाके की गैरमजरूआ जमीन का 75 प्रतिशत इन फैक्टरियों और भू-माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है।' गंगापुर गांव के कालीचरण सोरेन बताते हैं कि '1994-95 की बात है, दलालों के माध्यम से जमीनों की लूट हुई। 15000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन लिया गया और वादा किया गया कि स्कूल और अस्पताल खुलेंगे, रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।'

धुंआ और राख भरे दिन और रात कटते कटते आज वहां के लोग 20 साल से ऊपर की जिंदगी गुजार चुके हैं। पेड़, जंगल, पौधों, बाहर टंगे कपड़े, ...सब कुछ काला है। जानवरों के रंग बदरंग दिखते हैं। घर की छतें काली हैं। यहां काम करने वाले लोग कालिख से पुते होते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि बरसात के दिनों में कई दिनों तक सिर्फ काला पानी बहता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जानवर क्या खाते होंगे और उनकी दशा क्या होगी! गांव के लोग बताते हैं कि जानवरों को अक्सर गला घोंटू रोग होता है और मर जाते हैं। सब्जी उगाना मुश्किल हो चुका है। साल भर में एक ही फसल होती है। इसका उत्पाद भी आधा हो चुका है। यहां के गांव में, इन गांवों की जनसंख्या 200 से 300 तक होती है, में पांच से सात टीबी के मरीज हैं और इससे मौत की संख्या भी बढ़ रही है। अब महुआटांड़ गांव में दो ऐसे बच्चों का जन्म हुआ है जिसमें से एक की आंख की बनावट ही नहीं है और दूसरे की जीभ नहीं है। इसी तरह गंगापुर गांव में एक बच्चे का जन्म से ही एक हाथ नहीं है जबकि दूसरे बच्चे का पैर टेढ़ा-मेढ़ा है। इन बच्चों के जन्म के बाद से इस इलाके के लोगों में दहशत और गुस्सा बढ़ गया है। महुआटांड गांव के लोगों ने इस प्रदूषण को रोकने के लिए 2009 में हुए विधानसभा चुनाव का वोट बहिष्कार किया। इस बात का प्रचार होने के बावजूद भी इस संदर्भ में आगे किसी ने भी कार्यवाही नहीं की।

इलाके में काम कर रहा 'मजदूर संगठन समिति' ही है, जो किसानों, मजदूरों और अन्य प्रभावित लोगों के लिए काम कर रहा है। इस संगठन का एक कार्यालय चतरो में ही खुला हुआ है, जहां सबसे अधिक प्रदूषण है। इस इलाके में यह संगठन 2002 से सक्रिय हुआ। गांव के मजदूर और आदिवासियों पर जमींदारों का कब्जा इस कदर था कि उन्हें उनकी जमीनों पर गुलामों जैसा काम करना पड़ता था। 'मजदूर संगठन समिति' के संघर्ष से उन्हें कुछ मजदूरी हासिल होना शुरू हुआ। 2010 तक आते-आते इस संगठन ने फैक्टरियों में मजदूर के शोषण उत्पीड़न के खिलाफ गोलबंदी किया और न्यूनतम मजदूरी, बोनस और मुआवजा की लड़ाई को लड़ा। फैक्टरी मालिकों की गुंडागर्दी पर रोकथाम लगी। 2010-2013 के बीच 'मजदूर संगठन समिति' और अन्य संगठनों के नेतृत्व में गिरिडीह जिला प्रशासन, राज्यपाल, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल आदि को ज्ञापन दिया गया, प्रदर्शन किया गया लेकिन आज भी यहां के लोग 'ऊपर' से होने वाली कार्यवाही का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान मीडिया के लोग भी आये लेकिन अब भी यहां की आवाज अनसुनी ही है।

आज जब दिल्ली का प्रदूषण राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुका है, कुल मौतों की 30 प्रतिशत जिम्मेवारी प्रदूषण के हिस्से आया है और सर्वोच्च न्यायालय 2008 के पर्यावरण के मानकों पर पुनर्विचार करने के लिए नई कमेटी गठित करने का आदेश दे चुका है। तब निश्चय ही यह जिम्मेदारी बनती है कि गिरिडीह और ऐसे ही शहर, गांव के लोगों को जिंदा रहने के अधिकार पर बात हो, मौत का साया बने धुंध, धूल, धूंआ व कचड़ा फेंक रही फैक्टरियों पर अंकुश लगाया जाय और जरूरत हो तो उसे बंद किया जाय।

रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन 'मजदूर संगठन समिति' पर प्रतिबंध का विरोध करें!

-सम्पादकमण्डल, लाल चिनगारी

कविताएं

कॉलेज में पढ़ने वाली एक कामरेड द्वारा भेजी गई एक कविता

हमारे खून का रंग लाल है
क्योंकि हमारा इतिहास लाल भूमि पर तैयार है।
हमारे अपनों ने अपने खून से
हमारे झंडे का रंग लाल किया है
इसलिए हम अपने खून से इस रंग को
और गहरा करने की लेते हैं शपथ।

हमें खेद है, अपने उन साथियों पर
जिन्होंने शपथ तो खाई थी
इस रंग को और गहरा करने की
लड़े भी कभी इस झंडे के लिए
मगर डर गये दुश्मनों के तेज वार से
कर लिया अपने खून का रंग सफेद
जबकि हम जानते हैं
यह तो युद्ध का नियम है
कभी दुश्मनों के वार कमजोर पड़ेंगे
तो कभी दुश्मन तीव्रता के साथ चोट करेंगे,
पर क्या उससे हम डर जाएं,
घृणा है हमें इस सोच से।
वे डरे हुए हमारे साथी
शायद भूल गये अपनी शपथ को
और भूल गये अपने ही साहस को भी
जो उन्होंने लड़ते वक्त दिखाई थी।

लाल भूमि के सिपाही
भला कैसे डर सकते हैं
किसी भी दमन से।
हमारे अपनों ने बहाया है खून,
आगे भी हमारे अपनों का ही बहेगा खून
इस शोषित समाज में।
कैसे कर सकता है दगा
कोई अपनों के खून से
खेद है उन साथियों पर।

जब दुश्मनों का वार तेज हो
तब तो हमें रहना है और भी निर्भीक
ढूंढना है सटीक जवाब दुश्मन के वार का
देते हैं लालच वे आत्मसमर्पण के लिए
पर क्या कोई दौलत साथियों के खून से बड़ा है?
हमारे साथियों के खून का जो कतरा
उस लाल झंडे में है मौजूद
क्या उस गौरव से कुछ बड़ा है?
नहीं, नहीं, एकदम नहीं।
हमारा गौरव हमारा झंडा है,
हमारी क्रांति है, हमारी लड़ाई है।

कर रहें हैं वे भर्ती,
हमारे अपने ही भाईयों को फोर्स में
पर बताना है, समझाना है हमें
अपने अनभिज्ञ भाइयों को
हकीकत क्या है?
वे डर का माहौल पैदा करके
बनाते है हमारे ही भाइयों को
लड़ाई का गद्दार,
दिखाना है हमें अपने साथियों को
असली तस्वीर।
हमें बदलना है प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल में
क्योंकि हम जानते है
अनुकूल-प्रतिकूल का नियम।
इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति से
हम हताश नहीं हो सकते
ढूंढ सकते है उसमें अनूकूल बनाने की स्थिति
क्योंकि हमारा खून लाल है,
जिस लाल रंग से रंगा है हमारा झंडा,
रंगी है हमारी धरती
और रंगी है हमारी लाल क्रांति।

एक पीएलजीए कामरेड द्वारा पहली बार लिखी गई तीन कविताएं

पीएलजीए और पुलिस में फर्क

अरे,
तुम भी पुलिस के विभिन्न नामों के जवान कहलाते हो
मैं भी जन मुक्ति छापामार सेना कहलाता हूं
तेरे हाथ मे भी बंदुक है, तुम भी ट्रेनिंग लिये हो
मेरे हाथ मे भी बंदुक है, मैं भी ट्रेनिंग लिया हूं
बस फर्क इतना है,
सरकार तुझे बंदुक दिया है, मुझे मारने के लिए
मुझे संगठन से बंदुक मिला है, जनता की रक्षा के लिए।

तुम भी किसी गरीब मेहनतकश किसान का बेटा हो
मैं भी किसी गरीब मेहनतकश किसान का बेटा हूं
तुम भी किसी मां का दूध पीकर बड़े हुए हो
मै भी किसी मां का दूध पीकर बड़ा हुआ हूं
तुम मुझे देखकर पहले गोली मारोगे, तो मैं मरूंगा
मैं तुझे देखकर पहले गोली मारूंगा, तो तुम मरोगे
कहीं तुम यह तो नहीं सोचते हो,
कि तुम्हारी बंदुक से मौत निकलेगी
और माओवादियों की बंदुक से खिलता हुआ गुलाब
जो तुम्हारे गाल को जाकर चुमेगा।

सभी पुलिस वालों से हमारा आह्वान है,
भ्रम में रहना छोड़ दो
रोज दिन मारे जा रहे हो और भी मारे जाओगे
मरोगे तो तुम्हें हत्यारा सरकार शहीद का दर्जा देगी
मै मरूंगा तो जनता मुझे शहीद का दर्जा देगी
जब तेरे बारे में लोग पूछेंगे, कैसे मौत हुआ?
तब जनता कहेगी
सरकार का पालतू कुत्ता बनकर काम कर रहा था
जिसके कारण माओवादियों ने मार गिराया
जब मेरे बारे में लोग पूछेंगे, कैसे मौत हुआ?
जनता सर उठाकर कहेगी
गरीब जनता के हक, इज्जत, अधिकार व आजादी के लिए
गरीब जनता के दुश्मन से लोहा लेते हुए
युद्ध के मैदान में अपना जान कुर्बान किया।

नारी

मैं एक नारी हूं
मैं जन्म से ही मां-बाप का बोझ बन जाती हूं
तरह-तरह की ठोकर खाती हूं
दर-दर भटकती रहती हूं।

मैं एक नारी हूं
मैं समाज के बंधन में बंधी हूं
समाज के नजर से ही खुद को देखती हूं
जन्म के बाद से ही पिता-भाई के अधीन में रहती हूं।
मैं एक नारी हूं
शादी के बाद पति से मार खाती हूं
दुनिया की नजर में
बच्चा पैदा करनेवाली मशीन हूं
डायन भी बन जाती हूं
डायन बताकर समाज से बहिष्कृर हो जाती हूं।

मैं एक नारी हूं
दुनिया की सभी नारी
भोग की एक वस्तु की तरह इस्तेमाल होती है
गरीब माँ-बाप की बेटी के कारण
और दहेज प्रथा के कारण
कुआं में कूद कर, केरोसिन डालकर जलाकर
फांसी में झूलाकर मारी जाती हूं।

मैं एक नारी हूं
मैं अकेले कहीं नहीं जा पाती हूं
हमेशा समाज के बंधन में रहती हूं
अकेले हाट-बाजार, मेला, कॉलेज जाने में
घर से पाबंदी लगायी जाती है
दुनिया की हालत देखकर अकेले घूमने से डरती हूं
कुछ दरिंदों द्वारा गैंग-रेप से डरती हूं।

मैं एक नारी हूं
पुरूष प्रधान सत्ता से दबी हुई हूं
दुनिया को बनाने में भी
मैं अहम भूमिका निभायी हूं
फिर भी हमें समान अधिकार नहीं है
पुरूषों के समान मैं भी काम करती हूं
फिर भी पुरूषों के समान मजदूरी नहीं पाती हूं।

हां, मैं एक नारी हूं
बहुत सहा लेकिन अब नहीं सहूंगी
देश में जारी नवजनवादी क्रांति में कुदूंगी
हमें जब तक अपना मंजिल न मिले, लड़ते रहूंगी
और आगे बढ़ती रहूंगी, हिम्मत नहीं हारूंगी
क्योंकि क्रांति के बिना
संपूर्ण नारी मुक्ति नहीं हो पाएगी।

ऐसी है मोदी-रघुवर सरकार

भारत के प्रधानमंत्री मोदी सरकार
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर सरकार
जब से बनी है इनकी सरकार
पूरे भारत देश में मचा दिया है हाहाकार
दोनों ही साम्राज्यवादियों का है चाटुकार।

दोनों अपना-अपना भाषण में है कहता
पूरे भारत में विकास के है नदी बहती
मोदी जब-जब लंबा भाषण है देता
या घंटों-घंटों मन की बात है करता

एक बात कहने को कभी नहीं है भूलता
हर दस मिनट में
मेरे भाइयों और बहनों जरूर है कहता
मोदी जब भी भाषण में है बोलता
जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला कर है बोलता
मोदी हर भाषण में और एक बात
कभी नहीं है भूलता
मैं हूं नरेंद्र मोदी गरीब किसान का बेटा
मैं पहले होटल में चाय था बेचता।

सच तो सब है जानता
मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद
साम्राज्यवाद का बन गया है कुत्ता
तभी तो प्रधानमंत्री बनने के बाद
10 लाख रूपये का कोट है पहनता
और पूरे देश की जनता को है दिखाता
फिर भी कहता है मैं हूं गरीब किसान का बेटा।

मोदी अपने आप को कहता है सबसे बड़ा जादूगर
पूरे देश में चलता है भाजपा का चमत्कार
भाजपा सरकार बनने के बाद
सबसे ज्यादा हो रहा है बलात्कार
रघुवर कहता है मैं हूं झारखंड का सरकार
रघुवर कहता है मैं कर दूंगा झारखंड का चमत्कार
झारखंड में गैर-आदिवासी का है सरकार
विकास के नाम पर आदिवाासियों की
जिंदगी कर दिया बेकार
पूरे भारत में माओवादियों को खत्म करने के नाम पर
मिशन-2017 के तहत ऑलआउट ऑपरेशन के नाम पर
मेहनतकश गरीब आदिवासी जनता पर
चला रहा है शोषण-जुल्म और अत्याचार।

जनता आज विवश होकर
रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भटक रहा दर-दर
भारत सरकार गरीबों के तकलीफों से है बेखबर
रघुवर सरकार डींग हांककर बोलता है
मेरा झारखंड सबसे सुंदर
कहता है झारखंड सरकार
झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्र में
माओवादियों का खात्मा कर करूंगा विकास
विकास के नाम पर रोड, बिजली, घर, डैम बनाकर
आदिवासियों को गुमराह करके
जगाना चाहता है अपना विश्वास
जगह-जगह में विस्थापन कर आदिवासियों का
कर रहा है सत्यानाश
करोड़ों-करोड़ मेहनतकश जनता
अपने पीएलजीए पर रखता है विश्वास
जनमुक्ति छापामार सेना को देर नहीं लगी समझने में
दोनों सरकार का चाल
मेहनतकश गरीब जनता के बीच दोनों ही सरकार के
चालाकी का कर दिया पर्दाफाश।

कौन रोक सकेगा?

('सिंगरेणी मजदूर आंदोलन का इतिहास' नामक तेलुगू किताब से साभार)

पानी का बहने का गुण है
बहनेवाली पानी को बांध बनाकर रोकने से
जमीन के भीतर से आगे बढ़ने का गुण है।
गर्मी अपना तेवर दिखाने से- रूप बदलकर
भांप बनकर, बादल का रूप लेकर,
कई जगहों में बरसने का गुण है
बांधों को भी तोड़कर बहने की शक्ति है।
अवरोध व कितने भी बाधाएं आने से भी
टेढ़े-मेढ़े, घुमावदार, भंवर के जैसा घूमते हुए
लक्ष्य तक पहुंचने का भी गुण है
भू-गर्भ में भी वह बहती है
माहौल के अनुसार
वे ठोस, हवा, द्रव का रूप लेती है
बूंद-बूंद का बारिश बनकर,
धारा-धाराओं में बहते हुए,
नदी-नालाएं मिलकर
नदी, महानदियां बहकर
छन-छनकर महानदियां अपने मंजिल की ओर बढ़ती है।
हथेली को बढ़ाकर सूरज की रोशनी को कौन रोक सकेगा
जनशक्ति को, बहने के गुण को कौन रोक सकेगा?

दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करना गुलामी के बराबर है! रंग-बिरंगे लालच दिखाकर अपने पक्ष में झुकाने की दुश्मन की एल.आई.सी. नीति का मुंहतोड़ जवाब दें!

महत्वपूर्ण बुकलेट व पर्चे

सीएमसी द्वारा पीएलजीए सप्ताह (2-8 दिसम्बर, 2017) पर जारी बुकलेट

पूरे देश में छापामार युद्ध-जनयुद्ध को तेज व विस्तार करें!

भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का सफाया के लिए दुश्मन द्वारा जारी प्रतिक्रांतिकारी व नया रणनीतिक हमला 'समाधान' (2017-2022) को परास्त करें!

प्रिय कामरेडो व जनता!

वर्ष 2000 के 2 दिसम्बर, भारतीय क्रांति का ऐतिहासिक दिवस है। साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद और सामंतवाद के शोषण व उत्पीड़न से देश के उत्पीड़ित जनता की मुक्ति के लिए भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में जनमुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) के निर्माण का यह दिन समूचे देश की जनता को सदा याद रखने का दिवस के रूप में बन गया है। हमारी पार्टी के संस्थापक, शिक्षक व भारतीय क्रांति के महान नेता अमर शहीद कामरेड चारू मजुमदार और कामरेड कन्हाई चटर्जी के दिशा-निर्देशन में हमारे प्रिय नेता व अमर शहीद कामरेड्स श्याम, महेश व मुरली के प्रेरणा से, हजारों शहीदों की शहादत से उर्जावान हो देश तथा दुनिया के उत्पीड़ित जनता के अधूरे सपनों को साकार करने हेतु उस दिन पीएलजीए की स्थापना हुई।

अगले 2 दिसम्बर को हमारे वीर पीएलजीए के 17 वर्ष पूरे होने जा रहा है। इस अवसर पर सभी पार्टी कमेटियों व कमानों, पार्टी सदस्यों, पीएलजीए के साहसिक कमांडरों व योद्धाओं, जन मिलिशिया बलों, क्रांतिकारी जन सरकारों व जन संगठनों के नेता व कार्यकर्ताओं तथा उत्पीड़ित जनता को केन्द्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी), भाकपा (माओवादी) लाल अभिवादन पेश करता है। पिछले एक साल में देश भर में ऑपरेशन ग्रीन हंट के प्रतिक्रांतिकारी हमले को परास्त करने के लिए चौतरफा (राजनीतिक, सैनिक व सांगठनिक आदि के तौर पर) प्रतिरोध करने के प्रयास में शामिल सभी कामरेडों को सीएमसी क्रांतिकारी अभिवादन पेश करती है। बुरकापाल सहित विभिन्न साहसिक हमलों को सफलतापूर्वक अंजाम देने के क्रम में अपनी जान न्योछावर करने वाले वीर छापामार योद्धाओं को, कई मुठभेड़ों, फर्जी मुठभेड़ों में, भीतरघात व दुश्मन के कोवर्ट ऑपरेशनों में, दुर्घटनाओं में, जेलों में, सर्पदंश, बीमारी आदि कारणों से जान गंवाने वाले सभी अमर शहीदों को विनम्रतापूर्वक क्रांतिकारी श्रद्धांजली अर्पित करती है। उनके कम्युनिस्ट मूल्यों, साहसिकता, निडरता, जनता के प्रति उनके समर्पि भावना से हम सब सीख व प्रेरणा लेते हुए, उनके अध ूरे सपनों व अरमानों को पूरा करने का शपथ लेंगे। सीएमसी का विश्वास है कि पूरे देश में संचालित छापामार युद्ध कार्रवाइयों में घायल हुए कामरेड शीघ्र स्वस्थ होकर जुझारूपूर्ण जोश के साथ फिर से युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ेंगे।

इस अवसर पर 2 से 8 दिसम्बर तक समूचे देश में संघर्षरत सभी इलाकों में, गांवों व शहरों में पीएलजीए के 17वीं वर्षगांठ को क्रांतिकारी जोश व उत्साह के साथ मनाने का पार्टी के तमाम कतारों, पीएलजीए यूनिटों, क्रांतिकारी जन सरकारों व जन संगठनों व जनता को सीएमसी आह्वान करती है। दुश्मन द्वारा जारी प्रतिक्रांतिकारी व नयी रणनीतिक हमला 'समाधान' (2017-2022) को परास्त करने के लक्ष्य से पीएलजीए को संगठित करने के सहायतार्थ इस अवसर पर पूरे देश के पैमाने पर पूरा दिसम्बर माह में भर्ती अभियान संचालित करने का आह्वान करती है।

भारत की नव जनवादी क्रांति को सफल बनाने और एकता कांग्रेस-9वीं कांग्रेस द्वारा निर्देशित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एकात्म होकर और पूरजोर प्रयास करते हुए, ऑपरेशन ग्रीन हंट हमले को परास्त करने के लिए लड़ते हुए इस वर्ष लगभग 140 कामरेड शहीद हुए। इनमें 30 महिला कामरेड भी शामिल हैं।

इनमें हमारे पार्टी के दो केन्द्रीय कमेटी सदस्य के साथ-साथ डीके में 98, बीजे में 19, तेलंगाना में दो, एओबी में 7, ओड़िशा में दो, पश्चिम बंग में एक, एमएमसी में दो, पश्चिमी घाटियों में एक कामरेड शामिल हैं। इनमें तीन राज्य कमेटी स्तर के कामरेड, सात जेडसी/डीवीसी कामरेड, तीन सब-जोनल कमेटी के कामरेड, 22 एसी/पीपीसी कामरेड, 50 से ज्यादा पार्टी व पीएलजीए के सदस्य, लगभग 40 क्रांतिकारी जन सरकारों व संगठनों तथा मिलिशिया कार्यकर्ता और लगभग 15 क्रांतिकारी जनता शामिल हैं।

इन शहीदों में भारतीय क्रांति के नेता व हमारे पार्टी के केन्द्रीय कमेटी के सदस्य कामरेड नारायण सन्याल (विजय दा, पोलित ब्यूरो सदस्य) और कामरेड कुप्पु देवराज (रमेश, योगेश), राज्य कमेटी स्तर के कामरेड रघुनाथ महतो (बीजे सैक सदस्य), हिमाद्रि राय (पश्चिम बंग के एससी सदस्य), अजिता (कावेरी, पश्चिमी घाटी एसजेडसी सदस्या) शामिल हैं।

पीएलजीए के 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस साल भर में अपनी जान न्योछावर करने वाले सभी अमर शहीदों को याद करते हुए, विनम्रतापूर्वक शिश झुकाकर उन्हें क्रांतिकारी

जोहार पेश करते हैं। उनके अरमानों को पूरा करने के लिए आखिरी दम तक लड़ने की शपथ लेते हैं।

मिशन-2017 को परास्त करने के लिए देश भर में हमारे द्वारा संचालित राजनीतिक, सैनिक व सांगठनिक प्रयास व उसके परिणाम :

समूचे देश में क्रांतिकारी आंदोलन का उन्मूलन के लिए केन्द्र व राज्य सरकारें 2014 की शुरूआत से ही ऑपरेशन ग्रीन हंट के तीसरा चरण का हमला प्रारम्भ किया है। लेकिन नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए (नेशनल डेमोक्रटिक एलायन्स-राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) केन्द्र की सत्ता में आने के बाद पूरे देश में ये हमले और ज्यादा फासीवादी रूप लिया है तथा और तेज व व्यापक रूप में जारी है। मिशन-2016 को हमारे पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए-जन मिलिशिया, क्रांतिकारी जन सरकार व जन संगठन तथा क्रांतिकारी जनता चौतरफा प्रत्याक्रमण की कार्यनीतियों के जरिए मुकाबला करते हुए परास्त किया है। इसके बाद दुश्मन द्वारा मिशन-2017 की योजना बनायी गयी। हमारे आंदोलन के शक्ति-क्षमताओं के आधार पर देश भर में राजनीतिक, सैनिक व सांगठनिक प्रयास को तेज करके मिशन-2017 को एक हद तक रोकने में हम कामयाब हुए हैं। इसमें महत्वपूर्ण है- शोषक-शासक वर्गों के प्रतिक्रांतिकारी युद्ध का प्रतिरोध करते हुए जारी जनयुद्ध व छापामार युद्ध। इसके साथ-साथ रोजमर्रा व मौलिक समस्याओं पर जन आंदोलन को संचालित करना, संयुक्त मोर्चे की गतिविधियां बढ़ाना, विस्थापन विरोधी आंदोलनों को तेज व व्यापक करना आदि दुश्मन के हमले का मुकाबला करने में बहुती-ही मददगार साबित हुआ है। पार्टी और सैनिक क्षेत्रों में सभी स्तरों में नेतृत्वकारी शक्तियों को शिक्षित करने के लिए नेतृत्वकारी प्रशिक्षण (Leadership Training) कैंपों को संचालित करने, नए कार्यनीतियों को बनाने के लक्ष्य से सामाजिक शोध करने, कृषि क्रांतिकारी कार्यक्रमों व क्रांतिकारी सुधारों को लागू करके बेहतरीन परिणाम हासिल किये हैं।

अब मिशन-2017 को परास्त करने के लिए पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए और क्रांतिकारी जनता द्वारा संचालित जनयुद्ध व छापामार युद्ध कार्रवाइयों के ब्योरा पर नजर डालेंगे।

इस वर्ष डीके में 72 पुलिस, अर्धसैनिक व कमांडो बलों का सफाया कर 96 पुलिस वालों को घायल किये गये हैं। दुश्मन के से 21 एके-47 रायफलों सहित 35 आधुनिक हथियार, लगभग 3,500 कारतूस जब्त किए हैं। इसी दौरान 40 पुलिस मुखबिरों, दो जन दुश्मनों और छः दुश्मन के दलालों का सफाया किया गया है। जनता को विस्थापित करने वाले विभिन्न दलाल कार्पोरेट वर्गों के परियोजनाओं को रोकने के लिए कई जगहों पर रोड, पुल, मोबाइल टॉवर, रेल लाइन, गाड़ियों व इमारती लकड़ी को जला दिया गया और ध्वस्त किया गया।

डीके में संचालित जवाबी प्रत्याक्रमण अभियानों (TCOC) और प्रतिरोध कार्रवाइयों के तहत चार बड़े कार्रवाइयां - कोत्ताचेरुवु, बुरकापाल, कारमपल्ली, तोंडामरका हुई हैं। इनके साथ-साथ कई छोटे व मझौले कार्रवाइयां हुई हैं। ये कार्रवाइयां, खासकर बुरकापाल एम्बुश समूचे देश के क्रांतिकारी शिविर को ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी क्रांतिकारी शिविर में नयी उमंग व विश्वास बढ़ायी हैं। इसी तरह दुश्मन के बलों के मनोबल पर गम्भीर चोट पहुंचायी हैं।

डीके में संचालित टीसीओसी और प्रतिरोध कार्रवाइयां मिशन-2017 का दबर्दस्त व मुहतोड़ जवाब दिया। इन कार्रवाइयों के साथ-साथ देश भर में संचालित छापामार युद्ध कार्रवाइयों के साथ-साथ इनकी सफलता की नींव रखने वाला जन आधार की व्यापकता और आज की देशीय व अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति को ध्यान में रखकर दुश्मन अपने रणनीतिक मिशन-2017 में बदलाव लाना पड़ा और 'समाधान' के नाम पर अगले पांच वर्षों (2017-2022) में भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को उन्मूलन करने की नयी प्रतिक्रांतिकारी योजना और रणनीति व कार्यनीति को तय करना पड़ा।

डीके में संचालित टीसीओसी व प्रतिरोध कार्रवाइयां छामापार आधार क्षेत्रों (गुरिल्ला बेस) की रक्षा करने में मददगार साबित हुई। बुरकापाल जैसे बड़े कार्रवाइयां गुरिल्ला बेसों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वर्ष के टीसीओसी द्वारा व्यापक रूप से प्राथमिक स्तर के इंप्रूवाइज्ड आर्टिलरी निर्माण व इस्तेमाल बढ़ने के कारण नए अनुभव हासिल हुए हैं। स्नाइपर कार्रवाइयों की व्यापकता बढ़ी है। क्रांतिकारी आंदोलन के आपूर्ति के सभी तरह के स्रोतों को रोक कर पीएलजीए के युद्ध कार्रवाइयों की व्यापकता व तीव्रता को कम करने की केन्द्र व राज्य सरकारों की योजना के जवाब में डीके में छापामार युद्ध कार्रवाइयां नये अनुभव के साथ क्रांतिकारी शिविर में आत्मविश्वास बढ़ा रही हैं। पीएलजीए बलों को केन्द्रीकरण कर बुरकापाल की तरह संयुक्त ऑपरेशनों को संचालित करना, स्थानीय स्रोतों पर निर्भर होकर प्राथमिक स्तर के आर्टिलरी का निर्माण करना, स्नाइपरों को तैयार करना, इंप्रूवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसों के जरिए माइन युद्ध तंत्र को तेज व व्यापक करना आदि इस अवधि में डीके के छापामार जोन से हासिल नए अनुभव हैं। ये अनुभव देश भर में विभिन्न छापामार जोनों में व लाल प्रतिरोध इलाकों में पीएलजीए बलों को विकसित करने में मददगार होगी।

एओबी में 2016-2017 में संचालित टीसीओसी व प्रतिरोध कार्रवाइयों में 15 पुलिस मारे गये और 21 घायल हुए। इसमें मुंगारुगुम्मि-सुंकि एम्बुश बड़ी कार्रवाई थी। इसमें ओएसएपी (ओड़िशा राज्य के सशस्त्र पुलिस) के 9 जवान का सफाया और चार को घायल किया गया।

तेलंगाना में 2016-2017 में संचालित छापामार युद्ध

कार्रवाइयों में चार पुलिस मारे गये और तीन घायल हुए। लम्बे अंतराल के बाद तेलंगाना में छापामार कार्रवाइयों में पुलिस वालों को सफाया करने में कामयाब होना अच्छा बदलाव है।

मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ (एमएमसी) में 2016-2017 में संचालित छापामार युद्ध कार्रवाइयों में चार पुलिस को सफाया और तीन को घायल किया गया। ओड़िशा में एक पुलिस को सफाया कर सात पुलिस को घायल किया गया।

इस तरह मध्य रीजियन के डीके, एओबी, तेलंगाना, ओड़िशा और एमएमसी में पिछले डेढ़ वर्ष के समय काल में 96 पुलिस मारे गये और 134 घायल हुए।

पूर्वी रीजियन के बिहार-झारखण्ड, पूर्वी बिहार-पूर्वोत्तर झारखण्ड, पश्चिम बंग राज्यों में पिछले 10 महीनों में पीएलजीए द्वारा संचालित 40 से ज्यादा प्रतिरोध कार्रवाइयों में 12 पुलिस मारे गये और सात घायल हुए। एक जनविरोधी राजनेता और 10 प्रतिक्रांतिकारी तत्वों को सफाया किया गया। करोड़ों रूपयों के सरकारी, शोषक वर्गों और दलाल नौकरशाह कार्पोरेट कंपनियों के संपत्ति को ध्वस्त किया गया।

विगत 10 महीनों में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, झारखण्ड, एओबी, ओड़िशा, तेलंगाना, एमएमसी, पश्चिम बंग, पश्चिमी घाटियों के विभिन्न छापामार जोनों और लाल प्रतिरोध इलाकों में 200 से ज्यादा छापामार हमलों को पीएलजीए ने अंजाम दिया। इन हमलों में लगभग 110 पुलिस मारे गये और लगभग 135 पुलिस घायल हुए। लगभग 75 जन दुश्मनों, जन विरोधी राजनेताओं, प्रतिक्रांतिकारी तत्वों, मुखबिरों और कोवर्टों को सफाया किया गया। इसके साथ-साथ हमारे क्रांतिकारी इलाकों में हजारों जनता को गोलबंद कर सामंतवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी और विस्थापन विरोधी जन आंदोलन, राज्यहिंसा के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलन जिसमें बड़े पैमाने पर महिलाएं शामिल थीं, किये गये।

इस तरह अभी तक क्रांतिकारी इलाकों में अर्जित अनुभवों पर निर्भर होकर, डीके, बीजे आदि छापामार जोनों, लाल प्रतिरोध इलाकों और नए विस्तारित इलाकों में इन अनुभवों को ठोस परिस्थितियों के मुताबिक लागू करके, विभिन्न इलाकों में संचालित छापामार युद्ध को तेज व व्यापक करके, देश भर में बड़े पैमाने पर जनता को गोलबंद कर सामंतवाद विरोधी व साम्राज्यवाद विरोधी वर्ग संघर्षों को तेज करके हम नि:संकोच साफ-साफ एलान कर सकते हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी 2017-2022 नयी प्रतिक्रांतिकारी योजना को भी हम परास्त कर सकेंगे।

गत वर्ष 2016 से तुलना करें तो, इस साल (10 महीने में) देश भर में छापामार कार्रवाइयों में तीव्रता और व्यापकता में जरूर वृद्धि हुई है। इसके बावजूद दुश्मन के भीषण हमलों में हमारे पार्टी, पीएलजीए और आरपीसी-जन संगठनों के आत्मगत शक्तियों में भी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके साथ-साथ उल्लेखनीय संख्या में हमारे हथियार और कारतूस भी दुश्मन के हाथों में गया है। जैसे कामरेड लेनिन ने कहा है, वाकई में क्रांति प्रतिक्रांति का सामना करना जितना सही है, उस प्रतिक्रांतिकारी तत्वों को परास्त करके जनयुद्ध-गुरिल्ला युद्ध को आगे बढ़ना भी उतना ही सही है। दुश्मन की योजनाओं के मुकाबिले उसके समान जवाबी कार्यनीति बनाकर व्यवहार में उसे लागू करने के लिए हमारी सभी ताकतों को केन्द्रित करना, बोल्शेविक अभियान की रोशनी में विभिन्न गैर-सर्वहारा रूझानों के खिलाफ पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए को सुदृढ़ करने और बड़े पैमाने पर जनता को गोलबंद कर उन्हें हथियारबंद कर जनयुद्ध को तेज करके ही वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता है।

बुरकापाल एम्बुश के उपरान्त दुश्मन द्वारा बनायी गयी नयी प्रतिक्रांतिकारी योजना ही है 'समाधान' रणनीति :

बीते वर्ष में संचालित टीसीओसी और प्रतिरोध कार्रवाइयों के तहत देश भर में हमारी पीएलजीए द्वारा चलायी गयी छापामार युद्ध कार्रवाइयां दुश्मन के मिशन-2017 के खिलाफ जबर्दस्त प्रतिरोध खड़ा किया। विशेष कर, बुरकापाल एम्बुश के उपरान्त भारत के शोषक-शासक वर्ग और केन्द्र व राज्य सरकारों में बहुत हड़कंप मच गयी। तुरंत 8 मई को दिल्ली में केन्द्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजन की गयी और भारत के माओवादी आंदोलन को उन्मूलन करने के लिए नयी प्रतिक्रांतिकारी योजना-रणनीति व कार्यनीति बनायी गयी। इस प्रतिक्रांतिकारी योजना के मुताबिक अगले पांच वर्षों (2017-2022) में देश में माओवादी आंदोलन को उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रतिक्रांतिकारी योजना के रणनीति-कार्यनीति के मुख्य पहलू निम्न प्रकार हैं :

1. माओवादी विरोधी अभियानों में हिस्सा लेने वाले पुलिस, अर्धसैनिक व कमांडों बल आत्मरक्षात्मक तरीकों को छोड़ कर पूरी तरह आक्रामक हमले करने, माओवादी आंदोलन के मजबूत इलाकों के अंदर घुस कर हमले करने का निर्णय लिया गया है। यानी हमारे गुरिल्ला बेसों और रणनीतिक इलाकों पर केन्द्रीकृत हमले हो सकते हैं।
2. भारतीय वायुसेना और विभिन्न अर्धसैनिक बलों के एयरबोर्न (युद्ध विमान व हेलिकॉप्टरों से हमले करने वाले) बलों के हवाई हमले करने का निर्णय लिया गया है।

   हवाई हमले करने के लिए, माओवादी हमलों में घायल हुए पुलिस वालों को ले जाने के लिए 24 घंटे एयर सपोर्ट उपलब्ध कराने के तंत्र बस्तर संभाग के विभिन्न इलाकों में स्थापित कर रहे हैं। अगले दिनों में हमारे आंदोलन के मजबूत इलाकों/रणनीतिक इलाकों

में जरूरत के मुताबिक इस तरह के हमले करने के लिए एयर सपोर्ट उपलब्ध कराने के तंत्र स्थापित कर सकते हैं। इन सबों के आधार पर पीएलजीए के बलों पर रात में भी हमले तेज किये जा सकते हैं।

3. खुफिया तंत्र को और विस्तार व मजबूत करने का निर्णय लिया है। ह्यूमन इंटेलिजेन्स (मानव आधारित खुफिया तंत्र) सहित विशेष कर टेकनीकल और इलेक्ट्रोनिक इंटेलिजेन्स को विस्तार व मजबूत करने का निर्णय लिया है। यूएवी/ड्रोन, उपग्रह (सेटेलाइट), थार्मल इमेजिंग, इनफ्रारेड टेकनोलॉजी, सीसी टीवी कैमरा, रॉडारों को इस्तेमाल कर खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करने का निर्णय लिया है।

   हमारे लिए सिविल और फौजी सामग्री आपूर्ति करने और अन्य काम करने वाले लोगों को ढूंढ़ निकाल कर उन्हें मुखबिर-कोवर्टों के रूप में बदलने का प्रयास तेज कर सकते हैं। विभिन्न तरह के टेकनीकल और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेन्स तंत्र के जरिए पीएलजीए की गतिविधियों पर लगातार निगरानी तेज कर सकते हैं।

4. इन प्रतिक्रांतिकारी हमलों को सक्षम तरीके से संचालित करने के लिए अभी तक कोलकता में मौजूदा सीआरपीएफ के रणनीतिक कमान केन्द्र को रायपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है। अभी तक छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर में मौजूद एकीकृत कमान के साथ-साथ जिला स्तर में ऑपरेशनल और टैक्टिकल एकीकृत कमानों को गठित करने का निर्णय लिया है।

   इसके मुताबिक जिला स्तर में अभियानों के लिए योजना बनाने हेतु विभिन्न जिलों के नागरिक (सिविल) अधिकारी, अर्धसैनिक व वायुसेना के अधिकारी- सभी को मिला कर एकीकृत ऑपरेशनल कमानों को गठित करने के साथ-साथ उन अभियानों को क्षेत्र में संचालित करने के लिए जाने वाले सभी तरह के केन्द्र व राज्य बलों उच्च अधिकारियों के साथ कार्यनीतिक एकीकृत कमानों का गठन कर सकते हैं।

5. केन्द्र व राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय में खामियों को सुधार कर बेहतर समन्वय हासिल करने का निर्णय लिया है। इसके मुताबिक कंबैट ऑपरेशनों, सड़क निर्माण कार्य के लिए सुरक्षा, आरओपी आदि का अभियानों में शामिल होने वाले बलों के मदद में जरूर एक तिहाई राज्य के बल हिस्सा लेने और उन स्थानीय बलों को आगे रखने का निर्णय लिया है।

6. साम्राज्यवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के लूट के लिए जरूरी मौलिक सुविधाओं की स्थापना करने के लिए अपने द्वारा लागू की जाने वाली योजनाओं पर 'विकास' का मोहर लगाना और उन्हें विरोध करने और उनकी सुरक्षा में लगे पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर हमला करने पर उन कार्रवाइयों का 'विकास विरोधी' नाम देकर हमारे ऊपर बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार अभियान संचालित करने का निर्णय लिया है।

7. काउण्टर इंसर्जेन्सी और काउण्टर टेरारिस्ट ऑपरेशनों में इज्रायल की मदद लेने का निर्णय लिया है। माओवादी बलों पर हमले करने भारतीय अर्धसैनिक बल व वायसेना को इज्रायल द्वारा प्रशिक्षण दिला रहा है। अत्याधुनिक, बयोटेक हथियारों व टेकनोलॉजी का आयात कर रहे हैं।

8. दण्डकारण्य के सुकमा जिले को कोर एरिया के रूप में चयनित कर हमले करने के लिए विशेष योजना बनायी गयी है। इसके लिए दो कोबरा बटालियनों को तैनात करने का निर्णय लिया है।

9. माओवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उनके आर्थिक स्रोत पर चोट पहुंचाने का निर्णय लिया है।

उक्त रणनीति-कार्यनीति को लागू करने के लिए आठ मोर्चों पर काम करने का प्रस्ताव से आठ अक्षरों को निकाल कर 'समाधान' शब्द बनाया गया, उसी को अपने वर्तमान रणनीति के रूप में केन्द्रीय गृहमंत्रालय द्वारा पेश किया गया: एस-स्मार्ट लीडरशिप (सक्रिय नेतृत्व), ए-एग्रेसिव स्ट्रैटेजी (आक्रामक रणनीति), एम-मोटिवेशन एण्ड ट्रेनिंग (प्रेरित करना और प्रशिक्षित करना), ए-एक्शनाबुल इंटेलिजेन्स (कार्रवाई में इस्तेमाल किया जाने वाला गुप्त समाचार), डी-डॉश बोर्ड बेस्ड इंडिकेटर्स (हाथ में उपलब्ध सूचक), एच-हार्नेसिंग टेकनोलॉजी (टेकनोलॉजी का इस्तेमाल करना), ए-एक्शन प्लान फोर ईच थ्रेट (प्रत्येक चुनौती का सामना करने की उचित कार्य-योजना), एन-नो एक्सेस टु फाइनॉन्सिंग (आर्थिक स्रोतों पर रोक लगाना)- SAMADHAN - समाधान - यही रणनीति है।

15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा क्विट इंडिया के 75वीं वर्षगांठ तक यानी 2022 तक भारत देश को 'नया भारत' के रूप में विकसित करने का एजेंडा एलान किया गया है। मोदी का आह्वान के मुताबिक इसका घोषित लक्ष्य है- कचड़ा मुक्त स्वच्छ भारत, गरीबी का उन्मूलन कर विकसित भारत, भ्रष्टाचार-मुक्त, आतंकवाद से मुक्त, जातिवाद-सम्प्रदायवाद (fundamentalism) से मुक्त भारत को गठित करना। यह सिर्फ आम जनता को भ्रम में डालने के सिवाय और कुछ नहीं है। इस घोषित एजेंडा के पीछे छिपा हुआ असली लक्ष्य यही है कि देश को साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीपति व बड़े सामंती वर्गों के हितों के लिए किसी तरह का अवरोध पैदा न हो- इस तरह का भारत

गठित करना और साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीपति व बड़े सामंती वर्गों की सत्ता को सुदृढ़ करना। एक तरफ अमेरिकी साम्राज्यवाद के प्रति दक्षिण एशियाई वफादार के रूप में भारत को खड़ा कर चीन का मुकाबला करना; दूसरी तरफ देश में उच्च जातियों के प्रभुत्व को सुदृढ़ करने के लिए उत्पीड़ित जातियों, विशेषकर, दलितों को कुचलने (उनके अर्थ में जातिवाद से मुक्त करने) के जरिए, धार्मिक अल्पसंख्यकों को दबाने (उनके अर्थ में सम्प्रदायवाद से मुक्त करने) के जरिए ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद को मजबूत करना; साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीपति व बड़े सामंती वर्गों के खिलाफ वर्ग संघर्ष और सशस्त्र संघर्ष करने वाले माओवादियों को कुचलने के जरिए, कश्मीर, उत्तर-पूर्व के राष्ट्रीय-मुक्ति आंदोलनों को कुचलने (उनके अर्थ में आतंकवाद से मुक्त करने) के जरिए 'हिंदू राष्ट्र' की स्थापना करना- ये ही है 'नवभारत निर्माण' का असली लक्ष्य। इसलिए भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को पूरी तरह सफाया करना ही 'नवभारत' निर्माण के पीछे भारत के शोषक-शासक वर्गों का लक्ष्य है। इन दोनों को जोड़कर देखने से ही पता चलेगा कि 'समाधान' हमले के तहत कितना फासीवादी तरीका अपनाया जाएगा।

इस प्रतिक्रांतिकारी नयी योजना व रणनीति-कार्यनीति के मुताबिक उसके मुख्य केन्द्रीकरण दण्डकारण्य और बिहार-झारखण्ड पर होने के बावजूद, समूचे देश में क्रांतिकारी आंदोलन को उन्मूलन करना ही उसका लक्ष्य है। इसका मुकाबला कर परास्त करने के लिए जनता को व्यापक तौर पर जागरूक करने व संगठित करने का प्रयास सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिए पूरी क्रांतिकारी शिविर को तैयार होना चाहिए।

देशीय और अंतरराष्ट्रीय पटल पर क्रांति के अनुकूल बढ़ती परिस्थिति का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के हमले को परास्त करें

1991 से लेकर आज तक विगत 26 वर्षों में केन्द्र व राज्य सरकारें भूमण्डलीकरण की नीतियों, उसके तहत मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों को लागू करने के कारण मजदूर व किसान जनता के जीवन दूभर हो गया है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र बहुराष्ट्रीय कार्पोरेटों के हाथों में होने के कारण मजदूरों को नाम के वास्ते भी जो अधिकार है उसे कुचला जा रहा है। इसके कारण संगठित व असंगठित क्षेत्रों के लाखों मजदूरों की रोजगार चले जाने के कारण सड़कों पर उतर कर संघर्ष करने का रास्ता अपना रहे हैं। मजदूर आंदोलनों पर, उनके नेतृत्वकारियों के ऊपर भीषण दमन चलाया जा रहा है। इनेकों मजदूर नेताओं को फर्जी मुकदमों में जेलों में ठूंसा जा रहा है और आजीवन कारावास की सजा भुगतने को बाध्य है। इसके बावजूद पूरे देश में जुझारू मजदूर आंदोलन जारी है। दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र संकट में फंसा हुआ है। फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण किसान कर्ज के बोझ तले जीवन बिताने को मजबूर है। विश्व बैंक के आदेशों को विगत ढाई दशकों से केन्द्र व राज्य सरकारें लागू करने के कारण भारतीय कृषि क्षेत्र तबाह हो गया है। छोटे व मध्यम वर्ग के किसानों का जीवन छिन्न-भिन्न हो गया है। इसलिए विगत ढाई दशकों में ढाई लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। मोदी के तीन साल के शासन काल में 36 हजार किसानों ने आत्महत्या की है। इसी बीच फसलों के उचित मूल्य के लिए मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, राजस्थान, तमिलनाडु आदि राज्यों के किसान जुझारू आंदोलन किये हैं। अगले दिनों में किसान आंदोलन और जुझारू रूप ले सकता है और संगठित होकर आगे बढ़ सकता है।

कालाधन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के नाम पर मोदी सरकार अचानक बड़े नोटों को रद्द की है। यह कालाधन पर तो अंकुश लगा नहीं पाई, इसके विपरीत कृषि क्षेत्र, छोटे उद्योग, असंगठित क्षेत्र और खुदरा व्यापार माला-माल हो गया। बड़े नोटों को रद्द करने के साथ-साथ मोदी सरकार की साम्राज्यवाद-परस्त नीतियों के कारण औद्योगिक विकास धिमी पड़ गयी है। इन सभी के कारण भारतीय अर्थ व्यवस्था की 'विकास दर' बहुत गिर गयी है। मुद्रास्फीति बढ़ रही है। इससे छोटे उद्यमियों व व्यापारियों के साथ-साथ समाज के सभी तबके आर्थिक रूप से तीव्र मुसीबतों का सामना कर रहे हैं।

देश में 18 करोड़ शिक्षित बेरोजगार हैं। हर साल एक करोड़ लोगों को नौकरी व रोजगार दिलाने का मोदी का चुनावी वादा इन तीन सालों में साफ- साफ साबित हो गया है कि वह झूठा है। इन तीन सालों में मोदी सरकार सिर्फ ढाई लाख नौकरियां ही दे पाई है। हर साल एक करोड़ 30 लाख लोग डिग्री पढ़ाई पूरी कर रोजगार के बाजार में शामिल हो रहे हैं। इन्हें रोजगार दिला नहीं पाने वाली जनविरोधी सरकारों के रूप में केन्द्र व राज्य सरकारें भण्डाफोड़ हो रही हैं। इससे आगामी दिनों में इस बेरोजगार सेना जुझारू आंदोलनों में उतरने की सम्भावनाएं बढ़ रही हैं।

वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकियों को ही पहली प्राथमिकता (अमेरिकियों को ही पहले नौकरियों में लेने, बेहतरीन वेतन देने) की नीतियां लागू करते हुए एच 1 बी वीसा के मामले में बदलाव लाया है। इससे अमेरिका जाकर नौकरी करने के इच्छुक लोगों के लिए रोजगार के अवसर घट गये हैं। ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि साम्राज्यवादी, पूंजीवादी देश भी प्रवासियों पर कई निषेध लागू किये हैं। इससे भारतीय आईटी उद्योग में 5-6 लाख नौकरियां चले जाने की परिस्थिति पैदा हो गयी है। दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संकट जारी है, इससे विदेशों में भारत वासियों को

नौकरियों से न सिर्फ निकाला जा रहा है, बल्कि नए अवसर भी नहीं के बराबर रह गया है। वहीं रंगभेद के तहत प्रवासी भारतीयों पर अमेरिका सहित कई देशों में हमले बढ़ रहे हैं। इससे आइटी उद्योग के कर्मचारियों सहित अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों और छात्र आंदोलन का राह पकड़ रहे हैं।

एक देश-एक कर के नाम पर 1 जुलाई से लागू की गयी जी.एस.टी. (वस्तु और सेवा कर) नीति से देश भर में लाखों छोटे उद्यम और छोटे व्यापारी दिवालिया होकर, देश में सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों व उनके दलालों के उत्पादन और व्यापार संस्थान का ही दबदबा कायम होने की स्थिति पैदा हुई है। इससे देश के छोटे उद्यमी और छोटे व्यापारी भी अगले दिनों में आंदोलन में उतरने की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है।

देश में ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादी हमले दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, उत्पीड़ित राष्ट्रों और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों पर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसके विरोध में ये सभी तबके विभिन्न तरीके अपना कर संघर्ष कर रहे हैं। हाल ही में, ये हमले बेरोकटोक जारी है। कर्नाटक में लोकप्रिय प्रगतिशील संपादक और लेखिका गौरी लंकेश की हत्या की गयी। गुजरात के उना में दलितों पर हमला और उसका प्रतिरोध के बाद उत्तरप्रदेश के सहारनपुर आदि जगहों में दलितों पर बेरोकटोक हमले जारी हैं। कश्मीर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन और गोरखालैंड की मांग को लेकर जारी जुझारू आंदोलन पर सेना और अर्धसैनिक बलों का प्रयोग कर उनका दमन तेज किया गया है। विश्वविद्यालयों के छात्रों पर हमले बढ़ रहे हैं। महिलाओं पर, विशेषकर विश्वविद्यालयों में छात्राओं पर पितृसत्तात्मक पाबंदियां लगाकर मनुधर्म को थोपा जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद के खिलाफ स्थानीय स्तर से लेकर केन्द्र तक विभिन्न जगहों में एकजुट होकर, जुझारू व एकताबद्ध आंदोलन करने की दिशा में परिस्थितियां परिपक्व हो रही हैं। हिंदू फासीवादियों के हमले भारतीय समाज में मौलिक अंतरविरोधों को और तेज करते हुए क्रांतिकारी परिस्थितियों को और अनुकूल बना रही हैं। ये सब ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा को गठित करने के लिए बहुत ही अनुकूलताएं उपलब्ध करा रही हैं।

वर्ष 2008 में अमेरिका से शुरू होकर पूरे विश्व में फैले आर्थिक संकट से अभी तक उबर नहीं पाया है। सभी साम्राज्यवादी देशों द्वारा इस संकट को सुलझाने के लिए किये गये सभी प्रयास विफल होते जा रहे हैं। साम्राज्यवादी देश इससे निपटने के लिए आर्थिक तौर पर 'संरक्षण नीतियां,' राजनीतिक रूप से फासीवाद और सैनिक रूप से युद्ध करने का मार्ग अपना रहे हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी मौलिक अंतरविरोध तीखा होते जा रहा है।

मध्यपूर्व (पश्चिम एशिया), दक्षिणी चीन सागर के इलाका, कोरियाई प्रायद्वीप साम्राज्यवादी अमेरिका, रूस और चीन के संघर्षों के केन्द्र बने हुए हैं। चीन, उत्तर कोरिया के खिलाफ अमेरिका ने पांच लाख से ज्यादा अपने और दक्षिण कोरिया के फौजी टुकड़ियों को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भेजी है। साम्राज्यवादी चीन अपने शोषण के हितों के लिए पहले से ही अपनी तैयारियां कर रहा है। साम्राज्यवादी रूस एक तरफ चीन के साथ रिश्ता बढ़ाते हुए, मध्यपूर्व में अपनी स्थिति को कायम रखने के लिए अमेरिका के साथ लोहा ले रहा है।

इस वर्ष मई महीने में चीन की राजधानी बीजिंग में वन बेल्ट-वन रोड (ओबीओआर) योजना के बारे में चर्चा करने के लिए चीन ने बेल्ट एण्ड रोड फोरम (बीआरएफ) के दो दिन की बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में 29 देशों के अधिनेता और एक सौ से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वन बेल्ट-वन रोड योजना से अमेरिका को लग रहा है कि वह विश्व अर्थ व्यवस्था में अपना प्रभुत्व के लिए बड़ी चुनौती के रूप में तब्दील होगी।

कमजोर होता जा रहा अमेरिकी साम्राज्यवाद के प्रभुत्व को कायम रखने के लिए उस देश का राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा लागू नीतियां विश्व शांति के लिए गम्भीर खतरे के रूप में तब्दील हो रही हैं। ट्रम्प सत्ता में आने के तुरंत बाद सिरिया और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक टुकड़ियों की तादाद बढ़ाकर वहां हमले तेज किया है। मध्यपूर्व को अपना स्थायी शिविर के तौर पर तब्दील कर वहां के तेल और बाजारों को लूटने के लिए, इरान के खिलाफ साउदी अरब को खड़ा करते हुए उन दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ाने की कुटिल उपाय अपना रहा है। इस दशाब्दी में 35,000 करोड़ डॉलर लागत वाला हथियार साउदी अरब को बेचने का समझौता किया है। साउदी अरब और इरान के विवाद से शिया-सुन्नी मतभेदों को जोड़कर मध्यपूर्व के सभी देश दो स्थायी विरोधी पक्ष के रूप में आमने-सामने होने की परिस्थितियां सुलगती रही है। चीन के विरोध में जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया और भारत को खड़ा कर रहा है। ये सभी बदलाव विश्व शांति के लिए गम्भीर खतरा पैदा कर रहा है।

इसके परिणामस्वरूप क्रांति के अनुकूल बढ़ते बदलावों का विश्व सर्वहारा वर्ग, क्रांतिकारियों, क्रांतिकारी पार्टियों को सही ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके तहत हमारे देश में साम्राज्यवाद और देश के दलालों के खिलाफ जनयुद्ध को तेज करने की जरूरत है।

वर्तमान साम्राज्यवादी देशों द्वारा आर्थिक और राजनीतिक तौर पर अपनायी जा रही नीतियां जिस तरह उन देशों में शोषक वर्गों के दक्षिणपंथी और फासीवादी पार्टियां बढ़ने का अवसर दे रही हैं, उसी तरह सर्वहारा वर्ग और कम्युनिस्ट पार्टियों के उद्‌भव होने तथा छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों के रूप में विकसित होने, उनके द्वारा जुझारू संघर्ष संचालित करने के

लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर रही हैं।

हमारे देश में साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीपति और सामंती शोषण व उत्पीड़न की तीव्रता के कारण रोजगार खो जाने वाले किसान, जंगलों पर अपना अधिकार खो जाने वाले आदिवासी, नौकरियां खो जाने वाले मजदूर, कर्मचारी, नौकरी पाने का कोई आशा-भरोसा नहीं करने वाले छात्र, ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादी हमलों के शिकार दलित, मुस्लिम, आदिवासी, उत्पीड़ित राष्ट्र- सभी पहले के मुकाबले अभी व्यापक व जुझारू रूप से गोलबंद हो रहे हैं। यह रूझान और बढ़ सकता है। और व्यापक व जुझारू रूप से बढ़ सकने वाले ये ही आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन की अग्रगति के लिए व दुश्मन के हमले को परास्त करने के लिए बहुत बड़ा स्रोत व आधार है। अंतरराष्ट्रीय व देशीय तौर पर वृद्धि हो रही इन अनुकूलताओं के आधार पर उचित कर्तव्य व कार्यनीति तय कर दुश्मन के हमले को परास्त करें। भारती की नवजनवादी क्रांति को आगे बढ़ाएं।

कर्तव्य :

फरवरी 2017 में हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी द्वारा जारी किया गया 'वर्तमान परिस्थिति-हमारे कर्तव्य' नामक सर्कुलर में आम तौर पर अगले दो वर्ष के समय काल में पूरा करने वाले कर्तव्यों और कार्यनीतियों के बारे में दिशा-निर्देश जारी किया था। उन्हें ध्यान में रखकर निम्नांकित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करना होगा।

1. भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को सफाया करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' हमले (2017-2022) को परास्त करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करें!

केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा तय किया गया नया प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' हमला एक चौतरफा हमला ही है। एल.आई.सी. रणनीति के दिशा-निर्देशन में तय किया गया यह हमला राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक व सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में चरम फासीवादी तरीकों में, क्रांतिकारी जनता, पार्टी कतारों व पीएलजीए योद्धाओं को गुमराह करने की धोखेबाजी कार्यनीति से, बड़े पैमाने पर मनोवैज्ञानिक युद्ध से जोड़ कर लागू किया जाता है। जनता को दिलों से अपने अनुकूल ढालने के (perception management) रूप में अमल किया जाता है। 'नवभारत' निर्माण के लिए भारत के शोषक-शासक वर्गों द्वारा तय रणनीतिक योजना के साथ जोड़ कर देखने के बाद ही इस हमले के बारे में सामग्रिक रूप से एक समझ बना सकेंगे। इसलिए 'नवभारत' निर्माण के अंदर षड्यंत्र और समाधान हमले के फासीवादी स्वभाव के बारे में पार्टी कतारों व पीएलजीए योद्धाओं को राजनीतिक तौर पर एक समझ बनाकर क्रांतिकारी जनता को समझाना होगा।

भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को उन्मूलन करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा तय नयी प्रतिक्रांतिकारी योजना तो आक्रामक है ही, लेकिन उसकी मजबूत व कमजोर पहलू- दोनों को और उसे मुकाबला करने के लिए हमारे मजबूत व कमजोर दोनों पहलुओं को सही तरीके से विश्लेषण करना होगा। इस समझ पर आधारित होकर इस प्रतिक्रांतिकारी हमले का मुकाबला करने की आक्रामक व आत्मरक्षात्मक कार्यनीतियां तय करनी होगी। इस समझ को हमारी पार्टी व पीएलजीए कतारों तक, स्थानीय सांगठनिक इकाइयों और क्रांतिकारी जनता तक ले जाना होगा और उन सभी को दुश्मन के हमले का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक रूप से तैयार करना होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है।

गांवों में मुठ्ठीभर जन विरोधी व मुखबिर दुश्मन का पक्ष लेने के बावजूद, बहुसंख्यक जनता क्रांतिकारी आंदोलन के पक्ष में खड़ी है (जन आधार)। यही हमारी बहुत बड़ी ताकत है। यह हमारी रणनीतिक रूप से अनुकूल पहलू है। इसके साथ-साथ टेरेन (धरातल) की अनुकूलता है। विभिन्न स्तरों के पार्टी और पीएलजीए के नेतृत्वकारी कामरेड हमारी ताकत है। बीते 10 सालों में कार्पेट सुरक्षा के इलाकों में छापामार युद्ध और माइन युद्ध तंत्र संचालित करने वाले पीएलजीए के कमांडरों और योद्धाओं के अनुभव इस नये हमले को परास्त करने के लिए मजबूत आधार के रूप में खड़ा है। लेकिन गुरिल्ला युद्ध के नियमों को लागू करने में, गुप्त कामकाज में जारी कमजोरियां हमारी कमजोरी है। हमारे बलों के अंदर एक तबके में दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने की कमजोरियां मौजूद हैं। कुछ जगहों पर जन खुफिया व्यवस्था नहीं होना हमारी कमजोरी है। इससे उबर सके, तो हमारे पीएलजीए एक अजेय सेना के रूप में विकसित होकर दुश्मन द्वारा जारी नये हमले को परास्त कर सकेगी।

देश के सभी आंदोलन के इलाकों में लगभग 5,20,000 पुलिस व अर्धसैनिक बलों को तैनात करने के बावजूद, उस पर निर्भर होकर कार्पेट सुरक्षा व्यवस्था को विस्तार करने के बावजूद, दुश्मन का परेशानी यही है कि इन बलों द्वारा माओवादी आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता। इसलिए वह नयी योजना बनाया है। यह दुश्मन का बड़ी कमजोरी है। हवाई हमले एक तरफ दुश्मन की शक्ति को सूचित करता है, दूसरी तरफ वे उनकी कमजोरी का प्रमाण भी। इसलिए हवाई हमलों का मुकाबला करने के लिए एयर डिफेन्स ड्रिल्स प्रैक्टीस करते हुए, उपलब्ध हथियारों के साथ उन्हें मुकाबला करना होगा। इससे हम अनुकूलताएं पैदा कर सकते हैं।

2. 'नवभारत' निर्माण के नाम पर भारतीय शोषक-शासक वर्ग अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने की इस योजना के बारे में देश भर में राजनीतिक तौर पर भण्डाफोड़ करने के प्रचार आंदोलनों को तेज करें!

शोषक-शासक वर्ग द्वारा अपनाये जा रहे जनविरोधी, देश विरोधी साम्राज्वाद- परस्त नीतियों से देश के उत्पीड़ित जनता के अंदर दिन ब दिन बढ़ती जा रही सामाजिक आशांति, क्रांति का स्रोत न बने- इसके लिए 'गरीबी उन्मूलन' के नाम पर ग्रामीण व शहरी गरीबों के लिए सिर्फ कुछ घर बनाने से गरीबी हल नहीं होगी, ग्रामीण व शहरी गरीब जनता की जमीन समस्या, उत्पादक साधनों पर सत्ता और राजसत्ता से संबंधित समस्या है। जब तक वह समस्या हल नहीं होगी तक तक शोषक-शासक वर्गों द्वारा लागू किये जाने वाले सुधारें जो भी हो, गरीबी हल नहीं कर सकते। पिछले 70 सालों से शोषक-शासक वर्ग हमारे देश की जनता को झूठे विकास कार्यक्रमों से धोखा दे रहा हैं। अभी इस 'नवभारत' निर्माण योजना भी और एक धोखा है। इस धोखे का शिकार नहीं बनना चाहिए - इस तरह की समझदारी जनता के अंदर बढ़ानी होगी।

3. भारत के शोषक-शासक वर्गों के युद्धोन्माद और अंध राष्ट्रवाद का भण्डाफोड़ करें!

देश के अंदर गरीबी, निरक्षरता, बीमारी, भुखमरी, किसान की आत्महत्याएं आदि सामाजिक आर्थिक समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भारत के शोषक-शासक वर्ग युद्धोन्माद और अंधराष्ट्रवाद को भड़का रहा है। इसका शिकार हुए बिना लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना होगा। इनसे शिकार होने पर क्रांतियां विफल हो सकती हैं।

4. तेजी से बढ़ता फासीवाद के खिलाफ पार्टी के हाथों मजबूत औजार के रूप में पीएलजीए और संयुक्त मोर्चा को ढालें (remould करें)!

तेजी से बढ़ता फासीवाद समाज के अंतरविरोधों को और तेज करता है। परिणामस्वरूप क्रांतिकारी परिस्थितियां क्रांतिकारी संकट की ओर आगे बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक रूप से जागरूक शक्तियां अनुकूल स्थिति में रहेंगे। वे लोगों को प्रेरित कर लाखों की तादात में जन उभारों का निर्माण करने की भूमिका निभा सकती हैं। शक्ति-संतुलन में बदलाव ला सकती हैं। लेकिन वे इस भूमिका को निभाने के लिए पार्टी के हाथों में मजबूत औजार के रूप में पीएलजीए और संयुक्त मोर्चा को ढालने का प्रयास करना होगा। इसके लिए वे राजनीतिक रूप से होने वाले बदलावों को समझना होगा, उनके अनुरूप खुद को विकसित करना होगा। पहलकदमी और लचीलापन हासिल करना होगा।

5. ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद के खिलाफ क्रांतिकारी शक्तियों, जनवादियों, प्रगतिशील शक्तियों, संगठनों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, धर्मनिरपेक्षों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं को एकजुट कर व्यापक संयुक्त मोर्चा और मजबूत व जुझारू आंदोलन का निर्माण करें!

6. आंदोलन के सभी इलाकों में साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी, राज्य विरोधी वर्ग संघर्षों को तेज करें!

व्यापक ग्रामीण इलाकों में जमींदारों, सूदखोरों, शाहुकारों के लूट व शोषण के खिलाफ खेतिहर-गरीब व मध्यम किसानों को मजबूत वर्ग संघर्षों में गोलबंद करना होगा। साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण के खिलाफ विस्थापन आदि राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक समस्याओं पर बड़े पैमाने पर जनता को राजनीतिक आंदोलनों में एकजुट करना होगा। उन आंदोलनों को जनयुद्ध के साथ जोड़ना होगा। क्रांतिकारी, जनवादी संगठन, शक्तियों, व्यक्तियों, व्यापक जनता को एकत्रित कर व्यापक पैमाने पर मजबूत जन आंदोलन निर्माण करना होगा।

7. बदलती सामजिक परिस्थितियों के अनुरूप जनयुद्ध की कार्यनीतियां विकसित करने के लक्ष्य से सभी राज्यों/स्पेशल एरिया/स्पेशल जोनों में सामाजिक शोध व वर्ग विश्लेषण का कार्य संचालित करें! उनके आधार पर सही कार्यनीतियां रेखांकित कर ठोस परिस्थितियों के साथ सृजनात्मक रूप से जोड़कर जनयुद्ध को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं!

8. पार्टी व फौजी नेतृत्वकारी कतारों व कार्यकर्ताओं के सैद्धांतिक स्तर का उन्नतीकरण के कार्यक्रम को लागू करें!

9. पीएलजीए को राजनीतिक, सैनिक व सांगठनिक तौर पर मजबूत करें!

- समूचे देश में हमारे आंदोलन के सभी इलाकों में पीएलजीए में नयी भर्ती को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा। जन आधार को बढ़ाने के लिए वर्ग संघर्ष को तेज करते हुए, उसमें आगे आने वाली सक्रिय जुझारू शक्तियों को पहचान कर उन्हें ध्यान देकर भर्ती करना होगा। जहां हमारा आंदोलन कमजोर है, सीमित व्यक्तियों को और सापेक्षिक तौर पर मजबूत इलाकों से दसियों या सैकड़ों संख्या में भर्ती करना होगा।
- कठिन दौर से उबरने का प्रयास को मदद देने के लक्ष्य से पार्टी और पीएलजीए बलों के सैद्धांतिक-राजनीतिक स्तर बढ़ाने वाला अभियान चालू करना होगा।
- दुश्मन द्वारा अपनाए जा रहे काउण्टर गुरिल्ला वारफेयर की कार्यनीति का मुकाबला करने लायक हमारे बलों को सैनिक प्रशिक्षण देना होगा।
- पार्टी और फौजी क्षेत्र के नेतृत्वकारी शक्तियों को शिक्षित करने का कार्यक्रम (लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम (एल.टी.पी.)) और फौजी क्षेत्र के नेतृत्वकारियों को शिक्षित करने का कार्यक्रम (एम.एल.टी.पी.) संचालित

कर सभी स्तरों में नेतृत्वकारी शक्तियों को शिक्षित करना होगा।

- सभी कम्बैट यूनिटों से चयनित कामरेडों को स्नाइपर, बूबीट्रैप, रिमोट टेकनोलोजी पर प्रशिक्षण कक्षाएं संचालित करना होगा। इन विषयों में विशेषज्ञों (specialists) को तैयार करना होगा। युद्ध कार्रवाइयों में सफलता की दर बढ़ानी होगी। युद्ध कार्रवाइयों में जीत हासिल करने के लिए प्राथमिक स्तर के इंप्रूवाइज्ड आर्टिलरी को व्यापक तौर पर इस्तेमाल करना होगा।
- दुश्मन के कमजोरियों को अध्ययन करने, बेहतर योजना बनाने, सक्षम तरीके से सी-4 लागू करने, दृढ़ता/साहसिक ढंग से लड़ने आत्मबलिदान की चेतना बढ़ा कर युद्ध कार्रवाइयों को सफल बनाना होगा। पीएलजीए की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए गम्भीर प्रयास करना होगा।
- सभी स्तरों में कमान व कमीशनों की शक्ति-क्षमताओं को बढ़ाना होगी। इनकी बैठकें नियमित रूप से करनी होगी।

10. दुश्मन का मुखबिर-कोवर्ट जाल को ध्वस्त करें!

दुश्मन का सूचना आधारित हमलों के लिए मुख्य आधार पुलिस मुखबिर ही है। इसलिए, मुखबिर समस्या का सामना करने के लिए सभी एसी, सब-जेडसी/सबडीवीसी, जेडसी/डीसी/डीवीसीयों में चर्चा कर राजनीतिक-सैनिक कार्यक्रमों को नियमित रूप से संचालित करना होगा। मुख्य मुखबिरों को सफाया कर, बाकी लोगों को विभिन्न तरीकों की सजा देनी होगी।

11. गुप्त कामकाज, गुरिल्ला युद्ध नियमों को लागू करें! दुश्मन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न किस्म के निगरानी (थर्मल इमेजिंग, इनफ्रारेड, रॉडार, जीपीसी आदि) उपकरणों से भनक नहीं लगा सके - इस तरह के हमारी केमोफ्लेज और गतिविधियां में बदलाव लाएं!

केन्द्रीय सैन्य आयोग का आह्वान :

15 अगस्त 1947 की सत्ता हस्तांतरण के बाद 70 साल बीत चुका है। इन 70 वर्षों की अवधि में देश के सभी तरह के और सभी रंग के राजनीतिक पार्टियां केन्द्र या राज्यों में गद्दी पर बैठ कर सत्ता चलायी है। लेकिन इन सारी पार्टियां और इस देश की संसदीय व्यवस्था जनता के एक भी रोजमर्रा व मौलिक समस्याओं को निपटने में पूरी तरह विफल रही है। भविष्य में भी इन राजनीतिक पार्टियों व संसदीय व्यवस्था जनता की समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगी। अभी नरेंन्द्र मोदी द्वारा प्रचारित 'नवभारत निर्माण' भी जनता के समस्याओं को हल नहीं कर सकता। वह शोषक वर्गों को और सुदृढ़ करने के सिवाय गरीबी, जातिवाद और सम्प्रदायवाद को उन्मूलन नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी के एजेण्डे पर विश्वास रखने का मतलब है, देश की जनता और एक बार धोखे का शिकार हो जाना। इसलिए देश की जनता और एक बार धोखे में न फंसे- इसके लिए नव जनवादी क्रांति की जीत के लिए सशस्त्र संघर्ष के राह पर आगे बढ़ना ही होगा।

पिछले तीन साल के मोदी का शासन में ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादी हमलों से एक भी उत्पीड़ित वर्ग या उत्पीड़ित सामाजिक जन समुदाय नहीं बची है। एक भी विपक्षी पार्टी या एनजीओ को इन हमलों को रोकने का दम नहीं है। अगर इन हमलों का मुकाबला करना है, तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) और पीएलजीए में सभी उत्पीड़ित जनता, उत्पीड़ित सामाजिक जन समुदाय संगठित व सशस्त्र होकर प्रतिरोध करना ही होगा। इसलिए हमारा केन्द्रीय सैन्य आयोग (सी.एम.सी), भाकपा माओवादी का आह्वान है कि सभी उत्पीड़ित जनता, उत्पीड़ित सामाजिक जन समुदाय, धार्मिक अल्पसंख्यकों व उत्पीड़ित राष्ट्र भाकपा (माओवादी) और पीएलजीए में हजारों-लाखों की संख्या में भर्ती हो जाएं।

पिछले वर्ष में समूचे देश में ऑपरेशन ग्रीन हंट हमलों को परास्त करने के लक्ष्य से हमारी पीएलजीए द्वारा संचालित साहसिक टीसीओसी और प्रतिरोध की कार्रवाइयों में हासिल सफलताओं के बारे में बड़े पैमाने पर प्रचार करें। इस पूरे दिसम्बर माह में भर्ती अभियान को संचालित करें।

☆ पार्टी, पीएलजीए और संयुक्त मोर्चा को संगठित करें!

☆ पीएलजीए में बड़ी संख्या में युवक-युवतियों को भर्ती करें!

☆ सामंती व साम्राज्यवाद विरोधी वर्ग संघर्ष को तेज करें!

☆ मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद जिन्दाबाद!

☆ पीएलजीए जिन्दाबाद!

बीजे सैक द्वारा 20 दिसम्बर, 2017 को बिहार-झारखंड बन्दी कार्यक्रम के लिए जारी पर्चा

ऑपरेशन ग्रीन हंट व मिशन-2017 के तहत जनता पर थोपा गया बर्बर युद्धाभियान के विरोध में दिसम्बर 18-19 दो दिवसीय विरोध दिवस और दिसम्बर 20 को एक दिवसीय बंदी कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनावें!

प्रिय झारखण्ड-बिहार के मजदूर-किसान, छात्र-नौजवान, महिला, बुद्धिजीवी, तमाम जनवादी व प्रगतिशील दोस्तो, प्रबुद्ध नागरिको और कामरेडो,

विदित है कि जनता पर थोपा गया बर्बर युद्धाभियान अभी उसका चरम पर है। जैसेकि पिछले कुछ दिनों से बूढ़ा पहाड़ के चारों ओर लातेहार-गढ़वा-पलामू-गुमला क्षेत्र को लेकर लगभग एक-दो किलोमीटर बाद-बाद में एक रणनीतिक बंदी शिविर जैसा बनाकर इलाका कब्जा करने के लक्ष्य पर जो युद्ध चलता है, उसी लक्ष्य को सामने रखकर इन सारे क्षेत्रों में अर्द्ध-सैनिक बलों तो तैनात है ही, लेकिन मिशन-2017 का जो अभियान चला रहे हैं- उससे माओवादियों को उखाड़ फेंकने के नापाक इरादों से जो युद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उसके दौरान पिछले एक-दो महीनों से सेना के आर्मर यूनिट के जरिए तोप से गोला-बारी की जा रही है। वायु सेना का हेलिकॉप्टर व युद्धक विमान को भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

उदाहरणस्वरूप बूढ़ा पहाड़ में नवम्बर 23 से 26 तक आर्मर यूनिट के द्वारा तोपों से लगातार गोला व बमबारी की गयी, अक्टूबर महीना के 8 से 10 तारीख के अंदर में पश्चिम सिंहभूम के किरीबुरू, छोटानागरा, गुवा, नोवामुंडी आदि क्षेत्रों में घेरकर शाम 4-5 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक युद्धक विमानों से प्रचण्ड डरवानी आवाज से इस्तेमाल किया गया है। ज्ञात रहे कि 2011 के दिसम्बर महीना में वैशाली-छपरा जिला के गंडक नदी के दियारा इलाका में नौसेना के स्पीड बोट का इस्तेमाल कर दिनभर गस्ती लगाया गया और कभी-कभी माओवादी के अड्डा स्थल सोचकर गोली भी चलायी गयी। इसके अलावे सेना का टोही विमान, ड्रोन और हेलिकॉप्टर की निगरानी की बात तो रोज दिन की बात बन गयी है। केन्द्र और रघुवर व नीतीश सरकारों द्वारा चलाया जा रहा यह बर्बर युद्धाभियान का भयानक परिणामों को प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रचार तो नहीं किया जा रहा है, बल्कि कुछ प्रगतिशील पत्रकार व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा जो कुछ प्रयास दिखाई पड़ता है, उस पर भी पूरी तरह रोक लगाने के लिए प्रशासन व पुलिस द्वारा जबरदस्त दबाव बनाया जाता है, धमकी दिया जाता है ऐसा कि गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। जिसके चलते ही मीडिया में ये सब खबर नहीं आ पा रही है। सरकार का इसके पीछे उद्देश्य है कि इस कुकर्म को देश-दुनिया की जनता न जान सके।

ऐसे ही कुछ दिन पहले लुगू पहाड़ क्षेत्र में भी आर्मर यूनिट को इस्तेमाल व हवाई हमला करके माओवादियों को पूरी तरह से खतम करने का एलान किया गया है। स्थिति ऐसी है कि गया जिला के इमामगंज, डुमरिया बांकेबाजार, देव, छकरबंदा, बारा और पलामू के हरिहरगंज के अंदर के विशाल क्षेत्र, चतरा के कोलेश्वरी के विशाल क्षेत्र, कुंदा, प्रतापपुर, लावालोंग, हंटरगंज आदि क्षेत्र; सारंडा, कोल्हान, पोड़ाहाट, बुण्डू, तमाड़, अड़की और खरसांवा जिला का कुचाई, दलभंगा, चांडिल, नीमडीह दलमा पहाड़ के आसपास के इलाके; सिल्ली, कसमार, लुगू, जिलगा और पारसनाथ व उसके आस-पास के विशाल इलाका; फिर, हजारीबाग जिला के बड़कागांव और चतरा के सिमरिया, गिद्धौर, इटखोरी और उसके आस-पास के इलाका; गिरिडीह के उत्तरी हिस्सा, नवादा जिला के कौवाकोल और जमुई के गिद्धेश्वरी पहाड़ के आस-पास के इलाका; मुंगेर के भीमबांध इलाका; दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा आदि पहाड़-जंगल व आस-पास के विशाल इलाका इन सारे क्षेत्रों में शोषक-शासक द्वारा छेड़ा गया युद्ध अभियान अभी वही 2017 के मिशन के अधीन चलाया जा रहा है। फिर, मैदानी क्षेत्र मगध, उत्तरी बिहार के प. चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, बेगुसराय, खगड़िया के विशाल मैदानी इलाके को भी पूरे तौर पर पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। जहां लोग बंदूक की आवाज के साये के अंदर जीवन बिताने को मजबूर हो गये हैं। एक बात में कहा जाए तो दुश्मन द्वारा छेड़ा गया ये युद्ध दरअसल अन्यायपूर्ण युद्ध है। असल में ये तमाम अन्यायपूर्ण युद्ध का लक्ष्य है झारखण्ड के पूरे खनिज संपदा सहित जल व प्राकृतिक संपदाओं और बिहार के विशाल उर्वर जमीन व जन संपदा को सबसे अमीर कारपोरेटों व दलाल नौकरशाह पूंजीपति के हाथों में दे देना। इसलिए ये युद्ध तो माओवादियों का खात्मा करने के नाम पर चलाया जा रहा है। पर, असली मकसद है पूरा खनिज व प्राकृतिक संपदा से भरा इलाके के तमाम आदिवासी-मूलवासी, दलित, भूमिहीन व गरीब किसान तथा मेहनतकश जनता सहित उन क्षेत्रों में

निवास कर रहे सभी लोगों को पूरी तरह से खदेड़कर उस पर लूटेरे वर्गों का पूरा नियंत्रण कायम करना। ताकि मनमौजी लूट-खसोट पर किसी प्रकार का बाधा न रहे। इसी को ही फासीवाद का सबसे खूंखार रूप कहना कोई अत्युक्ति नहीं होगी। पर ऐसी स्थिति में जनता भी चुपचाप बैठी हुई नहीं है। वे भी संगठित व सशस्त्र होकर तथा सिद्धू-कान्हू, वीर बिरसा की लड़ाई से प्रेरित होकर पिछले कई सालों से भाकपा (माओवादी) की रहनुमाई में इंसान जैसा जीने का अधिकार के लिए लड़ रही है। जल-जंगल-जमीन व तमाम आर्थिक-राजनीतिक अधिकारों के लिए तथा व्यापक किसानों के आत्महत्या की खिलाफ, कृषि उत्पादों के उचित मूल्य व कर्ज माफी के लिए और कृषि क्षेत्र पर गरीब, मध्यम किसानों के हाथों से जमीन छीनकर कारपोरेट फार्मिंग खेती करवाने की साजिश के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। सच्ची बात तो यही है कि जनता ही लड़ रही है। भाकपा (माओवादी) तो जनता के दोस्त, जनता के सहयोद्धा, सुख-दुख का सहभागी और रहनुमाई भी है। जनता तय कर चुकी है कि जब तक शोषण-अत्याचार का राज खत्म होकर मजदूर-किसान तथा जनता का राज स्थापित नहीं होगा तब तक अधिकारों की लड़ाई चलती रहेगी। चाहे इसके लिए झारखण्ड-बिहार में कितनी ही संख्या में शहादत क्यों न देना पड़े। भाकपा (माओवादी) वादा कर रही है कि माओवादी पार्टी जनता के बीच है, जनता के साथ रहेगी और जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी।

अतः बीजे सैक तमाम मजदूर, किसान, मेहनतकश जनता सहित तमाम जनवादी व प्रगतिशील शक्तियों, मानवाधिकार कार्यकर्ता, प्रबुद्ध नागरिकों, छात्र-युवा, महिला, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलाकारों, साहित्यकारों, डॉक्टर-इंजीनियरों और बीजे सैक के अधीनस्थ तमाम पार्टी कमेटियों, फौजी संगठनों के तमाम पीएलजीए के योद्धाओं, केकेसी-आरपीसी व जन संगठनों के कार्यकर्ताओं सहित क्रांतिकारी जनता से आह्वान करती है कि इस अन्यायपूर्ण युद्ध के खिलाफ गोलबंद होकर प्रतिवाद व प्रतिरोध आंदोलन का निर्माण करें और 18-19 दिसम्बर, 2017 को विरोध दिवस के रूप में पालन करें, 19 दिसम्बर को मशाल जुलूस का कार्यक्रम ग्रहण करें व 20 दिसम्बर, 2017 को 24 घंटा बिहार-झारखण्ड बंद कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनावें।

★

दक्षिण जोनल कमेटी द्वारा जारी पर्चा

आदिवासियों के अधिकार, परंपरा और अस्तित्व मिटाने के लिए व्याकुल है भाजपा के रघुवर दास सरकार

जल-जंगल-जमीन पर सदियों से हमारा अधिकार है। हम आदिवासी ही जंगलों को उजड़ने से बचाये हैं। लेकिन आज हमें उन अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। इसलिए हमें फिर से अपना अधिकार लड़कर हासिल करना होगा।

प्रिय झारखण्डवासियो,

विदित हो कि अलग झारखण्ड राज्य की स्थापना करने का झारखण्डी जनता का एकमात्र उद्देश्य था जल-जंगल-जमीन सहित तमाम संपदा पर, अपनी भाषा, शिक्षा और संस्कृति पर तथा झारखण्ड के शासन-प्रशासन पर आदिवासी-मूलवासियों का संपूर्ण अधिकार कायम करना। अलग झारखण्ड राज्य की स्थापना के लिए किये गये संघर्षों में आदिवासी समुदाय ही सबसे अधिक कुर्बानियां दिये हैं। पर, झारखण्ड में आज आदिवासियों को ही हाशिये पर धकेल दिया गया है। आज का झारखण्ड में जल-जंगल-जमीन सहित तमाम संपदा पर देशी-विदेशी पूँजीपतियों व कॉरपोरेट घरानों का कब्जा है तथा शासन-प्रशासन की बागडोर भी गैर-झारखण्डियों के हाथों में है। साथ ही यहां के स्थानीयता नीति भी गैर-झारखण्डियों के हितों को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। यह झारखण्ड सचमुच में क्या वैसा ही झारखण्ड है, जैसा हमारा सपना था? नहीं! बिल्कुल नहीं। आज का झारखण्ड हम आदिवासी-मूलवासियों का सपना नहीं था। इस झारखण्ड का विकास के लिए हम आदिवासियों का ही विनाश किया जा रहा है। हम आदिवासियों को ही विकास का बाधक कहा जा रहा है। अलग झारखण्ड राज्य बनने के बाद भी मेहनतकश आदिवासियों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उनका विस्थापन और पलायन पहले की तरह आज भी बदस्तूर जारी है।

ज्ञात हो कि 80 और 90 के दशक के पहले पूरे झारखण्ड के जंगलों पर और सारंडा व दलमा जैसे रिजर्व फॉरेस्ट (आरक्षित वनों) पर वन-विभाग और माफियाओं का कब्जा था। इस कारणवश यहां के आदिवासी और मूलवासियों का जंगलों पर कोई अधिकार नहीं था। जंगल के एक पत्ता तोड़ने तक की मनाही थी। ऐसे में वहां जंगल काटकर गांव बसाना कितना मुश्किल कार्य था! 70-80 के दशक के पहले

से एमसीसी और अभी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेतृत्व में झारखण्ड के मेहनतकश जनता ने गोलबंद होकर जनफौज बनाया और वन-विभाग तथा माफियाओं के राज को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। गांव-गांव में क्रांतिकारी किसान कमेटी का निर्माण कर जंगल पर अपना अधिकार कायम कर लिया। उसके बाद कई नये गांव पोड़ाहाट, कोल्हान और सारंडा के भीतर बसाये गये। आगे चलकर सारंडा और पोड़ाहाट में पार्टी के नेतृत्व में क्रांतिकारी जन कमेटी (जन सरकार का भ्रूण रूप) का निर्माण किया गया था। इन गांवों में क्रांतिकारी जन कमेटी की देख-रेख में कई विकास कार्य किये गये, जिससे वहां की जनता अपने जीवन-यापन के लिए काफी हद तक आत्मनिर्भर हो रही थी। लेकिन वर्ष 2011 में 'ऑपरेशन एनाकोंडा' काफी जघन्य व बर्बर तरीके से चलाया गया और सारंडा व पोड़ाहाट इलाके को पुलिसिया छावनी व बंदी शिविर में तब्दील कर दिया गया। साथ ही जंगलों पर दुश्मन द्वारा फिर से कब्जा जमा लिया गया।

आज फिर से सारंडा, पोड़ाहाट और दलमा में बसे आदिवासियों को जंगल का अतिक्रमणकारी कहकर उन्हें वहां से भगाने की तैयारी सरकार चला रही है। यह सरकार सारंडा और दलमा में आदिवासियों को वहां का निवासी मानने से इन्कार कर रही है और उन्हें वनवासी कहा जा रहा है। यहां के आदिवासियों को भगाने के लिए रघुवर सरकार एक नया प्लान तैयार किया है। उसके तहत जंगली जानवरों को संरक्षित करने के लिए जंगल को बचाया जयेगा और इस इलाके में इको सिस्टम विकसित किया जायेगा। इस बात से सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है कि उसके लिए गरीब आदिवासियों से ज्यादा चिंता जंगल के जानवरों को बचाने की है। इको सिस्टम बनाने के पीछे सरकार की मंशा है यहां के निवासियों को वनवासी कहकर पहले भगाना और फिर उनके जल-जंगल-जमीन को पूँजीपतियों के हाथों में सौंपना।

मालूम हो कि पश्चिम सिंहभूम के सारंडा इलाके के भू-गर्भ में प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क भी है। उसकी लूट दलाल नौकरशाह पूँजीपति और कार्पोरेट घरानों द्वारा सदियों से की जा रही है। इस लूट के कारण सारंडा इलाके में आज कई बड़े पहाड़ों का अस्तित्व मिट चुका है। लेकिन सरकार की उन पूँजीपतियों को अतिक्रमणकारी कहने की हिम्मत नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यह सरकार गरीबों की नहीं, बल्कि उन्हीं पूँजीपतियों की है। इसलिए यहां के प्राकृतिक संसाधनों की पूँजीपतियों द्वारा लूट की खुली छूट देने के लिए रोज ऐसे कानूनों को सामने ला रही है, जो मूलत: मेहनतकश आदिवासी-मूलवासियों के हित विरोधी है।

आज जब भाजपा के रघुवर दास सरकार के आदिवासी-मूलवासी व जन विरोधी नीति व रवैया को देख और पुलिस-प्रशासन के जुल्म व दमन के शिकार आदिवासी झारखंडी जनता संविधान प्रदत्त अधिकार पंचायत उपबंध अधिनियम पेसा कानून को गांव में ग्रामसभा के जरिये लागू करने के उद्देश्य से पत्थलगड़ी (पत्थरों पर ग्रामसभा के अधि कार लिखकर गाड़ने) के कार्यक्रम परम्परागत रूप से चला रही है। पत्थलगड़ी का यह कार्यक्रम नया नहीं है, पहले से जारी है और पत्थलगड़ी आदिवासियों की संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। ऐसे में रघुवर दास सरकार द्वारा पत्थलगड़ी को संविधान विरोधी और गरीबों के खिलाफ साजिश करार देना हास्यास्पद है तथा संविधान प्रदत्त पेसा कानून से आदिवासियों को वंचित करने की रघुवर दास सरकार की साजिश के सिवा और कुछ नहीं है। पत्थलगड़ी परंपरा आदिवासी समुदाय की सदियों की परंपरा रही है। खूंटकट्टी आदिवासी के पास कोई जमीन का पट्टा नहीं होता है, उनका जमीन का प्रमाण पत्थलगड़ी से ही होता है। पत्थलगड़ी व्यवस्था खत्म हुआ तो आदिवासियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा।

आवें, जल-जंगल-जमीन पर अपना हक-अधिकार कायम करने के लिए हमारे पूर्वजों (सिद्धू-कान्हू और वीर बिरसा मुण्डा) द्वारा दिखाये गये संघर्षों के शानदार रास्ते पर आगे बढ़ें। हमारे पूर्वजों ने शोषक वर्गों के साथ समझौता नहीं, बल्कि आखिरी दम तक संघर्ष किया है। लेकिन आज जितने भी वोटबाज/संसदीय पार्टियां हैं, वे सब के सब अपने चंद स्वार्थों के लिए शोषक वर्गों के साथ समझौता कर लिया है। हमें उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। भाकपा (माओवादी) ही हमारे देश में एक मात्र पार्टी है जो हमारे पूर्वजों द्वारा दिखाये रास्ते पर चल रही है और 'अबुआ: दिशोम रे अबुआ: राज' के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष कर रही है। विस्थापन और पलायन का शिकार होने के बजाय संघर्ष की राह पर चलकर उन लूटेरों (शोषक वर्ग) का खत्मा करना होगा। लड़कर ही हमें जल-जंगल-जमीन सहित अपनी भाषा, शिक्षा, संस्कृति तथा आत्मनिर्णय के अधिकार को हासिल करना संभव है।

सरकार संरक्षित प्रतिक्रियावादी सशस्त्र खुफिया गिरोह टीपीसी, जेपीसी, पीएलएफआई, जेजेएमपी, शांति सभा, सेन्द्रा कमेटी आदि का राजनीतिक भंडाफोड़ कर उखाड़ फेकें!

-सम्पादकमण्डल, लाल चिनगारी

उत्तरी छोटानागपुर जोनल कमेटी द्वारा जनवरी, 2018 में जारी पर्चा

तथाकथित मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंको तथा पूरे जोश-खरोश के साथ जनता की जनसत्ता स्थापित करने के काम को और आगे बढ़ावें!

प्रिय कामरेडो व दोस्तो,

जैसाकि सर्वविदित है कि गत 2017 साल के 9 जून को गिरिडीह जिला के पीरटांड़ प्रखंड अन्तर्गत ढोलकट्टा गांव निवासी मोतीलाल बास्के की फर्जी मुठभेड़ में हुई हत्या तथा हत्या के दोषी पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दायर हो, उनकी गिरफ्तारी हो और आहत परिवारजनों को मुआवजा यानी समुचित सुविधाएं मुहैया हो, इसके लिए जनआन्दोलन क्रमशः 13 जून से शुरू होकर 4 दिसम्बर 2017 तक लगातार चलते रहा। आन्दोलन सड़क से सदन तक पहुंचा।

लगातार सात महीने तक चलते रहा जनआन्दोलन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों में से बाबूलाल मरांडी, शिबु सोरेन, हेमंत सोरेन और रघुवर दास सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे आजसू पार्टी के विधायक, झामुमो के सांसद-विधायक सहित और-और पार्टियों के नेता भी शामिल रहे। लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी यानी फर्जी मुठभेड़ में की गयी हत्या की सरकार ने आजतक कोई सुधी नहीं ली। हत्या के दोषी पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दायर होना, उनकी गिरफ्तारी होना और आहत परिवारजनों को मुआवजा मिलना तो दूर की बात रही। ऐसाकि लगातार सात महीने तक आन्दोलन चलता रहा, पर आज तक एक अदना सा अफसर तक नहीं पहुंचा हत्याकाण्ड की संज्ञान लेने के लिए।

लेकिन, हां ये साफ है कि लगातार सात महीने तक चला जनान्दोलन से सरकार का लोकतंत्र का पुलिस-प्रशासन का चेहरा बेनकाब हुआ है। और ये बात किसी की समझदारी से बाहर नहीं रही कि मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था झूठ फरेब और ढकोसला है। यानी मौजूदा सरकार अमीरों की है गरीबों की नहीं। इनके सिविक एक्शन प्लान का मतलब है जनता को कुछ सुविधा देना, लेकिन यहां देखा जाए तो हुआ है उल्टा, जनता को मारा जा रहा है। तो क्या यही है लोकतंत्र? नहीं। लोकतंत्र का मतलब ही है ''जनता का, जनता के लिए एवं जनता द्वारा'' यानी पहले लोक तब तंत्र। पर यहां ठीक इसके उल्टा है लोक हाशिये पर हैं और तंत्र का बोलबाला है अर्थात् लोक गायब हैं तंत्र हावी है। इसलिए ही उक्त घटनाक्रम को लेकर सात महीने तक चला आन्दोलन का नतीजा जनता की उम्मीद के अनुसार नहीं निकला। ऐसे में ऐसी तथाकथित लोकतांत्रिक मौजूदा सत्ता व्यवस्था से नतीजे की उम्मीद लगाए रहना बेकार है। चाहे सरकार में कोई भी चुनावबाज पार्टी या दल क्यों न हो, न्याय दे नहीं सकती। इसलिए अपनी सरकार यानी जनता की जनसरकार बनाना निहायत जरूरी है।

अतः भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के उत्तरी छोटानागपुर जोनल कमिटी किसान-मजदूर, छात्र-नौजवान, मेहनती महिलाएं, दलित, आदिवासी, शोषित-उत्पीड़ित जनता, धार्मिक अल्पसंख्यकों, प्रगतिशील बुद्धिजीवी, क्रांतिकारी जनवादी ताकतों से आह्वान करती है कि तथाकथित मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने तथा पूरे जोश-खरोश के साथ जनता की जनसत्ता स्थापित करने के काम को और आगे बढ़ावें।

भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी द्वारा दिसम्बर, 2017 में जारी प्रेस विज्ञप्ति

जिनगु नरसिम्मा रेड्डी का शर्मनाक विश्वासघात और आत्मसमर्पण मुर्दाबाद!

समझौताविहीन संघर्ष और निःस्वार्थ कुर्बानी की क्रांतिकारी परंपरा जिंदाबाद!

क्रांति अपने रास्ते से सभी कचरों को हटाकर आगे बढ़ेगी!

हमारी पार्टी के एक केन्द्रीय कमेटी सदस्य जिनगु नरसिम्मा रेड्डी (राजेश, सूरज) ने दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वह पहले ही सर्वहारा वर्ग की विचारधारा, माओवादी पार्टी, दीर्घकालीन लोकयुद्ध, क्रांतिकारी आन्दोलन और उत्पीड़ित जनता की अपराजेयता पर विश्वास खो चुका था। वस्तुनिष्ठ बदलावों से वर्ग संघर्ष में पैदा हुए मुश्किलों और नये बदलावों व दुश्मन के तीव्र होते हर तरह के हमलों का सामना ना कर पाने से, उसने भाग खड़े होने के सबसे स्वार्थी, घृणित और कायर रास्ते का चुनाव किया और निर्लज्जता से दुश्मन के सामने घुटने टेक दिया। यह भारतीय सर्वहारा, उसके हिरावल दस्ते-पार्टी, भारतीय क्रांति और देश की मेहनतकश जनता से सीधा-सीधा विश्वासघात है। यह हजारों क्रांतिकारी शहीदों का अपमान है, जो उस दुश्मन के साथ लड़ते हुए शहीद हो गये, जिसको राजेश ने आज गले लगा लिया है। इसके साथ ही, क्रांतिकारी आन्दोलन में उसके तीन दशकों के राजनीतिक जीवन का निन्दनीय अन्त हो गया है। हमारी केन्द्रीय कमेटी उसके विश्वासघात की कड़े शब्दों मे निन्दा करती है और पार्टी की कतारों, संपूर्ण क्रांतिकारी खेमे, व्यापक संघर्षरत जनता और भारतीय क्रांति के दोस्तों को ऐसे विश्वासघातियों और उनके घृणित आत्मसमर्पणवादी रास्ते को अस्वीकार करने की अपील करती है। नरसिम्मा रेड्डी के पतन और आत्मसमर्पण से अडिग हमारी केन्द्रीय कमेटी दृढ़ता और सुस्पष्ट ढंग से हमारी पार्टी के फौरी और अंतिम लक्ष्य का अनुसरण करने के लिए वर्ग संघर्ष के रौशन लाल झण्डे को उंचा उठाए रखने की अपनी शपथ को दोहराती है।

नरसिम्मा रेड्डी 80 के दशक के शुरूआत मे आन्दोलन से तब जुड़ा था, जब वह हैदराबाद की एक फैक्ट्री मे तकनीशियन के तौर पर काम कर रहा था। बाद में वह पेशेवर क्रांतिकारी बना और पार्टी ने उसे वारंगल के एटुनागारम् जंगल के एक छापामार दस्ते में काम करने के लिए भेजा था। बाद में वह 1986 और 1995 के दरमियान दल कमांडर, एरिया कमेटी सदस्य, जिला कमेटी सदस्य और सचिव के तौर पर विकसित हुआ। 1995 में उस जोन में छापामार युद्ध को उच्च स्तर पर विकसित करने के लिए उत्तर तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी बनाई गई, तब वह एन.टी.एस.जेड.सी. के लिए निर्वाचित हुआ। सन् 2001 में वह एन.टी.एस.जेड.सी. का सचिव बना और 2007 तक इस पद पर रहा। वह 2001 में केन्द्रीय कमेटी के लिए निर्वाचित हुआ और 2001 से 2007 के बीच एक केन्द्रीय कमेटी के सदस्य के तौर पर उत्तर तेलंगाना में ही काम किया। 2007 मे उसे केन्द्रीय मिलिट्री कमीशन में को-ऑप्ट किया गया और वे उत्तर तेलंगाना और केन्द्रीय रीजन के कुछ अन्य भागों में काम किया। 2011 में उसे उड़ीसा बदली किया गया और 2016 के अन्त तक वह वहीं कार्यरत था। पिछले एक साल से वह वैचारिक और राजनीतिक ढुलमुलपन में बुरी तरह डूब चुका था और नवम्बर 2017 में उसने संबंधित केन्द्रीय कमेटी सदस्य को आत्मसमर्पण करने के अपने फैसले से अवगत करा दिया था।

यह सही है कि नरसिम्मा रेड्डी ने क्रांतिकारी आन्दोलन में तीन दशकों के अपेक्षाकृत लम्बे समय के लिए भागीदारी की थी और राजनीतिक रूप से विकसित होकर उसकी सर्वोच्च नेतृत्वकारी कमेटी, केन्द्रीय कमेटी का सदस्य बना था और इस प्रक्रिया में आन्दोलन में योगदान किया था। पर उसके साथ ही साथ, उसमें कई गंभीर कमजोरियां और व्यक्तिवाद, नौकरशाही और झूठे अहंकार जैसी गैर-सर्वहारा प्रवृत्तियां भी थी, जोकि उसके संपूर्ण राजनीतिक जीवन में बनी रही। उसके साथ छापामार दस्तों और पार्टी कमेटियों में काम करने वाले कामरेडों और नेतृत्वकारी कामरेडों ने उसके इन नकारात्मक पहलुओं पर लगातार संघर्ष किया। संबंधित कमेटियों ने उसे सुधारने के लिए हर कदम पर प्रयास किया और उसने भी एक तरह या दूसरे तरह से अपनी कई आलोचनाओं को माना, पर उसकी कमजोरियां, गलतियां और बाधाएं बनी रही। खासकर पिछले कुछ सालों में यह नकारात्मक पहलू बढ़ गये और आखिरकार पार्टी और आन्दोलन के इन वर्तमान हालातों में प्रधान पहलू बन गये। दुश्मन का आतंक उसके उपर इस हद तक सवार हो गया था कि वह पार्टी द्वारा दिये गये कार्यभार भी पूरा करने लायक नहीं रहा था। दुश्मन के संभावित हमलों का बहाना बनाकर महत्वपूर्ण बैठकों में आने से भी इंकार कर दिया। उच्च कमेटी के साथियों के अलावा, उसकी रक्षा मे तैनात कामरेड भी उसके डरपोक व्यवहार और पलायनवाद की आलोचना किये थे। हालात और दुश्मन का तीव्र हमला यह मांग करता है कि पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्वकारी साथी रणक्षेत्र में दृढ़ता और विशवास के साथ रहे और साहस के साथ पार्टी, पीएलजीए और क्रांतिकारी आन्दोलन की रक्षा के अभिन्न अंग के रूप में खुद को सुरक्षित रखे। क्रांतिकारी कार्य के सभी क्षेत्रों समेत सैन्य क्षेत्र में भी ऐसा करना होता है। पर एक केन्द्रीय कमेटी सदस्य होने के नाते

नरसिम्मा रेड्डी पार्टी द्वारा उसे दी गई उच्च स्तर की जिम्मेदारियों और कार्यभारों को उच्च स्तर की राजनीतिक चेतना, तैयारी, साहस, अनुशासन, अत्म-बलिदान, स्व-आलोचनात्मक रूख और अन्य नेतृत्वकारी गुणों को दर्शाते हुए पूरा करने की कसौटी पर खरा उतरने मे नाकाम रहा।

हमारी केन्द्रीय कमेटी ने नरसिम्मा रेड्डी के काम को उसकी लगातार चल रही कमजोरियों और सीमाओं, जोकि गम्भीर स्तर तक पहुंच गई थी, की दृष्टि से समीक्षा की। केन्द्रीय कमेटी निष्कर्ष निकाली कि वह गंभीर रूप से मनोगतवाद की दलदल मे फंस चुका था, जिसकी परिणति उसका दुश्मन के बारे में अति-मूल्यांकन और क्रांतिकारी आन्दोलन व जनता की ताकत के बारे में कम-आकलन के तौर पर हुई। उसने अपनी सहनशीलता और अपने लक्ष्य के मायने खो दिया, पार्टी की नेतृत्वकारी कमेटी के सदस्य होने के नाते वास्तविक हालातों का विश्लेषण करने के नाकाबिल हो गया, बारम्बार गलत सांगठनिक तौर-तरीके अपनाया और पार्टी द्वारा उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों को निभाने मे पूर्णत: विफल हो गया। यह उसका पार्टी कमेटियों पर अपनी व्यक्तिपरक और व्यक्तिवादी सोच थोपने के अतिरिक्त था। अलग-अलग समस्याओं पर संकीर्ण और मनमाने तरीके अपनाना, जनवादी केन्द्रीयता और सर्वहारा अनुशासन की अवहेलना करते हुए बवाल खड़े करना और तर्कविहीन वाद-विवाद करना, उसकी आदत बन गई थी। कई बार तो उसने संबंधित पार्टी कमेटियों में गतिरोध खड़ा कर दिया और कई बार दूसरे साथियों द्वारा उसकी कमजोरियों को दूर करने के लिए एकता-संघर्ष-एकता के सिद्धांत पर आधारित आलोचना किये जाने पर बैठक का बहिष्कार करने की धमकियां तक दे डाली। पर वह अपने नकारात्मक पहलुओं की गंभीरता को पहचानने में असफल रहा, हठधर्मितापूर्वक स्व-आलोचनात्मक रूख अख्तियार करना अस्वीकार कर दिया, मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद की रोशनी में अपने विश्व दृष्टिकोण को पुन: ढालने में असफल रहा। ना सिर्फ यह उसके पतन का कारण बना बल्कि पार्टी को भी बहुत नुकसान पहुंचाया।

इन सब को ध्यान में रखकर केन्द्रीय कमेटी ने इस आशा के साथ कि वह अपनी गलतियों और कमजोरियों को समझेगा और अपने साथियों के साथ मिलकर खुद को सुधारने का प्रयास करेगा, उसे दो साल के लिए केन्द्रीय कमेटी से निलंबित किया था। तब भी उसने ना तो इस फैसले को सकारात्मक रूप से लिया, न ही कोई स्व-आलोचना की। केन्द्रीय कमेटी द्वारा उसे दी गई राज्य कमेटी सदस्य की जिम्मेदारी को लेना भी अस्वीकार कर दिया । टूटपुंजिये झूठे अहंकार और खुदगरज तंग नजरिये से वशीभूत होकर उसने पार्टी के फैसले को मानने से इंकार कर दिया, अपने अन्दर के गैर-सर्वहारा रूझानों के खिलाफ संघर्ष करने से भी इंकार कर दिया और खुद को एक पक्का कम्युनिस्ट क्रांतिकारी के तौर पर देखने में असफल रहा। क्रांति और जनता को विनम्रतापूर्वक और सिर झुका कर सेवा करने के बजाय उसने आत्मसमर्पण करने और दुश्मन की सेवा करने वाला नीच आदमी बनना ज्यादा अच्छा समझा। इस तरह, एक क्रांतिकारी से कट्टर विश्वासघाती और बदमाश बनने का उसका रूपांतरण पूरा हो गया।

जब केन्द्रीय कमेटी ने उसके निलंबन का फैसला लिया, उसने पार्टी लाइन से राजनीतिक मतभेद खड़े कर दिये। उसने चर्चा उठायी कि ''भारत अब अर्ध-सामंती व अर्ध-उपनिवेशिक नहीं रहा, यह एक पूंजीवादी देश में बदल गया है।'' इसलिए, परिस्थितियों के अनुसार हमारी पार्टी लाईन बदली जानी चाहिए और वर्तमान हालातों में पार्टी को आम बगावत की लाईन अख्तियार करनी चाहिए। उसने यह सब अपने मंच पर चर्चा नहीं किया, बल्कि कुछ अलग-अलग कामरेडों के साथ चर्चा किया। उन कामरेडों ने उसे सलाह दी थी कि ''तुम्हें मुद्दे को सुलझाने के लिए पार्टी के मंच पर चर्चा करनी चाहिए।'' पर वह इसके लिए तैयार नहीं था और वह पार्टी छोड़ चला गया। यह राजनीतिक मतभेद और कुछ नहीं बल्कि अपने पतन पर पर्दा डालना है।

सभी क्रांतियां टेढ़े-मेढ़े रास्तों, उतार-चढ़ावों और मुश्किल हालातों से होकर गुजरती है। इन चुनौतियों को बहादूरी से पार कर ही एक सर्वहारा पार्टी इस्पात बनती है और क्रांति को विजय तक पहुंचाने की काबिलियत हासिल करती है। ऐसे समय पर, सभी कम्युनिस्टों खासकर वह जो गैर-सर्वहारा वर्ग से कम्युनिस्ट पार्टी में आये हैं, के लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि वह अपनी विचारधारात्मक और राजनीतिक समझदारी को और गहरा करें, खुद को सर्वहारा के विश्व दृष्टिकोण अपना कर ढालें और मजबूती से उस पर लगे रहें, उन्हें और ज्यादा दृढ़ता से जनवादी केन्द्रीकरण के नियम का पालन करना, कामरेडों और जनता के साथ और नजदीकी से जुड़ना, व्यवहार से सीखना, गलतियों को सुधारना, खुद से संघर्ष करना, निष्काम भाव से जनता की सेवा करना चाहिए और आखिरी मंजिल तक एक समर्पित क्रांतिकारी बने रहने के लिए संघर्ष के अग्रिम मोर्चे पर खड़े रहना चाहिए। पर इस तरह के परीक्षा के समय असफल होने वाले भी हमेशा रहेंगे। इतिहास बताता है कि ऐसे मुट्ठी भर व्यक्तियों का जो खुद को पुन: ढाल नहीं पाते और जो कुर्बानी के लिए तैयार नहीं होते, उनका निर्णायक समय पर भाग खड़ा होना आम बात है। वह हमेशा अपने बचाव को प्रधानता देते हैं। वह क्रांतिकारी खेमे को छोड़ भाग जाते हैं और कई बार दुश्मन की सेवा करने वाले प्रतिक्रांतिकारी बन जाते हैं। नरसिम्मा रेड्डी, ऐसे क्रांतिकारी का एक नकारात्मक उदाहरण है, जिसने कैडर और जनता के साथ घुलना-मिलना छोड़ दिया था, जिस पर

दुश्मन का डर सवार हो गया था और जिसने अपनी कमजोरियों से संघर्ष करना बंद कर दिया था। क्रांति ऐसे लोगों को रद्दी माल के तौर पर रद्द कर देगी और वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया में समय-समय पर इन्हें उठाकर बाहर फेंक देगी।

इसमे कोई हैरानी की बात नहीं होगी, अगर ऐसे घृणित व्यक्ति कल को दुश्मन की सुर में सुर मिलाने लगे और पार्टी, उसके नेतृत्व, क्रांतिकारी आन्दोलन और भारतीय क्रांति के भविष्य पर आशंका दिखाने लगे एवं दुश्मन की मदद से ऐसे लोग पार्टी और क्रांति को नुकसान पहुंचाने के एक मात्र उद्देश्य के साथ झूठे बुद्धिजीवी, पत्रकार, समाजसेवी आदि बन कर जनता के सामने आए। हमारे कामरेडों, दोस्तों और भारतीय क्रांति के शुभचिन्तकों को ऐसी संभावनाओं के बारे में चौकस रहना चाहिए और उनका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। यह समझकर कि यह दुश्मन का गोयबल्सवादी प्रचार का हिस्सा है, वर्ग-चेतन मेहनतकश जनता को ऐसे द्रोहियों की ऊट-पटांग को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए। द्रोहियों और विश्वासघातियों के विपरीत प्रत्येक सर्वहारा क्रांति, समझौता ना करने वाले कम्युनिस्ट योद्धाओं को सामने लाती है, जो अपनी आखिरी सांस तक जनता की सेवा करते हैं। भारतीय क्रांति भी कोई अपवाद नहीं है, इसके पास हजारों निस्वार्थ कुर्बानी देने वाले वीर शहीदों की लम्बी और शानदार विरासत है। उनमें हमारे महान नेता और कैडर जैसे कि कामरेड सी.एम. और के.सी. , सरोज दत्त, सुशितल राय चौधरी, अमूल्य सेन, सत्यम, कैलासम, अप्पु, वर्गिज, बिश्वकर्मा, बालन, दिनकर, श्याम, महेश, मुरली, करम सिंह, परिमल सेन, राजमौली, वड़कुर चन्द्रमौली, अनुराधा गांधी, पटेल सुधाकर, चेरूकेरी राजकुमार, कोटेश्वर राव, रऊफ, सुशील राय, श्रीधर श्रीनिवासन, नियामुद्दीन, आशीष यादव, प्रसाद, दया, प्रभाकर, भगनू, शहीदा, आरके, यादन्ना, माधव, महेन्द्र, मस्तान राव, पुल्ली अन्जना, कंचन, शशिधर महतो, जनार्दन, भुमैया-किश्टा गौड़ और हजारों अन्य शहीद कामरेड हैं, जिनमें से कुछ का यहां नाम दे रहे हैं। यह सब क्रांति और जनता के प्रति अपनी वचनबद्धता पर अडिग रहे। यह सब जनता के सच्चे नायक हैं, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है।

प्रतिक्रांतिकारी शासक वर्गों के भुगतान-रजिस्टरों में दर्ज कुछ विश्वासघातियों का भागना, उनका धोखा और कपट क्रांति को कभी रोक नही सकता। वह सिर्फ कुछ वक्ती रूकवाटें डाल सकते हैं और कुछ वक्ती नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर क्रांति ऐसे सभी कीटों को झाड़ू लगाकर कब्र में पहुंचा देगी और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगी। सर्वहारा क्रांतिकारियों के नेतृत्व द्वारा और वीर शहीदों से प्रेरणा पाकर इस देश की लाखों-लाख उत्पीड़ित जनता ऐसे लोगों और उनके आकाओं को इतिहास की रद्दी की टोकरी में डाल देगी और अपनी अंतिम जीत हासिल करेगी।

पाठकों से अपील

आप सभी भली-भांति जानते हैं कि लाल चिनगारी के प्रकाशन में कई तरह के दिक्कतों के बावजूद नियमित रूप से इसे प्रकाशित किया जा रहा है।

अत: आप सभी लाल चिनगारी पाठकों को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक दिन हमारे इलाके में बर्बर ऑपरेशन ग्रीन हंट के तीसरे चरण में 'मिशन 2017' के तहत घट रहे घटनाओं जैसे-बर्बर पुलिसिया जुल्म-अत्याचार, पुलिस, प्रतिक्रियावादी और वर्ग दुश्मनों द्वारा गठित विभिन्न नामों के सशस्त्र खुफिया गुण्डा गिरोह के द्वारा मार-पीट, हत्या, बलात्कार करने से लेकर विभिन्न तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावे हमारी पार्टी के द्वारा संचालित जनमुक्ति छापामार सेना के द्वारा कई शानदार कार्रवाइयों समेत जनता के द्वारा कई जनांदोलन किये गए हैं एवं किये जा रहे हैं। इस कार्रवाइयों के दौरान हमारे पीएलजीए के योद्धा बहादूरी के साथ संघर्ष करते हुए शहादत दे रहे हैं। फिर पुलिस व सशस्त्र खुफिया गुण्डा गिरोहों के मिलीभगत से हमारे नेता, कार्यकर्त्ता व समर्थक जनता की फर्जी मुठभेड़ में हत्याएं कर रहे हैं।

अत: सभी लाल चिनगारी पाठकों से अपील किया जाता है कि ऐसे तमाम घटनाओं का रिपोर्ट आप नियमित रूप से लाल चिनगारी संपादकमंडल को भेजें। साथ ही साथ विभिन्न मुद्दों पर लेख-आलेख, खासकर शहीदों की जीवनी फोटो के साथ नियमित रूप से भेजते रहें और लाल चिनगारी में प्रकाशित लेखों पर भी अपनी प्रतिक्रिया भेजें ताकि लाल चिनगारी को और भी समृद्ध किया जा सके।

-सम्पादकमंडल, लाल चिनगारी

पीएलजीए की महत्वपूर्ण कार्रवाइयों की रिपोर्ट

यू. जोन की रिपोर्टः-

बीजे सैक द्वारा घोषित बिहार-झारखंड में 18-19 दिसम्बर को विरोध दिवस व 20 दिसंबर को 24 घंटे बंदी यू. जोन में सफल किया गया

बुढ़ा पहाड़ पर हो रहे सेना के आर्मर यूनिट द्वारा बमबारी के खिलाफ बीजे सैक की ओर से घोषित 18-19 दिसम्बर, 2017 को विरोध दिवस के साथ-साथ 19 दिसम्बर को व्यापक रूप से मशाल जुलूस व 20 दिसम्बर को 24 घंटे बंद को लेकर क्रांतिकारी किसान कमिटी, जनमिलिशिया व पीएलजीए के कामरेडगण ने यू. जोन अंतर्गत कई इलाके में पहले पोस्टरिंग किया। गिरिडीह जिला के गिरिडीह मुफस्सिल के बनियाडीह, मोहनपुर, श्रीरामपुर, पचम्बा आदि जगहों पर, डुमरी प्रखण्ड में कई जगहों पर व पीरटांड़ प्रखण्ड के चिरकी, मधुबन, हरलाडीह, धावाटांड़ आदि जगहों पर, बोकारो जिला के पेंक, गोनियांटो, हरलाडीह, नारायणपुर, जुड़ामना आदि जगहों पर एवं हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ प्रखण्ड के गाल्होबार, नरकी आदि जगहों पर पोस्टर चिपकाया गया। 19 दिसम्बर की रात 8-9 बजे के बीच हथियार के साथ मशाल जुलूस जनमिलिशिया एवं क्रांतिकारी किसान कमिटी के नेतृत्व में तीन जगहों पर सफल किया गया।

इसके बाद बंदी को सफल करने के लिए गिरिडीह-डुमरी रोड पर किसान कमिटी और जनमिलिशिया के कामरेडों ने पेड़ काट कर रोड को अवरूद्ध किया, आधा घंटा के बाद एक ट्रक आई, जैसे ही साथी लोग गाड़ी को जलाने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही पुलिस अंधाधुंध फायरिंग करने लगी, इस फायरिंग को देख कर किसान कमिटी के साथी पीछे हट गये, लेकिन दिन भर एक भी गाड़ी नहीं चली।

इस तरह से बीजे सैक द्वारा बुढ़ा पहाड़ पर हो रहे बमबारी के खिलाफ विरोध दिवस व 20 दिसम्बर के बिहार-झारखंड बंद को यू. जोन में सफल किया गया।

एसपीओ भर्था मांझी का सफाया

गिरिडीह जिला के मधुबन थाना अंर्तगत ग्राम भागाबान्ध के एसपीओ भर्था मांझी विगत 2 सालों से पुलिस का दलाल यानी एसपीओ का काम करते आ रहा था। जबसे रिझुवारी (पारसनाथ पहाड़) में सी.आर.पी.एफ. का कैंप बना है, उसी समय से वह पुलिस कैम्प में रहकर हमारी पार्टी और दस्ता की गतिविधि के बारे में लगातार समाचार संग्रह करके पुलिस को दे रहा था। इसके अलावे, रिझुवारी कैम्प से छापामारी करने जब भी निकलती थी, तब रास्ता छोड़कर सीधे जंगल-जंगल से पुलिस का पायलटिंग करके हमारे गांव व दस्ता के शेल्टर में पुलिस को ले जाता था। इतना ही नहीं, हमारे गांव स्तर के कार्यकर्ता के बारे में समाचार संग्रह करना, समर्थकों की सूची बनाकर पुलिस को देना, जंगल के रास्ता को बताना-दिखाना आदि जनविरोधी-पार्टीविरोधी कार्य भी वह कर रहा था।

भर्था का ऐसा कुकर्म देख कर जनता में उसके प्रति घोर घृणा भर गई थी, तब केकसी व पीएमएस के कामरेडों ने मिलकर भर्था को पकड़ा और पीएलजीए के हवाले कर दिया। तव पीएलजीए ने जनअदालत लगाकर भर्था को जनअदालत के फैसलानुसार 8 जनवरी, 2018 को सफाया कर दिया, इसका प्रभाव जनता पर काफी अच्छा पड़ा।

एसपीओ युगल राणा का सफाया

हजारीबाग जिला के चरही थानार्न्तगत ग्राम गोन्दलपुरा का युगल राणा आज से 7-8 साल पहले से एसपीओ का सक्रिय रूप से काम करते आ रहा था। युगल राणा ने हमारे कई कार्यकर्ता को गिरफ्तार करवाया था और 2009 में चरही रोड पार करते समय हमारे पीएलजीए को पुलिस एम्बुश में फंसाया था, जहां घन्टों गोलीबारी भी हुई थी। हमारे पीएलजीए द्वारा सुझ-बूझ से संघर्ष करने के कारण हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावे भी और कई प्रकार के नुकसान पहुंचा चुका था।

युगल राणा के ऐसे कुकर्म को देख वहां का पीएमएस लगातार उसपर नजर रख रहा थे, पर मौका नहीं मिल पाने के कारण लम्बे दिनों तक उसको सजा नहीं दे पाया था। पर जैसे ही मौका मिला, हमारे पीएमएस के कामरेडों ने युगल राणा को 7 जनवरी, 2018 को मौत का सजा दे दिया। जिसका अच्छा प्रभाव पूरे इलाके में पड़ा है और इस इलाके के एसपीओ के बीच डर पैदा हो गया है।

डी. जोन की रिपोर्टः-

मजदूर विरोधी ठेकेदार के 5 वाहन को आग लगाया गया

दक्षिण जोनल कमिटी अंर्तगत पोड़ाहाट सबजोनल क्षेत्र के गांव कुदाबुरू थाना-सोनुवा, जिला-पश्चिम सिंहभूम पनसुवां डैम के केनाल के कार्य में लगे केडी कंस्ट्रक्सन कंपनी के 5 वाहन (1 जेसीबी व 4 ट्रैक्टर) को जलाया गया, पनसुवां डैम से लेकर 30 किलोमीटर तक काम करा रहे केडी कंस्ट्रक्सन कंपनी के मालिक से सम्पर्क कर कार्य को

रूकवाया गया था एवं जनता का सही मजदूरी दर देने के लिए कहा गया था। लेकिन मालिक मजदूरों को सही भुगतान नहीं कर रहा था, इसलिए काम को पुनः रूकवाया गया। उसने कुछ दिन तो काम बंद रखा, लेकिन फिर से मौका देखकर एवं उस क्षेत्र में दुश्मन की गतिविधि जब रही थी, उसी समय काम चालू कर दिया और पहले जिस रवैया से काम चला रहा था, वैसे ही काम करा रहा था। मजदूरों से कभी-कभी 10-12 घंटा भी काम करवाता था और गाली-गलौज व मारपीट भी करता था। मजदूर उसके डर से कुछ भी नहीं बोल पाता था।

यह बात ग्रामीण आम जनता द्वारा हमारे पी.एल.जी.ए. साथियों को बतायी गई, तो हमारे पी.एल.जी.ए. ने जनता व मिलिशिया के साथियों के साथ मिलकर 8 जनवरी, 2018 को दिनदहाड़े जाकर सभी गाड़ी को एक-एक करके आग के हवाले कर दिया।

झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास व डीजीपी ने घोषणा किया था कि 2017 के दिसम्बर महीना तक माओवादियों का खत्मा कर दिया जएगा, उसी लक्ष्य से पोड़ाहाट सबजोनल के अंतर्गत 5 स्कूल भवन में पुलिस कैम्प कर 5 हजार फौजी को तैनात कर लगातार 20-25 दिन तक अभियान चलाया था लेकिन अभियान-अभियान ही रह गया। हमारा कुछ भी नुकसाान नहीं कर पाया, हमारे संगठन का काम-काज पहले जिस तरह चल रहा था, ठीक वैसे ही आज भी चल रहा है। 8 जनवरी, 2018 को दुश्मन के नजदीक जाकर हमारे पीएलजीए ने साहस के साथ कार्रवाई किया, इस कार्रवाई से जनता के बीच में हमारे संगठन का अच्छा प्रभाव पड़ा है।

एसपीओ असियन पुर्ती का सफाया

असियन पुर्ती (28), पिता- पतरस पुर्ती, पोस्ट-उलिहातु-बड़ी निजकेला, थाना-अड़की, जिला- खूंटी (झारखंड) का रहने वाला था। असियन पुर्ती 2009 से पहले हमारे पार्टी का ही काम-काज कर रहा था। वह गद्दार कुंदन पाहन के देख-रेख में ही काम कर रहा था, वह कुंदन पाहन का कुरियर का काम करता था। आशियन को कुंदन पाहन जो भी मिलिट्री संबंधित सामान बोलता था, वह आसानी से लाकर दे देता था। लेकिन पाहन को तब तक कुछ भी नहीं पता था, जिस कारण कुंदन पाहन एक एसपीओ को मारने के लिए कार्बाइन भी उसको दिया था। असियन सारा सामान कहां से ला रहा है? इसको कौन सप्लाई दे रहा है? जब यह बात सामने आई, तो उसके ऊपर शक होने लगा, तो उस पर संगठन के तरफ से निगरानी रखा गया। तब उसका पता चला कि उसे सारा सामान खूंटी एवं रांची एसपी ही उपलब्ध कराता था एवं उससे सारी गतिविधि के बारे में रिपोर्ट लेता था। यह बात जब तक पार्टी को पता चला, तब तक उसको भी भनक लग गया। बाद में वह सतर्क हो गया एवं पार्टी से अब बनाना शुरू किया और बाद में पार्टी से दिया हुआ एक हथियार के साथ जाकर खूंटी व रांची एसपी से जा मिला व पुलिस ऑफिसर के देख-रेख में खूंटी एवं रांची में ही रहने लगा। उसका गांव-घर पार्टी कार्य क्षेत्र के अंदर में है, लेकिन वह गांव-घर छोड़कर पत्नी को भी खूंटी में ले जाकर एसपी के देख-रेख में ही दोनों पति-पत्नी रहने लगा और वहीं से पार्टी की गतिविधि की रिपोर्ट लेकर पुलिस के आला अधिकारी को देते रहा।

आसियन पुर्ती एक मिशनरी (आदिवासी) लड़का था और वह लोकल था, इसलिए उसका रिश्तेदार चारों तरफ ही था, जिस कारण उसको रिपोर्ट रांची-खूंटी में रहकर भी फोन के जरिए आसानी से मिल जाता था। उसका संबंधी भी समझता था कि वह भाकपा (माओवादी) पार्टी का काम करता है। यह समझकर पूरा-पूरी रिपोर्ट कर देता था। वह भी अपने आप को पार्टी वाला ही बोलकर रिपोर्ट लेने का काम करता था। स्थानीय होने के चलते वह 4-5 भाषा भी आसानी से बोल लेता था। उसका कार्यक्षेत्र खूंटी, अड़की, मारांगहादा, बुण्डु, तमाड़ चौका, चाण्डिल, रांची, सरायकेला, खरसावां तक था और वह सभी जगहों के एसपी का इतना विश्वासी हो गया था कि जब रिपोर्ट कर देता था, तो उसके रिपोर्ट के अनुसार ही चाहे रात हो या दिन किसी भी समय और किसी भी जगह, चाहे कितना भी जंगल इलाका हो पुलिस घुस जाती थी। कभी-कभार तो ऐसा भी देखा गया कि तुरंत एक्शन टीम बनाकर एवं उस टीम का पायलटिंग करके खुद पीएलजीए को मार गिराने का लक्ष्य लेकर घुसता था। वह पुलिस के खाने-पीने का भी व्यवस्था करता था एवं नया-नया एसपीओ का भी व्यवस्था करता था और कई एक साथियों को पकड़वाने एवं सरेंडर करवाने का भी काम दिया गया था। हमारे एक साथी को कवासाल बाजार से पकड़वाया।

एक दिन 6-7 आदमी मिलकर एक सफेद बोलोरो से इलाके में घुसा एवं हमारे संगठन के 5-6 कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा एवं अपने पिस्टल से 3 गोली भी चलाया ताकि जनता के बीच में दहशत बना रहे एवं डर से उसका साथ दे। पार्टी का जंगल में छिपाया हुआ 48 माईन को पुलिस के साथ जाकर उठाया एवं पुलिस को दे दिया था। ये सब करने के एवज में पुलिस उसको भारी रकम देता था, जिस कारण वह और आगे बढ़कर काम करता था। पुलिस के दिशा-निर्देशन पर रिपोर्ट उठाने का एक नया पॉलिसी अपनाया था, वह कम उम्र की लड़की, जो हाई स्कूल एवं कस्तुरबा विद्यालय में पढ़ाई करती है, उन सब लड़की को भी अपने चंगुल में फंसाकर उनलोगों के शरीर के साथ खिलवाड़ भी करता था एवं 3-4 हजार रूपये का लोभ-लालच देकर हमारे गरीब आदिवासी बहन-बेटियों के जरिए पूरे इलाके का रिपोर्ट उठाता था। इस तरह से उसने अपने काम को जारी रखा था।

एक बार हमारी पार्टी की तरफ से सुधरने को लेकर भी सुझाव भेजा गया था, पर वह अपने कुकर्म से बाज नहीं आया बल्कि खूंटी व रांची एसपी के देख-रेख में एक नया संगठन बनाया। उस संगठन का नाम रखा 'शांति सभा', इस संगठन को एसपीओ सबको मिलाकर ही बनाया गया है। उसके प्रमुख सरगना के रूप में असियन पुर्ती भी था। इनलोगों का काम था पार्टी संगठन को जो भी व्यक्ति मदद देगा, उसके घर-परिवार को मार दिया जाएगा, इस तरह की मीटिंग पूरे खूंटी, मारांगहादा, अड़की इलाका में 30-40 मोटरसाईकिल में घुम-घुमकर कर रहा था। इतना ही नहीं गांव-गांव में जाकर जनता को धमकाता था, गाली-गलौज व मार-पीट करके जबरन मीटिंग में बैठाता था, अगर मीटिंग में कोई जनता नहीं पहुंचने पर उसके ऊपर जुर्माना के रूप में 500/-रू. रखा था एवं उनलोगों से मोटरसाईकिल में घूमने के लिए 20-40 रू. करके प्रत्येक घर से लेता था। इस तरह का डर जनता के बीच पैदा करके पूरे इलाके में रखा था एवं कुछ-कुछ हमारी समर्थक जनता डर के मारे सरेंडर तक भी किया।

अपने कुकर्मों की वजह से वह बहुत दिन से पीएलजीए के निशाने पर था। जब हमारे पीएलजीए एवं मिलिशिया के साथी को मौका मिला, तब जाकर बड़ी साहस के साथ, जबकि दोनों तरफ सामने ही पुलिस कैम्प है, पुलिस के बीच में घुसकर असियन पुर्ति को 20 सितम्बर, 2017 को मार गिराया एवं उसका मोबाइल, पर्स एवं मोटरसाईकिल, जो पुलिस ने उसको दिया था, उसको उठाकर साथ में लेते आया। उसके पर्स मिले कागजातों से पता चला कि पहले तो उसको एसपीओ में रखा था, बाद में पुलिस में परमानेंट नौकरी के रूप में रखा गया था। पीएलजीए की इस बहादूरीपूर्ण एक्शन से जनता में काफी अच्छा प्रभाव पड़ा। ★

गीत

शहादत वरण करो-2
मत मांगों कोई भीख दया का
ऐसा यारो प्रण करो।।

मांग रही है, वसुधा माता
वीरों का बलिदान।
मौत है हर जन्मधारी का
एक अंतिम परिणाम।
मौत से मत तू डरो अब यारो,
मौत से मत तू डरो।। शहादत.....

स्वाधीनता-स्वतंत्रता
जनवादी-जनतंत्रता।
सर्वहारा नेतृत्व में,
मालेमा का मंत्र का।
साम्यवाद के लक्ष्य में यारो
आगे सदा बढ़ो।। शहादत.....

परचम तेरा लाल-लाल है
सब रंगों से प्यारा।
हंसिया-हथौड़ा युक्त पताका
सबका जीवन आधार।
एकता-संघर्ष-एकता की यारो,
नीति ग्रहण करो।। श्हादत.....

★

.....बहुत पहले ही पूंजीवादी इतिहासकार वर्गों के इस संघर्ष के ऐतिहासिक विकास का और पूंजीवादी अर्थशास्त्री वर्गों की आर्थिक बनावट का वर्णन कर चुके थे। मैंने जो नयी चीज की, वह यह सिद्ध करना था कि: 1. वर्गों का अस्थित्व उत्पादन के विकास के खास ऐतिहासिक दौरों के साथ बंधा हुआ है; 2. वर्ग संघर्ष लाजिमी तौर से सर्वहारा के अधिनायकत्व की दिशा में ले जाता है; 3. यह अधिनायकत्व स्वयं सभी वर्गों के उन्मूलन तथा वर्गहीन समाज की ओर संक्रमण मात्र है।....

-सर्वहारा के महान शिक्षक मार्क्स (वेडेमेयर के नाम पत्र से साभार)

एक छापामार कैम्प में आयोजित पीएलजीए स्थापना दिवस समारोह की तस्वीर (ऊपर)
एवं झूठा गणतंत्र दिवस के विरोध में घोषित काला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की तस्वीर (नीचे)